आरआईएस
वार्षिक रिपोर्ट
2016–17

अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

विषय वस्तु

महानिदेशक की रिपोर्ट		*i*
I	नीतिगत अनुसंधान	1
II	नीति शोध पत्र	41
III	नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ	43
IV	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	126
V	प्रकाशन कार्यक्रम	134
VI	आकंड़े एवं सूचना केंद्र	140
VII	मानव संसाधन	143
VIII	वित्तीय विवरण	149

आरआईएस संचालन परिषद

अध्यक्ष

राजदूत श्याम सरन
(23 जनवरी 2017 तक)

राजदूत हरदीप सिंह पुरी
(16 मार्च 2017 से)

उप–अध्यक्ष

राजदूत वी.एस. शेषाद्री
(30 मार्च 2017 तक)

पदेन सदस्य

डॉ. एस. जयशंकर
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

सुश्री रीता ए. तेवतिया
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री शक्तिकांत दास
सचिव
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

प्रोफेसर आशुतोष शर्मा
सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री अमर सिन्हा
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय

अपदेन सदस्य

डॉ. बलदेव राज
महानिदेशक
नेशनल इन्सिटिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बेंगलुरू

श्री जयंत दासगुप्ता
प्रबंध भागीदार, लक्ष्मीकुमारन एवं श्रीधरन एटोरनेएस तथा डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व राजदूत

श्री शेषाद्री चारी
वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक एवं लेखक
नई दिल्ली

श्रीमति श्यामला गोपीनाथ
अध्यक्षा, एचडीएफसी बैंक

सदस्य सचिव (पदेन)

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

राजदूत एस. टी. देवारे
पूर्व सचिव
विदेश मंत्रालय

सदस्य

प्रोफेसर एन. एस. सिद्धार्थन
मानद प्राध्यापक, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक
भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

सुश्री सिंधुश्री खुल्लर
भूतपुर्व सीईओ, नीति आयोग

श्री संतोष झा
संयुक्त सचिव, (पीपीएंडआर, जीसीआई)
विदेश मंत्रालय

विशेष आमंत्रित सदस्य

प्रोफेसर रथिन रॉय
निदेशक
राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान

डा. नागेश कुमार
निदेशक, सामाजिक विकास डिवीज़न,
युनाइटेड नेशन्स इकोनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पेसिफिक बैंकॉक, थाइलैंड

सदस्य सचिव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

महानिदेशक की रिपोर्ट

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

आरआईएस में समीक्षाधीन अवधि के दौरान अनुसंधान के साथ–साथ नीतिगत संवादों में भी काफी तेजी से वृद्धि हुई है। आरआईएस इस दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर कार्यरत रहा वे हैंः सतत विकास लक्ष्य, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, आईबीएसए, दक्षिण–दक्षिण विकास सहयोग, आईओआरए–ब्लू इकोनॉमी, बिम्सटेक, एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी), आसियान–भारत, दक्षिण एशिया विकास सहयोग, विज्ञान कूटनीति, इत्यादि। आरआईएस के अनुसंधान एजेंडे के जिन चार प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत इन सभी पर विस्तार से चर्चा हुई वे हैं : वैश्विक मुद्दे एवं विकास सहयोग की संरचना; व्यापार, निवेश एवं क्षेत्रीय सहयोग पर पहल; व्यापार में सुविधा; कनेक्टिविटी एवं क्षेत्रीय एकीकरण; नई प्रौद्योगिकियां एवं विकास से जुड़े मुद्दे।

माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में 7 अक्टूबर 2016 को *'भारत और सतत विकास लक्ष्यः आगे की राह'* नामक आरआईएस प्रकाशन का विमोचन किया। इस प्रकाशन में 19 व्यापक प्रपत्र (पेपर) हैं जिनमें परस्पर संबंधित दो थीम 'वित्त' और 'प्रौद्योगिकी' के साथ एसडीजी के पूर्ण विस्तृत परिवेश को समाहित किया गया है। इस वर्ष नीति आयोग, भारत में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर आरआईएस ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के एजेंडे के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय स्तर के कई परामर्शों का आयोजन किया है।

आरआईएस ने बिम्सटेक और आईबीएसए से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए दो प्रमुख पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं वे हैंः *'बिम्सटेक द रोड अहेड'* और *'आईबीएसए – ट्रिनिटी फॉर डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी'*। इनका विमोचन माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा किया गया।

क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संस्थान ने जिन विषयों पर अपने प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया है वे हैंः अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे एवं विकास नीति; दक्षिण–दक्षिण सहयोग; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत एवं व्यवहार पर ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम; व्यापार सुविधा पर कार्यशालाएं; और क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण इत्यादि।

आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) भी आसियान–भारत आर्थिक एकीकरण को मजबूत बनाने और इसे गहन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में शामिल रहा है। रिपोर्ट में इसके विस्तृत कार्यकलाप कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है। एआईसी के सौजन्य से प्रमुख प्रकाशनों में *'आसियान–भारत हवाई कनेक्टिविटी रिपोर्ट'* और *'भारत–जापान सीईपीए'* एवं *'भारत–सिंगापुर सीईसीए'* का आकलन शामिल हैं।

आरआईएस के सौजन्य से हासिल होने वाली शोध सामग्री का प्रचार–प्रसार करना आरआईएस की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस उद्देश्य की पूर्ति आरआईएस की जीवंत वेबसाइट और विभिन्न प्रकाशनों के जरिए होती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरआईएस के सौजन्य से प्रमुख प्रकाशनों में कई रिपोर्ट जैसे कि *दक्षिण–दक्षिण सहयोग 2016; दक्षिण–दक्षिण क्षमता निर्माण कार्यक्रम से प्राप्त अंतर्दृष्टिय स्वास्थ्य, स्वभाव और जीवन की गुणवत्ता; ब्रिक्स वेलनेस इंडेक्स की ओर* इत्यादि शामिल हैं।

आरआईएस अपने अनुसंधान एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए देश–विदेश के विभिन्न नेटवर्कों और प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) दोनों से ही निरंतर गठबंधन कर रहा है। इनमें कई संस्थान जैसे : ईआरआईए; आईओआरए सचिवालय; एसएसीईपीएस साझेदार (नीतिगत अध्ययन संस्थान, कोलंबो; नीतिगत संवाद केंद्र, बांग्लादेश ; समन्वित विकास अध्ययन संस्थान, नेपाल; लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय, पाकिस्तान और सतत विकास नीति संस्थान, पाकिस्तान); एशिया फाउंडेशन; ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन; शारदा विश्वविद्यालय; राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, बेंगलुरू; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; वित्त मत्रांलय; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; आयुष मंत्रालय; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान इत्यादि शामिल हैं। हम आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रम के साथ उनके सक्रिय और प्रभावकारी सहयोग के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं।

मैं इस अवसर पर आरआईएस की संचालन परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों और अनुसंधान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं विशेषकर श्री हरदीप पुरी और श्री सुधीर देवारे का धन्यवाद करता हूं। मैं संस्थान के विभिन्न कार्यकलाप कार्यक्रमों के संचालन के लिए मूल्यवान जानकारियां एवं सहयोग देने के लिए अनुसंधान संकाय और स्टाफ की तरफ से आरआईएस में अपने सहयोगियों का भी आभारी हूँ। हम आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रमों का निरंतर समर्थन करने के लिए विदेश मंत्रालय के आभारी हैं।

lfpu pr|o|nh

I

नीतिगत अनुसंधान

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

डब्ल्यूटीओ के समक्ष मुद्दे

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. एस.के. मोहंती, डॉ. रवि श्रीनिवास, डॉ. सब्यसाची साहा और डॉ. प्रियदर्शी दास

विश्व व्यापार से संबंधित मुद्दों को आरआईएस के अनुसंधान कार्यक्रम में काफी प्रमुखता दी जाती रही है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अस्तित्व में आने के बाद से ही आरआईएस ने कई अध्ययन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। यही नहीं, आरआईएस ने वाणिज्य विभाग सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कई परामर्श बैठकों का आयोजन किया है। इसके साथ ही आरआईएस ने अपने प्रमुख प्रकाशन यथा *'विश्व व्यापार एवं विकास रिपोर्ट'* को भी प्रस्तुत किया है जिसमें विश्व व्यापार संगठन के समक्ष मौजूद प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ब्यूनस आयर्स में होने वाले 11वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने सम्मेलन के एजेंडे पर अनेक नीतिगत सारपत्र पेश करने का लक्ष्य रखा है।

दिसंबर 2017 में ब्यूनस आयर्स में होने वाले डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मुद्दे

इस सम्मेलन में दोहा विकास एजेंडे (डीडीए) पर आगे बढ़ने के लिए कृषि सब्सिडी एवं खाद्य सुरक्षा जैसे पुराने मुद्दों के अलावा निवेश में सहूलियत, ई–कॉमर्स और मत्स्य पालन पर सब्सिडी जैसे नए मुद्दों पर भी चर्चा की जानी है। भारत कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का हल खोजने में काफी दिलचस्पी रखता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापार के नियम किसानों को सहायता प्रदान करने एवं सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्य पदार्थों का भंडारण करने और खाद्य सुरक्षा की सुविधा देने के मार्ग में आड़े न आएं। भारत के साथ–साथ कई विकासशील देशों ने यह बात रेखांकित की है कि विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी व्यापार के स्वरूप

को विकृत कर देती है। सम्मेलन में किस तरह का हल उभर कर सामने आएगा, यह स्पष्ट नहीं है। इस सम्मेलन में संभवतः कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकल पाएगा। हालांकि, इस दिशा में ठोस प्रगति सम्मेलन के नतीजे के रूप में सामने आ सकती है।

- दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) में विकासशील देशों की बहुत रुचि तो है, लेकिन इस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रही है, कई विकसित देशों में संरक्षणवादी प्रवृत्तियां काफी जोर पकड़ती जा रही हैं और अब द्विपक्षीय/क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को अहमियत दी जाने लगी है, इसलिए जब तक पुरजोर प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक डीडीए की दिशा में कोई भी प्रगति नहीं होगी और विभिन्न देश इसकी अनदेखी करना पसंद करेंगे। ऐसे में क्या किसी कार्य योजना के जरिए डीडीए में रुचि फिर से बढ़ाई जा सकती है, यह एक प्रमुख मुद्दा है।
- ई–कॉमर्स विशेषकर भारत एवं चीन जैसे विकासशील देशों में काफी तेजी से अपनी पैठ बनाता जा रहा है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ई–कॉमर्स को भी एक विषय या प्रसंग के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव रखे गए हैं। भारत इसको लेकर काफी सतर्क है। यही कारण है कि भारत डब्ल्यूटीओ के तहत ई–कॉमर्स पर किसी संधि/समझौते के लिए वार्ताओं या प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने के पक्ष में नहीं है। इस क्षेत्र में विनियामक एवं नीतिगत कदम की गुंजाइश बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वाणिज्यिक हितों से परे हटकर ई–कॉमर्स को विशेष अहमियत देता है और 'डिजिटल इंडिया' से जुड़ी अपनी पहलों के साथ उसे एकीकृत करना चाहता है।
- मत्स्य पालन पर सब्सिडी एक और ऐसा मुद्दा है जो एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। मत्स्य पालन क्षेत्र के दीर्घकालिक टिकाऊपन को देखते हुए 'गैर जिम्मेदाराना ढंग से मछली पकड़ने' और 'असुरक्षित ढंग से मछली पकड़ने' को प्रोत्साहित करने वाली सब्सिडी पर निश्चित रूप से सवालिया निशान लगाने होंगे। हालांकि, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर छोटे मछुआरे हैं और जहां के मत्स्य पालन क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता पर बड़ी ही बारीकी से विचार किया जा रहा है उसके लिए घरेलू हितों की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि भारत इस मुद्दे पर बड़ी सावधानी के साथ चर्चा कर रहा है।
- निवेश में सहूलियत एक और नया मुद्दा है। यहां भी सवाल विभिन्न देशों द्वारा नीतिगत और नियामकीय कदम उठाने की गुंजाइश को लेकर है। यही कारण है कि भारत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान विचार–विमर्श के एक नए विषय के रूप में इस पर बहस के लिए विशेष जोर देने के पक्ष में नहीं है।

अतः नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान विचार–विमर्श किए गए अनसुलझे मुद्दों के अलावा कुछ नए मसलों पर भी चर्चा के लिए विशेष जोर दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, टीएफए पर अमल से जुड़ा मुद्दा भी है। इस बात की प्रबल संभावना है कि जहां एक ओर पुराने मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से संभवतः हल नहीं किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर नए मुद्दों को आगे विचार–विमर्श के लिए प्रमुख विषयों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नए मुद्दों पर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी।

विकासशील देशों पर मत्स्य सब्सिडी का असर

प्रो. एस. के. मोहंती/सुश्री पंखुड़ी गौड़

व्यापार, पर्यावरण और विकास पर मत्स्य सब्सिडी के असर को लेकर अनगिनत आलेख लिखे जा चुके हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक मत्स्य स्टॉक पर इसके नकारात्मक असर को लेकर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों पर गंभीर चिंता जताई गई है। हालांकि, इस संबंध में सदस्य देशों में कोई सहमति नहीं हुई है। पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक एवं व्यापार को विकृत करने वाली मत्स्य सब्सिडी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास सुर्खियों में रहे हैं और अब ब्यूनस आयर्स में होने वाले आगामी डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी।

हालांकि, समुद्री पर्यावरण पर मत्स्य सब्सिडी का असर और मत्स्य स्टॉक में कमी मुख्य चिंता का विषय है। 'एफएओ' के मुताबिक, तकरीबन 30 फीसदी वैश्विक स्टॉक को एक ऐसे स्टॉक के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है जहां वर्ष 2014 में अत्यधिक मछलियां पकड़ी गई थीं। यह व्यापक रूप से मान लिया गया है कि मत्स्य सब्सिडी के कारण इस क्षेत्र में आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसका असर खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने साफ तौर पर यह कहा है कि मत्स्य सब्सिडी दरअसल मछली पकड़ने के बेड़े की क्षमता बढ़ाए जाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे मछली स्टॉक के संरक्षण के उनके प्रयासों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मत्स्य सब्सिडी का प्रावधान न केवल मछली के स्टॉक के लिए हानिकारक है, बल्कि यह पूरी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है, जिससे समुद्री जीवों का समस्त परिवेश प्रभावित होता है।

इसके अलावा, औद्योगिक और कारीगरी या कुटीर ढंग से मछली पकड़ने के लिए मत्स्य सब्सिडी देने के पीछे का तर्क एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह देखा गया है कि इस तरह की सब्सिडी से बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने की वाणिज्यिक या औद्योगिक गतिविधियां लाभान्वित हो रही हैं और इस तरह की गतिविधियों से मत्स्य स्टॉक कम होता जा रहा है। हालांकि, कुटीर मछुआरों को दी जा रही इस तरह की सब्सिडी मत्स्य स्टॉक पर ज्यादा दबाव डाले बिना ही उनके भोजन और आजीविका सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान दे रही है। अतः विश्व व्यापार संगठन में व्यवसायिक और जीवन निर्वाह की दृष्टि से मछली पकड़े जाने को ध्यान में रखते हुए मत्स्य सब्सिडी समाप्त करने के मुद्दे पर अलग–अलग चर्चा की जानी है।

हालांकि, मत्स्य सब्सिडी का सटीक अनुमान लगाने के लिए इस विषय की एक ठोस परिभाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व व्यापार संगठन, एफएओ, ओईसीडी, एपीईसी, इत्यादि ने मत्स्य सब्सिडी को अलग–अलग ढंग से परिभाषित एवं वर्गीकृत किया है और इस वजह से उनके अनुमानों में काफी भिन्नता है। अतः एकल वैश्विक परिभाषा और पद्धति को अपनाया जाना चाहिए जिससे मत्स्य सब्सिडी में कमी करने से संबंधित एसडीजी लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। संबंधित अध्ययन का उद्देश्य इस सवाल का जवाब देना है कि मत्स्य सब्सिडी ने मछली के स्टॉक पर आखिरकार किस तरह से असर डाला है। मछली के स्टॉक पर मंडराते खतरे को भांपते हुए मत्स्य सब्सिडी के रूप में दिए जाने वाले अनुदान और वित्तीय सहायता के असर का आकलन करने की सख्त जरूरत है। अध्ययन के तहत यह भी पता लगाया जाएगा कि केवल छोटे एवं कुटीर मछुआरों के लिए ही सब्सिडी का प्रावधान करने से कैसे लंबे समय तक मत्स्य स्टॉक के टिकाऊ जैविक स्तर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अतः मत्स्य सब्सिडी के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने और नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

प्रथम चरण के एक हिस्से के रूप में आरआईएस ने न केवल भारत में 'राष्ट्रीय परामर्श' की मेजबानी की, बल्कि न्यूयॉर्क और अदीस अबाबा में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख बैठकों के दौरान भागीदार संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर अलग से कई आयोजनों की भी मेजबानी की। भारत में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर आरआईएस ने वर्ष 2016 में एसडीजी और भारत पर व्यापक जानकारियों वाली एक पुस्तक भी पेश की थी जिसमें सभी 17 एसडीजी और कार्यान्वयन के मुद्दों से जुड़े उपायों को शामिल किया गया था। एसडीजी पर आरआईएस का कार्यकलाप कार्यक्रम उन राष्ट्रीय परामर्शों की श्रृंखला के लगभग पूरा हो जाने के साथ ही संभवतः अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है जिनकी मेजबानी विशिष्ट लक्ष्यों पर आरआईएस ने नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर की थी, ताकि देश स्तर पर अपनाने के लिए नीतिगत चर्चाओं को सुचारू बनाया जा सके।

द्वितीय चरण में आरआईएस की अंतर्निहित विशेषज्ञता के साथ–साथ आरएसी के सुझाव के अनुरूप एसडीजी पर आरआईएस की अनुसंधान टीम ने एक केंद्रित दृष्टिकोण अपना लिया है। तदनुसार, विशिष्ट एसडीजी जैसे कि 2,3,4,5,8,9,10,14 और 17 पर गहन अनुसंधान करने का इरादा है।

इन अनुसंधान विषयों में मुख्य एजेंडा एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए रूपरेखा का पता लगाना, जिला स्तर पर कार्यान्वित करना और राष्ट्रीय विकास एवं एसडीजी पर रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय संकेतकों के औचित्य को सत्यापित तथा अनुशंसा करना है। अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में राज्यों में क्षेत्रीय परामर्शों का आयोजन किया जाएगा और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों या मंचों का पता लगाया जाएगा।

एसडीजी 3 : स्वास्थ्य

प्रो. टी.सी. जेम्स और डॉ. रवि श्रीनिवास

इस अध्ययन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी उम्र के लोगों का स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित एसडीजी 3 लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत के समक्ष मौजूद समस्याओं का विश्लेषण करना है। विश्लेषण के आधार पर कुछ ऐसे सुधारात्मक उपायों को सुझाना प्रस्तावित है जो भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की वर्तमान एवं संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशासन के स्तर पर आवश्यक हो सकते हैं। इसके तहत अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए विकास के ढांचों के वैकल्पिक तरीकों की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा। भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में अध्ययन के तहत एसडीजी 3 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतिक कदमों के साथ–साथ स्थानीय विशिष्ट नीति पर विचार करना भी प्रस्तावित है। संकेतकों के लिए एक मजबूत देशव्यापी निगरानी व्यवस्था विकसित करने में जो चुनौतियां हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एसडीजी 3 के सीमा पार आयाम का भी पता लगाया जाएगा। इस अध्ययन में लगभग 18 से लेकर 24 माह तक लग सकते हैं।

एसडीजी 4 : शिक्षा

डॉ. बीना पांडे

एसडीजी पर आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इस अध्ययन में शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लक्ष्य 4 शिक्षा के सभी

स्तरों पर मुख्य रूप से गुणवत्ता, पहुंच, समता (इक्विटी) और समावेशन (क्यूएईआई) पर फोकस करता है। भारत को पंद्रह वर्ष की समय सीमा के भीतर लक्ष्य 4 प्राप्त करने के लिए क्यूएईआई एक व्यवहार्य मॉडल की पेशकश कर रहा है जिसमें शिक्षा का व्यापक रूप से ध्यान रखा जाता है। अध्ययन के तहत शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही अध्ययन के तहत लक्ष्य 4 से जुड़े उद्देश्यों को संदर्भित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए उन्हें नई शिक्षा नीति तैयार करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने पर इसके सकारात्मक असर में एकीकृत किया जाएगा। यही नहीं, भारत के भीतर उपलब्ध शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव है। अध्ययन के आखिर में एक परिचर्चा पत्र पेश किया जाएगा।

एसडीजी 5 : स्त्री–पुरुष समानता

डॉ. बीना पांडे

एसडीजी 5 पर अध्ययन मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, रोजगारों तक पहुंच, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और महिलाओं एवं लड़कियों की गरिमा, सुरक्षा तथा आजादी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके तहत अन्य लक्ष्यों, विशेषकर गरीबी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ जल और स्वच्छता एवं ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित लक्ष्यों के साथ एसडीजी 5 को जोड़ने की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के तहत यह पता लगाया जाएगा कि एसडीजी 5 एवं इसके लक्ष्य आखिरकार कैसे संकेतकों में तब्दील होंगे और क्या ये निगरानी के लिए प्रभावकारी एवं उपयोगी साबित होंगे। इसके तहत महिलाओं को प्रभावित करने वाले/उनसे संबंधित मौजूदा कानूनों पर भी गौर किया जाएगा, ताकि उनमें सही सामंजस्य बैठाते हुए उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके और इसके साथ ही उभरती जरूरतों पर अतिरिक्त विधायी उपायों या संशोधनों का भी मार्ग प्रशस्त हो सके। अध्ययन के तहत विभिन्न मंत्रालयों, उपक्रमों, स्थानीय निकायों इत्यादि के बीच प्रभावकारी सामंजस्य सुनिश्चित करने के तरीकों का भी पता लगाया जाएगा, ताकि संबंधित प्रयासों में दोहराव और संसाधनों की बर्बादी से बचा जा सके।

एसडीजी 8 एवं 9 : बेहतरीन कार्य एवं आर्थिक विकास और उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सब्यसाची साहा और सुश्री प्रतिभा शॉ

देश में आर्थिक विकास के लिए भारत के बाह्य क्षेत्र से लाभ उठाने हेतु आरआईएस ने विगत वर्षों के दौरान भारत के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जिनमें वस्तुओं एवं सेवा के व्यापार और निवेश को कवर किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने से संबंधित भारत की मौजूदा चुनौतियों के संदर्भ में आरआईएस में जारी अनुसंधान के तहत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह अध्ययन औद्योगिक नीतियों और क्षेत्रवार सब्सिडी के संदर्भ में किया जा रहा है। वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों की विशेषता दर्शाने वाले छोटे वक्र के दोनों ही सिरों पर अधिक से अधिक मूल्य वर्धन के लिए न केवल श्रम गहन क्षेत्रों, बल्कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों पर भी विशेष जोर दिया गया है। आरआईएस में अनुसंधान की यह कड़ी

रोजगारों और औद्योगीकरण से जुड़े एसडीजी 8 और 9 पर आरआईएस के अनुसंधान प्रयासों के पूरक के तौर पर है।

एसडीजी 10 और 12: कम विषमता और सतत खपत एवं उत्पादन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सब्यसाची साहा, और सुश्री प्रतिभा शॉ

एसडीजी की अवधारणा एवं उद्देश्य वैश्विक और राष्ट्र दोनों ही स्तरों पर व्याप्त विषमताओं को कम करना है (जैसा कि एसडीजी 10 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है) और देशों एवं समाजों को टिकाऊ तौर–तरीकों (खपत और उत्पादन) को अपनाने के लिए विवश करना है (जैसा कि एसडीजी 12 में विशेष जोर दिया गया है)। वैश्विक विषमताओं, विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ विशेष एवं अलग व्यवहार के क्षेत्र में तय किए गए कई लक्ष्यों, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार एलडीसी एवं ओडीए के जरिए वैश्विक संसाधनों के समान वितरण, वित्तीय प्रवाह और एफडीआई पर आरआईएस अपनी स्थापना के समय से ही निरंतर अनुसंधान करता रहा है। व्यापार एवं निवेश और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के कॉलम के तहत समान क्षेत्रों में जारी अनुसंधान को और आगे बढ़ाया जाएगा एवं उसे नई दिशा दी जाएगी, ताकि एसडीजी के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित किया जा सके और बहुपक्षीय प्रक्रिया, क्षेत्रीय सहयोग एवं राष्ट्रीय नीतियों का मार्गदर्शन किया जा सके।

आरआईएस आय आधारित उपायों से परे हटकर नागरिकों की भलाई के लिए आर्थिक विकास की गुणवत्ता की राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा से संबंधित अनुसंधान में शामिल रहा है। इसे उभरते देशों विशेषकर ब्रिक्स के संदर्भ में भी 'ब्रिक्स वेलनेस इंडेक्स' नामक एक मापदंड (टेम्पलेट) के रूप में विस्तारित किया गया है, जो टिकाऊ जीवन शैली, समग्र स्वास्थ्य, सतत ऊर्जा खपत, अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग के पैमानों पर आधारित है। वेलनेस इंडेक्स पर आरआईएस का अनुसंधान एसडीजी 12 के उद्देश्यों के पूरक के तौर पर है जिस ओर निकट भविष्य में आरआईएस संकाय का व्यापक ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है।

एसडीजी–14: स्वस्थ महासागर/नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति

प्रो. एस. के. मोहंती/डॉ. प्रियदर्शी दास/सुश्री पंखुड़ी गौड़/सुश्री सानुरा फर्नांडीज/सुश्री उपासना सीकरी

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)–14 में स्वामित्व का स्तर कई देशों में बहुत अधिक रहा है और कई देशों ने अपनी परिप्रेक्ष्य विकास योजनाओं में लक्ष्य की मूलभूत विशेषताएं शामिल कर ली हैं। समुद्र तटवर्ती देश और छोटे द्वीप विकासशील देश (एसआईडीएस) महासागरों के संरक्षण और अपने संसाधनों की निरंतरता के लिए एसडीजी–14 को बढ़ावा देने वाले प्रमुख देशों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हालांकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा और लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिभाषा एवं पद्धति से जुड़े मुद्दों सहित व्यापक निहितार्थ वाली अपेक्षाएं अत्यंत महत्वाकांक्षी रही हैं। हालांकि, एसडीजी–14 के अपेक्षित नतीजे तय समय सीमा में आ जाने की उम्मीद है।

नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) संसाधनों, विशेषकर महासागर संसाधनों का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास की गति बढ़ाने वाले एक वैकल्पिक विकास प्रतिमान के रूप में उभर कर सामने आ रही है। यह तथ्य निश्चित तौर पर विशेष अहमियत रखता है क्योंकि जहां एक ओर भूमि संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर

समुद्री संसाधन इस खाई को पाटने के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, बशर्ते कि उनके संरक्षण के लिए प्रभावकारी नजरिया हो। नीली अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के जरिए समुद्री संसाधनों के आर्थिक लाभों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः एक ठोस आधार के रूप में नीली अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करना और एसडीजी–14 की दिशा में काम करना उपयोगी साबित होगा। महासागरों की निरंतरता अथवा इन्हें अक्षुण्ण रखने का मुद्दा आम तौर पर इन आयामों पर केंद्रित होता हैः आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक। एसडीजी–14 में उल्लिखित लक्ष्यों पर अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि इस लक्ष्य का अधिक झुकाव पर्यावरणीय आयाम के प्रति है। ऐसे में सामाजिक और आर्थिक आयाम थोड़े असंतुलित से हो गए हैं। नीली अर्थव्यवस्था से जुड़ी रणनीति इस विषम विकास को संतुलित करने में मददगार साबित हो सकती है।

'नीली अर्थव्यवस्था' की अवधारणा के तहत समुद्र और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के बारे में चर्चा की जाती है। एसडीजी–14 और ब्लू इकोनॉमी के अधिदेशों में काफी हद तक सामंजस्य है। हालांकि, एसडीजी–14 के मुकाबले ब्लू इकोनॉमी का अधिदेश कहीं ज्यादा स्पष्ट है। यही कारण है कि इनके बीच व्यापक सामंजस्य है। 'ब्लू इकोनॉमी' में पारंपरिक क्षेत्र जैसे कि मत्स्य पालन, जलीय कृषि, तटीय पर्यटन, खनन, जहाज निर्माण एवं समुद्री परिवहन, इत्यादि और गैर–पारंपरिक क्षेत्र जैसे कि गैर–पारंपरिक बहुमूल्य वस्तुएं, गहरे समुद्र में खनन, गैर–अक्षय ऊर्जा, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न शौकिया सेवाएं जैसे कि मोती की खेती, समुद्री पारिस्थितिकी–पर्यटन शामिल हैं। नीली अर्थव्यवस्था और एसडीजी–14 की तुलना करने पर यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि एसडीजी–14 दरअसल ब्लू इकोनॉमी का एक उपवर्ग है।

हालांकि, समुद्री संसाधनों का संग्रहण धीरे–धीरे कम होते जा रहा है जिससे भारी चिंता बन रही है और भविष्य में संसाधनों के उपयोग के लिए समुद्री संसाधनों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। अतः एसडीजी–14 लक्ष्य की प्राप्ति आवश्यक है जो समुद्री और तटीय संसाधनों को संरक्षित एवं सुरक्षित करेगा और इसके साथ ही संसाधनों की दोबारा भराई या पुनर्भरण करने में भी मदद करेगा। इस अध्ययन के तहत एसडीजी–14 एवं ब्लू इकोनॉमी के बीच आपसी नाता स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और विभिन्न देश एसडीजी–14 पर अमल के परिणामों का उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों में ही नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने में कर सकते हैं। यह नीली अर्थव्यवस्था पर आरआईएस का दूसरा खंड (पुस्तक) होगा। यह मोनोग्राफ (विशेष लेख) आरआईएस की एक पहल है और इसके वर्ष 2018 के मध्य में पूरा हो जाने की उम्मीद है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)–17 : लक्ष्यों के लिए साझेदारियां

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सब्यसाची साहा, और सुश्री प्रतिभा शॉ

एसडीजी में अंतिम लक्ष्य यथा एसडीजी 17 सार्वभौमिक रूप से एवं व्यापक ढंग से शेष 16 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यान्वयन के साधन का प्रतीक है। इसके लिए वित्तीय एवं अन्य संसाधनों के पर्याप्त प्रावधान, उपयुक्त, किफायती एवं सुलभ तकनीकी समाधानों, क्षमता निर्माण, विशेष रूप से व्यापार एवं वित्त के क्षेत्र में वैश्विक व्यवस्थाओं को समायोजित करने, हितधारकों की साझेदारियों और निगरानी के लिए बेहतर क्षमताओं एवं प्रभावकारी पैमानों की आवश्यकता है। आरआईएस अपनी स्थापना के समय से ही व्यापार, निवेश, विकासशील देशों की संभावनाओं का पता लगाने के

लिए वित्त एवं प्रौद्योगिकी और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान इस देश की विकास प्राथमिकताओं की रक्षा करने से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर अनुसंधान में काफी तल्लीनता से जुड़ा रहा है। विकास के लिए वित्त पोषण, क्षमता निर्माण के लिए सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) तक पहुंच एवं नियमन के साथ–साथ सतत विकास से जुड़े पैमाने/संकेतक आरआईएस द्वारा क्षेत्रीय और दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर किए गए अनगिनत अध्ययनों के अभिन्न अंग रहे हैं। आरआईएस के हाल ही में आये प्रकाशनों ने एसडीजी के परिप्रेक्ष्य से इस तरह के मुद्दों का पता लगाया है। स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण, बहु–हितधारक साझेदारियों और डेटा एवं निगरानी से संबंधित नीतिगत रूपरेखा को मजबूत करने के लिए आरआईएस ने भारत में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण पर एक नया शोध कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि जिला स्तर पर नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग और वैश्विक सहायता की संरचना

एजेंडा 2030 के लिए उत्तर–दक्षिण प्रवाह और सीमा–पार सहयोग का तुलनात्मक विश्लेषण

प्रो. सचिन चतुर्वेदी और प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती

यह जर्मन विकास संस्थान, बॉन, जर्मनी के साथ आरआईएस की एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना है, जिसके लिए जर्मन विकास संस्थान ने वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। इस परियोजना का शीर्षक है 'सामंजस्य (एकजुटता) या विचलन : एजेंडा 2030 के समर्थन में सतत विकास के लिए सीमा पार सहयोग'। इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: विकास सहयोग के प्रति ओईसीडी और एसएससी के नजरिए में अंतर की मौलिक एवं गैर–सौदेबाजी विशिष्टताओं की पहचान करना; सामूहिक कदम के जरिए सतत विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाते वक्त कुछ उपयोगी वस्तुओं को विश्व भर में सभी लोगों को मुहैया कराने के लिए सामंजस्य के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना; वैश्विक सार्वजनिक चीजों जैसे शांति बनाये रखने (पीस कीपिंग), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जीएवीआई, वैक्सीन गठबंधन, अनुसंधान सहयोग और इंटरनेट का सृजन करने के प्रयासों के तहत एक बहु–केंद्र संस्थागत ढांचे में सामूहिक कदम उठाने की विशिष्टताओं की पहचान करना।

आरआईएस की टीम के योगदानों में शांति बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जीएवीआई, वैक्सीन (टीका) गठबंधन पर अध्ययन के लिए वैचारिक रूपरेखा विकसित करना और मामला अध्ययन (केस स्टडी) तैयार करना शामिल हैं। इस गतिविधि से जुड़े प्रथम प्रपत्र (पेपर) का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही प्रकाशन के लिए भेज दिया जाएगा।

भारतीय दक्षिणीय सहयोग पर आंकड़ों का एकत्रीकरण

प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. सुशील कुमार

आरआईएस एक आंकड़े एकत्रीकरण करने और दक्षिणीय सहयोग के ढांचे में भारत की विकास सहायता को अंतर्निहित करने पर काम करता रहा है। इस डेटाबेस की समयावधि वर्ष 1946 से लेकर अब तक है। इन आंकड़ों की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें विकास संविदा की सभी महत्वपूर्ण रूपरेखाएं जैसे कि अनुदान, ऋण राशि

(क्रेडिट लाइन), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, व्यापार एवं निवेश, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता शामिल हैं। इस डेटाबेस में द्विपक्षीय प्रवाह के साथ–साथ बहुपक्षीय प्रवाह भी शामिल है। इस डेटाबेस में मंत्रालय–वार भारत के विकास सहयोग के प्रवाह को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, इस डेटाबेस में क्षेत्रवार भारत की विकास सहयोग परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है।

दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/ प्रो.मिलिंदो चक्रवर्ती/ श्री प्रत्यूष

दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने का सैद्धांतिक मॉडल अब तक मापदंड कायम करने वाला बना हुआ है जिसका आधार कई ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता जैसे कि मांग आधारित, बिना–शर्त का, राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए सम्मान, साझा लाभ, राष्ट्रीय स्वामित्व आदि जो पिछले छह दशकों में दक्षिण के साझेदारों के बीच आपसी रजामंदी से विकसित हुए हैं। इसे एक प्रक्रिया के तौर पर पेश किया गया जो उत्तर–दक्षिण सहयोग के प्रयासों को मदद करने वाला है ताकि उत्तर और दक्षिण के नागरिकों के औसत भौतिक जीवन की गुणवत्ता की अभिसारिता को बढ़ावा मिले।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग और त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से विकास साझेदारी में हस्तक्षेप के मामले में हासिल अनुभवों की अच्छी संख्या को देखते हुए, इस अध्ययन का उद्देश्य हैः

- "विकास घटकों' के संदर्भ में विश्व भर में दक्षिण–दक्षिण सहयोग/त्रिकोणीय सहयोग की रूपरेखा का विश्लेषण करना
- भागीदारों के बीच पारस्परिक लाभ बढ़ाने और एसडीजी की उपलब्धियों को समाहित करने में भारत की विकास सहयोग गतिविधियों के योगदान का आकलन करना और मूल्यांकन करना। इसमें जिन पर कोई समझौता नहीं हो सके ऐसे बिना–शर्त के सिद्धांतों और साझेदारों की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाता वे सिद्धांत शामिल हैं
- साझेदार देशों में लोगों से लोगों के संपर्क में बढ़ोतरी करने के माध्यम से विभिन्न संबंधित पक्षों वाले माहौल में एसएससी गतिविधियों को लागू करने के लिए प्रभावी रोडमैप की पहचान करना
- अब तक (परोक्ष सूत्रों) और भारत की ओर से सम्मिलित कुछ चुनिंदा प्रयासों से एकत्रित प्राथमिक आंकड़े, सामुदायिक कार्रवाई के सिद्धांतों, संपत्ति के अधिकारों, लेनदेन की लागत पर एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर दक्षिण–दक्षिण सहयोग के एक सकारात्मक (संचालन) सैद्धांतिक मॉडल को विकसित करना, मुख्य–एजेंट, जानकारी और विकास के संस्थागत विश्लेषण (आईएडी) ढांचे को विकसित करना

भारत के विकास सहयोग के निर्धारक तत्व : एक अर्थमितीय विश्लेषण

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. मनमोहन अग्रवाल और डॉ. सुशील कुमार

आरआईएस भारत के विकास सहयोग के प्रमुख निर्धारक तत्वों का आकलन करने के लिए दो चरणों में काम कर रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य भारत के विकास सहयोग का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न अर्थमितीय तकनीकों जैसे कि प्रॉबिट मॉडलिंग, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर (ओएलएस) आकलन का पता लगाना है। यह अध्ययन व्यापक डेटासेट पर आधारित है जिसमें वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक

की अवधि के दौरान 135 देशों के साथ भारत के विकास सहयोग का आंकलन किया गया है। इसके तहत पहले इस संभावना का अनुमान लगाया जाएगा कि भारत साझेदार देश को कितना विकास सहयोग प्रदान करता है। इस अध्ययन में अवलंबित परिवर्तनीय (वैरिएबल) डेटा एक डमी है जो एक मान (वैल्यू) तब लेता है जब भारत ओईसीडी के प्राप्तकर्ता देशों की सूची में शामिल किसी विकासशील देश को विकास सहयोग देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। इस मामले में कुल मिलाकर 153 देश हैं। दूसरा, भारत जिस देश को विकास सहयोग प्रदान करता है उसे ध्यान में रखते हुए अध्ययन के तहत 2000 अमेरिकी डॉलर के स्थिरांक (कॉन्सटैंट) में उस विकास सहयोग राशि (लॉग) का अनुमान लगाया जाएगा जिसे किसी विशेष विकास साझेदार को देने का वादा किया गया है। इस मॉडल के स्वतंत्र परिवर्तनीय डेटा प्रति व्यक्ति जीडीपी, विकास में फासला, आपदा से प्रभावित लोग, जनसंख्या, दूरी, संयुक्त राष्ट्र में मतदान, राष्ट्रमंडल, द्विपक्षीय निर्यात, संसाधनों में होने वाली कमी, राजनीतिक अधिकार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, (डमी परिवर्तनीय डेटा एशिया और अफ्रीका) हैं। भारत के विकास सहयोग के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत के विकास सहयोग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय डेटा प्राप्तकर्ता की प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से 'जरूरत' है। इसके अलावा, राजनीतिक अधिकारों की ताकत महत्वपूर्ण है। इसी तरह ऋण–पत्रों को मंजूरी के लिए निर्यात हित अहम हैं।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग परियोजनाओं के असर का आकलन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती और श्री प्रणय सिन्हा

चूंकि दक्षिण–दक्षिण सहयोग के असर पर चर्चाएं और उसकी प्रभावकारिता तेजी से बढ़ रही है, इसलिए विकासशील देशों की सरकारों के पास प्रभाव आकलन की एक रूपरेखा होना अत्यंत आवश्यक है। आरआईएस चूंकि एसएससी संबंधी मुद्दों से अत्यंत गंभीरतापूर्वक जुड़ा हुआ है, इसलिए आकलन रूपरेखा का विचार मौजूदा प्रयासों से काफी मेल खाता है। आने वाले समय में प्रभाव आकलन की रूपरेखा के साथ 'एसएससी की समझ' को जोड़ने के लिए एक पाठ्यक्रम भी विकसित किया जा सकता है। इस तरह के एक कार्यक्रम को वर्ष 2018 के आरंभ में एक 'शीतकालीन अध्ययनशाला (विंटर स्कूल)' के रूप में पेश करने की योजना है।

इस कवायद के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- विकासशील देशों के प्रतिभागियों को विकास सहयोग के प्रभाव आकलन पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन (एक्सपोजर) कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करना।
- एसएससी के असर का आकलन करने के लिए एक ऐसी नई रूपरेखा विकसित करने की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा करना, जो डीएसी द्वारा अपनाई जा रही रूपरेखा से भिन्न हो।

'दक्षिण–दक्षिण सहयोग का ज्ञान देने वाले भारतीय तकनीकी एंव आर्थिक सहयोग कार्यक्रम' के लिए अनुसंधान सामग्री

प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती और श्री प्रणय सिन्हा

आरआईएस के साथ–साथ उससे इतर के हालिया शोध निष्कर्षों के अनुरूप 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग का ज्ञान देने वाले भारतीय तकनीकी एंव आर्थिक सहयोग कार्यक्रम' के पाठ्यक्रम को अब संशोधित कर दिया गया है। नए पाठ्यक्रम की पेशकश नवंबर 2017 से शुरू होने वाले आगामी सत्र से की जाएगी।

छोटे द्वीप विकासशील देश (एसआईडीएस)

विश्व अर्थव्यवस्था में एसआईडीएस की भूमिका

प्रो. एस. के. मोहंती/सुश्री पंखुड़ी गौड़

छोटे एवं विकासशील द्वीप देशों (एसआईडीएस) को सदैव ही आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर देशों के रूप में देखा जाता रहा है, जहां तकनीकी एवं मानव क्षमता अपेक्षा से कम पाई जाती है, काफी दूर अवस्थित होते हैं, वैश्विक व्यापार पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, उष्णकटिबंधीय एवं उप–उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अतिसंवेदनशील स्थलों पर अवस्थित होते हैं, जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, समुद्र तट असुरक्षित होते हैं, उत्पादन स्तर मामूली या नगण्य होता है, आय के असमान वितरण के साथ सीमित मानव एवं संस्थागत पूंजी होती है, अपनी प्रमुख आर्थिक पहलों के वित्तपोषण के लिए अपेक्षाकृत कम घरेलू संसाधन उपलब्ध रहते हैं, इत्यादि। एसआईडीएस को जिन–जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वे केवल व्यापार एवं निवेश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सतत विकास सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी विद्यमान हैं।

हालांकि, एसआईडीएस में ऐसे समुद्री क्षेत्र होते हैं, जो उनके भूमि क्षेत्रों से कहीं बड़े होते हैं और जहां की नीली अर्थव्यवस्था में जबरदस्त आर्थिक संभावनाएं निहित होती हैं। उनके पास बड़े 'ईईजेड' के रूप में विशाल अप्रयुक्त प्राकृतिक पूंजी होती है जिनमें जैव विविधता, मत्स्य पालन, प्रवाल भित्ति, और विभिन्न अन्य समुद्री संसाधन शामिल हैं। एसआईडीएस के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण संभवतः नीली अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है जो विकास और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के बीच संतुलन बैठाएगी। ये अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश और विकास सहयोग में अपनी सहभागिता के मामले में एक या दो अर्थव्यवस्थाओं का सहारा लेती हैं। इसी वजह से उन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों से निपटने में मुश्किलें पेश आती हैं। इस अध्ययन के तहत विश्लेषण करते हुए यह बताया जाएगा कि कैसे एसआईडीएस देश अपने किसी भी आर्थिक जोखिम को समाप्त करने के लिए 'ब्लू इकोनॉमी दृष्टिकोण' का उपयोग कर सकते हैं। अध्ययन के तहत इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि कैसे एसआईडीएस देश मौजूदा व्यापार ढांचे में हासिल अपनी तुलनात्मक बढ़त पर काम कर सकते हैं और दुनिया के शेष हिस्सों को समान रूप से टक्कर देने के लिए अपने पास उपलब्ध पारंपरिक एवं गैर–पारंपरिक संसाधनों का और ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अध्ययन के तहत 'क्षेत्रीय समूहों से इतर अर्थव्यवस्थाओं' के साथ इन देशों की सहभागिता की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा, ताकि उनके यहां आर्थिक समृद्धि बढ़ सके। यह अध्ययन आरआईएस द्वारा संचालित है और इसके वर्ष 2018 में पूरा होने की उम्मीद है।

जी–20 के अंतर्गत व्यापार और निवेष के मामले

प्रोफेसर राम उपेंद्र दास

व्यापार और निवेश अपने आप में उद्देश्य नहीं है, बल्कि विकास से संबंधित उद्देश्यों जैसे रोजगार के अवसरों का सृजन, गरीबी उन्मूलन आदि की प्राप्ति का साधन हैं। वैश्वीकरण तथा राष्ट्रों एवं क्षेत्रों की बढ़ती परस्पर निर्भरता वाले इस दौर में व्यापार और निवेश के प्रवाह का महत्व बहुत अधिक बढ़ चुका है। इन प्रवाहों और इनको संचालित करने वाली द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय नीतिगत व्यवस्थाओं और संस्थाओं की निश्चित प्रकृति ने केवल संचालन की महत्वपूर्ण वैश्विक निहितार्थों वाली

जबरदस्त खामियों को ही रेखांकित किया है, जिन पर उच्च नीतिगत स्तर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। व्यापार और निवेश के वृद्धि और विकास संबंधी महत्वपूर्ण निहितार्थ होने के कारण वैश्विक स्तर पर उच्च स्तरीय ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सफल परिणामों के माध्यम से समग्र वैश्विक आर्थिक निष्पादन सुनिश्चित किए जा सकें। ऐसा संभव बनाने के लिए कुछ निश्चित कार्य बिंदु निर्धारित करने होंगे और उन्हें जी–20 देशों के समक्ष रखना होगा।

इसके आधार पर इस्तांबुल, अंतालिया और बीजिंग में 2015 में तथा बीजिंग में 2016 में टी–20/जी–20 बैठकों में प्रस्तुतियां की गईं। तुर्की में की गई प्रस्तुतियों का प्रभाव जी–20 के चीनी अध्यक्षता वाले एजेंडे पर था।

जीं–20 में एजेंडा 2030

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी/प्रोफेसर राम उपेंद्र दास

विशिष्ट तौर पर जी–20 की जर्मन अध्यक्षता के अंतर्गत इस कार्य का दायित्व ग्रहण किया गया। 2030 एजेंडा, जी–20 के सभी कार्य क्षेत्रों को कवर करता है, जैसा कि इस साल के हेंगझाओ जी–20 शिखर सम्मेलन में स्वीकृत कार्य योजना में उल्लिखित 15 सतत विकास क्षेत्रों (एसडीएस) द्वारा दर्शाया गया है। यह कार्य योजना शेर्पा ट्रेक में तैयार की गई थी और इसका समर्थन विकास कार्य समूह (डीडब्ल्यूजी) द्वारा किया गया। 15 एसडीएस में से ज्यादातर जर्मन टी–20 के अन्य कार्यबलों (वैश्विक स्वास्थ्य के अलावा–यह मामला टीएफ में एकत्र विशेषज्ञों द्वारा कवर नहीं किया गया) द्वारा भी कवर किए गए हैं।

जीडीआई, बॉन की सम्मति से हम 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन से संबंधित तीन सिलसिलेवार प्रश्नों पर कार्य करने का प्रस्ताव करते हैं, जो अपनी नवोन्मेषी विशेषताओं को रेखांकित करता है और जो कार्ययोजना के कार्यान्वयन और विनिर्देशों को अग्रेषित करते समय जी–20 के फोकस में भी है। हमें इन तीन क्षेत्रों में पिछले और मौजूदा विमर्शों को जोड़ने और जी–20 तथा उसके अपने विमर्शों के संदर्भ में उपयुक्त नयी जानकारी और प्रस्तावों को प्रदान की जरूरत है। इनमें जी–20 सदस्य देशों द्वारा कार्यान्वयन, जी–20 में विभिन्न कार्य–वर्गों में नीतिगत सामंजस्य तथा 2030 एजेंडा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बदलावकारी भूमिका शामिल है। इन पर 30 नवम्बर–3 दिसम्बर 2016 में बर्लिन में टी–20 आयोजन के आरम्भ में चर्चा होनी थी।

व्यापार और निवेष के मामलों का वैष्विक संचालन और जीं–20

प्रोफेसर राम उपेंद्र दास

व्यापार और निवेश अपने आप में उद्‌देश्य नहीं है, बल्कि विकास से संबंधित उद्‌देश्यों जैसे रोजगार के अवसरों का सृजन, गरीबी उन्मूलन आदि की प्राप्ति का साधन हैं। वैश्वीकरण तथा राष्ट्रों एवं क्षेत्रों की बढ़ती परस्पर निर्भरता वाले इस दौर में व्यापार और निवेश के प्रवाह का महत्व बहुत अधिक बढ़ चुका है। इन प्रवाहों और इनको संचालित करने वाली द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय नीतिगत व्यवस्थाओं और संस्थाओं की निश्चित प्रकृति ने केवल संचालन की महत्वपूर्ण वैश्विक निहितार्थों वाली जबरदस्त खामियों को ही रेखांकित किया है, जिन पर उच्च नीतिगत स्तर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। व्यापार और निवेश के वृद्धि और विकास संबंधी महत्वपूर्ण निहितार्थ होने के कारण वैश्विक स्तर पर उच्च स्तरीय ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सफल परिणामों के माध्यम से समग्र वैश्विक आर्थिक निष्पादन सुनिश्चित किए जा सकें।

ऐसा संभव बनाने के लिए, कुछ निश्चित कार्य बिंदुओं, जिन पर जी–20 नेताओं को विचार करने की जरूरत है, का खाका तैयार करने के लिए अनुसंधान जारी है। आरआईएस जी–20 प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती रही है और उसने फरवरी 2015 में इस्तांबुल, अंतालया में नवम्बर 2015 और बीजिंग में दिसम्बर 2015 में आयोजित जी–20 बैठकों में भाग लिया था।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

भारत के क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय व्यापार पर अध्ययन – मॉरीशस के साथ सीईसीपीए, मर्कोसुर, कोमेसा, एलएसी व्यापक आर्थिक एवं साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)

भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक एवं साझेदारी समझौता (सीईसीपीए) संयुक्त अध्ययन समूह की रिपोर्ट

प्रो. एस. के. मोहंती/सुश्री पंखुड़ी गौड़/सुश्री सानुरा फर्नांडीज

भारत और मॉरीशस के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध 18वीं सदी से ही रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों में इनका अहम योगदान रहा है। दोनों देशों ने विविध क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों और सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। नवंबर 2003 में 'सीईसीपीए' को अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक सिफारिशें देने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के लिए वार्ताएं वर्ष 2006 में शुरू की गई थीं और वस्तुओं के व्यापार से संबंधित अध्याय पर परस्पर सहमति के साथ–साथ हस्ताक्षर भी किए गए। ऐतिहासिक दोहरा कराधान निवारण समझौते (डीटीएए) पर 10 मई, 2016 को हस्ताक्षर किए गए और साल के आखिर तक जेएसजी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

दोनों देशों के बीच सीईसीपीए वार्ताएं वर्ष 2016 में बहाल हुई थीं। भारत–मॉरीशस सीईसीपीए पर वार्ताओं की बहाली होने पर पहली बैठक 12–13 सितंबर, 2016 को मॉरीशस में हुई थी और जेएसजी रिपोर्ट 2004 को अपडेट करने का निर्णय लिया गया। जेएसजी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से दो टीमों का गठन किया गया। भारत की ओर से आरआईएस की सेवाएं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) द्वारा ज्ञान भागीदार के रूप में ली गईं और उसे मसौदा रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीईसीपीए जेएसजी रिपोर्ट का प्रारंभिक मसौदा आरआईएस द्वारा तैयार किया गया था। आरआईएस ने आरंभ में पृष्ठभूमि, निवेश, सेवा व्यापार, वस्तु व्यापार एवं सामान्य आर्थिक सहयोग पर अध्या यों के साथ–साथ सिफारिशों का सार भी तैयार किया और मॉरीशस में भारतीय समकक्ष ने रिपोर्ट पर अपनी अहम जानकारियां प्रदान कीं। भारत एवं मॉरीशस की टीमों ने 27–28 सितंबर, 2017 को हुए आखिरी दौर में छह अध्यायों पर परस्पर चर्चा की और उनका आदान–प्रदान किया। मसौदा रिपोर्ट में यह अवलोकन किया गया है कि भारत एवं मॉरीशस के बीच व्यापार, निवेश, सेवाओं और सहयोग के अन्य क्षेत्रों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। सीईपीए व्यवस्था के बाद से ही संभावित कल्याण लाभों पर ध्यान केंद्रित एक अध्याय तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और इसे रिपोर्ट में भी

शामिल किया जाएगा। इस अध्ययन को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है और सीईसीपीए जेएसजी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने तक इसे जारी रखा जाएगा।

ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध

प्रो. एस. के. मोहंती/सुश्री पंखुड़ी गौड़/सुश्री सानुरा फर्नांडीज/सुश्री उपासना सीकरी

भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने को प्राथमिकता प्रदान की है। व्यापार, निवेश, सहायता राशि के प्रवाह और जन संपर्क के क्षेत्र में दक्षिण एशिया में अब भारत और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों या देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी का दायरा अतीत के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। 'हार्ट ऑफ एशिया' से संबंधित भारत की हालिया नीति की दृष्टि से भारत–ईरान द्विपक्षीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऊर्जा आयात के लिए ईरान भी खास मायने रखता है। भारत–बांग्लादेश सहयोग अब शुल्क (टैरिफ) उदारीकरण से भी परे चला गया है क्योंकि उन्होंने एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते और समुद्री सहयोग के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने भी एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अफगानिस्तान ने एक पीटीए एवं रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उनके द्विपक्षीय आर्थिक संबंध काफी सुदृढ़ हो गए हैं।

अध्ययन में ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर चार देश–अध्ययन शामिल होंगे। इस अध्ययन का उद्देश्य चयनित दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की मौजूदा स्थिति पर गौर करना और व्यापार एवं निवेश में सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना है। यह अध्याय भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापक भागीदारी समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। ईएचएस, पीटीए, एफटीए, सीईपीए, इत्यादि के लिए बातचीत की संभावनाओं को टटोला जाएगा। अध्ययन के तहत विश्लेषण के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनमें व्यापार संबंधी प्रदर्शन, व्यापारिक क्षमता, निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता, दीर्घकालिक आयात हित, शुल्क दरें (टैरिफ), एनटीबी, व्यापार में विविधीकरण, विकासशील देश से प्रतिस्पर्धा, वरीयता प्रणाली के तहत शुल्क दरों में अंतर, एफडीआई, इत्यादि शामिल हैं। इस तरह की रणनीति के तहत लक्षित उत्पादों, फोकस वाले क्षेत्रों, व्यापारिक क्षमता, निवेश अवसरों, व्यापार नीति में बदलावों, इत्यादि के मामले में विचाराधीन दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों में इस देश की प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। इस अध्ययन का वित्त पोषण भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किए जाने की संभावना है।

भारत–मर्कोसुर पीटीए का विस्तार

प्रो. एस. के. मोहंती/सुश्री उपासना सीकरी

'फोकस एलएसी' कार्यक्रम पर भारत की महाद्वीपीय विशिष्ट रणनीति के बावजूद लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई (एलएसी) क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार का स्तर अपेक्षा से काफी कम रहा है। हाल के वर्षों में एशिया के लिए एलएसी देशों द्वारा अपनाई गई रणनीति के परिणामस्वरूप भारत और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार

संबंधों में काफी सुधार हुआ है। अब भारत इस क्षेत्र के कुछ बड़े देशों जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इत्यादि के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गंतव्य बन गया है। जहां एक ओर भारत से इस क्षेत्र को होने वाले निर्यात में काफी विविधता है जिसमें मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर लैटिन अमेरिकी क्षेत्र से भारत में होने वाला आयात कृषि एवं निम्न प्रौद्योगिकी उत्पादों में केंद्रित है। मर्कोसुर के व्यापार की क्षेत्रीय कवरेज व्यापक थी, लेकिन वेनेजुएला के निलंबन के कारण इसमें काफी गिरावट आई है।

भारत और मर्कोसुर ने एक सीमित अधिदेश के साथ वर्ष 2009 में एक पीटीए पर हस्ताक्षर किए थे। लगभग 450 वस्तुओं पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक घटाने के बावजूद भारत व्यापार उदारीकरण से कोई खास लाभ नहीं उठा सका। भारत की व्यापार समझौता उपयोग दर भारत–मर्कोसुर पीटीए के मामले में सबसे कम रही है जो देश की 27 प्रतिशत की औसत उपयोग दर की तुलना में लगभग 14 फीसदी ही है। हालिया बातचीत के तहत पीटीए का दायरा बढ़ाकर उसमें 3000 वस्तुओं को शामिल करने की दिशा में काम करने की अनुमति दी गई है। यूरोपीय संघ और अमेरिका से परे अपने व्यापार में विविधता लाने के लिए एलएसी के सलाहकारों के बीच सहमति बढ़ती जा रही है। निवेश के दृष्टिकोण से भारत के लिए एलएसी भी खास मायने रखता है क्योंकि इस क्षेत्र को भारत सहित दुनिया के बाकी हिस्सों से सबसे अधिक निवेश प्राप्त होता है।

इस अध्ययन का लक्ष्य उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनमें भारत क्षेत्र–वार और देश–वार अवधारणा पर विशेष बल देकर क्षेत्रीय समूह के साथ अपना व्यापार बढ़ा सकता है। भारत के लिए इस क्षेत्र में व्यापक व्यापार संभावनाएं हैं और पीटीए से इन व्यापार अवसरों का दोहन करने में आसानी होने की उम्मीद है। गैर–शुल्क बाधाएं और शुल्क दरें (टैरिफ) इन दोनों के बीच व्यापार में मुख्य अवरोध बनती जा रही हैं। अध्ययन के तहत दोनों ही क्षेत्रों में इन आयामों को कवर किया जाएगा। इनके बीच निवेश प्रवाह के रुख और संभावनाओं को समझने के लिए निवेश संपर्कों का अध्ययन करने की जरूरत है। ब्राजील और अर्जेंटीना चूंकि लैटिन अमेरिका में ऑटोमोबाइल एवं आईसीटी मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चेन) में काफी सक्रिय हैं, इसलिए अध्ययन के तहत इन क्षेत्रों में भारत की सहभागिता की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, अध्ययन के तहत रचनात्मक सामग्री से जुड़ा व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही अध्ययन के तहत कॉमट्रेड, डब्ल्यूआईआर, आईटीसी इन्वेस्ट मैप डेटाबेस का उपयोग करके व्यापार और निवेश के रुख का विश्लेषण किया जाएगा।

भारत–कोमेसा सीईपीए संयुक्त अध्ययन समूह रिपोर्ट

प्रो. एस. के. मोहंती/डॉ. प्रियदर्शी दास

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और कोमेसा सचिवालय की संयुक्त पहल से भारत–कोमेसा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को औपचारिक रूप देने की व्यवहार्यता रिपोर्ट को दोनों ही पक्षों द्वारा अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया गया था। संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) की रिपोर्ट तैयार करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अध्ययन में अपना ज्ञान भागीदार बनने और मसौदा रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी लेने के लिए आरआईएस से संपर्क किया। रिपोर्ट तैयार करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से दो टीमों का गठन किया गया। भारत और कोमेसा की दोनों टीमों ने अपने बीच चार अध्यायों का आदान–प्रदान किया जिनमें परस्पर करार करने वाली अर्थव्यवस्थाओं का वृहद आर्थिक अवलोकन, वस्तु व्यापार

का उदारीकरण, सेवा व्यापार का उदारीकरण और निवेश उदारीकरण शामिल हैं।

इन क्षेत्रों के संदर्भ में मसौदा रिपोर्ट में यह पाया गया है कि भारत और कोमेसा देशों में व्यापार, निवेश, सेवाओं के विस्तार के लिए प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के साथ–साथ सहयोग के अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक संभावनाएं हैं। अध्ययन में उन व्यापार संभावनाओं का पता लगाया गया जो भारत–कोमेसा सीईपीए के जरिए दोनों पक्षों को हासिल हो सकती हैं। इसमें शुल्क एवं गैर–शुल्क बाधाओं की मौजूदा संरचना, उत्पाद उद्गम के नियमों, व्यापार में सहूलियत, एफडीआई नीतियों तथा इन क्षेत्रों में आगे और सुधार लागू करने के रोडमैप पर प्रकाश डाला गया है। जहां एक ओर शुल्क दरों में कमी के परिणामस्वरूप भारत और कोमेसा के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर उत्पाद उद्गम के नियमों, व्यापार सरलीकरण, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, एसपीएस और टीबीटी उपायों में सुधार करने के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। अध्ययन के तहत भारत एवं कोमेसा के बीच सेवा व्यापार की संभावनाओं का भी पता लगाया गया और दोनों देशों के कुछ विशिष्ट सेवा क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया।

विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पक्षों की प्रतिस्पर्धी ताकत को ध्यान में रखते हुए सीईपीए के तहत क्षेत्रवार सहयोग से लाभान्वित होने के लिए सौदेबाजी करने की व्यापक संभावनाएं हैं। यह कवायद पूरी होने से पहले जेएसजी रिपोर्ट में दो और अध्याय शामिल करने की योजना बनाई गई थी। इनमें से एक अध्याय सीईपीए उपरांत व्यवस्था से संभावित कल्याण लाभों पर केंद्रित था और अंतिम अध्याय आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित था। अफ्रीका में एक बड़ा क्षेत्रीय समूह बनाने के लिए कोमेसा, ईएसी और एसएसीयू के बीच त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (टीएफटीए) का शुभारंभ करने के कारण जेएसजी रिपोर्ट की कवायद पूरी करने की समूची प्रक्रिया अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। यह अध्ययन जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। यह अध्ययन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।

भारत को लेटिन अमेरिका (लेक क्षेत्र) में एक प्रमुख वैश्विक भागीदार के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति

प्रो. एस. के. मोहंती / सुश्री पंखुड़ी गौड़ / सुश्री सानुरा फर्नांडीज / सुश्री उपासना सीकरी

भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (लेक क्षेत्र) नीति पर अपना ध्यान केंद्रित करके इसे निरंतर अपनाता रहा है, ताकि इस क्षेत्र के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। विदेश व्यापार नीति रिपोर्ट 2009–2014 में इस नीति पर और भी अधिक व्यापक रूप से चर्चा की गई है। हाल ही में लेक क्षेत्र नीति भारत में आत्मविश्लेअषण और नीतिगत संशोधन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रही है। वैसे तो यह नीति वर्ष 1997 में ही लागू कर दी गई थी, लेकिन इस क्षेत्र–व्यापार रणनीति से विगत वर्षों के दौरान भारत को कोई खास लाभ नहीं हो पाया है। वर्तमान में भारत और लेक क्षेत्र के बीच हो रहा कुल व्यापार भारत के वैश्विक व्यापार एवं निवेश प्रवाह का एक छोटा–सा हिस्सा है। भारत ने अब तक इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश की अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं किया है।

इसके ठीक विपरीत, नब्बे के दशक में चीन द्वारा अपनाई गई 'लुक वेस्ट' नीति ने इस क्षेत्र के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाने में उसकी काफी मदद की है। व्यापार की कुल मात्रा के साथ–साथ सहभागिता के व्यापक दायरे की दृष्टि से भी लेक क्षेत्र देशों के साथ चीन के आर्थिक संबंध भारत की तुलना में मजबूत रहे हैं। अतः

लेक क्षेत्र क्षेत्र सहित दुनिया के प्रमुख बाजारों में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य और विकासशील देशों के बाजारों में चीन की आक्रामक व्यापार एवं निवेश नीतियों को ध्यान में रखते हुए भारत की लेक क्षेत्र नीति का व्यापक आकलन करना अत्यंत आवश्यक है।

मराकेश सम्मेलन के बाद पीटीए और एफटीए की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत संभवतः प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को परखने/मजबूत करने की नीति पर अमल कर रहा है। इसके साथ ही भारत इस क्षेत्र में विभिन्न आरटीए/प्रांतों (काउंटी) के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसी तरह कई एलएसी देश तरह–तरह के आरटीए के जरिए अनेक एशियाई देशों से जुड़े हुए हैं। अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के अपने दीर्घकालिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु गहन आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त साझेदारों/आरटीए का चयन किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए उन कारकों को समझना जरूरी है जो भारत और एलएसी के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को विफल कर रहे हैं।

इसके साथ ही उन व्यापारिक बाधाओं की पहचान करने की आवश्यकता है जो इस राह में रोड़े अटकाती रही हैं। इसी तरह समूचे एलएसी क्षेत्र में इन बाधाओं को सुसंगत बनाने के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं की उपयुक्तता पर गौर करना भी आवश्यक है। क्या द्विपक्षीय व्यापार के फीके प्रदर्शन के लिए एफडीआई प्रवाह को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या इस क्षेत्र में चीन की निरंतर मौजूदगी भारत की एलएसी व्यापार रणनीति के लिए एक खतरा है?

इन समकालीन व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए वर्तमान अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैंः (1) इस क्षेत्र में भारत के आर्थिक हित के संदर्भ में एलएसी देशों की व्यापार नीतियों का आकलन करना, (2) ज्यादा पारदर्शी तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए इस क्षेत्र के कारोबारी माहौल को प्रतिबिंबित करने हेतु एलसीए क्षेत्र के व्यापक आर्थिक हालात पर गौर करना, (3) क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं/आरटीए के साथ भारत की व्यापारिक साझेदारी के स्वरूप और दुनिया के अन्य प्रमुख देशों के साथ उनके व्यापार संबंधों का विश्लेषण करना, (4) भारतीय निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता के मद्देनजर एलएसी क्षेत्र में भारत की उत्पाद/क्षेत्रवार व्यापार क्षमता का आकलन करना, (5) इस क्षेत्र में एफडीआई की आवक एवं उसके बाह्य प्रवाह के स्रोतों, रुझान और संभावनाओं की पहचान करना, (6) चीनी निवेश के कारण भारत के निवेश की गुंजाइश कम हो जाने के मद्देनजर एलएसी में भारत के मौजूदा ओएफडीआई के रुख की तुलना करना एवं उसमें अंतर बताना, और (7) देश के दीर्घकालिक व्यापारिक हितों के साथ उन तत्वों का आकलन करना जो संशोधित एलएसी व्यापार रणनीति की मुख्य बातों (कंटेंट) का स्थान ले सकते हैं।

इस अध्ययन का उद्देश्य भांति–भांति के आंकड़ों का उपयोग करते हुए विभिन्न परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाना है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, विशेष कर अन्य उभरते बाजारों की प्रतिस्पर्धी व्यापार उदारीकरण नीति, व्यापार प्रतिस्पर्धी क्षमता और व्यापार संपूरकता से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय सहयोग के लिए अर्थव्यवस्थाओं की अंतर निर्भरता का आकलन करना होगा। अध्ययन का उद्देश्य भारत और एलएसी देशों के बीच व्यापार एवं निवेश सहयोग का भावी खाका (रोडमैप) पेश करना है। अलग–अलग स्तर पर व्यापार विश्लेषण से भारत और एलएसी देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। इससे परस्पर करार करने वाले पक्षों को

घरेलू अर्थव्यवस्था में व्यापार और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए व्यापक संभावनाओं वाले उभरते क्षेत्रों में निवेश के मौके तलाशने में मदद मिल सकती है। यह अध्ययन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।

भारत के एफटीए/सीईसीए : प्रभाव और भावी दिशा

प्रोफेसर राम उपेंद्र दास

भारत के एफटीए के प्रभाव के सकारात्मकता से बहुत दूर होने संबंधी वर्तमान विवरण की पृष्ठभूमि में, इस अध्ययन का लक्ष्य विभिन्न संबद्ध पहलुओं का निष्पक्ष आकलन करना है।

वैचारिक और अनुभवजन्य कार्य संपन्न हो चुका है और अध्ययन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विशेषज्ञों के साथ दो परामर्श बैठकों में कुछ आरंभिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए।

यूरेषियाई आर्थिक संघ (ईएईयू) और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर संयुक्त संभाव्यता अध्ययन

प्रोफेसर राम उपेंद्र दास

एक ओर भारत और आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गीस्तान और रूसी संघ के आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच की अन्योन्याश्रितता की पहचान करते हुए भारत के यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक सहयोग संबंधों के दृष्टिकोण और प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह की स्थापना की गई है। भारत की वर्तमान आर्थिक गतिशीलता साथ ही साथ संगठन के सदस्य देशों के आर्थिक निष्पादन को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं और निवेश के व्यापार और साथ ही साथ आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में भी समग्र संबंध कायम करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अध्ययन की आवश्यकता इस तथ्य के कारण भी है कि इस क्षेत्र के साथ अतीत में बहुत मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं और उन्हें ऊर्जा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के कारण सुदृढ़ बनाया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से आरआईएस को जेएसजी और उनके प्रायोजन के साथ अध्ययन करने के संबंध में सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया।

यह अध्ययन यूरेशियाइ आर्थिक सहयोग, मॉस्को के सहयोग के साथ संपन्न किया गया। आरआईएस ने भारत और मॉस्को में आयोजित सभी जेएफएसजी बैठकों में भाग लिया।

भारत–म्यांमार सीमा व्यापार में वृद्धि के लिए नीतिगत और कार्यान्वयन उपाय

प्रोफेसर राम उपेंद्र दास

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग 98 प्रतिशत सीमा अंतर्राष्ट्रीय सरहद के रूप में है। यह क्षेत्र उत्तर में चीन के साथ, दक्षिण–पश्चिम में बांग्लादेश के साथ, पश्चिमोत्तर में भूटान के साथ और पूर्व में म्यांमार के साथ सीमाएं साझा करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक रूप से अनुकूल स्थिति और समृद्ध प्राकृतिक संसाधन उसके विकास को

न सिर्फ दक्षिण–पूर्वी देशों के संगठन –आसियान के साथ, बल्कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ भी सहयोग के आधार के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। खासतौर पर म्यांमार के माध्यम से भारत की 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीति के अंग के रूप में कम्बोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे अनेक आसियान देशों के साथ उसका क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संभव हो सका है। भारत के साथ सीमा व्यापार के मामले को सुलझाने के लिए, जो म्यांमार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, उसकी शुरूआत भारत को सिर्फ म्यांमार के साथ ही नहीं, बल्कि भारत सीएलएमवी सहयोग की व्यापक कार्यनीति के अंग के रूप में एकीकृत करके की जा सकती है। संभावनाओं का उपयोग करने और नीतिगत व्यवस्था विकसित करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आरआईएस से इस विषय पर अध्ययन करने का अनुरोध किया और उसका प्रायोजन किया।

अध्ययन पूरा किया जा चुका है और उसे वाणिज्य सचिव, भारत सरकार सुश्री रीता तेवतिया द्वारा जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया।

पूर्व और दक्षिण–पूर्व एशिया को शेष एशिया के साथ एकीकृत करने के लिए भारत एक आर्थिक केंद्र के रूप में

प्रोफेसर राम उपेंद्र दास

मेक इन इंडिया पहल पर भारतीय नीति के निरुपण पर बल देने के साथ ही साथ विविध विश्वसनीय तथ्यों द्वारा रेखांकित वर्ष 2016 में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की भावी संभावनाओं से युक्त भारत की हाल की आर्थिक गतिशीलता यह दर्शाती है कि भारत जहां एक ओर पूर्व एशिया, आसियान को और वहीं दूसरी ओर दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यहां तक कि अफ्रीका के पूर्वी तट को एकीकृत करने के लिए एक आर्थिक केंद्र के रूप में उभर सकता है। हालांकि इस सुझाव को समग्र एशिया विकास योजना (ईआरआईए), 2010 के आधार पर व्यापक प्रारूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित अध्ययन के निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्य हैं :

- एशिया के विभिन्न भागों के एकीकरण के लिए भारत को एक आर्थिक केंद्र बनाने के लिए विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य आधार प्रस्तुत करना
- जिन उप–क्षेत्रों में भारत ऐसी भूमिका निभा सकता है, वहां के आयामों और क्षेत्रों की पहचान करना
- उपरोक्त के लिए सक्षम परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए नीतिगत उपायों और कार्य पद्धतियों का सुझाव देना
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन कुछ आयामों/विषयों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं, उनमें शामिल हैं : (1) क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का वैचारिक आधार,(2) विनिर्माण और सेवाओं में संभावित व्यापार और क्षेत्री मूल्य श्रृंखलाएं,(3)अवसंरचना और सम्पर्क, (4) भारत अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में तथा (5)कौशल अन्योन्याश्रितताओं का आकलन, निर्माण और उपयोग।

एनटीएम और उनके व्यापार प्रभावों पर अध्ययन

गैर–शुल्क उपायों का अध्ययनः आंकड़ाकोष, कार्यप्रणालियां और व्यापार प्रभाव

प्रो. एस. के. मोहंती/सुश्री पंखुड़ी गौड़

गैर–शुल्क उपायों (एनटीएम) पर अत्यंत विस्तृत जानकारी फिलहाल उपलब्ध तो है, लेकिन साधारण निर्यातकों और शैक्षणिक तहकीकात या पूछताछ की दृष्टि से यह अधूरी है। एनटीएम पर डेटाबेस चयनात्मक कवरेज और विभिन्न देशों में आम प्रारूप के अभाव की वजह से इनके व्यापार प्रभावों का त्वरित आकलन करने में सक्षम नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन के अथक प्रयासों के बावजूद एनटीएम संबंधी डेटा का विश्लेषण बोझिल है और इसमें काफी समय लगता है। इसी तरह कार्यप्रणाली के संदर्भ में एनटीएम की परिभाषा और मात्रा निर्धारण में काफी विरोधाभास नजर आता है। यही कारण है कि व्यापार में एनटीएम संबंधी परिवर्तनों के प्रभाव के अनुभवजन्य विश्लेषण की गुणवत्ता अत्यंत व्यक्तिपरक है और डेटा एवं अर्थमितीय तकनीक के चयन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चूंकि एनटीएम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लिए व्यापार नीति के भावी साधन या प्रपत्र हैं, अतः किसी ऐसे एकल अध्ययन में एनटीएम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना बेहद जरूरी है जो नीति निर्माताओं, छात्रों और व्यापार डेटा के साधारण उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक होगा। वैसे तो अध्ययन के अधिकांश भाग में विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण शामिल होगा, लेकिन अध्ययन का उद्देश्य एनटीएम से जुड़े समावेशी या विवादास्पद अकादमिक कथनों को अनावश्यक रूप से खींचने से बचना है। इस विषय पर उपलब्ध व्यापक सामग्री को देखते हुए अध्ययन आरंभ होने की तारीख से लेकर एक साल की अवधि में इसे पूरा किया जाएगा। प्रारंभिक महीनों के निष्कर्षों के आधार पर कुछ नीतिगत सारपत्र पेश करने की कोशिश की जा सकती है।

गैर–शुल्क उपायों के व्यापार प्रभावों का अनुभवजन्य आकलन

डॉ. प्रियदर्शी दास

व्यापार नीति व्यापक बदलाव दर्शाते हुए शुल्कों के बजाय अब गैर–शुल्क उपायों और व्यापार उपायों की ओर उन्मुख हो गई है। यह कम प्रासंगिक होती जा रही शुल्क–व्यवस्था और वर्ष 2008–09 में गहराई वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद बढ़ते संरक्षणवाद के अनुरूप है। गैर–शुल्क उपायों पर ज्यादा अमल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है क्योंकि 'खुद को लाभ, दूसरों को नुकसान' पहुंचाने वाली नीति आत्मघाती साबित होगी। इसके मद्देनजर गैर–शुल्क उपायों के व्यापार प्रभावों पर अध्ययन सामयिक और नीति निर्माण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले, इस अध्ययन के तहत गहन विश्लेषण के लिए चुनिंदा विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर अध्ययन के दायरे और कवरेज को समय–समय पर बढ़ा दिया जाएगा।

आसियान–भारत व्यापार में गैर–शुल्क उपाय (एनटीएम)

डॉ. प्रबीर डे और डॉ. दुरइराज कुमारसामी

गैर–शुल्क बाधाओं के कारण आसियान और भारत के बीच व्यापार बाधित हुआ है। इस अध्ययन का उद्देश्य विशेषकर व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) और स्वास्थ्य रक्षा एवं पादप स्वास्थ्य संबंधी उपायों यानी सैनेटरी एंड फायटो–सैनिटरी (एसपीएस)

उपायों से संबंधित गैर–शुल्क उपायों को लागू करने पर कारोबारियों द्वारा व्यक्त की जा रही चिंताओं पर गौर करना है। विश्व व्यापार संगठन के एसपीएस और टीबीटी समझौतों के तहत सदस्य देशों को पादप, पशु और मानव जीवन की रक्षा के लिए उत्पाद मानकों को अपनाने की इजाजत दी गई है। समझौतों में यह भी कहा गया है कि मानदंडों को किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक तरीके से लागू नहीं किया जाना चाहिए। कभी–कभी जटिल आवश्यकताओं और प्रशासनिक बाधाओं के कारण इन तकनीकी नियमों का पालन करना कठिन हो जाता है। लागू किए जा चुके उपायों से संबंधित जानकारी तक अपर्याप्त पहुंच भी व्यापार को प्रभावित करती है। नतीजतन, साझेदार देशों द्वारा लागू एनटीएम बाजार पहुंच पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं और कंपनियों को व्यापार अवसरों से लाभ उठाने से रोक सकती हैं। यह अध्ययन विदेश मंत्रालय के लिए किया जा रहा है और इसका उद्देश्य चुनिंदा उत्पादों के मामले में 'आसियान में भारत' और 'भारत में आसियान' के समक्ष मौजूद एनटीएम की तीव्रता या अधिकता का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही डेटा पर आधारित है। समय अवधिः अप्रैल 2016 – मार्च 2018, मौजूदा स्थितिः वर्तमान में प्राथमिक सर्वेक्षण जारी है। मंत्रालय को एक मसौदा दिसंबर 2017 तक प्रस्तुत किया जाएगा।

आईओआरए – व्यापार, मत्स्य पालन

आईओआरए क्षेत्र में मत्स्य पालन के आर्थिक पहलू

(प्रो. एस. के. मोहंती / डॉ. प्रियदर्शी दास)

'आईओआरए' पिछले दशक के दौरान एफ्रो–एशियाई क्षेत्र में एक जीवंत क्षेत्रीय समूह के रूप में उभर कर सामने आया है। इस क्षेत्र में पांच कस्टम्स यूनियनों की मौजूदगी के कारण उसे 'खुले तौर पर क्षेत्रीय सहयोग की अवधारणा को अपनाना होगा। हालांकि, इसका इंट्रा–क्षेत्रीय व्यापार (आईआरटी) वर्ष 2013 में 29.2 फीसदी था। यह आईओआरए में एफटीए की संभावना को सीमित करता है। एक वैकल्पिक नीतिगत रणनीति के रूप में क्षेत्रवार स्तर पर क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। अतीत में इस क्षेत्र के दूरदर्शी लोगों ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में मत्स्य पालन क्षेत्र की पहचान की है। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान कई मामलों में, विशेष रूप से भोजन, पोषण, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा आय के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मत्स्य पालन सेक्टर पर आरआईएस के वर्तमान कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र में मत्स्य पालन सेक्टर के आर्थिक आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अध्ययन के तहत मत्स्य पालन सेक्टर के विशिष्ट क्षेत्रवार मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। इनमें आजीविका सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, उत्पादन संरचना, व्यापार आयामों के साथ–साथ आईओआरए में क्षेत्रीय संस्थागत व्यवस्था की व्यवहार्यता भी शामिल है, ताकि इस क्षेत्रीय फोरम के कामकाज को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे कई अन्य आर्थिक मुद्दे हैं जिन पर विस्तृत शोध की जरूरत है। मछली की कीमतों में अस्थिरता, क्षेत्रवार सब्सिडी संबंधी मसले (हालांकि इस पर चर्चा डब्ल्यूटीओ में की गई है), एनटीबी, मत्स्य पालन से जुड़े क्षेत्रीय मानक पर चर्चा, खाद्य प्रसंस्करण, इत्यादि इन मुद्दों में शामिल हैं। मत्स्य पालन पर आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत भविष्य में विश्लेषण करने के लिए इन मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए)

आईबीएसए से जुड़े मुद्दे

(प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सब्यसाची साहा और डॉ. बीना पांडे)

आरआईएस अपनी ओर से ब्रिक्स और आईबीएसए पर फोकस करता रहा है। आरआईएस संकाय ने विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की साझेदारी वाले इन दो महत्वपूर्ण मंचों (फोरम) पर प्रकाशन और प्रस्तुतियों के जरिए नियमित रूप से योगदान दिया है। आरआईएस वर्ष 2016 में ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार की पहलों में अत्यंत सक्रियतापूर्वक शामिल था। यही नहीं, आरआईएस ने ब्रिक्स कल्याण पर पुस्तक सहित कई प्रकाशनों का शुभारंभ किया। आरआईएस ने भी जियामेन शिखर सम्मेलन से पहले वित्त मंत्रालय को आवश्यक जानकारियां प्रदान की हैं। आरआईएस ने आईबीएसए साझेदारी पर पहले की रिपोर्टों को प्रस्तुत किया और फिलहाल वह 'अगले आईबीएसए शिखर सम्मेलन की ओर' विषय पर एक नई रिपोर्ट पेश करने पर विचार कर रहा है, जिसका आयोजन भारत में होने की संभावना है। आईबीएसए के भीतर अनुसंधान एजेंडे और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आरआईएस 'विदेश मंत्रालय आईबीएसए फेलो' की मेजबानी भी कर रहा है। मेरे वे हालिया प्रकाशन ब्रिक्स मुद्दों पर हैं जिन पर इससे ऊपर प्रकाश डाला गया है।

आरआईएस में आईबीएसए फेलोशिप

आरआईएस अपनी स्थापना के बाद से ही आईबीएसए से संबंधित मुद्दों पर काम करता रहा है। वर्ष 2013 में आरआईएस द्वारा आईबीएसए देशों के लिए एक शैक्षणिक फोरम का आयोजन किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, अपरिहार्य कारणों से शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। अब हमें इस आशय की जानकारी मिल रही है कि आईबीएसए शिखर सम्मेलन अगले साल के आरंभ में किसी समय आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में आरआईएस ने निम्नलिखित अनुसंधान कार्यक्रमों की शुरुआत की। हम इस समय पांच आईबीएसए फेलो की भी मेजबानी करेगें।

आईबीएसए देशों के बीच सामाजिक नवाचार एवं एकीकरण : त्रिकोणीय सहयोग के लिए प्रेरणा

(डॉ. बीना पांडे)

चूंकि भारत वर्ष 2018 में आईबीएसए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसलिए इस अध्ययन के तहत वैश्विक रणनीतियों, एसएससी की हिमायत, एस एंड टी संबंधी उन प्रतिबद्धताओं और सामाजिक क्षेत्र की उन प्रतिबद्धताओं के लिहाज से आईबीएसए के वर्तमान पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो इसकी स्थापना के बाद से ही विभिन्न विज्ञप्तियों एवं घोषणा–पत्रों में प्रमुख स्थान पाते रहे हैं। इसके तहत उन सबक का भी पता लगाया जाएगा जिन्हें एक दूसरे के अनुभवों से सीखा जा सकता है। अध्ययन के तहत यह भी पता लगाया जाएगा कि पारस्परिक लाभकारी तरीके से इनकी संपूरकताओं में समन्वय आखिरकार कैसे स्थाापित किया जा सकता है।

अध्ययन के तहत व्यापक फोकस प्रभावकारी दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में त्रिपक्षीय सहयोग पर होगा। अध्ययन के तहत इन देशों में सामाजिक विकास, शिक्षा के विस्तार एवं प्रतिधारण, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और पारिश्रमिक आधारित रोजगार से जुड़े मुद्दों से निपटने

के लिए अपनाए गए अभिनव तौर–तरीकों का पता लगाया जाएगा। अंत में, यह विशेष अध्ययन सभी संबंधित आईबीएसए देशों में वर्ष 2030 तक एसडीजी की प्राप्ति से जुड़ी चिंताएं दूर करने के लिए समावेशी विकास हेतु उठाए गए नीतिगत प्रयासों के जरिए संरचनात्मक कदमों से हासिल अनुभवों को बखूबी प्रस्तुत करेगा।

एशिया अफ्रीका विकास दायरा (एएजीसी)

एशिया अफ्रीका विकास दायरे (एएजीसी) का विचार नवंबर 2016 में भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के संयुक्त घोषणापत्र में उभर कर सामने आया। आरआईएस ने आसियान एवं अफ्रीका के प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) के साथ परामर्श के बाद जकार्ता स्थित आसियान एवं पूर्वी एशिया आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए) और टोक्यो स्थित विकासशील अर्थव्यवस्था संस्थान (आईडीई–जेट्रो) के साथ साझेदारी में 'विजन डॉक्यूमेंट' तैयार किया था। मोटे तौर पर, एएजीसी निम्नलिखित मुख्य स्तंभों पर आधारित हैः 1) क्षमता और कौशल बढ़ाना, 2) गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और संस्थागत कनेक्टिविटी, 3) विकास और सहयोग परियोजनाएं 4) पारस्परिक जन भागीदारी। वर्तमान में आरआईएस अपने सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर इन प्रमुख विषयों पर व्यापक शोध कर रहा है, जो अंततः इस प्रमुख पहल के तहत सबसे व्यावहारिक प्रस्तावों और उनके कार्यान्वयन की रूपरेखाओं की पहचान के लिए मुख्य आधार होंगे। इस कवायद के एक भाग के रूप में व्यापक दायरे वाली एक पुस्तक लिखने की भी योजना बनाई गई है, जिसमें व्यापार सुविधा, स्वास्थ्य, कृषि, नीली अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन विकास, ऐतिहासिक संबंध और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के डोमेन विशेषज्ञों का अहम योगदान होगा। एएजीसी पर अध्ययन को एक विशेष प्रकाशन के रूप में पेश किया जाएगा।

भारत–अफ्रीका विकास सहयोग

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/ श्री प्रत्यूष

आरआईएस–भारतीय विकास सहयोग मंच, डीपीए सहयोग से, और अफ्रीका में भारत के विकास सहयोग की सफलता के कुछ उदाहरणों पर आधारित एक अध्ययन से। अध्ययन ने 2015 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत–अफ्रीका फोरम सम्मेलन के एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण बिंदु उपलब्ध कराए थे।

भारतीय विकास सहयोग मंच में खास तौर पर दक्षिण के दोनों देशों से विकास सहयोग के ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता को सामने लाने की क्षमता है। भारतीय विकास सहयोग मंच, भारत के विकास सहयोग के सर्वश्रेष्ठ तरीकों को एक जगह लाने में मदद करता है। शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और व्यवहारिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों से लेकर क्षेत्र में विशेषज्ञों को एकजुट करने और भारत की अपनी विकास सहायता में शामिल करने के लिए सर्वोत्तम नीतियों को चुनने में मदद करता है।

यह अध्ययन खास तौर पर जमीनी स्तर पर क्षमता विकसित करने की उन परियोजनाओं पर ध्यान देता है जो इस क्षेत्र में भारत की ओर से सफलतापूर्वक लागू की गई हैं और जो प्रभावी रूप से भारत के विकासशील देशों में विकास सहयोग कार्यक्रमों के सफल स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। इसमें विभिन्न अफ्रीकी देशों में छोटी विकास परियोजनाओं (एसडीपी) को लागू करने की गुंजाइश पर चर्चा करने का भी विचार शामिल है। ये ऐसी योजनाएं हैं जैसी भारत ने नेपाल और भूटान में लागू की हैं।

ब्लू इकोनॉमी फोरम

प्रो. एस. के. मोहंती/डॉ. प्रियदर्शी दास/सुश्री पंखुड़ी गौड़/सुश्री सानुरा फर्नांडीज/सुश्री उपासना सीकरी

ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) सामान्य रूप से एक स्वीकार्य विकास प्रतिमान के रूप में उभर कर सामने आई है जिसने आर्थिक विकास को सतत विकास के साथ प्रभावकारी ढंग से मिश्रित किया है। नब्बे के दशक के आरंभ से ही जारी वैश्विक बहस ने विश्व समुदाय को नीली अर्थव्यवस्था के आइडिया की प्रभावकारिता को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है। विकसित और विकासशील दोनों ही देशों ने छोटे, मझोले, बड़े, एलडीसी और छोटे द्वीप विकासशील देशों (एसआईडीएस) सहित तटवर्ती देशों के लिए एक नए विकास मॉडल के रूप में नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही इसे बाकायदा बढ़ावा भी दिया है। यह विकास मॉडल इस मूल आधार के साथ शुरू हुआ कि महासागर और उनसे संबंधित गतिविधियां तटवर्ती देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए खास मायने रखती हैं और ये गतिविधियां ब्लू इकोनॉमी का मुख्य भाग हैं। समुद्री मछली पकड़ने, नौवहन, समुद्री व्यापार जैसी पारंपरिक गतिविधियों के साथ–साथ अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में काफी गहराई से जुड़ी अनगिनत गतिविधियां भी नीली अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हैं। ये गतिविधियां कृषि, खनिज, निर्माण, ऊर्जा, विनिर्माण एवं सेवाओं सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इसके अलावा नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों का दायरा काफी व्यापक है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और सेवाओं संबंधी गतिविधियों दोनों का ही संयोजन किया गया है। वैसे तो ब्लू इकोनॉमी से जुड़े अनगिनत मुद्दे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कई देशों के लिए विश्व अर्थव्यवस्था के सबसे गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आ रही है। इसका दायरा (कैनवास) काफी विस्तृत है, लेकिन किसी भी देश की नीली अर्थव्यवस्था को उसके सभी आयामों में जानना एक दुष्कर कार्य है। नीतिगत कदम उठाने के मद्देनजर महासागर संसाधनों का संरक्षण, सुरक्षा और टिकाऊ उपयोग इस पर जारी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक बहस के मुख्य मुद्दे हैं। ब्लू इकोनॉमी से जुड़े प्रतिमान में टिकाऊपन संपूर्ण और पारस्परिक रूप से अंतर्निहित है। यही कारण है कि समुद्री संसाधनों के उपयोग में अदक्षता को दूर करने और समुद्री अर्थव्यवस्था की सीमाएं बढ़ाने के लिए ठोस समाधान इसमें मौजूद हैं।

ब्लू इकोनॉमी फोरम (बीईएफ) का उद्देश्य आईओआरए क्षेत्र में अवधारणा को बढ़ावा देने के विषय पर खुले संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित मंच (प्लेटफॉर्म) के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करना है। फोरम इन बातों पर भी फोकस करेगाः नीली अर्थव्यवस्था की क्षमता, संभावनाओं और चुनौतियों पर अध्ययन कराना, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के प्रोफेशनलों को नियमित रूप से आवश्यक जानकारियां सुलभ कराना, और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में इसे सुचारु ढंग से अपनाए जाने की वकालत करना। फोरम के शोध निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार रिपोर्टों, विशेष लेखों, नीतिगत सारपत्रों, सांख्यिकीय विवरण और सूचना–पत्र के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा, फोरम एसएमई की भूमिका, महिला सशक्तिकरण, छोटे द्वीप विकासशील देशों की कमजोरियों और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न संबंधित मुद्दों पर अध्ययन कराएगा। फोरम इसके साथ ही आईओआरए और अन्य क्षेत्रों के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं कारोबारी समुदाय के बीच संबंधों को सुगम करेगा। नीली अर्थव्यवस्था ने तटवर्ती देशों के कई क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है और विभिन्न क्षेत्रों के महत्व के लिहाज से देशों के बारे में कोई 'शैलीगत तथ्य' नहीं हैं। यह

फोरम जहां एक ओर आईओआरए क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सभी समुद्री एवं संबंधित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण मानता है, वहीं दूसरी ओर मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि, अपतटीय एवं गहरे समुद्र में खनन, नवीकरणीय सागर ऊर्जा, समुद्री निर्माण, तटीय पर्यटन व शहरीकरण, बंदरगाह एवं नौवहन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और समुद्री सेवाओं सहित कुछ क्षेत्रों को फोरम की गतिविधियों के प्रारंभिक वर्षों में प्राथमिकता दी जा सकती है। फोरम की शैक्षणिक गतिविधियों में इन सेक्टरों के पारंपरिक के साथ–साथ उभरते क्षेत्रों दोनों को ही कवर किया जाएगा।

आईओआरए में गैर–सूचित और अनियंत्रित ढंग से मछली पकड़ने का मुद्दा

प्रो. एस. के. मोहंती/सुश्री पंखुड़ी गौड़

वैसे तो मत्स्य पालन क्षेत्र तटवर्ती देशों में दूर–दूर तक फैला हुआ है, लेकिन इन देशों को घटते मत्स्य स्टॉक की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन देशों में मछली पकड़ने वाले बड़े समुदाय भोजन, आजीविका, इत्यादि के लिए मत्स्य पालन पर अत्यधिक निर्भर हैं। दुनिया भर में मछली के स्टॉक पर मंडराता खतरा चिंता का विषय रहा है जिस पर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)–14 के रूप में वैश्विक एजेंडा 2030 में विशेष जोर दिया गया है। एसआईडीएस देशों सहित कई आईओआरए देशों में मत्स्य स्टॉक में कमी की दर बेहद ज्यादा है। मत्स्य स्टॉक में कमी के कारण अनियंत्रित ढंग से मछली पकड़ने में भारी कमी आई है जिसका असर स्थानीय आबादी की आय, रोजगार, पोषण मूल्य और व्यापार पर पड़ रहा है। एफएओ के एक अनुमान के मुताबिक, जैविक टिकाऊ स्तर से संबंधित मत्स्य स्टॉक की हिस्सेदारी विश्व भर में वर्ष 1974 के 90 फीसदी से घटकर वर्ष 2013 में 68.6 प्रतिशत पर आ गई। यही नहीं, आईओआरए का अनुभव भी इससे भिन्न नहीं है।

मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य स्टॉक में कमी होने के कुछ कारणों में 'अपेक्षा से अधिक मछली पकड़ना' और 'जरूरत से ज्यादा क्षमता' भी शामिल हैं। ये दोनों ही लक्षण स्वाभाविक तौर पर अवैध, गैर–सूचित और अनियंत्रित (आईयूयू) ढंग से मछली पकड़ने से संबंधित हैं जिसका चलन काफी जोर–शोर से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में है। इसके अलावा, विकासशील देश आईयूयू ढंग से मछली पकड़े जाने की प्रवृत्ति के प्रमुख शिकार हैं। आईयूयू ढंग से मछली पकड़ने की गतिविधियां बढ़ जाने के चलते 'संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन लाल सूची' के तहत प्रजातियों की संख्या बढ़ गई है। वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर आईयूयू ढंग से मछली पकड़ने का आकलन लगाए जाने से जुड़े कई मुद्दे हैं। यही कारण है कि आईयूयू ढंग से मछली पकड़े जाने के आकलन पर अब तक आम सहमति नहीं बन पाई है।

यह वर्तमान अध्ययन आईओआरए में उत्पादन और व्यापार क्षेत्रों पर आईयूयू ढंग से मछली पकड़ने के निहितार्थों की पहचान करने पर केंद्रित होगा। अध्यंयन के तहत इस क्षेत्र में आईयूयू ढंग से मछली पकड़ने से जुड़ी आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत का पता लगाया जाएगा। यही नहीं, अध्ययन के तहत विभिन्न ध्वज (फ्लैग) देशों में आईयूयू ढंग से मछली पकड़ने में शामिल बेड़े के स्वरूप का भी पता लगाया जाएगा। यह अध्ययन उन नीतियों पर भी फोकस करेगा जो आईयूयू ढंग से मछली पकड़ने की मात्रा में कमी लाने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ में अपनाई जा रही हैं। आईयूयू ढंग से मछली पकड़ने जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है जो विशेषकर अनेक तटवर्ती देशों की सदस्यता वाले 'आईओआरए' में घटते मत्स्य स्टॉक के लिए जिम्मेदार हैं। यह अध्ययन आरआईएस की एक पहल है और यह वर्ष 2018 की पहली तिमाही में पूरा हो जाने की उम्मीद है।

वैकल्पिक विकास रणनीति के रूप में ब्लू इकोनॉमी

प्रो. एस. के. मोहंती / डॉ. प्रियदर्शी दास / सुश्री पंखुड़ी गौड़ / सुश्री सानुरा फर्नांडीज / सुश्री उपासना सीकरी

किसी भी तटवर्ती देश के विकास के लिए समुद्री संसाधनों का दक्ष उपयोग अत्यंत आवश्यक है। सदियों से मानव सभ्यताएं अनेक चीजों जैसे कि भोजन, मत्स्य पालन, खनिज, दवाओं, मनोरंजन एवं पर्यटन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अर्थात दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार के लिए महासागरों पर निर्भर रही हैं। त्वरित आर्थिक विकास की दौड़ में शामिल होकर तटवर्ती देशों ने जैविक और पारिस्थितिक सीमाओं से परे जाकर महासागर संसाधनों, खासकर मत्स्य पालन, तेल एवं गैस, प्रवाल भित्ति इत्यादि का अपेक्षा से अधिक दोहन किया है। संसाधन उपयोग के इस गैर–टिकाऊ तौर–तरीके के कारण महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों के विलुप्त होने, समुद्री जीव विज्ञान के अवक्षय, समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का अंदेशा है। नीली अर्थव्यवस्था एक प्रतिमान है जो पर्यावरणीय स्थिरता से आर्थिक विकास के उद्देश्यों को जोड़ती है और इसके साथ ही समुद्री संसाधनों के पुनर्जनन एवं पुनःपूर्ति पर विशेष जोर देती है। इस कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत इन घटकों पर फोकस किया जाएगा : (ए) नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टरों की पहचान एवं आकलन करना, (बी) ब्लू इकोनॉमी से जुड़े व्यापार के बारे में अनुमान लगाना, (सी) राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि मत्स्य पालन, गहरे समुद्र में खनन, तटीय पर्यटन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, महासागर ऊर्जा, समुद्री सेवाओं, इत्यादि का आर्थिक योगदान, (डी) नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग के लिए क्षेत्रीय पहल, और (ई) नीली अर्थव्यवस्था के कानूनी एवं नियामकीय पहलू। ब्लू इकोनॉमी के इन आयामों में से प्रत्येक का गहराई से अध्ययन किया जाएगा, ताकि नीति निर्माण के लिए सार्थक जानकारियां मिल सकें। अध्ययनों के निष्कर्ष एक रिपोर्ट, पुस्तक, परिचर्चा पत्रों और नीतिगत सारपत्रों के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। हमने कुछ क्षेत्रवार अध्ययन शुरू करने के लिए संवाद की शुरुआत बाकायदा कर दी है। यह ब्लू इकोनॉमी पर आरआईएस का व्यापक कार्यकलाप कार्यक्रम है।

ब्लू इकोनॉमी और गैर–पारंपरिक सुरक्षा समस्याएं : संभावित सुरक्षा खतरे में कमी की रणनीति बनाना

प्रो. एस. के. मोहंती

राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उस 'गैर–पारंपरिक सुरक्षा' पर फोकस बढ़ता जा रहा है, जो गैर–सैन्य सुरक्षा खतरे के कारण जरूरत बनती जा रही है क्योंकि इस वजह से कई लोगों की आजीविका सुरक्षा पर संकट मंडराने लगा है। गैर–पारंपरिक सुरक्षा (एनटीएस) खतरों को युद्ध और संघर्ष से परे माना जा सकता है क्योंकि युद्ध की स्थिति में लाखों लोगों की आर्थिक सुरक्षा संकट में पड़ जाती है। इन सुरक्षा खतरों में राजनीतिक और सामाजिक–आर्थिक आयाम शामिल हैं। इस तरह की चुनौतियां अक्सर लोगों की जिंदगी एवं खुशहाली को खतरे में डाल देती हैं और गैर–सैन्य कदमों से उत्पन्न होती हैं। ये चुनौतियां मानव प्रेरित गड़बड़ियों से उत्पन्न होती हैं और संबंधित देश द्वारा समय पर आवश्यक कदम न उठाए जाने के कारण इस तरह की आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव अक्सर स्पष्ट होते हैं। इस तरह की एनटीएस चिंताएं समावेशी विकास को बाधित कर देती हैं, संबंधित देश की कमजोरी को बढ़ा देती हैं और लोगों के दुखों को लंबे समय तक जारी रखने की स्थितियां बना देती हैं। भारत को वर्तमान में कई एनटीएस मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं, नीली अर्थव्यवस्था इनमें से कई खतरों के आंशिक या स्थायी समाधान प्रदान कर सकती है। अनगिनत एनटीएस चिंताओं के बीच नीली अर्थव्यवस्था खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और आजीविका की सुरक्षा, इत्यादि सुनिश्चित कर सकती है। इनमें से कुछ सुरक्षा उपयुक्त नीतिगत रणनीति के जरिए ब्लू इकोनॉमी का समुचित प्रबंधन करके प्रभावकारी ढंग से सुनिश्चित की जा सकती है। 21वीं सदी में मेगा क्षेत्रीय समूहों के उद्भव के साथ ही वैश्विक मुख्यधारा गतिविधियों से संबंधित देशों का 'वैश्विक बहिष्कार' करने संबंधी निरंतर प्रयासों से एनटीएस चिंताओं की कवरेज अब कहीं अधिक स्पष्ट होती जा रही है। ऐसी अशांत वैश्विक आर्थिक स्थिति में भारत कई सेक्टरों में नीली अर्थव्यवस्था को प्रभावकारी ढंग से संभाल नहीं सकता है, अतः ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। भारत ने कई सेक्टरों में बड़ी क्षमताओं का निर्माण किया है। वहीं, भारत पड़ोसी हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में अन्य देशों से कई सेक्टरों में सहायता की मांग कर सकता है। भारत की पहल से एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने से भारत एवं आईओआर को कई एनटीएस चिंताओं को दूर करने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लोगों की भलाई सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

पेसर प्लस

पेसर प्लस और प्रशांत द्वीप अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाएं

डॉ. प्रियदर्शी दास

द्वीप अर्थव्यवस्थाएं छोटी होती हैं। यही नहीं, वे प्राकृतिक एवं आर्थिक संकटों की चपेट में आ जाती हैं। द्वीप अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक संरचना का झुकाव कुछ विशेष क्षेत्रों की ओर होता है जिनमें मुख्यतः समुद्री संसाधन क्षेत्र जैसे कि मत्स्य पालन, पर्यटन, नौवहन, इत्यादि शामिल हैं। फिजी, टोंगा, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, वनातु और सोलोमन द्वीप जैसी प्रशांत द्वीप अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश एवं सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर निर्भर हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं ने इन दो क्षेत्रीय आर्थिक शक्तियों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। 'पेसर प्लस' एक नया व्यापार समझौता है जिसमें विकास सहयोग के जरिए व्यापार विस्तार, निवेश संवर्धन, उद्यम विकास और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्धताओं की एक व्यापक संरचना होने का दावा किया गया है। अपनी खूबियों के साथ–साथ पेसर प्लस में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो प्रशांत क्षेत्र में अवस्थित द्वीप अर्थव्यवस्थाओं की विकास संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर और ज्यादा शोध एवं आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। इस कार्यकलाप कार्यक्रम का उद्देश्य एशिया–प्रशांत क्षेत्र में अभी जारी क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण के संबंध में द्वीप अर्थव्यवस्थाओं की विकास संभावनाओं पर उपयोगी जानकारी सृजित करना है।

निर्यात संवर्धन के लिए सेवा

विकास और निर्यात संवर्धन के लिए सेवाओं से लाभ उठाना

डॉ. प्रियदर्शी दास

पिछले दो दशकों के दौरान विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात एवं जीडीपी वृद्धि दर में सेवाओं का योगदान उल्लेखनीय रहा है। सेवा क्षेत्रों के आकार

में वृद्धि के साथ ही अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक विविधीकरण की व्यापक गुंजाइश है। भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि 2000 के दशक के दौरान भारत में आर्थिक विकास की गति तेज करने के साथ–साथ रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित हुई। एशिया के अन्य उभरते बाजारों में भी विगत महीनों के दौरान सेवाओं के निर्यात में इसी तरह की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर भारत का विशिष्ट संदर्भ देते हुए विकासशील देशों में व्यापार और आर्थिक विकास में सेवाओं की भूमिका पर एक अनुभवजन्य अध्ययन कराने की आवश्यकता है। इस अध्ययन से सेवा क्षेत्रों के विकास और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से अंतर–संबंधों पर नए निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है।

ग. व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

आसियान–भारत विशेष शिखर सम्मेलन

एआईसी से कहा गया है कि वह जनवरी 2018 में नई दिल्ली में होने वाले आसियान–भारत विशेष शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए विदेश मंत्रालय के आसियान प्रभाग की सहायता करे। एआईसी से निम्नलिखित गतिविधियां शुरू करने को कहा गया हैः (1) आसियान–भारत कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन – इसके ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल होना, (2) आसियान–भारत व्यवसाय एवं निवेश शिखर सम्मेलन – व्यापार और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला पर एक सत्र का संचालन करना (3) आसियान–भारत वस्त्र बैठक/सीईओ फोरम/एमजीसी बिजनेस कॉनक्लेव – अवधारणा नोट तैयार करना, और (4) आईएएससीएस के दौरान लीडर्स रिट्रीट – समुद्री सहयोग पर एक अवधारणा नोट तैयार करना।

भारत और आसियान के बीच उभरते उत्पादन नेटवर्क

डॉ. प्रबीर डे, डॉ. दुरइराज कुमारसामी और सुश्री श्रेया पैन

आसियान–भारत एफटीए ने आसियान देशों और भारत के बीच उत्पादन नेटवर्कों की जरूरत उत्पन्न कर दी है। विदेश मंत्रालय के लिए किए जा रहे इस अध्ययन का उद्देश्य उन उद्योगों के भीतर सीमा–पार उत्पादन नेटवर्क बनाने की संभावनाओं का पता लगाना है जिनमें भारत को आसियान की मांग या आपूर्ति क्षमता से मेल खाने वाली क्षमताएं एवं पूरकताएं हासिल हैं और इसके साथ ही ठीक उलट स्थिति भी है। इसके अलावा, इस अध्याय के तहत उत्पादन नेटवर्कों के निर्माण में आड़े आने वाली चुनौतियों की पहचान करने का प्रयास भी किया जाता है। विशेष रूप से, अध्ययन के तहत आसियान एवं भारत के बीच उत्पादन नेटवर्कों को बढ़ावा देने में इस बात की पहचान की जाती है कि कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा के मामले में क्या–क्या अंतर हैं। इसके साथ ही संभावित उपाय भी बताए जाते हैं। इसके लिए समयावधि अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक होगी। इस अध्ययन में से एक अध्याय को पहले ही एमजीसी रिपोर्ट में शामिल किया जा चुका है, जो मई 2017 में प्रकाशित हुई थी। अंतिम रिपोर्ट नवंबर 2017 तक तैयार हो जाएगी।

आसियान–भारत कनेक्टिविटी का विकास भारत में आर्थिक गलियारों (कॉरिडोर) के प्रभावों का आकलन करना

प्रो. प्रबीर डे, डॉ. दुरइराज कुमारसामी, सुश्री उपेंद्र कौर

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच भूमि–पुल की भूमिका निभाता है। यहां कई कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं होती रही हैं जिनमें से कुछ की योजना बनाई जा रही है और कुछ विकसित हो रहे हैं। इन गलियारों (कॉरिडोर) की बदौलत पूर्वोत्तर में विकास कैसे संभव होगा? इस अध्ययन का एक उद्देश्य उन संभावित आर्थिक लाभों का आकलन करना है जो पूर्वोत्तर भारत को मिलने की अपेक्षा की जाती है। इस अध्ययन के तहत एक ऐसा आर्थिक भूगोल मॉडल विकसित किया जाता है जिसका परीक्षण उप–राष्ट्रीय डेटा के साथ किया जाता है। इसके साथ ही अध्ययन के तहत विकास के मामले में भारतीय राज्यों का विशेष उल्लेख करते हुए भारत में आर्थिक (परिवहन) गलियारों के असर का आकलन किया जाता है। भारत को पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ जोड़ने वाले इन चार महत्वपूर्ण गलियारों का चयन किया गया हैः (1) बीसीआईएम–आर्थिक कॉरिडोर, (2) पूर्वी–पश्चिमी कॉरिडोर (स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा), (3) त्रिपक्षीय राजमार्ग, और (4) कलादान मल्टी–मोडल पारगमन परिवहन परियोजना। इसके लिए समयावधि अगस्त 2016–मार्च 2018 होगी। एक मसौदा परिचर्चा के लिए नवंबर 2017 में तैयार हो जाएगा।

क्षेत्रीय एकीकरण एवं सहयोग

भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय संबंधः एक ज्यादा मजबूत आसियान–भारत साझेदारी की ओर

डॉ. प्रबीर डे, और प्रो. हिमांशु प्रभा रे

हाल के वर्षों में म्यांमार और सीएलएमवी में भारत की आर्थिक साझेदारी में निरंतर वृद्धि दर्ज की जाती रही है। उप क्षेत्रीय सहयोग की व्यवहार्यता पर चर्चाएं की जा रही हैं। इस अध्ययन के उद्देश्य ये हैंः (1) आसियान–भारत साझेदारी के संदर्भ में भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय संबंधों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का पता लगाना (2) त्रिपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों एवं नीतियों को प्रस्तुत करना, और (3) शोध निष्कर्षों को प्रकाशित करके नीति निर्माताओं के ध्यानार्थ लाना और शोध निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार करना। यह अध्ययन आसियान अध्ययन केंद्र (एएससी), चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय, बैंकाक के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जाता है। समयावधिः अगस्त 2016–मार्च 2018, वर्तमान स्थितिः कार्य प्रगति पर है। अतीत में दो कार्यशालाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। वर्तमान में एक परिणाम दस्तावेज संकलित किया जा रहा है। एक पुस्तक फरवरी/मार्च 2018 में प्रकाशित होगी।

दक्षिण एशिया के विकास एवं सहयोग पर रिपोर्ट

प्रो. सचिन चतुर्वेदी और प्रो. एस. के. मोहंती

दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे बड़े, गतिशील और सबसे तेजी से विकासोन्मुख क्षेत्रों में से एक है। इसमें विकसित होने के लिए मजबूत उत्पादक क्षमता है क्योंकि इस क्षेत्र की कई अर्थव्यवस्थाओं का बचत–निवेश अनुपात अच्छा–खासा है और वहां नियत पूंजी निर्माण का तेजी से विस्तार हो रहा है। इतना ही नहीं, यह निजी पूंजी प्रेषणों

के सर्वोच्च प्राप्तकर्ताओं में से भी एक है। सार्क के सदस्य देशों को साफ्टा के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ अत्यंत तेजी से क्षेत्रीय एकीकरण सुनिश्चित करने के तरीकों की पहचान करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया के बाकी हिस्सों से एफडीआई की आवक आकर्षित करने के लिए जबरदस्त जोश का अभाव भी देखा जा रहा है। दक्षिण एशिया में सहयोग के अगले चरण में निर्बाध साफ्टा विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना, दक्षिण एशिया आर्थिक संघ के निर्माण का प्रस्ताव और निवेश सहयोग की रणनीति, उत्पादन एकीकरण एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर ज्यादा फोकस करना शामिल हैं। पारस्परिक सहयोग के जरिए मौजूदा उत्पादक शक्तियों के साथ क्षेत्र की विकास जीवंतता को फिर से बहाल करने के लिए दक्षिण एशिया की ताकत को पहचानने एवं समझने की जरूरत है।

आरआईएस इस क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में सदा से ही सबसे आगे रहा है। आरआईएस ने इसके साथ ही इन पहलुओं पर कई अध्ययन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आरआईएस ने यहां तक कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संधि और सेवा व्यापार पर सार्क समझौता (एसएटीआईएस) के आरंभिक मसौदों को भी तैयार करने में अहम योगदान दिया है। दक्षिण एशिया विकास एवं सहयोग रिपोर्ट एक प्रमुख रिपोर्ट है जिसे वर्ष 1999 में पेश किया गया था। इस श्रृंखला में पांचवीं रिपोर्ट वर्ष 2015 में पेश की गई थी। अगली रिपोर्ट वर्ष 2018 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। इसे विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों में आरआईएस के साझेदार संस्थानों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया के लिए वैचारिक एवं व्यावहारिक आधार प्रदान करने के संदर्भ में दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्टों ने इस क्षेत्र तथा उससे परे भी अपनी अलग पहचान बना ली है।

'विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजनः दक्षिण एशिया में सतत आर्थिक विकास की रणनीति' पर एसएसीईपीएस का कार्यकलाप कार्यक्रम

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. एस. के. मोहंती और डॉ. सब्यसाची साहा

इस कार्यकलाप कार्यक्रम का उद्देश्य उन संरचनात्मक कारकों का विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान अध्ययन करना है जो दक्षिण एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर फैली गरीबी और भारी विषमता के लिए जिम्मेदार हैं।

परियोजना की थीम पर दक्षिण एशियाई विशेषज्ञों की एक कार्यशाला 5 दिसंबर 2016 को आयोजित की गई थी। सम्मेलन में 'पहुंच से संबंधित कई नए क्षेत्र' उभर कर सामने आए हैं, जिनकी पहचान सम्मेलन में भाग लेने वाले विशेषज्ञों द्वारा की गई। 'लेखों के मिलान' को एक संपादित पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए जाने की उम्मीद है।

प्रथम कार्यशाला में प्रस्तुतियों की गुणवत्ता उत्साहवर्धक रही है। अध्याय में योगदान करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित आयामों को व्यापक रूप से कवर करते हुए इसमें सविस्तार योगदान दें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने विश्लेषण में सर्वाधिक अद्यतन जानकारी एवं डेटा का उपयोग करें और मुख्य रूप से अपने अनुभवजन्य अवलोकनों के नतीजों के आधार पर ही कोई भी निष्कर्ष निकालें।

भारतीय संदर्भ की विशिष्टता दर्शाने वाला प्रपत्र (पेपर) आरआईएस में कार्यरत एक नामित शोध दल द्वारा तैयार किया जा रहा है। एक प्रमुख शैक्षणिक योगदान के रूप में यह पेपर तैयार करने की योजना बनाई गई है जिसमें मुख्य योगदान

आरआईएस का होगा, ताकि विनिर्माण क्षेत्र के विकास, क्षेत्रीय सहयोग और व्यापक आधार वाले रोजगार सृजन पर दीर्घकालिक विजन के लिए नीतिगत सोच पर प्रभावकारी ढंग से गहरा असर डाला जा सके।

आगे चलकर एक संपादित पुस्तिक एक प्रतिष्ठित प्रकाशक के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। प्रकाशक के साथ अनुबंध को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता एशिया फाउंडेशन से अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही है।

सुदृढ़ क्षेत्रीय आर्थिक गवर्नेंस के जरिए दक्षिण एशिया को मजबूत बनाना

प्रो. एस. के. मोहंती

दक्षिण एशिया धीरे–धीरे स्वयं को एक जीवंत, गतिशील और तेज विकास वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित कर रहा है, जो संभवतः इस क्षेत्र पर उपलब्ध समकालीन सामग्री के भावार्थ के अनुरूप नहीं है। चूंकि दक्षिण एशिया विश्व का एक उभरता क्षेत्र बनता जा रहा है, इसलिए विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों के जरिए इसकी आर्थिक ताकत में नई जान फूंकने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के साथ–साथ उसकी भूरि–भूरि प्रशंसा की जा सकती है, जिससे कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को तेज विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सके। यदि इस क्षेत्र की पहचान दमदार प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित हो जाती है तो इस क्षेत्र में और ज्यादा व्यापक आर्थिक सहयोग की दिशा में आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु क्षेत्रीय साझेदारों को नई नीतिगत पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सुदृढ़ क्षेत्रीय गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए नए क्षेत्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ ठोस पहल करने की आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र में आर्थिक गतिशीलता का आगाज किया जा सके।

इस क्षेत्र ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्य रूप से इस क्षेत्र के उल्लेखनीय विकास प्रोफाइल और अन्य क्षेत्रीय समूहों की तुलना में मजबूत वृहद आर्थिक प्रदर्शन करने की बदौलत ही यह संभव हो पाया है। दरअसल, 'क्षेत्र के भीतर होने वाले व्यापार (आईआरटी)' के अनुसार ही किसी क्षेत्र में मौजूद जमीनी वास्तविकताओं को बयां करने के लिए जिस 5 प्रतिशत के 'आईआरटी अनुपात' का उपयोग किया जाता है वह एक भ्रामक मानक है। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका में इस क्षेत्र के साथ द्विपक्षीय आईआरटी 15 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक रहा है। किसी भी मानक से यदि देखें तो ये आंकड़े अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं। हालिया कृत्रिम कवायदों से यह पता चलता है कि असाधारण प्रयासों से इस क्षेत्र का आईआरटी 6.2 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकता है। 5 फीसदी क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) का वर्तमान स्तर दक्षिण एशियाई क्षेत्र की संरचना के अनुरूप है। इस क्षेत्र की इन उपलब्धियों का कोई खास उल्लेख संबंधित सामग्री में नहीं किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य इस क्षेत्र में एक ऐसी मजबूत और संयोजित गवर्नेंस संरचना अपनाने के बारे में सुझाव देना है जिससे इस क्षेत्र की विशिष्ट उपलब्धियों को और बेहतर किया जा सके। समुचित प्रलेखन के जरिए विगत दशकों के दौरान इस क्षेत्र में हासिल वास्तविक लाभ को आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। उत्पादन, निवेश और व्यापार संबंधों के जरिए उच्च क्षेत्रीय विकास दर हासिल करने हेतु रणनीतिक तरीके से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय गवर्नेंस की रूपरेखा पेश की

जा सकती है। अन्य क्षेत्रीय समूहों के अनुभवों के आधार पर क्षेत्र के विशिष्ट आर्थिक कार्यकलापों जैसे कि वृहद आर्थिक स्थिरता, वित्तीय प्रणाली में स्थिरता, वित्तीय सहयोग एवं विकास वित्त और भौतिक बुनियादी ढांचे की जरूरतों से निपटने के लिए कई नए क्षेत्रीय आर्थिक संस्थानों का गठन किया जा सकता है।

आरसीईपी वार्ताएं निष्कर्ष की ओर : भारत के लिए निहितार्थ

प्रो. एस. के. मोहंती/सुश्री पंखुड़ी गौड़

भविष्य में 'टीपीपी' के पुनरुत्थान से जुड़ी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए आरसीईपी में होना एक बढ़िया अवसर है क्योंकि ऐसे में इस क्षेत्र के साथ एकीकरण को तेज किया जा सकता है। चूंकि भारत उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की दिशा में अग्रसर है, इसलिए अपनी बढ़ती व्यापार जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे एक बड़े बाजार की सख्त आवश्यकता है। 'आरसीईपी' आज विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे गतिशील मेगा क्षेत्रीय समूह है, अतः इस क्षेत्र के साथ भारत का एकीकरण सर्वोपरि है।

भारत पर आरसीईपी के असर के बारे में संबंधित सामग्री में अलग–अलग विचार पेश किए गए हैं। यह दलील दी जाती है कि आरसीईपी बातचीत के लिए एक व्यापक फोरम है जहां सेवा व्यापार, शुल्क एवं गैर–शुल्क बाधाओं को हटाने या उदारीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, इत्यादि सहित अनगिनत मुद्दों पर चर्चा की जाती है। उस मामले में भारत पर इन क्षेत्रवार समझौतों के निहितार्थ के आकलन में भिन्नता हो सकती है। इस बात का अंदेशा है कि भारत आरसीईपी वार्ताओं की प्रक्रिया में कई मोर्चों पर अवसर गंवा सकता है। इस क्षेत्रीय समूह के कई सदस्य यह चाहते हैं कि भारत विनिर्माण व्यापार क्षेत्र में और ज्यादा उदारीकरण करे। कुछ हलकों में यह अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि भारतीय कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों पर अत्यंत प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वैसी स्थिति में इस क्षेत्र के साथ मौजूदा व्यापार असंतुलन और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। वस्तु एवं सेवा व्यापार में उदारीकरण को आरसीईपी वार्ता में एकीकृत करने की भारत की उम्मीद धीरे–धीरे खत्म होती जा रही है। हालांकि, वार्ता प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और वार्ता के समापन के बाद असर के विश्लेषण पर गौर किया जा सकता है।

संबंधित सामग्री में कई सकारात्मक तत्व सामने आए हैं। भारत पहले ही आरसीईपी से जुड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ कई द्विपक्षीय सीईपीए पर हस्ताक्षर कर चुका है। इस तरह के कई मसलों के मद्देनजर इन समझौतों के कार्यान्वयन के बाद समग्र व्यापार स्थिति में सुधार हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का चीनी भय धीरे–धीरे कम हो रहा है क्योंकि देश में बढ़ता पारिश्रमिक उसकी बढ़ती आर्थिक समृद्धि से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे पर और भी अधिक विश्लेषणात्मक रूप से गौर किया जाना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र पर बदलते नीतिगत फोकस को ध्यान में रखते हुए निर्यात, औद्योगीकरण और महत्वपूर्ण घरेलू खपत के लिए आयात की मांग बढ़ रही है। व्यापार की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यापार के स्वरूप जैसे कि मध्यवर्ती/अंतिम, प्रौद्योगिकी गहन, गतिशील उत्पादों, इत्यादि पर बारीकी से गौर किया जाना चाहिए। आरसीईपी संबंधी व्यापार वार्ता के लिए फिर से अनुकूलन की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र में, भारत आरसीईपी उपरांत व्यवस्था में पूरी तरह से अवसर नहीं गंवा देगा। सेवा संबंधी वार्ता में मोड 4 के अलावा, 2 और 3 जैसे अन्य मोड की प्रभावकारिता पर संभवतः गौर नहीं किया जाएगा।

मौजूदा सामग्री में भारत पर आरसीईपी के असर को समझने में भारी अंतर है। ज्ञान में अंतर या खाई को पाटने हेतु आरसीईपी वार्ताओं के विभिन्न आयामों और भारत पर इसके असर से अवगत होने के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास से जुड़े मुद्दे

अनुसंधान गतिविधियों के मुख्य क्षेत्र

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. रवि श्रीनिवास, प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. अमित कुमार

- बौद्धिक संपदा अधिकार और पहुंच (दवाइयां, बीज)
- पारंपरिक भारतीय चिकित्सा सहित पारंपरिक ज्ञान
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (तकनीकी गवर्नेंस सहित)
- जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता
- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य नीति

रिस्पॉन्सिबल रिसर्च इनीशिएटिव (आरआरआई) प्रैक्टिस

आरआरआई–प्रैक्टिसः यह यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित तीन वर्षीय परियोजना है। यह वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और वर्ष 2019 में इसका समापन हो जाएगा। इसे ओस्लो और अकेरशस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ अप्लायड साइंसेज (एचआईओए), नॉर्वे द्वारा समन्वित किया जा रहा है। इसके प्रमुख उद्देश्य ये हैंः इस बात पर गौर करना कि विभिन्न देशों में उत्तरदायी अनुसंधान एवं नवाचार (आरआरआई) को किस तरह से समझा जाता है और फिर किस तरह से अमल में लाया जाता है, एक अवधारणा के रूप में आरआरआई के प्रति वित्त पोषण (फंडिंग) एजेंसियों एवं एसएंडटी नीति निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है, और आरआरआई के महत्वपूर्ण तत्वों जैसे कि नैतिकता और सार्वजनिक सहभागिता को अमल में लाने से जुड़े मुद्दे। वर्तमान स्थिति – परियोजना प्रगति पर है। इस परियोजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला 28 अप्रैल, 2017 को आयोजित की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने भाग लिया था। डीएसटी में सचिव ने मुख्य भाषण दिया था। परियोजना पर बैठक 20 से 22 सितंबर तक बर्लिन में हुई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस दिशा में आगे और अनुसंधान किया जा रहा है। 31 अक्टूबर को आधे दिन का परामर्श आयोजित किया गया।

रियल टाइम वाइड एरिया रेडिएशन सर्विलान्स सिस्टम

यह फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने और उपाय के असर सहित स्वास्थ्य में साक्ष्य नीति निर्माण तथा स्वास्थ्य नीति में विकल्पों के आकलन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर एक परियोजना है। यह पंचवर्षीय परियोजना (2014–2019) यूरोपीय अनुसंधान परिषद (ईआरसी) द्वारा वित्त पोषित और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर, ब्रिटेन द्वारा समन्वित की जा रही है। वर्तमान स्थिति : प्रगति पर है। चरण –2 के एक भाग के रूप में एक शोध परियोजना शुरू करने के लिए संशोधित अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसे वित्तपोषक ईआरसी द्वारा शीघ्र ही मंजूरी दी जाएगी। उसके आधार पर ही आरआईएस परियोजना के चरण–2 के एक भाग के रूप में केरल (एर्नाकुलम जिला) में शुरू किए जाने वाले एक अध्ययन में समन्वय स्थापित करेगा। संस्थागत नैतिकता मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

आईसीएमआर से मंजूरी ली जा रही है। आरआईएस केरल में इस अध्ययन पर करीबी नजर रखने के लिए एक नैतिकता समिति का गठन कर रहा है जो दिसंबर में शुरू होने की संभावना है।

जीवित संशोधित जीवों (एलएमओ) के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश विकसित करने पर एमओईएफ एंड सीसी की परियोजना

एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश विकसित करनाः एमओईएफ एंड सीसीने यूएनईपी–जीईएफ चरण–2 की क्षमता निर्माण परियोजना के तहत यह परियोजना आरआईएस को सौंप दी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत मेंएलएमओ के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश और विभिन्न विधाएं विकसित करना था। समय सीमा 2014–2017 थी। आरआईएस ने अपनी संशोधित अंतिम रिपोर्ट जून में पेश कर दी और इसे एमओईएफ एंड सीसी ने स्वीकार कर लिया है।

आरआरआई – क्षितिज

आरआरआई–क्षितिज– नई परियोजना। यह परियोजना मई 2017 में शुरू की गई थी। वियना में आयोजित शुरुआती बैठक में आरआईएस ने भी भाग लिया। यह परियोजना उन्नत अध्ययन संस्थान, वियना द्वारा समन्वित की जा रही है और यह तीन साल की अवधि के लिए है। आरआईएस इस परियोजना के तहत विभिन्न प्रदेय वस्तुओं में योगदान दे रहा है।

विज्ञान कूटनीति

विज्ञान कूटनीतिः यह डीएसटी द्वारा प्रायोजित तीन वर्षीय परियोजना है। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना है, ताकि राष्ट्रीय विकास में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। आरआईएस और एनआईएएस (बेंगलुरु) संयुक्त रूप से यह परियोजना शुरू करेंगे। समय सीमा हैः 2017–2020 और इसका शुभारंभ शीघ्र ही होगा।

यह प्रस्ताव आरआईएस और एनआईएएस का साझा प्रयास है। यह परियोजना राष्ट्रीय विकास के अहम मुद्दों पर विज्ञान कूटनीति की संभावनाओं को साकार करने का प्रस्ताव करती है। एसएंडटी नीतियों और विदेश नीति में बेहतर आपसी तालमेल बनाना और विज्ञान और कूटनीति का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना। तीन साल की इस परियोजना में परिकल्पना की गई है– 1) विभिन्न पहल के जरिए विज्ञान कूटनीति को बढ़ावा देना, 2) चयनित क्षेत्रों में एनआरआईध्पीआईओ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की क्षमताओं का दोहन, 3) एसएंडटी विकास में नीतिगत सहयोग उपलब्ध करवाना और 4) विज्ञान और तकनीक में रणनीतिक मुद्दों पर शोध आयोजित करना। इस परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैंः 1) एनआरआई/पीआईओ वैज्ञानिकों, तकनीकिविदों और विशेषज्ञों का अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, 2) नेटवर्क विकसित करना और 3) रणनीतिक सोच के लिए विज्ञान कूटनीति।

भारत में क्लीनिकल परीक्षणों का डब्लूएचओ के लिए अध्ययन

प्रो. टी. सी. जेम्स

स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हाल के वर्षों में क्लीनिकल परीक्षणों के नियमों में भारी बदलाव आए हैं। विशेषज्ञ समिति के सुझाव सामने आने के बाद नियमों में कई बदलाव लाए गए हैं। ये बदलाव इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए हैं। इन बदलावों का प्रभाव अब तक ज्ञात नहीं है। यह अध्ययन क्लीनिकल परीक्षण के नियमन में हुए बदलावों के प्रभाव के अध्ययन का प्रस्ताव करता है। इस अध्ययन में निम्न क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है भारत में क्लीनिकल परीक्षणों संबंधी नियम, स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत सरकार और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसका संदर्भ, सामग्री और निर्देश, सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले भारत में क्लीनिकल परीक्षण ोंसंबंधी नियमन और फैसला आने के बाद किए गए बदलाव।

अध्ययन में निम्न अवयव होंगेः

- क्लीनिकल परीक्षण संबंधी दिशा–निर्देश का व्यापक स्वरूप;
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएसओ) में रजिस्टर क्लीनिकल ट्रायल और विभिन्न वर्षों के दौरान उसकी संख्या;
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले और इसके बाद क्लीनिकल ट्रायल मंजूरी की संख्या की जांच;
- नए नियम की व्यवहारिक स्थिति अस्पताल, क्लीनिकल रिसर्च संगठनों, विशेषज्ञों और सीडीएसओ की प्रतिक्रिया जानने के लिए फिल्ड स्टडी करना;
- अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए), यूरोपीय औषधि एजेंसी (ईएमए) और यूके व आसियान देशों के नियमन के मुकाबले भारतीय कानून की स्थिति;
- क्लीनिकल ट्रायल के बेहतर सिद्धांत क्या हैं और क्या इन्हें भारत में शामिल किया गया है?;
- क्या इन नियमन में उपेक्षित बीमारियों के लिए किसी विशेष प्रावधान की जरूरत है? और
- उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां कदम उठाने की जरूरत है।

इसे उपलब्ध साहित्य के सर्वेक्षण और साथ ही फील्ड सर्वे की मदद से किया जा रहा है। उपलब्ध तथ्यों का सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है और टीम अब फील्ड स्टडी कर रही है। पहले चरण की रिपोर्ट डब्लूएचओ को सौंपी जा चुकी है। अंतिम रिपोर्ट में उन बदलावों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें दिशा–निर्देश और सुझावों में हाल में शामिल किया गया है। साथ ही उद्योग और मरीज के अनुकूल नीति और नियामक तंत्र के लिए सुझाव दिए जाएंगे। इस अध्ययन को जारी रखने के लिए डब्लूएचओ से वित्तीय मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।

भारत में सामान्य स्वास्थ्य सेवा में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को शामिल किए जाने पर अध्ययन

प्रो. टी. सी. जेम्स

भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के बहुत समृद्ध संसाधन उपलब्ध हैं। इसके लिए आयुष नाम से एक अलग से मंत्रालय भी गठित किया जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों

पर भारत पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की वकालत करता रहा है। इसी तरह ब्रिक्स जैसे बहु–पक्षीय मंचों पर भी हम सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पारंपरिक पद्धतियों को शामिल करने की वकालत करते रहे हैं। हालांकि भारत और चीन जैसे बड़े देशों में में इसकी मौजूदा स्थिति पर कोई व्यवस्थित अध्ययन उपलब्ध नहीं है। इस लिहाज से उठाए जा रहे भारत के कूटनीतिक कदमों को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि इस संबंध में पर्याप्त आंकड़े हों और इस विषय पर नीतिगत परिप्रेक्ष्य हो।

इसलिए निम्न पहलुओं को समाहित करते हुए एक अध्ययन का प्रस्ताव किया जाता हैः भारत और कुछ चुनिंदा जगहों जैसे चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और यूरोपीय संघ में नियामक व्यवस्था इन देशों में टीएम के उपयोग की मौजूदा स्थिति पारंपरिक और हर्बल दवाओं के उपयोग पर अंतरराष्ट्रीय समझौते और दिशा–निर्देश पारंपरिक और हर्बल दवा उद्योग की स्थिति।

इस अध्ययन में उपलब्ध साहित्य का सर्वे, नियामक व्यवस्ताओं का तुलनात्मक अध्ययन, पारंपरिक दवाओं के उपयोग के आंकड़े और भारत के प्रमुख कारोबारी सहयोगियों के साथ पारंपरिक और हर्बल दवा आयात और निर्यात के व्यापार आंकड़े। अंतिम रिपोर्ट में इन पर नीति संबंधि सुझाव होंगे– (1.) आईएसएम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जोड़ना और (2.) आईएसएम में कारोबार की संभावनाओं को तलाशना।

चुनिंदा देशों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर अध्ययन

प्रो. टी. सी. जेम्स

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पारंपरिक दवाओं का आम लोगों में उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। डब्लूएचओ पारंपरिक दवाओं में पर्याप्त दिलचस्पी ले रहा है और अब इस बात को मान्यता मिल रही है कि पारंपरिक दवाएं प्राथमिक, द्वितियक और शीर्ष स्तरीय स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही गैर–संक्रामक रोगों में पूरक और कई बार वैकल्पिक इलाज भी हो सकता है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि कुछ चुनिदां देशों में पारंपरिक दवाओं का उपयोग कैसे हो रहा है, इनका नियमन कैसे हो रहा है और इन्हें बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है। इससे भारत को अपनी पारंपरिक दवाओं के बाजार को समझने उसके अवसर को जानने और उसी अनुकूल उपाय करने में मदद मिलेगी।

पारंपरिक दवाओं में यह शोध लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सार्क और बिम्सटेक क्षेत्र के चुनिंदा देशों में करने का प्रस्ताव है। सार्क और बिम्सटेक का चयन इसलिए किया गया है, क्योंकि ये आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से भारत के बहुत करीब हैं। एशियाई देशों के बाहर इसकी भूमिका को समझने के लिए दो अन्य क्षेत्रों लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को लिया गया है, जहां पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था पहले से प्रचलित है।

इस शोध परियोजना के लिए अवधि छह से नौ महीने की सोची गई है। नीति संबंधी ढांचे, नियमन, आईपी नीतियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में पारंपरिक दवा की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इससे जो नतीजा निकलेगा उसमें एक बड़ी रिपोर्ट, तीन से चार नीतिगत ब्रीफ और विभिन्न विशेषज्ञ जर्नल के लेख जैसे अकाद्मिक नतीजे हासिल होंगे।

एशिया–प्रशांत क्षेत्र में कृषि जैव प्रौद्योगिकी की स्थिति की समीक्षा पर एफएओ का अध्ययन

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने एशिया–प्रशांत क्षेत्र में कृषि जैव प्रौद्योगिकी की स्थिति पर डेस्क समीक्षा करने और स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए आरआईएस से अनुरोध किया। इस पर काम जून 2017 में शुरू हुआ और जुलाई में मसौदा रिपोर्ट तैयार हो गई। इसे समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के एफएओ को भेजा गया था। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर 12–14 सितंबर 2016 को मलेशिया के कुआलालम्पुर में आयोजित क्षेत्रीय बैठक में परिचर्चा के लिए एक प्रस्तुति तैयार की गई थी। टिप्पणियों/अवलोकनों के आधार पर इस रिपोर्ट में संशोधन किए जा रहे हैं।

बीज क्षेत्र में भारत–अफ्रीका सहयोग पर अध्ययन

डॉ. टी.पी. राजेंद्रन और डॉ. अमित कुमार

भारत–अफ्रीका बीज क्षेत्र में विभिन्न अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। इस परिचर्चा पत्र में भारतीय बीज उद्योग के बाह्य उन्मुखीकरण एवं सब्जी फसलों के बीजों का व्यापार सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत संरचना का विश्लेषण किया गया है, अफ्रीकी बीज क्षेत्र की गतिशीलता से अवगत होने के लिए इस सेक्टर पर करीबी नजरें दौड़ाई गई हैं और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बीज क्षेत्र में सहयोग में आड़े आ रही चुनौतियों का पता लगाया गया है। यही नहीं, इसमें भारत–अफ्रीका बीज क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए अनेक निर्देशात्मक सिफारिशों और प्रगतिशील योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है।

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग और ट्रिप्स व्यवस्था में दवाओं तक पहुंच पर अध्ययन–चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच पर डब्ल्यूएचओ की परियोजना

प्रो. टी.सी. जेम्स

अध्ययन में इस बात पर फोकस किया गया है कि नई बौद्धिक संपदा व्यवस्था ने फार्मास्युटिकल उद्योग के साथ–साथ भारत एवं अन्य विकासशील देशों में सस्ती दवाओं तक पहुंच पर कैसे असर डाला है। अध्ययन का दायरा बढ़ाते हुए इसमें भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के इतिहास और इन तीन चरणों के दौरान इस उद्योग के विकास को भी कवर किया गया हैः (1) देश की आजादी से पहले के दिनों से लेकर वर्ष 1972 तक (2) वर्ष 1972 से लेकर वर्ष 2005 तक, जिस दौरान कोई भी उत्पाद पेटेंट नहीं था, और (3) वर्ष 2005 से लेकर वर्तमान तक। अध्ययन में इन बातों को भी कवर किया गया हैः वर्ष 2005 के बाद इस क्षेत्र में नजर आ रहे रुझान, उद्योग की वर्तमान स्थिति, वर्तमान परिदृश्य में भारत एवं अन्य विकासशील देशों में दवाओं तक पहुंच का मुद्दा, पेटेंटिंग में परिलक्षित होने वाले फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र से जुड़े नवाचार। चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच, अनुसंधान, नवाचार, व्यापार और बौद्धिक संपदा पर एक 'स्थिति पत्र' नवंबर 2017 तक तैयार हो जाएगा।

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम (एफआईटीएम)

प्रो. टी.सी. जेम्स

पारंपरिक चिकित्सा पद्धति (टीएम) के क्षेत्र में व्यावहारिक नीति निर्माण की दिशा में योगदान करने के लिए आयुष मंत्रालय की भागीदारी के साथ आरआईएस में एफआईटीएम की स्थापना की गई है। आयुष मंत्रालय, शिक्षाविदों, उद्योग और सिविल सोसायटी के बीच साझेदारी से एक पहल के रूप में उत्पन्न एफआईटीएम के तीन व्यापक उद्देश्य हैं:

- भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आईटीएम) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन करना, जिनमें बोद्धिक संपदा और भारत एवं अन्य देशों में पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण तथा पहुंच सहित पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के लिए नियामकीय ढांचा भी शामिल है।
- विभिन्न देशों द्वारा अपनाई जा रही एनटीबी सहित एसपीएस/टीबीटी और अन्य विनियामक नीतियों पर गौर करना, जो भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की वाणिज्यिक संभावनाओं पर आघात कर रही हैं।
- इस क्षेत्र के वैश्विक घटनाक्रमों (वैश्विक संस्थानों सहित) पर करीबी नजर रखना।

पारंपरिक ज्ञान, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण पर गहन अध्ययन

अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल दुनिया सहित टीके, जीआर एवं संबंधित पारंपरिक ज्ञान और भारत में टीसीई के संरक्षण के लिए वर्तमान में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की पर्याप्तता पर गौर करना है। इसका उद्देश्य जैव चोरी रोकने के लिए इन प्रावधानों की पर्याप्तता का आकलन करना और यदि कोई हो, तो मौजूदा कानूनों में आवश्यक परिवर्तन/अनुवृद्धि को प्रस्तावित करना भी है।

अध्ययन के तीन घटकों पर तीन दायरा प्रपत्र (स्कोपिंग पेपर) तैयार किए जा रहे हैं। इनमें निम्ननलिखित शामिल हैं :

- पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर गहन अध्ययन के लिए दायरा प्रपत्र
- आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण पर गहन अध्ययन के लिए दायरा प्रपत्र
- पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण पर गहन अध्ययन के लिए दायरा प्रपत्र

यह अध्ययन एक वर्ष के लिए है, जिसके आखिर में आयुष मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

पारंपरिक चीनी चिकित्सा को घरेलू स्तर पर मुख्य धारा में लाने और विश्व स्तर पर इसके प्रचार–प्रसार के लिए चीन की नीतिगत पहलों का अध्ययन

अध्ययन का उद्देश्य पारंपरिक चीनी चिकित्सा (टीसीएम) को अपनी सार्वजनिक/सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के तहत मुख्य धारा में लाने, विश्व स्तर पर टीसीएम का प्रचार–प्रसार करने और घरेलू स्तर पर टीसीएम को संरक्षित रखने एवं बढ़ावा देने के लिए बोद्धिक संपदा का उपयोग करने में चीन की नीतिगत पहलों का

अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य चीन के मुकाबले भारत की ताकतों और कमजोरियों का तुलनात्मक आकलन करना भी है। इससे मिलने वाले सबक को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों (टीएसएम) का प्रचार–प्रसार करने में शामिल/अनुकूलित किया जाएगा। अध्ययन पूरा हो जाने के बाद वर्ष 2018 के आखिर तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी।

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा कार्यक्रम के तहत अनुसंधान फेलोशिप

फेलोशिप का उद्देश्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आईटीएम) से संबंधित विषयों और संभावनाओं एवं चुनौतियों पर गहन अन्वेषण एवं अनुसंधान करना है। इस अन्वेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों सहित प्रकाशनों का उद्देश्य आईटीएम का प्रचार–प्रसार करने पर नीति संबंधी अनुसंधान सामग्री या जानकारियां प्रदान करना है। आईटीएम से संबंधित विभिन्न विषयों पर डोमेन विशेषज्ञों द्वारा आमंत्रित वार्तालाप भी इस परियोजना का एक हिस्सा हैं। आरआईएस फेलोशिप और आगामी प्रकाशनों के अनुदान का प्रबंधन करेगा।

विकासशील देशों में व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं विकास

प्रो. राम उपेंद्र दास

व्यापार एवं विकास के बीच एवं व्यापार तथा प्रौद्योगिकी के बीच भी संबंधों तथा कारण कार्य सिद्धांतों का विश्लेषण अक्सर सैद्धांतिक तथा अनुभवजन्य अन्वेषणों की एक दोहरी संरचना में किया जाता है। इस अध्ययन में एक वैचारिक संरचना के निर्माण, जिसे व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा विकास के बीच अंतःसंपर्कों पर अनुभवजन्य साक्ष्यों के साथ सिद्ध किया जा सके, का प्रयास किया गया है। इसका लक्ष्य खासकर, दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्व एशिया के विकासशील देशों में नीति के प्रभावों पर विचार करना है जिसके द्वारा व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा विकास के बीच सहयोग का उपयोग इन देशों में विकास की अवधारणाओं में बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है।

II

नीतिगत शोध पत्र

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- डीजीएफटी को विदेश व्यापार नीति की मध्यवाधि समीक्षा पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई
- पीटीए के लिए भारत–ईरान वार्ता
- आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग सहमति (ईटीसीए) समझौते के लिए भारत–श्रीलंका वार्ता
- पीटीए के लिए भारत–मर्कोसुर वार्ता
- 'ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों' पर एक अध्ययन प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग को सौंपा गया।
- 'भारत व्यापार और निवेश एजेंसी (आईटीआईए)' पर रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग को भेजी गई थी।

विदेश मंत्रालय

- हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए), (आईओआरए सीईपीए) में छोटे और द्वीप विकासशील देशों का आर्थिक एकीकरण
- 'महासागर सम्मेलन' एसडीजी 14 पर एसआईडीएस और एलडीसी' के लिए आरआईएस नोट को जेएस (आईओआर) के अनुरोध के अनुसार विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

नीति आयोग

विचार–विमर्श के विभिन्न आयोजनों से एसडीजी पर प्राप्त जानकारियां नीति आयोग तथा वीएनआर तैयार करने के लिए उपलब्ध करवाईं

अन्य

- टीसीएम को घरेलू स्तर पर मुख्य धारा में लाने और विश्व स्तर पर इसके प्रचार–प्रसार के लिए चीन की नीतिगत पहलों के अध्ययन का प्रस्ताव एफआईटीएम के तहत आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।
- पारंपरिक ज्ञान, आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण पर गहन अध्ययन के प्रस्ताव को एफआईटीएम के तहत आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।
- एफआईटीएम कार्यक्रम के तहत अनुसंधान फेलोशिप से जुड़ा प्रस्ताव आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।
- आरआरआई पर राष्ट्रीय कार्यशाला रिपोर्ट भारत सरकार के डीएसटी को जून 2017 में प्रस्तुत की गई
- आरआरआई पर भारतीय रिपोर्ट बर्लिन में आयोजित आरआरआई–प्रैक्टिस बैठक में 22 सितंबर 2017 को प्रस्तुत की गई

III

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

भारत और टिकाऊ विकास लक्ष्य

माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 7 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में 'भारत और टिकाऊ विकास लक्ष्य : आगे की राह' शीर्षक आरआईएस प्रकाशन का विमोचन किया। इस पुस्तक में 19 विस्तृत लेख हैं जो टिकाऊ विकास की समस्त श्रेणियों तथा दो अन्य विषय, वित्त और प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते हैं।

इस पुस्तक के लिए अपने संदेश में माननीया विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत टिकाऊ विकास के लिए 2030 एजेंडे को उच्च प्राथमिकता देता है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर 2015 में सर्वसम्मति से अपनाया था और जो

माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आरआईएस की *'भारत और टिकाऊ विकास लक्ष्य : आगे की राह'* शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन करती हुईं। साथ में हैं (बाएं से दाएं) संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक एवं भारत में यूएनडीपी के निवासी (स्थानीय) प्रतिनिधि श्री यूरी अफानसीव, आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सुश्री सुजाता मेहता और आरआईएस की अनुसंधान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री एस.टी. देवारे।

मानव जाति की खुशहाली एवं प्रगति के लिहाज से काफी अहम साबित होगा। मैं उन 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के समग्र कार्यान्वयन के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करना चाहती हूं जो हमारे खुद के प्रमुख कार्यक्रम और प्राथमिकताओं को काफी हद तक प्रतिबिंबित करते हैं। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक (रेज़िडेंट कोआर्डिनेटर) एवं भारत में यूएनडीपी के स्थानीय प्रतिनिधि श्री यूरी अफानसीव और विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सुश्री सुजाता मेहता ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस प्रकाशन में अहम योगदान करने वाले लेखकगण भी इसके विमोचन के दौरान उपस्थित थे।

माननीया विदेश मंत्री नें यह बात भी रेखांकित की है कि यह पुस्तक (वाल्यूम) 2030 एजेंडे के कार्यान्वयन में जुटे लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन साबित होगी और केंद्र एवं राज्य स्तरों पर प्रभावपूर्ण नीतिगत सामंजस्य विकसित करने में मददगार होगी। माननीया मंत्री की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आरआईएस की इस पुस्तक की प्रतियां भारत में लोकसभा और राज्य सभा दोनों के ही सभी माननीय सांसदों को उपलब्ध कराई गई हैं।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस अवसर पर कहा, 'प्रगति, समावेश और स्थायित्व के कई क्षेत्रों में एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु भारत ने पहले ही खुद के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर दिए हैं।' उन्होंने कहा, 'इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ–साथ एसडीजी के साथ सामंजस्य बैठाने में भी राज्य सरकारों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी बदौलत एसडीजी की प्राप्ति के लिए सभी सामाजिक और आर्थिक मानकों को कारगर ढंग से प्रभावित किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एसडीजी की प्राप्ति के प्रति भारत के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने में नीति आयोग सबसे आगे रहा है। आरआईएस इस संदर्भ में नीति आयोग, नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एसडीजी एजेंडे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आपसी सामंजस्य वाला नीतिगत ढांचा विकसित करने हेतु परामर्श संबंधी बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन करता रहा है।

आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने कहा, 'आरआईएस टिकाऊ विकास लक्ष्यों के एजेंडे के प्रभावी क्रियान्वयन पर आयोजित की जाने वाली घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचर्चाओं में व्यापक योगदान करने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और इसने अनेकानेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंत्रणाओं का आयोजन किया है।'

संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक एवं भारत में यूएनडीपी के स्थानीय प्रतिनिधि श्री यूरी अफानसीव ने भी भारत में एसडीजी की प्राप्ति हेतु पूरी सक्रियता के साथ निरंतर प्रयासरत रहने के लिए आरआईएस और नीति आयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सुश्री सुजाता मेहता ने एसडीजी के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

ब्रिक्स आर्थिक मंच

आरआईएस ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 13 एवं 14 अक्टूबर, 2016 को गोवा में सफलतापूर्वक प्रथम ब्रिक्स आर्थिक मंच का आयोजन किया। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ–साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं वरिष्ठ बैंकरों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ब्रिक्स आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव श्री समीर खरे ने बैठक का संदर्भ निर्धारित किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक (भारत) डॉ. सुबीर गोकर्ण ने उद्घाटन भाषण दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर पटेल ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

उद्घाटन सत्र के बाद ब्रिक्स तथा बहुपक्षीय संस्थानों, ब्रिक्स एवं विकास के लिए वित्त पोषण, ब्रिक्स एवं अभिनव अर्थव्यवस्था और ब्रिक्स एवं वित्तीय बाजारों पर चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। ब्रिक्स के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ वैश्विक मानक तय करने, नीतिगत समन्वय एवं संकट प्रबंधन पर एक पैनल परिचर्चा और ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों के साथ टिकाऊ विकास के लिए सहयोग पर एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के साथ एक विशेष संवाद सत्र भी आयोजित किया गया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री शक्तिकांत दास भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रतिभागियों ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच अधिक से अधिक समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का कार्य सुनिश्चित करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

भारत एवं एफटीए पर परामर्श और आगे की राह

भारत ने अपनी व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण नीति के एक हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग की शुरुआत की है और इसके साथ ही भारत ने अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें अर्ली हार्वेस्ट स्कीम से लेकर एफटीए/सीईपीए/सीईसीए तक शामिल हैं। हालांकि, इस तरह की व्यवस्थाओं के विभिन्न आयामों पर अलग–अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों के अनुसार, कल्याणकारी प्रभावों में निरंतर बेहतरी के लिहाज से एफटीए का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है, जबकि कुछ अन्य लोग यह तर्क देते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में विश्वसनीय

रणनीति का सख्त अभाव है। इस वाद–विवाद में मुख्य बाधा दरअसल अवधारणाओं को लेकर है, जो स्पष्ट अनुभवजन्य विश्लेषण पर आधारित नहीं हैं। इसके अलावा, विशाल–एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) जैसे कि टीपीपी और इसी तरह के अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाने से बहुपक्षवाद के समक्ष नई चुनौतियां उभर कर सामने आ गई हैं। आरआईएस ने एफटीए और संबंधित मुद्दों की दिशा में भारत की रणनीति पर अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिस्से के रूप में व्यापार नीति विशेषज्ञों और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 14 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में और मीडिया के साथ 1 मई 2016 को परामर्श बैठकें आयोजित कीं। सुश्री निर्मला सीतारमण, माननीया वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने सत्र की अध्यक्षता की। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया और विगत वर्षों के दौरान आरआईएस द्वारा किए गए व्यापक कार्यों के स्वरूप पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस ने एफटीए के बारे में आरआईएस के दृष्टिकोण पर एक प्रस्तुति दी। श्री अरविंद मेहता, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग के समक्ष मौजूद मुद्दों का जिक्र किया। इसके अलावा श्री जी.के. पिल्लई और श्री राहुल खुल्लर, दोनों पूर्व वाणिज्य सचिव, और सुश्री रीता ए. तेवतिया, वर्तमान वाणिज्य सचिव ने विभिन्न उपायों का उल्लेख किया। देश भर में फैले प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने भी 1 मई 2016 को उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

सुश्री निर्मला सीतारमण ने भारत का विदेश व्यापार बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य एफटीए से हो रहे फायदों में वृद्धि करना है। अतः इसके मद्देनजर भारत उन साझेदार देशों से अपेक्षाकृत अधिक बाजार पहुंच सुलभ कराने को कहेगा जिनके साथ उसने एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। यही नहीं, एफटीए से केवल आयात बढ़ने संबंधी आलोचना को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के तरीके खोजेगा। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू सुधारों में भी तेजी लाएगी और बुनियादी ढांचागत बाधाओं को दूर करने एवं विशेष रूप से छोटे व मझोले उद्यमों को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी, जो भारत के निर्यात में 40 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान करते हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एफटीए से कहीं और ज्यादा लाभ हासिल करना है। भारत से कृषि निर्यात बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। जब यह सवाल पूछा गया कि एफटीए संबंधी वार्ताएं तेजी से पूरी क्यों नहीं हो

माननीया वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण 1 मई 2016 को परामर्श में बोलती हुईं। साथ में हैं (बाएं से दाएं) प्रो. राम उपेंद्र दास, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री श्याम सरन, सुश्री रीता ए. तेवतिया, और श्री अरविंद मेहता।

पा रही हैं तो मंत्री महोदया ने कहा, 'प्रत्येक समझौते पर तय प्रक्रिया के मुताबिक काम जारी है। कोई भी समझौता यदि नहीं हो पा रहा है तो उसका कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कारण नहीं है। दरअसल, यदि वार्ता पर असर डालने वाला कोई व्यापक कारण है भी, तो वह समझौता करने की हमारी इच्छा से जुड़ा है।' इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार और निवेश के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत के साथ–साथ 'किसी आयातित उत्पाद के मूल देश' से संबंधित नियमों की विकासात्मक भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने पर भी चर्चा की गई। यह कोष उन क्षेत्रों (सेक्टर) के काम आ सकता है जिन पर एफटीए के कारण अत्यंत प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत को सभी स्तरों पर सेवा व्यापार के क्षेत्र में अपनी ताकत या खासियत पर नए सिरे से काम करना चाहिए। इस दौरान आरआईएस और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा बाजार पहुंच, सेवाओं, निवेश, बोद्धिक संपदा और ई–कॉमर्स सहित विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं।

माननीया वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारत और एफटीए पर दिए गए वक्तव्य के कुछ अंश

माननीया वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री निर्मला सीतारमण ने भारत की व्यापार नीति के विरोधाभासी होने के मुद्दे पर कहा कि भारत सरकार के पास इस बात को लेकर एक स्पष्ट तस्वीर है कि व्यापार के मोर्चे पर कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार व्यापार वार्ताओं के मामले में निश्चित रूप से लक्ष्यहीन नहीं है। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि हम एफटीए पर अनावश्यक रूप से काफी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि रोजगार सृजन के लिए निवेश और राष्ट्रीय हित हमारी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कई विकसित देशों के संरक्षण ावादी कदमों की ओर भी संकेत किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने जी–20 के कई सदस्य देशों के संरक्षणवादी कदमों का उल्लेख किया और कहा कि अगर भारत (वह भी जी–20 का एक सदस्य देश है) ने कोई ऐसा कदम उठाया जिसे वे (अमीर राष्ट्र) नकारात्मक समझ लेते हैं, तो वैसी स्थिति में वे भारत को संरक्षणवादी के रूप में पेश करने के लिए अभियान चलाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर वे अमीर देश, संरक्षणवादी उपाय करते हैं, तो वे इसके बारे में बातें नहीं करना चाहते हैं। सुश्री सीतारमण ने विशेष जोर देते हुए कहा कि अमीर राष्ट्र 'व्यापार में विकृति लाने वाली भारी–भरकम कृषि सब्सिडी' देते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक विश्व व्यापार संगठन में सही ढंग से चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने 'चीन द्वारा अपने उद्योग जगत को दी जा रही सब्सिडी' का भी उल्लेख किया और कहा कि यह स्टील सहित विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय निर्माताओं का अहित कर रही है। चीन सहित कई देशों द्वारा अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन किए जाने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के निर्यात में निरंतर हो रही कमी का हवाला दिया और कहा कि उनका व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि भारतीय मुद्रा का कुछ अवमूल्यन करने की जरूरत है। हालांकि, इस बारे में अंतिम फैसला आरबीआई को ही लेना है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वैसे तो भारत 16–देशों के समूह में कोई अवरोधक नहीं है, लेकिन वह इस समझौते के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को खोलने के लिए स्वयं के द्वारा की गई पेशकश पर झुकेगा नहीं और वह इन्हें आगे भी बरकरार रखेगा। दरअसल, आरसीईपी के अंतर्गत 'मोड 3 सेवाओं' पर भारत की पेशकश, जिसके तहत विदेशी

वाणिज्यिक मौजूदगी की अनुमति दी जाती है, अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक उदार है क्योंकि उसे केवल वित्तीय, बीमा और कानूनी सेवाओं को खोले जाने को लेकर आशंकाएं हैं।

बिम्सटेक और आईबीएसए रिपोर्टों का विमोचन

आरआईएस ने दो प्रमुख प्रकाशन प्रकाशित किए, जिनमें बिम्सटेक और आईबीएसए से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी गई है। '*बिम्सटेक – आगे की राह और आईबीएसए – विकास, लोकतंत्र और स्थायित्व के लिए ट्रिनिटी*' शीर्षक युक्त दो रिपोर्टों को भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा 9 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में विमोचन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के उपाध्यक्ष डॉ. वी.एस. शेषाद्री ने आरंभिक भाषण दिया। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री आलोक ए. डिमरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

आईबीएसए की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) के इतिहास में आईबीएसए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में डटा हुआ है। आईबीएसए के सदस्य देश बहुपक्षवाद एवं शांति की वकालत करते हैं, संप्रभुता के लिए सम्मान को बढ़ावा देते हैं, लोगों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, विकासशील एवं विकसित देशों के बीच व्यापार और आर्थिक पहलुओं को अपना भरपूर समर्थन देते हैं। इसी तरह, बिम्सटेक की रिपोर्ट में यह बात रेखांकित की गई है कि कई क्षेत्रों में प्रत्येक देश की क्षमताएं बिम्सटेक समूह के सदस्य देशों के बीच साझा करने और सीखने का एक स्रोत साबित हो सकती हैं। 'बंगाल की खाड़ी आर्थिक समुदाय' के संभावित गठन के लिहाज से बिम्सटेक एक महत्वपूर्ण निर्माण ब्लॉक है।

भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) '*बिम्सटेक – आगे की राह,* और '*आईबीएसए – विकास, लोकतंत्र और स्थायित्व के लिए ट्रिनिटी*' के शीर्षक वाली दो रिपोर्टों को पेश करते हुए।

भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र ने आसियान के लिए भारतीय मिशन, आसियान सचिवालय, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय के सहयोग से 19 जनवरी 2017 को जकार्ता में भारत और आसियान के

बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आसियान के लिए भारत के राजदूत सुरेश के. रेड्डी ने आरंभिक भाषण दिया। भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने मुख्य भाषण दिया। इंडोनेशिया के उप विदेश मंत्री श्री ए.एम. फचीर ने विशेष भाषण दिया। आसियान के उप महासचिव श्री वोंगथेप अर्थकईवल्वैंटी और वियतनाम के उप विदेश मंत्री श्री गुयेन क्योपक ड्जंग ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) राजदूत प्रीति सरन ने समापन भाषण दिया। डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आसियान के सभी सदस्य देशों ने अपने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को सम्मेलन के लिए नामित किया और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने इस एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन 23–24 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में 'आसियान–भारत सांस्कृतिक संबंध : ऐतिहासिक और समकालीन आयाम' पर आयोजित किए गए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अनुवर्ती आयोजन था। दूसरा सम्मेलन इसके साथ ही आसियान–भारत वार्तालाप भागीदारी की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिहाज से पहला आयोजन था।

सम्मेलन को चार सत्रों में विभाजित किया गया था, ताकि जन संपर्कों एवं सांस्कृतिक संबंधों के जरिए आसियान–भारत सामरिक भागीदारी के मार्ग की उभरती चुनौतियों की पहचान करने के साथ–साथ आसियान समुदाय के ब्लूप्रिंटों के नजरिए से विभिन्न चुनौतियों से पार पाने के लिए उपयुक्त नीतिगत विकल्पों की भी पहचान की जा सके। सम्मेलन में उन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, विश्लेषण किया गया और फिर एकजुट किया गया जिनसे आसियान और भारत के बीच के सांस्कृतिक संबंधों को समझने में मदद मिलेगी।

भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर आयोजित सम्मेलन में प्रतिभागी शिरकत करते हुए।

भारत–बांग्लादेश बहु क्षेत्रीय सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आरआईएस ने कोलकाता स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज (मकायास), द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी (एनएमएमएल) और नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (आईजीएनसीए) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 23–24 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में भारत–बांग्लादेश बहु क्षेत्रीय सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। श्री एम. जे. अकबर, माननीय राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। श्री मोजामेल हक, सांसद, मुक्ति युद्ध मामलों के माननीय मंत्री, बांग्लादेश सरकार मुख्य अतिथि थे। श्री अरिंदम मुखर्जी, सचिव, सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान ने स्वागत भाषण दिया। सुश्री श्रीप्रिया रंगनाथन, संयुक्त सचिव (बीएम), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया।

भारत में बांग्लादेश के माननीय उच्चायुक्त श्री सईद मुआजेम अली और नई दिल्ली स्थित आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी 'भारत बांग्लादेश आर्थिक सहयोगः चुनौतियां और अवसर' पर आयोजित सत्र के अग्रणी वक्ताओं में से एक थे। भारत सरकार में माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने सत्र की अध्यक्षता की।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने भी समापन सत्र में 'आगे की राह' विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। न्यायमूर्ति ए. एच.एम. शम्सुद्दीन चौधरी, पूर्व न्यायाधीश, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सत्र की अध्यक्षता की। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि थे।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी सम्मेलन में बोलते हुए। इस अवसर पर उपस्थित हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीया वस्त्र मंत्री, भारत सरकार।

ब्रिक्स शैक्षणिक फोरम

आरआईएस एंव ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) ने 19 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2016 तक गोवा में ब्रिक्स शैक्षणिक फोरम के चार दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री पार्सेकर ने कहा कि ब्रिक्स ने भू–आर्थिक संगठन के रूप में मुखर शक्ति हासिल कर ली है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। अत; भविष्य में ब्रिक्स को अंतरराष्ट्रीय कानून एवं निर्णय लेने की बहुपक्षीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और वैश्विक गवर्नेंस से जुड़े संस्थानों में उभरते एवं विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को मजबूत करना है, जो वर्तमान में बेहद कम है। उन्होंने एक विकास बैंक बनाने के लिए ब्रिक्स द्वारा की गई पहल की भी सराहना की, जो भागीदार देशों की जरूरतों को पूरा करेगा। सम्मेलन का विषय था 'उभरती भू–राजनीतिक व्यवस्था ब्रिक्स के लिए चुनौतियां और अवसर।

श्री संजय जोशी, निदेशक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने स्वागत और उद्घाटन भाषण दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिक्स को वैश्विक प्रबंधन में प्रभावकारी भूमिका निभाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ब्रिक्स को अपने अनुभव और ज्ञान के दम पर निपटना है।

श्री समीर सरन, उपाध्यक्ष, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इस अवसर पर संचालक (मॉडरेटर) थे। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के समापन भाषण के साथ यह सत्र समाप्त हुआ।

शैक्षणिक फोरम ने इन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया ; उभरती भू–राजनीतिक व्यवस्था; ब्रिक्स के लिए चुनौतियां एवं अवसर, उभरते वैश्विक व्यापार ढांचे में ब्रिक्स के लिए अवसर एवं चुनौतियां और ब्रिक्स के भीतर व्यापार विस्तार की संभावनाएं, विकास के लिए विकासशील देशों और एलडीसी को अंतरराष्ट्रीय वित्त एवं प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ब्रिक्स की भागीदारी– एक नया विकास प्रतिमान तैयार करना, आम स्वास्थ्य चुनौतियां एवं ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं, नए सुरक्षा खतरों के प्रबंधन पर ब्रिक्स का सहयोग, हाल ही में विकसित साझा संसाधनों और संबंधित वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का नियमन करना; ब्रिक्स की ओर से एक विजन, एसडीजी के कार्यान्वयन पर विचारों का आदान–प्रदान एवं अनुभवों को साझा करना, ऊर्जा का भविष्य; ब्रिक्स के लिए निहितार्थ एवं अवसर, महिला–पुरुष, विकास एवं राजनीति – ब्रिक्स के एक नए नेतृत्व विजन की ओर, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम तथा अनौपचारिक क्षेत्र – विकास के लिए ब्रिक्स का एक प्रस्ताव और ब्रिक्स का भविष्य।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने एसडीजी के कार्यान्वयन पर विचारों के आदान–प्रदान और अनुभवों को साझा करने पर आयोजित सत्र का संचालन किया। उन्होंने सतत विकास के लिए पहुंच, समता (इक्विटी) और समावेशन हेतु एक रूपरेखा निर्धारित की। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि हाल ही में हस्ताक्षरित एसडीजी यह परिभाषित करने जा रहे हैं कि भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्थाएं किस तरह से काम करेंगी। उन्होंने एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने की सिफारिश की। उन्होंने इस बारे में भी विस्तार से बताया कि वेलनेस इंडेक्स आगे की राह है। दरअसल, ब्रिक्स वेलनेस इंडेक्स को आरआईएस द्वारा ही ब्रिक्स वेलनेस कार्यशाला में प्रस्तावित

किया गया था। प्रो. एस.के. मोहंती, आरआईएस ने ब्रिक्स और वैश्विक व्यापार ढांचे पर एक व्यापक प्रस्तुति दी।

ब्रिक्स अकादमी फोरम पांच देशों के शिक्षाविदों द्वारा ब्रिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दों पर चर्चाएं करने और अपने विचार एवं सिफारिशें पेश करने के लिहाज से एक ट्रैक–2 प्लेटफॉर्म है। प्रत्येक सदस्य देश के विद्वानों ने विशेष महत्व वाले विषयों पर अपने विचार पेश किए। इसके अलावा, ब्रिक्स देशों के अनेक विद्वानों ने विचार–विमर्श में भाग लिया।

गोवा की माननीया राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा ने अपने समापन भाषण में कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक और ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच या फोरम है जो मानवता के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अन्य देशों के साथ आपसी सहयोग एवं संबंधों को काफी तेजी से सुदृढ़ करता है, अत; इस तरह के वार्षिक आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माननीया राज्यपाल ने इस बात पर रोशनी डाली कि

गोवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ब्रिक्स शैक्षणिक फोरम का उद्घाटन करते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) श्री व्लादिमीर डेविदोव, श्री लुईस फर्नांडो लारा रेसेंडे, श्री संजय जोशी, श्री समीर सरन, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री झाओ झोंगजियू और श्री जॉन पंपालिस।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत व्यापार और आर्थिक सहभागिता को तेजी से बढ़ा रहा है। ब्रिक्स देशों के समृद्ध ज्ञान और संसाधनों ने व्यापार का विस्तारीकरण संभव कर दिया है। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि ब्रिक्स राष्ट्र पारंपरिक कला और शिल्प की संसाधन शाला हैं, अत; ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देते वक्त इन पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स फोरम से ब्रिक्स देशों को व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ब्रिक्स देशों की स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की अहमियत का भी उल्लेख किया जो ब्रिक्स राष्ट्रों के समक्ष मौजूद स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। एसडीजी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र महिलाओं की भागीदारी के बिना सतत प्रगति नहीं कर सकता है और जब महिलाओं को सही शैक्षणिक अवसर दिए जाते हैं, तो वे लक्ष्यों को तय करने और उनकी प्राप्ति के लिए कहीं अधिक प्रतिबद्ध हो जाते हैं।

ओआरएफ के निदेशक श्री संजय जोशी ने अपने भाषण में इस बात पर भी रोशनी डाली कि एसडीजी की सफलता शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि क्षेत्रों में ब्रिक्स की कामयाबी पर निर्भर होने जा रही है। उन्होंने ब्रिक्स थिंक टैंक की दिशा में शुरुआती कदम के रूप में ब्रिक्स डिजिटल संग्रह की स्थापना के बारे में भी जानकारी दी।

आईओआरए ब्लू इकोनॉमी संवाद

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 4–5 नवंबर 2016 को 'हिंद महासागर में ब्लू इकोनॉमी की आर्थिक संभावनाओं और वाणिज्यीकरण के पहलुओं' पर आईओआरए ब्लू इकोनॉमी संवाद का आयोजन किया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। नई दिल्ली स्थित विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के महानिदेशक नलिन सूरी और आरआईएस के प्रो. एस. के. मोहंती ने प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता की।

भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने उद्घाटन भाषण दिया।

ब्लू इकोनॉमी संवाद के दौरान आईओआरए क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) की आर्थिक संभावनाओं को लेकर पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रबुद्ध परिचर्चाओं को प्रोत्साहित किया गया। नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा, मत्स्य पालन, गहरे समुद्र में एवं अपतटीय खनन, तटीय पर्यटन एवं शहरीकरण और समुद्री एवं सामरिक आयाम इन पांच क्षेत्रों में शामिल हैं।

भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) आईओआरए के नीतिगत संक्षिप्त वृतान्त *'आईओआरए में मत्स्य पालन क्षेत्र : क्षेत्र की ब्लू इकोनॉमी की संचालक शक्ति'* का विमोचन करते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, राजदूत सुधीर देवारे, अध्यक्ष, अनुसंधान सलाहकार परिषद, आरआईएस, और सुश्री रेणु पाल, संयुक्त सचिव (आईओआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।

‘ब्रिक्स वेलनेस इंडेक्स’ की ओर

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से कुछ समय पहले ‘ब्रिक्स वेलनेस फोरम’ का आयोजन कर्नाटक सरकार की मेजबानी में, आयुष मंत्रालय द्वारा 10–11 सितंबर 2016 को बंगलुरू में विदेश मंत्रालय और आरआईएस के साथ सहभागिता में किया गया था, ताकि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

श्री अनंत कुमार, माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार, श्री श्रीपद येसो नाइक, माननीय आयुष राज्य मंत्री, श्री रमेश कुमार, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, कर्नाटक सरकार और श्री श्री रवि शंकर, संस्थापक, आर्ट ऑफ लिविंग ने कार्यशाला का उद्घाटन किया।

श्री अजीत एम. शरण, सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय, डॉ. शालिनी रजनीश, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, डॉ. एच. आर. नागेंद्र, कुलाधिपति, एस–व्यास डीम्ड यूनिवर्सिटी, श्री ओ. ओ. सलागाई, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं जनसंपर्क विभाग, रूसी संघ का स्वास्थ्य मंत्रालय, श्री झू हैडोंग, उप महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग, सरकारी पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रशासन, प्रो. जेम्स कैंपबेल, विभाग प्रमुख, स्कूल ऑफ नैचुरल मेडिसिन, वेस्टर्न केप विश्वविद्यालय ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

श्री अनंत कुमार, माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक संगठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ‘हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत ऐसा फोरम (मंच) बनाने के लिए अवश्य ही पहल करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स देश दुनिया की आबादी के 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत चीन के साथ पारंपरिक चिकित्सा में अगुवाई करता है। विश्व योग दिवस समारोह ऐसा ही एक उदाहरण है।’ उन्होंने श्री श्रीपद येसो नाइक, माननीय आयुष राज्य मंत्री से इसे आगे बढ़ाने को कहा।

श्री अनंत कुमार, माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार, श्री श्रीपद येसो नाइक, माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और श्री के. आर. रमेश कुमार, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, कर्नाटक सरकार बेंगलुरू में ब्रिक्स वेलनेस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान ब्रिक्स देशों के सदस्यों के साथ मिलकर आरआईएस वॉल्यूम ‘स्वास्थ्य, स्वभाव और जीवन की गुणवत्ता ; ब्रिक्स वेलनेस इंडेक्स की ओर’ जारी करते हुए।

श्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि मंत्रालय का उद्देश्य मौजूदा अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करना और उन चिन्हित बीमारियों पर एक समयबद्ध शोध कार्यक्रम सुनिश्चित करना है, जिसके लिए इन प्रणालियों में उपचार की एक प्रभावकारी व्यवस्था है। उन्होंने कहा, 'आयुष एकीकृत दवाइयों से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयासरत है।'

श्री के. आर. रमेश कुमार, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, कर्नाटक सरकार ने कहा कि वेलनेस को केवल अमीर लोगों का ही विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अत; हमें एक ऐसी प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए जिसमें सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो।

इस अवसर पर श्री श्री रवि शंकर ने कहा कि लोगों के इलाज के लिए पारंपरिक दवाओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा, 'दवा की सदियों पुरानी प्रणालियों के प्रति पूर्वाग्रह की आवश्यकता नहीं है। इनकी खोज हजारों साल पहले हुई थी और हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही उनकी अहमियत साबित कर दी थी। योग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य अवधारणाओं के मद्देनजर पूरे विश्व ने भारत पर अपनी नजरें जमा दी हैं। कई देश हमारी पारंपरिक दवाओं के साथ–साथ योग को भी अपना रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम भारत में भी इनकी खूबियों से सभी लोगों को अवगत कराएं।'

श्री श्री ने कहा, 'भारत शेष दुनिया के साथ एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से अपने पारंपरिक ज्ञान को साझा कर सकता है। समय की मांग है कि आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा का गठबंधन कर दिया जाए।'

श्री अजीत एम. शरण के अनुसार, भारत आयुष में एक नया मार्ग तैयार कर रहा है। पारंपरिक चिकित्सा की संभावनाएं और अनुसंधान क्षमता एक नया आयाम ले रही हैं। आगे का रास्ता साक्ष्य आधारित अनुसंधान होगा। भारत ने इस क्षेत्र में चीन और रूस के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। समय की मांग यह भी है कि पारंपरिक दवाओं में बोद्धिक संपदा के लिए एक समझौता किया जाए।

पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा में लाने का आह्वान करते हुए डॉ. एच.आर. नागेंद्र ने कहा, 'भारत में एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक नीति की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को अकेले एलोपैथी तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यह पूर्ण चिकित्सा और इलाज सुनिश्चित नहीं करती है। आयुष और यहां तक कि चीनी दवाइयां भी कारगर प्रणालियां हैं, जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, माइग्रेन, मिर्गी, अस्थमा जैसे गैर–संचारी रोगों के बढ़ते बोझ को काफी हद तक कम कर सकती हैं।' उन्होंने बताया कि वैसे तो आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर, 2014 को ही हो गया था, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा प्रणाली में एकीकृत करने के प्रयास काफी पहले वर्ष 2006 में ही शुरू हो गए थे।

जहां एक ओर ब्राजील ने पश्चिमी प्रभावों का सामना करने के लिए एक आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की उम्मीद जताई है, वहीं दूसरी ओर भारत आयुर्वेद के वैश्वीकरण पर काम कर रहा है और इसने त्रिनिदाद एवं टोबैगो, हंगरी तथा थाईलैंड स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद आसन (चेयर) की स्थापना की है तथा जल्द ही रूस, इंडोनेशिया, स्लोवेनिया, लातविया और आर्मेनिया में भी एक–एक आयुर्वेद आसन की स्थापना की जाएगी। इन देशों ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को एकीकृत करने और इन क्षेत्रों में साक्ष्य–आधारित शोध को बढ़ावा देने के लिए अपने दृष्टिकोण, कानूनों और नीतियों को साझा किया।

डॉ. शालिनी रजनीश, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कर्नाटक सरकार ने कहा कि केंद्र को आयुष औषधियों की मुख्य धारा में लाने पर गौर करना चाहिए और उन्हें जन औषधालयों (जेनेरिक दवा स्टोर) के जरिए आम आदमी को उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने यह रेखांकित किया, 'इस तरह हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पारंपरिक दवा सभी व्यक्तियों, खासकर ऐसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं मिलने के कारण इन्हें खरीदने में रुचि नहीं रखते हैं।' प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस बात का उल्लेख किया कि देश की प्रगति के माप के तौर पर जीडीपी के विकल्प के रूप में वेलनेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि स्वास्थ्य, स्वभाव और जीवन की गुणवत्ता खास मायने रखती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परंपरागत दवाओं का निर्यात एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी उपायों के संदर्भ में वैश्विक मानकों को स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने मानकों, बोद्धिक संपदा और पारंपरिक दवाओं की व्यापक स्वीकार्यता के बारे में भी बात की।

इस अवसर पर आरआईएस के प्रकाशन *'स्वास्थ्य, स्वभाव और जीवन की गुणवत्ताः ब्रिक्स वेलनेस इंडेक्स की ओर'* का भी विमोचन किया गया। इस संबंध में दो मौलिक, लेकिन आपस में संबंधित प्रश्नों पर इसमें विचार किया गया। इसमें सबसे पहले तो ब्रिक्स में वेलनेस के पारंपरिक ज्ञान, अवधारणा और दर्शन से जुड़े ब्यौरे का अवलोकन किया गया है। इसमें इस तरह की प्रणालियों की समकालीन प्रासंगिकता को फिर से परिभाषित करने और अधिक प्रभावशीलता एवं विकास की रणनीति के रूप में अपनाने के लिए उन्हें आधुनिक आर्थिक प्रक्रियाओं से जोड़ने के भी प्रयास किए गए हैं। दूसरे, इस खंड में न केवल नीतिगत मार्गदर्शन करने, बल्कि नागरिकों के स्तर पर विकास के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण हेतु नई गति प्राप्त करने के लिए भी ब्रिक्स में वेलनेस के माप के लिए एक नई रूपरेखा का प्रस्ताव किया गया है।

'ब्रिक्स देशों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर अनुभव साझा करने' पर प्रथम पूर्ण सत्र की अध्यक्षता श्री अजीत एम. शरण ने की थी। श्री अनिल कुमार गनेरीवाला ने आयुष मंत्रालय का एक अवलोकन पेश किया। डॉ. राजीव वासुदेवन, एमडी और सीईओ, आयुर्वेद हॉस्पिटल्स ने पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण के बारे में बताया। डॉ. आईजैक मथाई, चेयरमैन, प्रबंधकीय एवं चिकित्सा निदेशक, सौक्या ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वेलनेस सुविधाओं के बारे में बताया।

श्री एरिक गोंकालव्स शुल्ज, स्वास्थ्य संबंधी एकीकृत प्रथाओं के बचाव में संसदीय मोर्चा, ब्राजील, प्रो. सेसिलिया डी मेलो ई सूजा, साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट, फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरो, ब्राजील, श्री ओ. ओ. सलागाई, श्री झू हैडोंग, प्रो. जेम्स कैंपबेल और श्री मरक्वार्ड फ्रैंकलिन सिम्पसन, प्रबंधक, सामुदायिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान संकाय ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए अपने–अपने देशों के अनुभवों को साझा किया।

प्रो. पुलिन नायक, पूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली और प्रो. रसिगान महाराज, मुख्य निदेशक, नवाचार पर आर्थिक अनुसंधान संस्थान, त्शवेन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका ने 'ब्रिक्स के लिए वेलनेस संकेतकों' पर दूसरे पूर्ण सत्र की सह–अध्यक्षता की। डॉ. कृष्ण कुमार, उप महानिदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. अमांडा गकाबाशे, विशेषज्ञ पारंपरिक चिकित्सा, विशेष परियोजना बिजनेस यूनिट, दक्षिण अफ्रीकी मानक ब्यूरो, प्रिटोरिया, डॉ.सेसिलिया डी मेलो ई सूजा, श्री एरिक गोंकालव्स शुल्ज, डॉ. अनिता करिलियो अरकास, अध्यक्ष, आयुर्वेद रूस–भारत संघ, सदस्य, पारंपरिक चिकित्सा

परिषद, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य संरक्षण समिति, रूसी संघ के स्टेट ड्यूमा ने चर्चाओं में हिस्सा लिया।

प्रो. सुखदेव स्वामी हांडा, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के औषधि आयोग (पीसीआईएम एंड एच) के वैज्ञानिक निकाय, आयुष मंत्रालय ने 'व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, मूल्य वृर्द्धन, निर्माण एवं व्यापार, व्यापार वर्गीकरण और जैव–संसाधनों के नियमन व मानकीकरण' पर आयोजित तीसरे सत्र की अध्यक्षता की। प्रो.एस. के. मोहंती, आरआईएस, डॉ. आन्द्रे डे मेलो ई सूजा, इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (आईपीईए) और प्रो. रसिगान महाराज, दक्षिण अफ्रीका पैनल के सदस्य थे।

प्रो. भूषण पटवर्धन, स्वास्थ्य विज्ञान अंतःविषय विद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और श्री झू हैडोंग ने 'वेलनेस एवं एसडीजी ; पोषण व स्वास्थ्य , पहुंच और कार्यान्वयन पर चौथे सत्र की सह–अध्यक्षता की। डॉ. नंदिनी के. कुमार, पूर्व उप महानिदेशक, आईसीएमआर, डॉ. अमांडा गकाबाशेय और डॉ. अनिता करिलियो अरकास ने परिचर्चाओं में भाग लिया।

श्री नवीन राज सिंह, सचिव, पर्यटन, कर्नाटक सरकार और डॉ. आन्द्रे डी मेलो ई सूजा ने 'वेलनेस एंड चिकित्सा पर्यटन' पर आयोजित पांचवें सत्र की सह–अध्यक्षता की। डॉ. आईजैक मथाई, सौक्या, डॉ. सी.के. कटियार, सीईओ, इमामी कंपनी समूह, कोलकाता, श्री जोस डोमिनिक, एमडी एवं सीईओ, सीजीएच अर्थ, सीजीएच होटल समूह और श्री के. वी. रमेश, एमडी, कैराली आयुर्वेदिक समूह ने परिचर्चाओं में भाग लिया।

श्री जितेंद्र शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब ने 'पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ की रणनीति' विषय पर आयोजित छठे सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. झांग क्यूई, समन्वयक, पारंपरिक चिकित्सा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा ने डब्ल्यूएचओ की रणनीति का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। प्रो. जेम्स कैंपबेल, प्रो. हुओ जुनशेंग, निदेशक, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय पोषण एवं स्वास्थ्य संस्थान, चीनी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र, श्रीमती ओ.एम. ड्रापकिना, निवारक चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा कार्य पर प्रथम उप निदेशक, स्वास्थ्य मंत्रालय, रूसी संघ, प्रो. सुखदेव स्वामी हांडा, प्रो. रैसुर रहमान, सलाहकार, यूनानी, आयुष मंत्रालय , डॉ. मनोज नेसारी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, श्री अरविंद वर्चस्वी, ट्रस्टी, श्री श्री आयुर्वेद ट्रस्ट परिचर्चा थे।

दो दिवसीय कार्यशाला श्री अनिल कुमार गनेरीवाला की अध्यक्षता में समापन सत्र के साथ समाप्त हुई। डॉ. आन्द्रे डी मेलो ई सूजा, झू हैडोंग, श्री ओ. ओ. सलागाई और प्रो. जेम्स कैंपबेल ने भाषण दिए। प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

भारत–जापान आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए निर्यात के मार्ग की बाधाओं को दूर करने की जरूरत : निर्मला सीतारमण

आरआईएस में स्थापित एआईसी ने नई दिल्ली में 6 अक्टूबर 2016 में भारत–जापान सीईपीए के तहत भारत से जापान को निर्यात के संवर्धन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत सरकार की

माननीया वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा 'भारत–जापान सीईपीए: एक मूल्यांकन' के शीर्षक वाली आरआईएस–एआईसी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के उपाध्यक्ष डॉ. वी.एस. शेषाद्री ने इस रिपोर्ट के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों का व्यापक विवेचन किया गया है। भारत सरकार के विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर और जापानी दूतावास में राजदूत (असाधारण एवं पूर्णाधिकारी) महामहिम श्री केंजी हीरामत्सु ने भी विशेष भाषण दिए। संगोष्ठी के दौरान अनेक मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। भारत से जापान को होने वाले कपड़ा और परिधान निर्यात को मूल्य एवं मात्रा के लिहाज से बढ़ाना, भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना, वर्ष 2020 तक जेनेरिक के अधिकाधिक उपयोग की दिशा में जापान के फैसले से उत्पन्न होने वाले कारोबारी अवसर – भारतीय कंपनियां किस तरह से अनुकूल कदम उठा सकती हैं तथा तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में आईटी एवं इससे संबद्ध सेवाओं के व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देना किस प्रकार संभव है।

भारत सरकार की माननीया वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री निर्मला सीतारमण *भारत–जापान सीईपीए* पर आरआईएस–एआईसी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हुईं।

ब्रिक्स समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एजेंडे को व्यापक करेगा : शशि थरूर

भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और आरआईएस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 3–4 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम का आयोजन किया था। यह भारत की मेजबानी में उसकी अध्यक्षता के दौरान अक्टूबर 2016 में गोवा में आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन से पहले महत्वपूर्ण ट्रैक–2 श्रेणी का आयोजन था। माननीय सांसद एवं विदेश मामलों पर स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉ. शशि थरूर ने उद्घाटन भाषण दिया। आरआईएस के

महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर एवं भारतीय विकास सहयोग मंच की अध्यक्षा सुश्री अनुराधा चिनॉय ने स्वागत भाषण दिए।

ब्रिक्स देशों एवं सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो दिवसीय विचार–विमर्श में भाग लिया, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, मानव सुरक्षा, गरीबी, इत्यादि के मुख्य सामाजिक क्षेत्रों के साथ–साथ टिकाऊ विकास, शहरीकरण एवं वित्तीय मुद्दों पर भी सिविल सोसायटी और निर्णय लेने वालों के बीच एक रचनात्मक संवाद सुनिश्चित करना था।

डॉ. शशि थरूर ने फोरम का उद्घाटन करते हुए कहा, 'ब्रिक्स एक वैकल्पिक फोरम है जो दुनिया की नीतियों को नया स्वरूप प्रदान करने वाले प्रभावशाली समुदायों के सामने मजबूती से डटा हुआ है। तीन ट्रिलियन की आबादी वाले ब्रिक्स देश दुनिया की आबादी के लगभग 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 20 प्रतिशत योगदान देते हैं और अब ये प्रभुत्वशाली ताकतों के रूप में उभर रहे हैं। आज ब्रिक्स की अनदेखी दरअसल इतिहास में नजर आ रहे बदलावों की अनदेखी है।' उन्होंने वैश्विक एजेंडे और नई विश्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने में ब्रिक्स सिविल फोरम की विशेष अहमियत पर भी प्रकाश डाला। डॉ. थरूर ने यह भी कहा कि मौजूदा प्रणाली को या तो हमारे लिए गुंजाइश निकालनी चाहिए अथवा पतन के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिक्स में सिविल सोसायटी की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल सोसायटी अपने विचारों में सामंजस्य सुनिश्चित करके और इनके बारे में सरकार को सूचित करके शिखर सम्मेलन के एजेंडे को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ब्रिक्स देशों ने पहले ही 'नव विकास बैंक' को बाकायदा अस्तित्व में ला दिया है और अब भी उनके बीच ज्ञान केंद्र (हब) बनाने की सख्त जरूरत है क्योंकि यह भूमंडलीकृत, आपस में जुड़ी हुई एवं नेटवर्क के जरिए संचालित होने वाली दुनिया की अत्यंत जरूरी आवश्यकता है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) श्री अमर सिन्हा ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि विचार–विमर्श से सरकार के ज्ञान का संवर्धन होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह दलील दोहराई कि ब्रिक्स नए विचारों का एक फोरम है जो वैश्विक वृत्तांत को नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने बिम्सटेक देशों को आमंत्रित किया है और वह यह जानना चाहता है कि वे नए वैश्विक एजेंडे के संबंध में ब्रिक्स देशों से क्या उम्मीद रखते हैं।

आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ब्रिक्स देश सुपर पावर नहीं हैं, लेकिन वे विश्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। यही देश फैसला करेंगे कि नई संस्थागत व्यववस्था का स्वरूप क्या होगा और इस नई व्यवस्था के बारे में तब तक निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक कि सरकार के कदमों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का समर्थन हासिल न हो जाए। सरकार अवश्य ही बेहतर कर सकती है, बशर्ते कि यह सिविल सोसायटी के जरिए लोगों से संवाद करना शुरू कर दे।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में विशेष जोर देते हुए कहा कि ब्रिक्स पूर्व लगभग 100 आयोजनों में ब्रिक्स के सदस्य देशों की ओर से सर्वाधिक मौजूदगी सिविल फोरम में ही दर्ज की गई थी और यह सिविल सोसायटीज की भागीदारी की बदौलत ही संभव हो पाई थी। उन्होंने

माननीय सांसद एवं विदेश मामलों पर स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉ. शशि थरूर ब्रिक्स सिविल फोरम में उद्घाटन भाषण देते हुए।

कहा कि सिविल सोसायटी में ही सभी सक्रिय लोगों अथवा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की अनूठी क्षमता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में भारतीय विकास सहयोग मंच ही वह महत्वपूर्ण जरिया है जो विकास सहयोग की रूपरेखा के अंतर्गत विकसित हुआ है। यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए), शिक्षाविदों और सिविल सोसायटी संगठनों की एक त्रिपक्षीय पहल है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर एवं भारतीय विकास सहयोग मंच की अध्यक्ष अनुराधा चिनॉय ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स के बहुपक्षीय मॉडल में वैश्विक गवर्नेंस को बदलने की क्षमता है। ब्रिक्स, सिविल सोसायटी के लिए खुला है और सिविल सोसायटी वैश्विक शक्तियों की सर्वोच्चता को ध्वस्त करने, मानवीय सहायता, आपसी लाभ, बहु–ध्रुवीय प्रणाली, टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, समावेशी विकास, बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद के लिए ब्रिक्स को अपनी ओर से सक्रिय सहयोग देती है।

माननीय केविन रुड ने आरआईएस में एशिया–प्रशांत समुदाय पर अपने विचार पेश किए

एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एएसपीआई) ने एशिया सोसायटी इंडिया सेंटर और आरआईएस के सहयोग से नई दिल्ली में 6 अप्रैल 2016 को एशिया में क्षेत्रीय गवर्नेंस के भविष्य और एशिया प्रशांत समुदाय के एक निश्चित स्वरूप लेने की संभावनाओं के बारे में एक विशेष परिचर्चा आयोजित की। एएसपीआई के अध्यक्ष एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री केविन रुड ने एशिया–प्रशांत क्षेत्र में एक ऐसे अखिल (पैन)–क्षेत्रीय संस्थान की जरूरत पर चर्चा की जो शांति और सुरक्षा का बखूबी प्रबंधन कर सके। श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने इस परिचर्चा का संचालन किया। श्री शिवशंकर मेनन, भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुश्री प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, श्री मार्शल बाउटन और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने भी संबोधित किया।

भारत–म्यांमार सीमा व्यापार बढ़ाने के बारे में अध्ययन

वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया ने *'भारत–म्यांमार सीमा व्यापार बढ़ानाः नीतिगत और कार्यान्वयन उपाय'* पर आरआईएस का अध्ययन पेश किया। यह अध्ययन प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस द्वारा तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम आरआईएस द्वारा 15 जून 2016 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। उन्होनें बताया कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य सीमा मार्गों के जरिए भारत और म्यांमार के बीच व्यापार संभावनाओं का दोहन करते हुए भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को प्रोत्साहन देना है जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशेष जोर दिया है। इस अवसर पर वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया ने इस बात पर रोशनी डाली कि भूमि मार्गों के जरिए भारत और म्यांमार के बीच होने वाले सीमा व्यापार में व्यापक बदलाव देखा गया है क्योंकि वस्तु विनिमय का स्थान सामान्य व्यापार ने ले लिया है। यही नहीं, उन वस्तुओं की सूची भी समाप्त कर दी गई जो हाल ही तक प्रतिबंधित थीं। इसका प्रभावकारी रूप से मतलब यही है कि सीमा के जरिए भारत–म्यांमार व्यापार अब शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता (डीएफटीपी) योजना और आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीजीए) के तहत हो सकता है। उन्होंने रोजगार सृजन के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापार को एक साधन बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। सीमा के दोनों ही तरफ बुनियादी ढांचे में निवेश को व्यापार के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में चिन्हांकित किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री रवि कपूर ने इस अध्ययन के औचित्य एवं आगाज का उल्लेख करते हुए कहा कि म्यांमार के साथ भारत के सीमा व्यापार और द्विपक्षीय सामान्य व्यापार की एक विशिष्टाता यह है कि सीमा व्यापार के मामले में आयात और निर्यात दोनों की ही वृद्धि दरें वास्तव में समग्र द्विपक्षीय व्यापार की वृद्धि दर से अधिक हैं। उन्होंने म्यांमार के विकास के साथ–साथ आसियान और अन्य बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी म्यांमार के साथ एकीकरण की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इन बाजारों में पहुंच के लिए म्यांमार को वरीयता प्राप्त है। श्री कपूर ने यह भी उल्लेख किया कि यह अध्ययन व्यापक है, क्योंकि इसमें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, सीमा–पार निवेश, व्यापार सुविधा और भारत–म्यांमार सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमा व्यापार के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

सुश्री रीता तेवतिया 'भारत–म्यांमार सीमा व्यापार बढ़ाना : नीति और कार्यान्वयन उपाय' पर आरआईएस और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अध्ययन को पेश करती हुईं। साथ में हैं (बाएं से दाएं) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री रवि कपूर और प्रो.राम उपेंद्र दास।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्षेत्र सर्वेक्षण और हितधारकों से हुए सलाह–मशविरा के साथ डेस्कटॉप अनुसंधान का संयोजन करते हुए यह अध्ययन किया गया है, ताकि विश्लेषण को यथार्थवादी और सिफारिशों को व्यावहारिक बनाया जा सके। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम उन नीतिगत सिफारिशों को लागू करने के लिए एक 'फास्ट–ट्रैक' दृष्टिकोण अपनाएं जो विशेष रूप से सीमा व्यापार और सामान्य रूप से इस क्षेत्र के विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर कर सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन में भारत–म्यांमार सीमा व्यापार बढ़ाने के लिए विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक या अनुभवजन्य आधार प्रस्तुत किया गया है। प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस ने यह दलील दी कि विचाराधीन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के साथ–साथ सीमा व्यौपार के भी अपेक्षा से कम रहने का एक प्रमुख कारण यह है कि इस क्षेत्र में शांति का अभाव है। इस अध्ययन में बड़े ही अनूठे तरीके से 'शांति के जरिए समृद्धि' की एक नई रूपरेखा अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है जिसके तहत इस क्षेत्र में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और फिर इसके जरिए इस क्षेत्र में निहित क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। अतः इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यदि सीमा व्यापार बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बना दिया जाए तो इस क्षेत्र के साथ–साथ सीमा पर भी आर्थिक गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ सकती हैं, युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करने को एक वास्तविक संभावना में तब्दील किया जा सकता है और इसके जरिए युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेने से रोका जा सकता है। सीमा व्यापार बढ़ाने का एक अच्छा तरीका यह है कि 'सीमा हाटों' की स्थापना की जाए जो स्थानीय व्यापार में सहायक साबित होने के साथ–साथ जन संपर्क बढ़ाने और दोनों देशों की सीमाओं के पार दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। सीमा पर अवस्थित स्थानीय बाजारों में स्थानीय उपज के विपणन की परंपरागत प्रणाली स्थापित करके यह कार्य बखूबी पूरा किया जाता है। सीमा के पास रहने वाले समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने सीमा हाट स्थापित करने का निर्णय लिया। वर्तमान में, अधिकारियों ने ऐसे 10 स्थानों पर सहमति जताई है जिन्हें सीमा हाट के रूप में स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर सीमा व्यापार, जिसे बंधन मुक्त तरीके से 'सामान्य व्यापार' के रूप में संपन्न किया जा सकता है, बढ़ाने के लिए सीमा पर प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं, मालगोदाम एवं भंडारण सुविधाओं, उदगम प्रमाण पत्र संबंधी सुविधाओं, एकीकृत चेक पोस्टों एवं सीमा हाटों की स्थापना, व्यापार संवर्धन गतिविधियों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझी जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं को बेहतर करने और सूचना उपलब्धता की खाई पाटने की दिशा में काफी तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना भी अत्यंत आवश्यक है।

आरआईएस में इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का आगमन

वरिष्ठ विश्लेषक श्री पी. गुल्तोम की अगुवाई में इंडोनेशियाई गणराज्य के विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर नीतिगत विश्लेषण एवं विकास केंद्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 मई 2016 को दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर आरआईएस के साथ एक बैठक की थी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में ये शामिल थे : श्री नोवरिजल,

परामर्शदाता, इंडोनेशियाई दूतावास, श्री फैज अहमद नुग्रोहो, विदेश मंत्रालय, इंडोनेशिया गणराज्य, श्री अकबर नुग्राहा, तृतीय सचिव, इंडोनेशियाई दूतावास और सुश्री एग्नेस रोजारी डेवी, नीति विश्लेषक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर नीतिगत विश्लेषण एवं विकास केंद्र।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर संवाद

आरआईएस ने द एशिया फाउंडेशन, साउथ सेंटर और भारत सरकार के सहयोग से 'विकास के अधिकार' की 30वीं वर्षगांठ और *'इंडियाज एप्रोच टू डेवलपमेंट कोऑपरेशन'* नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर 27 जून 2016 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। इस पुस्तक का संपादन प्रो. सचिन चतुर्वेदी और सुश्री एंथिया मुलाकाला ने किया। श्री विसेंट यू, प्रशासन प्रमुख एवं समन्वयक, ग्लोबल गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, साउथ सेंटर ने स्वागत भाषण दिया। श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और माननीय श्री अजीत कुमार, राजदूत असाधारण एवं पूर्णाधिकारी, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत का स्थायी मिशन ने आरंभिक भाषण दिए। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, डॉ. रिचर्ड कोजुलराइट, वैश्वीकरण एवं रणनीति प्रभाग के निदेशक, अंकटाड, सुश्री अनिता अमोरीम, उभरती एवं विशेष साझेदारी इकाई की प्रमुख, आईएलओ, डॉ. प्रबोध सक्सेना, हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव एवं पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, एडीबी, श्री झोऊ ताईडोंग, कार्यक्रम प्रबंधक, चीन–ब्रिटेन भागीदारी कार्यक्रम, विकास अनुसंधान केंद्र और डॉ. यूबा सोकोना, सतत विकास पर विशेष सलाहकार, साउथ सेंटर एवं आईपीसीसी पैनल के उपाध्यक्ष परिचर्चा थे। सत्र का संचालन श्रीमती एंथिया मुलाकाला, अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम के निदेशक, द एशिया फाउंडेशन ने किया। 'इंडियाज एप्रोच टू डेवलपमेंट कोऑपरेशन' पुस्तक में भारतीय विकास सहयोग के क्रमागत विस्तार का अवलोकन और विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में वैश्विक विकास और भारतीय विदेश नीति के प्रभावी साधन दोनों के ही रूप में इसके विशिष्ट महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तिक में इस बात पर फोकस किया गया है कि भारत ने किस तरह से विकास

श्री श्याम सरन दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर आयोजित संवाद में बोलते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) माननीय श्री अजीत कुमार, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, सुश्री एंथिया मुलाकाला और श्री विसेंट यू। माननीय श्री नवतेज सिंह सरना भारत के उच्चायोग में 'इंडियाज एप्रोच टू डेवलपमेंट कोऑपरेशन' नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) श्री ताइदोंग झो, डॉ. प्रबोध सक्सेना, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, सुश्री एंथिया मुलाकाला, श्री श्याम सरन, डॉ. एम्मा माउस्ले और सुश्री सुप्रिया रॉयचौधरी।

सहयोग के क्षेत्र में अपनी विभिन्न पहलों के जरिए दक्षिण एशिया के साथ–साथ और उससे परे भी साझेदार देशों के विकास प्रयासों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुस्तक में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारत के विकास, रुझान और उसके समक्ष मौजूद चुनौतियों पर रोशनी डाली गई है। संबंधित योगदान से शैक्षणिक और सरकारी नीति एवं कार्यप्रणाली, भारतीय एवं बाह्य दृष्टिकोणों के बारे में व्यापक जानकारी मिली है। इसमें दिया गया सिद्धांत वास्तुव में अनुभवजन्य शोध और विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों पर किए गए मामला अध्ययन (केस स्टेडी) से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, सहायता प्रदान करने वाले अन्य देशों के साथ तुलना भी की गई है। परिचर्चा के दौरान एक अपरिहार्य और स्वतंत्र मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की भूमिका और मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया क्योंकि इसके जरिए सभी मानवाधिकारों को पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है और सभी लोग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अधिकारों का आनंद उठा सकते हैं। परिचर्चा के दौरान दक्षिण–दक्षिण सहयोग से जुड़े भारतीय अनुभव पर फोकस करते हुए विकासशील देशों में विकास के अधिकार को आगे बढ़ाने में दक्षिण–दक्षिण सहयोग द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी रेखांकित किया गया।

इस पुस्तक का विमोचन 29 जून 2016 को ब्रिटेन स्थित विकास अध्ययन संस्थान (आईडीएस) में भी किया गया। सत्र की अध्यक्षता डॉ. जिंग ग्यूथ, द सेंटर फॉर राइजिंग पावर्स एंड ग्लोबल डेवलपमेंट (सीआरपीडी), आईडीएस ने की। श्री श्याम सरन ने आरंभिक भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, सुश्री एंथिया मुलाकाला, डॉ. एम्मा माउस्ले, भूगोल विभाग में रीडर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, श्री प्रबोध सक्सेना, हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव, श्री ताइदोंग झोऊ, कार्यक्रम प्रबंधक, चीन–ब्रिटेन भागीदारी कार्यक्रम, विकास अनुसंधान केंद्र, सुश्री सुप्रिया रॉयचौधरी, क्राइसिस एक्शन इस अवसर पर वक्ता थे। इस परिचर्चा ने पुस्तक में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर एक झलक प्रदान की। इस कार्यक्रम का आयोजन आरआईएस द्वारा द सेंटर फॉर राइजिंग पावर्स एंड ग्लोबल डेवलपमेंट (सीआरपीडी), आईडीएस के सहयोग से किया गया। लंदन स्थित भारत के उच्चायोग ने भी 30 जून 2016 को पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित किया। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त माननीय श्री नवतेज सिंह सरना ने स्वागत भाषण दिया। श्री श्याम सरन ने स्वागत भाषण दिया और पुस्तक का संदर्भ निर्धारित किया। पुस्तक में उठाए गए मुद्दों पर आयोजित पैनल परिचर्चा का संचालन सुश्री एंथिया मुलाकाला ने किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. एम्मा माउस्ले, डॉ. प्रबोध सक्सेना, श्री ताइदोंग झो और सुश्री सुप्रिया रॉयचौधरी परिचर्चा थे।

बोद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी तक पहुंच पर परिचर्चा

बोद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी तक पहुंच पर हाल ही में छिड़ी बहस के मद्देनजर आरआईएस ने नई दिल्ली में 4 जून 2016 को 'बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर), प्रौद्योगिकी तक पहुंच और नीतिगत विचार–विमर्श' पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने मुख्य भाषण दिया जिसमें उन्होंने बोद्धिक संपदा संबंधी मुद्दों और विशेषकर बीजों से संबंधित मूल्य नियंत्रण व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री एम. प्रभाकर राव, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ और डॉ. परेश वर्मा, प्रमुख, प्रबंधन समिति, जैव प्रौद्योगिकी की अगुवाई

वाले उद्यमों के संघ – कृषि (एबीएलई एजी) ने उद्योग का नजरिया पेश किया। इन दोनों ही विशेषज्ञों ने कृषि और बीज क्षेत्र के मुद्दों से संबंधित विचार प्रस्तुत किए। परिचर्चा में प्रमुख भागीदारी थे : श्री सिराज हुसैन, पूर्व कृषि सचिव, डॉ. अशोक गुलाटी, इन्फोसिस के चेयर प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर), डॉ. जीत सिंह संधू, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), डॉ. एस.आर. राव, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डॉ. आर. आर. हंचिलाल, अध्यक्ष, पौध किस्म संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण, डॉ. दिनेश एब्रोल, प्रोफेसर, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) और प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस, जिन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि व्यक्त की।

उद्योग के प्रतिनिधियों ने अपेक्षित एवं पारदर्शी नियामकीय प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया और इसके साथ ही प्रतिगामी विनियमन के प्रति आगाह किया क्योंकि इस वजह से विकास और नवाचार मंद पड़ जाएंगे। पौध किस्मों एवं बीजों के संबंध में भारतीय पेटेंट अधिनियम और पौध विविधता संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम की उपयुक्तता को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि पौध किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) में पराजीनी (ट्रांसजेनिक) किस्मों को कवर किया गया है। हालांकि, इसके साथ ही प्रजनक एवं किसान अधिकार अधिनियम के तहत दी जा रही रियायतों के दायरे को लेकर चिंता जताई गई क्योंकि उनके चलते आईपी संरक्षण कमजोर हो जाता है। 'उचित, तर्कसंगत और भेदभाव रहित पहुंच (एफआरएएनडी)' की प्रासंगिकता का सुझाव दिया गया था। लाइसेंसिंग, जिसका दूरसंचार उद्योग में व्यापक उपयोग किया जाता है, का बीज क्षेत्र में परीक्षण किया जा सकता है। इस दौरान उन छोटी और मझोली बीज कंपनियों की लाभप्रदता को लेकर चिंता व्यक्त की गई जो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही हैं। उद्योग ने संबंधित लक्षण वाले बीजों के लिए लाइसेंसिंग के नियम–शर्तों पर कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हालिया दिशा–निर्देशों (उसके बाद से ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है) पर गंभीर चिंता जताई है। जीएम फसलों के परीक्षण एवं अनुमोदन में लगने वाले समय और लागत पर भी प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही यह बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र भी कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूण

डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया मुख्य भाषण देते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) डॉ. दिनेश एब्रोल, डॉ. एस.आर. राव, श्री सिराज हुसैन, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री एम. प्रभाकर राव, डॉ. परेश वर्मा, डॉ. आर. आर. हंचिलाल और प्रो. टी.सी. जेम्स।

ा खिलाड़ी है। यह सुझाव दिया गया था कि नियमों एवं विनियमों और मूल्य निर्धारण से जुड़े मुद्दों में निहित विसंगतियां दूर की जा सकती हैं। यह भी बताया गया कि नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता प्रौद्योगिकी के संवर्धन और विनियमन से संबंधित विभागों के लिए प्राथमिक चिंता का विषय है। मूल्य निर्धारण के मुद्दे को पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सुलझाया गया था, लेकिन हालिया विवादों को देखते हुए इसे नवाचार को हतोत्साहित किए बिना ही फिर से सुलझाया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि दो लक्षणों जैसे कि शाकनाशी प्रतिरोधी तकनीक एवं कीट प्रतिरोधी तकनीक तथा उनका संयोजन सफल रहा है और कपास, सोयाबीन, कैनोला एवं मक्का में इनका वाणिज्यीकरण किया गया है जो विश्व भर में प्रमुख जीएम फसलें हैं। इस दौरान जीएम प्रौद्योगिकियों के जोखिम आकलन और आर्थिक मूल्यांकन से जुड़ी मौजूदा प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों को भी स्पष्ट किया गया था। इसके अलावा, जीईएसी से मंजूरी का इंतजार कर रही जीएम फसलों के लिए निर्णय लेने में अनिश्चितताएं समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। पीपीवीएफआर और अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण को नई किस्मों के लिए पंजीकरण के नियमन और पौधों के प्रजनकों, बीज कंपनियों एवं किसानों के हितों में संतुलन बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कपास के बीज की रॉयल्टी और बिक्री मूल्य की सीमा तय करने के लिए इस साल के आरंभ में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश की आलोचना की। उनका यह मानना था कि 'यदि बीज की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं हैं, तो इसकी कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए पौध किस्म अधिनियम के तहत कई कानून हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।' विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

सतत विकास के लिए औद्योगीकरण और रोजगार

आरआईएस ने नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से 2–3 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में 'भारत में सतत विकास के लिए औद्योगीकरण और रोजगार' पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया, जो एसडीजी 8 और 9 से संबंधित है। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और श्री यूरी अफानसीव, संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक, भारत ने अपने स्वागत भाषण में क्रमश; आरआईएस की पहलों और वैश्विक संदर्भ पर प्रकाश डाला। प्रो. अरविंद पनगरिया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने समापन भाषण दिया। उन्होंने यह बात रेखांकित की कि एसडीजी तय करने में भारत का व्यापक प्रभाव था। उन्होंने विशेष जोर देते कहा कि नीति आयोग के अपने हालिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ–साफ शब्दों में यह उल्लेख किया था कि हमारे विजन दस्तावेज में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इस संदर्भ में एसडीजी 8 और 9 मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि कई राष्ट्रीय उद्देश्यों को इनमें कवर किया गया है जो राष्ट्रीय उद्देश्यों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित सुपर–राष्ट्रीय उद्देश्यों के बीच उत्पन्न होने वाले टकराव से हमें बचाते हैं। उन्होंने इस पर भी विशेष जोर दिया कि गरीबी उन्मूलन सरकार का प्रमुख उद्देश्य है और स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास इत्यादि जैसे अन्य सभी उद्देश्यों को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब गरीबी उन्मूलन की समस्या से निजात मिल जाएगी। अच्छी आमदनी वाले लोगों के पास सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए कहीं अधिक क्षमता होती है। श्री अमिताभ कांत,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग ने मुख्य भाषण दिया और कहा कि हमारे पास एक विशाल कार्यबल है जो एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसकी संभावनाओं का पता लगाने एवं अधिकतम उपयोग करने के साथ–साथ इसे 'कौशल भारत' पहल से जोड़ने की जरूरत है।

श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने अध्यक्षीय भाषण दिया और विनिर्माण एवं एसडीजी के संदर्भ में रोजगार सृजन की अनिवार्यताओं पर रोशनी डाली। डॉ. पी. के. आनंद, वरिष्ठ सलाहकार (डीएमईओ), नीति आयोग ने परामर्श की संरचना प्रस्तुत की।

श्री यूरी अफानसीव ने 'सतत विकास और औद्योगीकरण के प्रतिमान' विषय पर पहले सत्र की अध्यक्षता की। श्री देवेंद्र सिंह, सचिव (उद्योग), हरियाणा सरकार, श्रीमती रश्मि सिंह, सचिव (उद्योग), अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, डॉ. नागेश कुमार, प्रमुख, यूएनएस्कैप (एसएंडएसडब्ल्यूए), नई दिल्ली, डॉ. अजय माथुर, महानिदेशक, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी), प्रो. पुलिन बी. नायक, पूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और श्री पी.के. बिस्वाल, अपर सचिव (योजना एवं अभिसरण), ओडिशा सरकार पैनल के सदस्य थे।

सत्र के दौरान अनेक प्रमुख मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया जिनमें मेक इन इंडिया और एसडीजी के संदर्भ में आर्थिक विकास के लिए सतत औद्योगीकरण में तेजी लाना, औद्योगिक उत्पादन में संसाधन दक्षता एवं हरित प्रौद्योगिकियां, 'कारोबार करने में आसानी' सुनिश्चित करना एवं राज्य स्तरीय नियामकीय बाधाओं को दूर करना और ठीक इसी संदर्भ में क्षेत्रवार प्राथमिकताएं एवं सर्वोत्तम प्रथाएं शामिल हैं।

प्रो. रमेश चन्द, सदस्य, नीति आयोग ने 'सतत आर्थिक विकास के लिए बेहतर समावेश की रणनीतियां' विषय पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। प्रो. बीना अग्रवाल, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय एवं आर्थिक विकास संस्थान, सुश्री रेणु पिल्लै, प्रधान सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, श्री दीपक कपूर, प्रधान सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता, महाराष्ट्र सरकार, प्रो. पी. जी. चेंगप्पा, राष्ट्रीय प्रोफेसर, आईसीएआर, बेंगलुरू और डॉ. जी. जी. कोप्पा, सहायक एफएओ प्रतिनिधि (कार्यक्रम) पैनल के सदस्य थे। प्रतिभागियों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जिनमें कृषि आय, उत्पादकता एवं नियमन के मसले, कौशल विकास के जरिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों का विविधीकरण (महिला श्रम बल की भागीदारी पर विशेष ध्यान), आजीविका संरक्षण के लिए तकनीकी उन्नयन, स्थायित्व से जुड़ी चुनौतियों

प्रो. अरविंद पनगरिया समापन सत्र को संबोधित करते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री श्याम सरन, प्रो. टी.सी.ए. अनंत और श्री यूरी अफानसीव।

को पहचानना और बिल्कुल ठीक इसी संदर्भ में क्षेत्रवार प्राथमिकताएं और सर्वोत्तम प्रथाएं शामिल हैं।

डॉ. शेर वेरिक, उप निदेशक (शालीन कार्य), आईएलओ, दक्षिण एशिया ने 'रोजगार सृजन और शालीन कार्य' पर आयोजित तीसरे सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र के परिचर्चा ये थे ; श्रीमती सुनीता सांघी, सलाहकार, नीति आयोग, श्रीमती काव्याश्री महंता, संयुक्त सचिव (श्रम और रोजगार), असम सरकार, श्री एस. के. जी. रहाते, प्रधान सचिव (श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास), झारखंड सरकार, श्री नोमैन माजिद, वरिष्ठ विशेषज्ञ (रोजगार नीति), आईएलओ, प्रो. संदीप सरकार, मानव विकास संस्थान, प्रो. सैकत सिन्हा रॉय, जादवपुर विश्वविद्यालय और श्री सुशील रामोला, प्रबंध निदेशक, आजीवन रोजगार योग्य बनाने के लिए बेसिक्स अकादमी। उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस करते हुए सभी के लिए अवसरों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने महिला–पुरुष समानता से जुड़े मसलों को मुख्यधारा में लाने, शारीरिक विकलांगता, अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम कानूनों एवं रोजगार की गुणवत्ता और ठीक इसी संदर्भ में सर्वोत्तम प्रथाओं एवं क्षेत्रीय विशिष्टताओं पर भी चर्चाएं कीं।

डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग ने 'लघु एवं मझोले उद्यमों और अनौपचारिक क्षेत्र' पर आयोजित चौथे सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र के लिए परिचर्चा ये थे ; प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस, श्री प्रणव कुमार, प्रमुख, व्यापार नीति, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), श्री मुकेश गुलाटी, कार्यकारी निदेशक, एमएसएमई क्लस्टरों के लिए फाउंडेशन और प्रो. बी. एन. गोल्डार, प्रोफेसर एवं आईसीएसएसआर के नेशनल फेलो, आर्थिक विकास संस्थान और श्री सुब्रत कुमार बिस्वाल, योजना विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार। सत्र के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों में ये शामिल थे ; एसएमई क्षेत्र के लिए एक हरित रणनीति तैयार करना – स्थायित्व मानदंडों के तहत वित्त तक पहुंच, एसएमई क्षेत्र में कारोबार करने में आसानी – अस्तित्व के लिए मंजूरी एवं सहायता, एसएमई के संदर्भ में वैश्विक वैल्यू चेन की चुनौतियां एवं अवसर और बिल्कुल ठीक इसी संदर्भ में सर्वोत्तम प्रथाएं और जानकारी की कमी।

सभी के लिए जल और स्वच्छता का सतत प्रबंधन

आरआईएस ने नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से 9 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में 'एसडीजी 6' की पृष्ठभूमि में 'सभी के लिए जल और स्वच्छता के सतत प्रबंधन' पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और श्री यूरी अफानसीव, संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक, भारत ने आरंभिक भाषण दिया। श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि जल प्रबंधन एक व्यापक विषय है जिसे समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है। जल से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए नई तकनीक के अलावा जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों पर गौर करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। परंपरागत तरीकों को मुख्यधारा में लाने और समुदायों को इस मुहिम में शामिल करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, श्री परमेश्वरन ने कहा कि जब तक स्वच्छता सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी तब तक स्वच्छ पेयजल सभी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। मल प्रमुख जल संदूषित पदार्थ है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की भी

चर्चा की, जो सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि 'एसडीजी 6' की प्राप्ति भारत के लिए खास मायने रखती है क्योंकि भारत में लगभग 500–600 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं और अगर यह संख्या कम नहीं हुई, तो एसडीजी 6 विश्व स्तर पर विफल साबित होगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया, 'भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) करने का लक्ष्य रखा गया है जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी।'

डॉ. पी. के. आनंद, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग ने राष्ट्रीय परामर्श के दौरान कहा कि पेयजल वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए मूल्य को तर्कसंगत बनाने की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। श्री यूरी अफानसीव, संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक, भारत ने अपने स्वागत भाषण में कहा, 'खाद्य पदार्थ, ईंधन और जल ऐसे तीन अहम तत्व हैं जो हमारे अस्तित्व एवं सुरक्षा को परिभाषित करते हैं। आबादी बढ़ रही है और हम अपने संसाधनों का व्यापक उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जल प्रबंधन एवं रीसाइक्लिंग में हम पीछे हैं। विश्व भर में दो मिलियन टन से भी अधिक मानव कचरे को जल संसाधनों में डंप कर दिया जाता है। जल पर टकराव और प्रतिस्पर्धा की स्थिति देखी जा रही है।' भारत द्वारा एमडीजी लक्ष्य हासिल कर लिए जाने की बात का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एसडीजी लक्ष्य कहीं अधिक महत्वाकांक्षी हैं, अत; एसडीजी की प्राप्ति के लिए बड़े कदमों अर्थात नीतियों और छोटे कदमों अर्थात लोगों की भागीदारी के बीच संयोजन की आवश्यकता है। उन्होंने यह बात भी रेखांकित की, 'भारत आभासी पानी का एक शुद्ध निर्यातक है और अमेरिका, कनाडा एवं अर्जेंटीना के क्लब में शामिल है। अत; नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है।'

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने इस बात पर प्रकाश डाला ; 'जल एक बड़ी चुनौती है, अत; यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने राष्ट्रीय एजेंडे को कैसे विकसित करते हैं। तकनीकी समाधान ढूंढ़ने की जरूरत है क्योंकि एसडीजी के बीच क्षेत्र–पार (क्रॉस–डोमेन) के साथ–साथ सीमा पार दोनों ही तरह के संबंध हैं जिसके लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके तहत इस बात को लेकर क्षेत्रवार चिंताएं भी हैं कि हम कृषि, उद्योग एवं ऊर्जा उत्पादन के साथ–साथ लोगों को आपूर्ति करने के लिए पानी का उपयोग कैसे करते हैं।' उन्होंने जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों से सीखने पर भी विशेष जोर दिया।

डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग ने 'पेयजल के संदूषण और तकनीकी समाधान' पर राष्ट्रीय परामर्श के पहले सत्र की अध्यक्षता की। अपने भाषण में उन्होंने

श्री परमेश्वरन अय्यर परामर्श में मुख्य भाषण देते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री यूरी अफानसीव, और डॉ. पी.के. आनंद।

इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि भारत में पानी की मांग वर्ष 2050 तक बढ़कर लगभग 1200 अरब घन मीटर के स्तर पर पहुंच जाएगी। यह तय है कि भारत को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अत; इस दिशा में समुचित नियोजन, प्रबंधन और तकनीकी उपयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम समस्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं या नहीं, इस दिशा में आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। श्री एन. सी. सक्सेना, सलाहकार, यूएनडीपी, श्री अजय कुमार सिन्हा, सचिव (जल आपूर्ति और स्वच्छता), पंजाब सरकार, श्री अनिमेष भट्टाचार्य, निदेशक, जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन, पश्चिम बंगाल सरकार, डॉ. ममता डैश, प्रबंधक, वाटर एड, श्री अमितांगशु आचार्य, विकास प्रोफेशनल एवं स्तंभकार और श्री मनीष वासुजा, यूनिसेफ इंडिया परिचर्चा थे।

डॉ. बिंदेश्वर पाठक, संस्थापक, सुलभ स्वच्छता एवं सामाजिक सुधार आंदोलन ने 'स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सर्वोत्तम प्रथाओं' पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने समृद्ध अनुभवों को साझा किया और कहा कि सुलभ आंदोलन महात्मा गांधी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया ; 'हम स्वच्छ भारत पर जागरूकता फैलाने के लिए राजनेताओं, निगमों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सिविल सोसायटीज का व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसे जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जा सके और इसके साथ ही ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) भारत बनाने के सपने को वास्तविकता में बदला जा सके। डॉ. अशोक कुमार जैन, सलाहकार (आरडी), नीति आयोग, श्री फ्रैंक ओढिअम्बो, यूनिसेफ इंडिया, डॉ. एम. गीता, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, छत्तीसगढ़ सरकार और श्री जय प्रकाश द्विवेदी, मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश सरकार परिचर्चा थे।

श्री श्याम बहादुर खादका, एफएओ प्रतिनिधि, भारत ने 'कृषि और उद्योग के लिए जल के दक्ष उपयोग' पर तीसरे सत्र की अध्यक्षता की। पैनल के सदस्यभ ये थे ; श्री जितेन्द्र कुमार, सलाहकार, नीति आयोग, श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, श्री आर. एस. जुलानिया, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार और डॉ. उपेंद्र कुलकर्णी, अध्यक्ष, इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, औरंगाबाद।

डॉ. पी.के. आनंद ने 'जल की पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण' पर आयोजित चौथे सत्र की अध्यक्षता की। श्री राकेश सिंह, प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, प्रो. ए.एल. रामनाथन, पर्यावरण विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय , श्री जी. पद्मनाभन, आपातकालीन विश्लेषक, यूएनडीपी भारत, श्री जितेन्द्र कुमार, सलाहकार, नीति आयोग और श्री धीमंत व्यास, तकनीकी सलाहकार (जल आपूर्ति), गुजरात सरकार परिचर्चा थे। श्री यूरी अफानसीव और डॉ. पी.के. आनंद के समापन भाषणों के साथ परामर्श समाप्त हुआ।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग

आरआईएस में स्थापित एआईसी, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ) और नेवल वार कॉलेज (एनडब्ल्यूसी) के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में भाग लेने वाले देशों के लिए 4–5 नवंबर, 2016 को गोवा में 'समुद्री सुरक्षा और सहयोग' पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ईएएस सम्मेलन का आयोजन किया। सभी ईएएस देशों ने सम्मेलन के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) सुश्री प्रीति सरन ने मुख्य भाषण दिया। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने आरंभिक भाषण दिया। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के निदेशक डॉ. विजय सखूजा ने विशेष भाषण दिया। नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल) सुश्री पूजा कपूर ने उद्‌घाटन भाषण दिया। आरआईएस में स्थापित एआईसी के प्रोफेसर/समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने स्वागत भाषण दिया। गोवा स्थित एनडब्ल्यूसी में कमांडेंट रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, एनएम, ने विशेष भाषण दिया।

समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग और समुद्री बहुपक्षवाद पर गहराई से बहस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्मेलन को इन पांच सत्रों में विभाजित किया गयाः एशिया–प्रशांत में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे, एशिया–प्रशांत में समुद्री संरक्षा के मुद्दे, समुद्री बहुपक्षवादः एशिया– प्रशांत के लिए अवसर, चुनौतियां और संभावनाएं, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संरक्षण, आगे की राह। इन सभी विषयों पर सम्मेलन में चर्चाएं और विश्लेषण किया गया और फिर उन विभिन्न अंशों को आपस में जोड़ा गया जो समुद्री क्षेत्र के लिए ईएएस में भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। एनएमएफ के निदेशक डॉ. विजय सखूजा ने समापन सत्र को संबोधित किया। एनडब्ल्यूसी में डिप्टी कमांडेंट कमोडोर अशोक राय और डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

ग्रुप फोटो : 'समुद्री सुरक्षा और सहयोग' पर दूसरे ईएएस सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस, सुश्री प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), सुश्री पूजा कपूर, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, रियर एडमिरल सुरेश मेहता।

आपदा जोखिम प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग पर सम्मेलन

आरआईएस में स्थापित एआईसी, गृह मंत्रालय (एमएचए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भूकंप जोखिम न्यूनीकरण केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में भाग लेने वाले देशों के लिए 2 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में 'आपदा जोखिम प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग पर ईएएस सम्मेलन' का आयोजन किया। सभी ईएएस देशों ने सम्मेलन के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने इस एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) में माननीय राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने उद्‌घाटन भाषण दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) सुश्री प्रीति सरन ने मुख्य भाषण दिया। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने आरंभिक भाषण दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक प्रो. संतोष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

ग्रुप फोटो : आपदा जोखिम प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग पर ईएएस सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ श्री किरेन रिजिजू, माननीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, सुश्री प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और क्षेत्रीय सहयोग पर गहराई से बहस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्मेलन को दो सत्रों में विभाजित किया गया था: (1) आपदा जोखिम न्यूनीकरण, टिकाऊ विकास लक्ष्य एवं क्षेत्रीय सहयोग और (2) आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग। सम्मेलन में चर्चाएं की गईं, विश्लेषण किया गया और फिर उन विभिन्न अंशों (कंपोनेंट) को आपस में जोड़ा गया जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुद्दों पर ईएएस में भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। आरआईएस में स्थापित एआईसी के प्रोफेसर/समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

कार्यसुचि 2030 पर सत्र: यूरोप और भारत में कार्यान्वयन

यूरोपीय आयोग के मुख्यालय ब्रुसेल्स से आए यूरोपीय संघ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 'एजेंडा 2030: यूरोप और भारत में कार्यान्वयन' विषय पर एक परस्पर संवादात्मक सत्र 9 दिसंबर, 2016 को आरआईएस द्वारा आयोजित किया गया था। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में श्री गुस्तावो मार्टिन प्रादा, निदेशक, विकास नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, श्री पेड्रो हेनरिक्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध अधिकारी, नीति और सामंजस्य (विकास), श्री माइकल जॉन एलिस, महानिदेशालय, नीति अधिकारी, नीति और सामंजस्य (विकास) और डॉ. जोहान हेस्से, काउंसलर, भारत के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के सहयोग प्रमुख के साथ–साथ भारत के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल की वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रेणुका श्रीनिवासन भी शामिल थीं। आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, प्रो. एस. के. मोहंती, प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, डॉ. टी.पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर ने परस्पर संवादात्मक सत्र में भाग लिया।

दक्षिण एशिया में टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

आरआईएस ने नीतिगत अध्ययनों के लिए दक्षिण एशिया केंद्र (एसएसीईपीएस) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 5 दिसंबर, 2016 को 'दक्षिण एशिया में टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन' पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में दक्षिण एशिया के संदर्भ में वृहद आर्थिक प्रदर्शन के उभरते रूझान, आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण, और बाह्य संबंध एवं टिकाऊ आर्थिक विकास से संबंधित आसन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। यह एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आई, जिस पर दक्षिण एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञों और नीति संबंधी शोधकर्ताओं ने संभावित नीतिगत रूपरेखा पेश करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर खुलकर प्रेरक शैक्षणिक परिचर्चा की।

वृहद आर्थिक प्रदर्शन के उभरते रूझान, आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण, और बाह्य संबंध एवं टिकाऊ आर्थिक विकास पर चर्चाएं इसके एजेंडे में शामिल थीं। दक्षिण एशिया की ओर से जिन प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया: उनमें शामिल थे प्रो. दीपक नैय्यर, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, डॉ. मुस्तफिजुर रहमान, कार्यकारी निदेशक, नीतिगत वार्ता के लिए केंद्र, बांग्लादेश; डॉ. समन केलेगामा, कार्यकारी निदेशक, नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस), श्रीलंका, डॉ. वकार अहमद, उप कार्यकारी निदेशक, टिकाऊ विकास नीतिगत संस्थान (एसडीपीआई), पाकिस्तान (स्काइप कॉल के माध्यम से); डॉ. पॉश राज पांडेय, अध्यक्ष, व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया वॉच (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल; डॉ. खोंडाकार गुलाम मोआज्जेम, अतिरिक्त अनुसंधान निदेशक, नीतिगत संवाद के लिए केंद्र (सीपीडी), बांग्लादेश; डॉ. फ्रेडरिको गिल सैंडर, सीनियर कंट्री इकोनॉमिस्ट, विश्व बैंक; डॉ. दिल्ली राज खनाल, संस्थापक अध्यक्ष, नीतिगत अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईपीआरएडी), पूर्व सांसद, नेपाल सरकार; डॉ. नोमान मजीद, रोजगार नीति पर आईएलओ के वरिष्ठ विशेषज्ञ, भारत; डॉ. शेर सिंह वेरिक, उप निदेशक, दक्षिण एशिया के लिए आईएलओ डीडब्ल्यूटी और भारत के लिए कंट्री ऑफिस, श्री विश्वनाथन सुब्रमण्यन, नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस), श्रीलंका। आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, प्रो.एस.के.मोहंती और डॉ. सब्यसाची साहा ने इसमें भाग लिया।

चित्र में (बाएं से दाएं) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. समन केलेगामा, प्रो. दीपक नैय्यर, डा. पॉश राज पांडेय, डॉ. मुस्तफिजुर रहमान, और डॉ. सागर परसाई।

दक्षिण एशिया के विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार सृजन की चुनौतियों पर महत्वपूर्ण सबक के साथ यह कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यशाला में विख्यात विशेषज्ञों ने विश्लेषणात्मक साक्ष्यों को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया, जिनके तहत दक्षिण एशिया में विनिर्माण क्षेत्र के विकास और इससे संबद्ध रोजगार सृजन की राह की विशिष्ट बाधाओं पर प्रकाश डाला गया। भावी दिशाएं तय करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया जिनमें मुख्य रूप से मौजूदा बाधाओं से पार पाते हुए और निर्यात आधारित विकास के अवसरों, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तथा व्यापार एवं निवेश में क्षेत्रीय सहयोग से लाभ उठाते हुए तीव्र औद्योगीकरण सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश को शामिल किया गया।

प्रो. सुखमय चक्रवर्ती पर विशेष व्याख्यान

आरआईएस के संस्थापक उपाध्यक्ष प्रो. सुखमय चक्रवर्ती (1983–1990) को भारत के सबसे प्रशंसित विकास अर्थशास्त्रियों में शुमार किया जाता था। आर्थिक नियोजन और विकास के दर्शन एवं कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों में उनकी गहरी रुचि थी। वह भारतीय प्रधानमंत्रियों की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और उन्होंने लगातार तीन प्रधानमंत्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। उन्होंने सत्तर के दशक के दौरान भारतीय योजना आयोग के एक सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं।

प्रो. चक्रवर्ती ने अपना जीवन ज्ञान के प्रसार के साथ–साथ अपनी शैक्षणिक प्रतिभा के जरिए आर्थिक नियोजन को एक उपयोगी प्रयोग बनाने में समर्पित कर दिया था। आरआईएस ने अपने प्रलेखन केंद्र (डॉक्यूमेंटेशन सेंटर) को प्रो. सुखमय चक्रवर्ती की स्मृति में समर्पित कर दिया है। इस अवसर पर 17 मार्च, 2017 को एक विशेष समारोह आयोजित किया गया जिसमें प्रो. मनमोहन अग्रवाल, आरबीआई चेयर प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम ने प्रो. सुखमय चक्रवर्ती के

(बाएं से दाएं) प्रो. वाई. के. अलघ, कुलाधिपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात, प्रो. मनमोहन अग्रवाल, आरबीआई चेयर प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम, डॉ. वी. एस. शेषाद्री, कार्यवाहक अध्यक्ष, आरआईएस, माननीय डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष, आरआईएस, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और प्रो. वी.आर. पंचमुखी, संस्थापक महानिदेशक, आरआईएस।

जीवन और उत्कृष्टम कार्यों पर एक विशेष व्याख्यान दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं आरआईएस के पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉ. मनमोहन सिंह की गरिमामय उपस्थिति भी इस अवसर पर रही और उन्होंने सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रो. चक्रवर्ती एवं उनके बहुमूल्य कार्यों के बारे में अपनी श्रेष्ठ धारणा को स्मरण किया।

गुजरात स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति प्रो. वाई. के. अलघ और आरआईएस के संस्थापक महानिदेशक प्रो. वी.आर. पंचमुखी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास नियोजन प्रक्रिया में प्रो. सुखमय चक्रवर्ती के विशाल योगदान को स्मरण किया। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें आरआईएस के अनुसंधान संकाय के कुछ पूर्व सहयोगी भी शामिल थे।

आरआईएस में इब्सा विजिटिंग फेलोशिप आरंभ

भारत सरकार के विदेश मामले मंत्रालय के सहयोग से आरआईएस इब्सा डायलॉग फोरम–ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के तहत भारत के अन्य दो भागीदार देशों में प्रत्येक से दो–दो शोध छात्रों (रिसर्च स्कॉलर) को इब्सा विजिटिंग फेलोशिप देगा। यह कार्यक्रम टिकाऊ विकास का समन्वय, समर्थन करने एवं इसे सक्षम बनाने के लिए एक कारगर बहुस्तरीय संस्थागत विकसित करने पर सुसंगत एवं अभिन्न प्रकार से फोकस करता है। यह दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील के वैसे शोध छात्रों के लिए उपलब्ध है जिनकी भागीदार देशों में इब्सा डायलॉग प्रक्रिया के लक्ष्यों एवं उद्वेश्यों की प्राप्ति की दिशा में गहन अनुसंधान करने में गहरी दिलचस्पी है।

आरआईएस ने 28 नवंबर 2016 को इब्सा फेलोशिप का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी की स्वागत टिप्पणियों के साथ आरंभ हुआ।

विदेश मामले मंत्रालय में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) सुश्री प्रीति सरन ने कार्यक्रम आरंभ करने के अवसर पर कहा कि इब्सा को विकासशील देशों के बीच सहयोग का एक सफल उदाहरण माना गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर तीनों देश बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। भारत सरकार के विदेश मामले मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री आलोक डिमरी; भारत में दक्षिण अफ्रीका उच्चायोग के उप उच्चायुक्त श्री बेन जौबर्ट ; एवं भारत में ब्राजील दूतावास की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन सुश्री क्लौडिया विऐरा सैंटोस ने भी इस अवसर पर टिप्पणियां कीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने की।

विदेश मामले मंत्रालय में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) सुश्री प्रीति सरन आरआईएस इब्सा विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम के लांच के अवसर पर उद्घाटन भाषण देती हुईं।

अमेरिका–भारत व्यापार एजेंडे को नया स्वरूप प्रदान करने की ओर अग्रसर

आरआईएस ने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 15–17 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में 'अमेरिका–भारत व्यापार एजेंडे को नया स्वरूप प्रदान करने की ओर अग्रसर' विषय पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने 'भारत–अमेरिका व्यापार संबंध' से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर भारतीय विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया।

हार्ट ऑफ एशिया और कनेक्टिविटी पर संगोष्ठी

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करने संबंधी 'हार्ट ऑफ एशिया' प्रक्रिया के तहत व्यापार, वाणिज्य एवं निवेश – विश्वास बहाली उपायों (टीसीआई–सीबीएम) के अंतर्गत 3 दिसंबर 2016 को अमृतसर में 'हार्ट ऑफ एशिया और कनेक्टिविटी पर संगोष्ठी' का आयोजन किया।

'हार्ट ऑफ एशिया' अफगानिस्तान को अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ–साथ सीआईएस देशों से भी जोड़ने की खातिर एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। एशिया, ईरान और सीआईएस क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में अफगानिस्तान की जो विशिष्ट सामरिक लोकेशन (अवस्थिति) है उसमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ भारतीय उद्योगों की साझेदारी में विविधता लाने की अपार क्षमता है।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और फिक्की के निदेशक श्री गौतम घोष के स्वा्गत भाषणों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। काबुल में भारत के राजदूत मनप्रीत वोहरा ने उद्घाटन भाषण दिया। आरआईएस के प्रोफेसर डॉ. राम उपेंद्र दास ने उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन दिया।

कनेक्टिविटी पर संगोष्ठी की मुख्य नीतिगत सिफारिशों में से कुछ ये हैं: पश्चिमी–पूर्वी भारतीय बंदरगाहों और चाबहार के बीच समुद्र–सड़क/रेल मल्टी–मोडल लिंकेज वाणिज्यिक दृष्टि से सुसंगत अथवा लाभप्रद है क्योंकि यह दक्षिण यूरोप (रेल), मध्य एशिया, रूस और उत्तरी यूरोप (रेलवे– सड़क) जाने वाले भारतीय माल (कारगो) का एक संकुलन है। इसे कामयाब बनाने के लिए 'अवधारणा का प्रमाण' हासिल करने की जरूरत है, जिसमें इन तीन कदमों को शामिल किया जा सकता है: थोड़ी सब्सिडी के साथ नियमित रूप से एक शिपिंग सेवा (सप्ताह में एक या दो बार) का संचालन करना, एक मल्टी–मोडल स्थल (प्वाइंट) के रूप में इस बंदरगाह का उपयोग करने में आने वाली समस्याओं को समझने के लिए 'सूक्ष्म स्तर' का परिचालन संबंधी अध्ययन कराना और उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर में टीआईआर संधि और कस्टम संबंधी सहूलियत के अन्य रूपों पर ध्यान केंद्रित करना। दक्षिण और मध्य एशिया को आपस में जोड़ने के लिए सबसे सस्ते एवं सबसे छोटे मार्गों का पता लगाना और उन्हें विकसित करना अत्यंत जरूरी है, जो वास्तव में सड़क मार्ग या भूमि मार्ग (लैंड रूट) होते हैं। इनमें भूमि से घिरे देशों को भूमि से जुड़े देशों में तब्दील करने की क्षमता होती है। इसे लाभप्रद बनाने के लिए ट्रांस–एशियाई राजमार्ग और ट्रांस–एशियाई रेलवे नेटवर्क के रूप में संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के कार्य पर परिचालन के लिहाज से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ये रेल–सड़क–समुद्र कनेक्टिविटी के मल्टी–मोडल संदर्भ में उपयुक्त

'हार्ट ऑफ एशिया और कनेक्टिविटी' पर संगोष्ठी के दौरान राजदूत मनप्रीत वोहरा उद्घाटन भाषण देते हुए।

साबित हो सकते हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी के रूप में ऐसी कोई अड़चन ही नहीं होनी चाहिए, जिससे व्यापार और निवेश के प्रवाह में बाधा उत्पंन्न हो। अतः व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचागत सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ एक परस्पर संवादात्मक सत्र के लिए 18 नवंबर, 2016 को आरआईएस का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में ये शामिल थेः श्री क्रिस्टोफर हैमेल, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वैश्विक भागीदारी, ज्ञान एवं रणनीति प्रभाग, आईएफएडी, रोम; श्री माउरीजिओ नवारा, ज्ञान प्रबंधन एवं आउटरीच अधिकारी, वैश्विक भागीदारी, ज्ञान एवं रणनीति प्रभाग, आईएफएडी, रोम; सुश्री फ्रांसिस्का रैप्पोकसियोलो, वैश्विक भागीदारी अधिकारी, वैश्विक भागीदारी, ज्ञान एवं रणनीति प्रभाग, आईएफएडी, रोम; और सुश्री मीरा मिश्रा, कंट्री कोऑर्डिनेटर, आईएफएडी, भारत।

आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; डॉ. टी.पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, डॉ. बीना पांडे, रिसर्च एसोसिएट; और डॉ. अमित कुमार, रिसर्च एसोसिएट ने प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श में भाग लिया।

कृषि क्षेत्र में भारत–अफगानिस्तान सहयोग पर संवादात्मक सत्र

आरआईएस ने दक्षिण–दक्षिण सहयोग केंद्र, शारदा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अफगानिस्तान से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ 'भारतीय कृषि में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और परिवर्तन प्रबंधन' पर एक संवादात्मक सत्र का आयोजन 23–25 मई 2016 के दौरान किया। पहले दिन शारदा विश्वविद्यालय में व्याख्यान आयोजित किए गए। श्री प्रसून कश्यप, प्रोजेक्ट एसोसिएट, दक्षिण–दक्षिण सहयोग केंद्र ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए 'भारतीय और अफगान कृषि पर एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य' पेश किया। प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती, निदेशक, दक्षिण–दक्षिण सहयोग केंद्र, शारदा

विश्वविद्यालय और विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने भारत में कृषि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की एक व्यापक रूपरेखा पेश की और बाद में 'क्या कारगर साबित होता है और क्या नहीं: भारत में आकलन अध्ययनों से सबक' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। दूसरे दिन, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित जैविक बागवानी उद्यान एवं किसानों के खेतों और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रीनहाउस कृषि इकाई के क्षेत्रीय दौरे किए गए। तीसरे दिन आरआईएस में व्याख्यान आयोजित किए गए। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, श्री गोपाल बागले, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और प्रो. टी.पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने प्रतिनिधियों के साथ कृषि क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। डॉ. एस.के. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त, भारत सरकार ने एक व्याख्यान दिया और 'भारतीय बागवानी क्षेत्र से जुड़े अनुभवों' पर एक प्रस्तुति दी। डॉ. अरविंद कौशल, प्रतिष्ठित फेलो, टेरी ने एक व्याख्यान दिया और 'पशुधन एवं पशुपालन क्षेत्र में भारतीय अनुभव' पर एक प्रस्तुति दी। डॉ. आर.के. सिंह, सीएमडी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने एक व्याख्यान दिया और 'कृषि में परिवर्तन प्रबंधन से जुड़े भारतीय अनुभव' पर एक प्रस्तुति दी।

भारतीय विज्ञान कूटनीति पर परामर्श

आरआईएस ने बेंगलुरू स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) के सहयोग से विज्ञान कूटनीति पर आरआईएस के प्रस्तावित विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय विज्ञान कूटनीति को बढ़ावा देने हेतु एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एनआईएएस में 7 अप्रैल 2016 को आधे दिन चली एक परिचर्चा बैठक का आयोजन किया। एनआईएएस के निदेशक डॉ. बलदेव राज ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस विषय पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया कि विज्ञान कूटनीति के क्षेत्र में एनआईएएस आखिरकार कैसे योगदान कर सकता है। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने आरआईएस एवं विदेश मंत्रालय का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उद्घाटन भाषण का आगाज किया और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एसएंडटी भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, डॉ. के. कस्तुरीरंगन, एमेरिटस प्रोफेसर, एनआईएएस, प्रो. वी. एस. राममूर्ति, एमेरिटस प्रोफेसर, एनआईएएस, प्रोफेसर राजाराम नागप्पा, विजिटिंग प्रोफेसर, एनआईएएस और डॉ. सुबा चंद्रन, प्रोफेसर, एनआईएएस और डॉ. अमित कुमार, रिसर्च एसोसिएट, आरआईएस ने इस बैठक में भाग लिया।

ब्रिक्स वेलनेस फोरम पर परामर्श

गत वर्षों में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2016 के मध्य में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले, निम्नलिखित विषयों पर सेमिनार/कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के रूप में देश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने की योजना बनाई गई: चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियां – जैव संसाधन का प्रबंधन एवं संस्थागत ढांचा और व्यापार वर्गीकरण तथा जैव–संसाधनों का मानकीकरण, पोषण: उत्पादक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना – स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पोषण और पोषण तक पहुंच, वेलनेस और एसडीजी, वेलनेस की अवधारण ाा एवं एसडीजी में वेलनेस की केंद्रीयता, वेलनेस एवं चिकित्सा पर्यटन और समग्र वेलनेस: शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, पर्यावरणीय और सामाजिक – एक समन्वित दृष्टिकोण, इत्यादि।

इनके एक हिस्से के रूप में आयुष मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर आरआईएस सितंबर 2016 में बेंगलुरू में दो दिवसीय वेलनेस फोरम की योजना किया

गया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य वेलनेस की सामान्य अवधारणा को बढ़ावा देना और वेलनेस हासिल करने के प्रयासों के तहत चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों की भूमिका पर प्रकाश डालना था। ब्रिक्स वेलनेस फोरम के संगठन पर चर्चा करने के लिए 30 अप्रैल 2016 को आरआईएस में विशेषज्ञ बैठक भी आयोजित की गई थी। डॉ. रंजीत पुराणिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री धूतपपेश्वर लिमिटेड, मुंबई एवं महासचिव, भारतीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माता संघ, डॉ. डी. रामनाथन, सीएमडी, सीताराम आयुर्वेद फार्मेसी लिमिटेड, त्रिशूर, डॉ. टी. जी. विनोद कुमार, वैज्ञानिक, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान इकाई (टीबीजीआरआई), तिरुवनंतपुरम, डॉ. अशोक पांडे, प्रख्यात वैज्ञानिक, नवाचार एवं अप्लायड जैव प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली, डॉ. सी.के. कटियार, सीईओ हेल्थकेयर (तकनीकी), इमामी लिमिटेड कोलकाता, डॉ. पी. के. आनंद, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग, नई दिल्ली, डॉ. रामा जयसुंदर, एम्स, नई दिल्ली और प्रो. टी. सी. जेम्स, आरआईएस ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने की थी। बैठक के दौरान चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के समक्ष मौजूद प्रमुख मुद्दों और इन प्रणालियों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चाएं हुईं। इसमें व्यापार वर्गीकरण, व्यापार बाधाओं, वेलनेस संकेतकों और वेलनेस की बुनियादी अवधारणाओं से संबंधित मुद्दों पर ब्रिक्स वेलनेस फोरम में चर्चा करने का सुझाव दिया गया। फोरम के दौरान चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया था।

जीवित संशोधित जीवों के सामाजिक–आर्थिक आकलन पर कार्यशाला

आरआईएस ने सामाजिक–आर्थिक आकलन, लागत–लाभ विश्लेषण और मार्गदर्शन दस्तावेज के लिए आवश्यक कार्यप्रणालियों के विकास हेतु विशिष्ट जनादेशों से युक्त जैव सुरक्षा संबंधी कार्टाजेना प्रोटोकॉल (सीपीबी) के अनुच्छेद 26.1 के तहत सामाजिक–आर्थिक चिंताओं से जुड़ी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की परियोजना के साथ संयोजन किया। इसके तहत आरआईएस ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और यूएनईपी के सहयोग से 26 मई 2016 को नई दिल्ली में परियोजना समीक्षा बैठक और अंतिम कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. रंजिनी वारियर, सलाहकार, एमओईएफसीसी, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। पांच साझेदार संस्थानों के प्रमुख और सह–प्रमुख जांचकर्ताओं (पीआई/सह–पीआई) ने प्रस्तुतियां दीं। इनमें ये शामिल थेः डॉ. आर. एन. पदरिया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली, प्रो. एन. ललिता, गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान (जीआईडीआर), अहमदाबाद, प्रो. सुरेश एस. पाटिल, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), रायचूर, डॉ. के. श्रीनिवास, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद और डॉ. के. मूर्ति, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), बेंगलुरू। प्रो. पी. जी. चेंगप्पा, आईसीएआर में राष्ट्रीय प्रोफेसर, आईएसईसी, बेंगलुरू, प्रो. मनमोहन अग्रवाल, सहायक वरिष्ठ फेलो, आरआईएस एवं आरबीआई चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम, प्रो. ई. हरिबाबू, पूर्व प्रोफेसर एवं उप कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, प्रो. टी. पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, आरआईएस और प्रो. चंद्रशेखर राव, आर्थिक विकास संस्थाशन, नई दिल्ली ने इन प्रस्तुतियों पर विशेषज्ञ टिप्पणी की। डॉ. के. रवि श्रीनिवास, आरआईएस ने आगे की राह की रूपरेखा प्रस्तुत की और ध

न्यवाद ज्ञापन किया। इससे पहले आरआईएस ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और यूएनईपी के साथ मिलकर 28 अप्रैल 2016 को परियोजना समीक्षा बैठक आयोजित की थी।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के आरंभिक भाषण के साथ हुआ। छह संस्थानों के प्रमुख और सह–प्रमुख जांचकर्ताओं (पीआई/सह–पीआई) ने प्रस्तुतियां दीं। इनमें ये शामिल थे : डॉ. आर. एन. पदरिया, आईएआरआई, नई दिल्ली, प्रो. एन. ललिता, जीआईडीआर, अहमदाबाद, प्रो. सुरेश एस. पाटिल, यूएएस, रायचूर, डॉ. एस. पी. सुभाष, एनएएआरएम, हैदराबाद, डॉ. ए. वी. मंजूनाथ, आईएसईसी, बेंगलुरू और डॉ. एस. वराधा राज, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर। प्रो. पी. जी. चेंगप्पा, आईसीएआर में राष्ट्रीय प्रोफेसर, आईएसईसी, बेंगलुरू, प्रो. मनमोहन अग्रवाल, सहायक वरिष्ठ फेलो, आरआईएस एवं आरबीआई चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम, प्रो. टी. पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, आरआईएस और प्रो. चंद्रशेखर राव, आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली ने इन प्रस्तुतियों पर विशेषज्ञ टिप्पणी की। डॉ. के. रवि श्रीनिवास, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। परियोजना के निष्कर्ष के रूप में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है।

भारतीय विकास सहयोग मंच में सिविल ब्रिक्स पूर्व परामर्श

इस साल भारत ही ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15–16 अक्टूबर 2016 को गोवा में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय 'उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान ढूंढ़ना' है। इस दौरान सम्मेलन या एकीकरण युक्त निरंतरता की भावना के साथ विशेषकर संस्था–निर्माण, पिछली प्रतिबद्धताओं को लागू करने और अभिनव समाधानों को ढूंढ़ने पर फोकस किया गया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर आरआईएस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एक 'ब्रिक्स सिविल सोसायटी बैठक' की संभावनाएं तलाशने को लेकर 2 अप्रैल 2016 को एक अनौपचारिक भारतीय विकास सहयोग मंच परामर्श का आयोजन किया, ताकि प्रमुख मुद्दों, भागीदारी के स्तर, तारीखों और संभावित विषयों का पता लगाया जा सके। इस अनौपचारिक भारतीय विकास सहयोग मंच परामर्श का आयोजन आरआईएस में ही किया गया।

ब्रिक्स के सदस्य देशों के विकास साझेदारी प्रशासक

इस साल अक्टूबर में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) और विदेश मंत्रालय ने आपस में मिलकर 6–7 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में ब्रिक्स के सदस्य देशों के विकास साझेदारी प्रशासकों (डीपीए) –समकक्षों की दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया। श्री दिनकर अस्थाना, संयुक्त सचिव (डीपीए– 2), विदेश मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया। श्री हेमेंद्र के. शर्मा, निदेशक (डीपीए–2), विदेश मंत्रालय ने आरंभिक भाषण दिया। प्रो. अनुराधा चेनॉय, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू और अध्यक्ष, भारतीय विकास सहयोग मंच ने विशेष भाषण दिया। श्री एस. के. दुदेजा, उप सचिव (डीपी–1), विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन किया।

ब्रिक्स के सदस्य देशों के डीपीए–समकक्ष की बैठक में प्रतिभागी।

श्री दिनकर अस्थाना ने 'ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विकास सहयोग के अनुभव साझा करने' पर आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता की। सुश्री क्लाउडिया विएरा सैंटोस, मिशन उप प्रमुख, ब्राजील दूतावास, नई दिल्ली, श्री मिखाइल एर्मोलोव, उप निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं सहयोग विभाग, रूस, श्री हेमेंद्र के. शर्मा, निदेशक (डीपीए–2), विदेश मंत्रालय , श्री ली बाईजुन, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सलाहकार, चीनी दूतावास, नई दिल्ली, सुश्री नथली वेरिन, नेशनल ट्रेजर, दक्षिण अफ्रीका और सुश्री डिनियो माथलको, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग (डीआईआरसीओ), दक्षिण अफ्रीका ने प्रस्तुतियां दीं।

उभरते वैश्विक विकास ढांचे पर डीपीए और भारतीय विकास सहयोग मंच की एक संयुक्त बैठक की सह–अध्यक्षता प्रो. गुलशन सचदेवा, जेएनयू एवं सदस्य, भारतीय विकास सहयोग मंच बोर्ड और श्री दिनकर अस्थाना ने की। डॉ. कौस्तुव बंदोपाध्याय, निदेशक, प्रिया (पीआरआईवाईए) ने भारतीय विकास सहयोग मंच के विकास और कामकाज पर प्रस्तुति दी। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, संयोजक, भारतीय विकास सहयोग मंच ने ब्रिक्स की अगुवाई वाली प्रक्रियाओं से संबंधित भारतीय विकास सहयोग मंच के दृष्टिकोण पर प्रस्तुति दी। श्री हर्ष जेटली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाणी ने भी समान विषय पर प्रस्तुति दी।

श्री दिनकर अस्थाना ने 'ब्रिक्स प्रभावकारी विकास सहयोग को किस तरह बढ़ावा दे सकता है' विषय पर आयोजित खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की। चर्चाओं के दौरान इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया ; ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा विकास सहयोग के क्षेत्र में प्रभावकारी एवं पूरक रणनीतियां जारी रखने की अनिवार्यता, विकास सहयोग की प्रभावशीलता और साझेदार देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीके एवं साधन, जिनमें सिविल सोसायटी संगठनों की भूमिका भी शामिल है।

इस बैठक ने ब्रिक्स के डीपीए को विकास सहयोग के क्षेत्र में वैश्विक, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करने और इस क्षेत्र में नीतिगत कदमों के जरिए चुनौतियों का सामना करने एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक के आयोजन के लिए भारत सरकार का हार्दिक धन्यवाद किया।

बोद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी तक पहुंच से संबंधित कानूनी अस्पष्टता का समाधान करना

कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी गहन उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर हालिया नीतिगत निर्णय के साथ ही नीति निर्माताओं के लिए 'पहुंच और बोद्धिक संपदा संरक्षण' पर खुली बहस शुरू हो गई है। इस संदर्भ में आरआईएस ने 4 जून 2016 को नई दिल्ली में 'बोद्धिक संपदा, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और नीतिगत विचार–विमर्श' पर एक परिचर्चा आयोजित की थी। सरकार, उद्योग जगत, शैक्षणिक जगत, अनुसंधान संगठनों, सिविल सोसायटी और मीडिया के प्रतिनिधियों ने इस परिचर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस परिचर्चा के बाद अगले कदम के रूप में यह महसूस किया गया कि पेटेंट अधिनियम और पीपीवी एंड एफआर अधिनियम के कुछ विशेष कानूनी प्रावधानों पर अभी और गहन चर्चा करने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने 27 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में 'बोद्धिक संपदा और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तक पहुंच से संबंधित कानूनी अस्पष्टता के समाधान पर परिचर्चा का आयोजन किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. एस. आर. राव, सलाहकार, डीबीटी ने विशेष भाषण दिया।

परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त करने वालों में ये प्रमुख थेः डॉ. आर. आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौध किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण (पीपीएफआरए), डॉ. डी. के. श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त (क्यूसी), कृषि वानिकी एवं जल मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू), डॉ. मालती लक्ष्मीकुमारन, निदेशक, लक्ष्मीकुमारन एवं श्रीधरन, डॉ. दीपा के. टिक्कू, भागीदार, केएंडएस पार्टनर्स, डॉ. सुधीर कोचर, एआरएस (सेवानिवृत्त), एक्स–आईसीएआर, स्वतंत्र आईपी विशेषज्ञ, श्री सुनील मैथ्यूज, वरिष्ठ वकील, श्री एसेनीज ओभान, पेटेंट अटॉर्नी, श्री अभिषेक साकेत, वकील, डॉ.अनिता रमन्ना पाठक, सहायक प्रोफेसर, एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, मुंबई, डॉ. योगेश गोखले, फेलो, टेरी, डॉ. एल. पुष्पा कुमार, सहायक प्रोफेसर, नालंदा विश्वविद्यालय, डॉ. क्षितिज कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर, एमिटी विश्वविद्यालय, प्रो. टी. सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस, डॉ. टी. पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, आरआईएस और डॉ. के. रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस। प्रो. सचिन चतुर्वेदी के समापन भाषण के साथ परामर्श समाप्त हुआ।

विकास सहयोग के प्रति भारत का दृष्टिकोण

श्री अमर सिन्हा, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय ने 9 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में *'इंडियाज एप्रोच टू डेवलपमेंट कोऑपरेशन'* नामक पुस्तक का विचोचन किया जिसका सह–संपादन सुश्री एंथिया मुलाकाला, अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए द एशिया फाउंडेशन की निदेशक और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने किया। यह कार्यक्रम आरआईएस द्वारा द एशिया फाउंडेशन और भारतीय विकास सहयोग मंच के सहयोग से आयोजित किया गया।

इस अवसर पर श्री अमर सिन्हा ने कहा, 'यह पुस्तक एक बौद्धिक रूपरेखा प्रदान करती है, समग्र संदर्भ तय करती है और भारतीय विकास सहायता ने जो कुछ भी किया है उन सभी पर फोकस करती है।' श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने उद्घाटन भाषण देते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए और कहा, 'भारत के विकास सहायता प्रयासों को कम करके आंका जाता है और इस पुस्तक में भारतीय विकास सहायता के बारे में अहम जानकारियां दी गई हैं।'

इस पुस्तक के बारे में परिचय देते समय सुश्री एंथिया मुलाकाला ने कहा कि भारत न केवल बढ़ती मात्रा एवं अपने दक्षिण–दक्षिण सहयोग की पहुंच के कारण, बल्कि दक्षिण के विशिष्ट विकास की गाथा और ज्ञान सृजन की अभिव्यक्ति में अपने नेतृत्व के कारण भी विकास सहयोग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आया है। इस पुस्तक ने दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर उपलब्ध सामग्री में बहुमूल्य योगदान किया है।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि साठ एवं सत्तर के दशकों के दौरान हुई प्रगति पर आधारित विकास गाथा वर्ष 1986 में 'विकास के अधिकार के घोषणा–पत्र' को अपनाने से और ज्यादा समृद्ध हुई क्योंकि इसने मानव विकास को केंद्र में ला दिया। उन्होंने पांच प्रमुख तत्वों यथा क्षमता निर्माण, अनुदान, ऋण रेखा, व्यापार एवं निवेश पर आधारित विकास सघन के बारे में भी बताया। इसके तहत उन्होंने वर्ष 2005 में हांगकांग में हुए विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा की गई पहल का उदाहरण दिया जिसमें भारत ने अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क–मुक्त कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) देने संबंधी अपने निर्णय की घोषणा की।

उत्तर–दक्षिण और दक्षिण–दक्षिण विकास सहयोग पर वैश्विक परिचर्चाओं से उत्पन्न मुद्दों के बारे में प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने विशेष जोर देते हुए कहा कि विकास सहयोग से संबंधित ओईसीडी की शर्तों को दक्षिण–दक्षिण सहयोग में लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अभिसरण या सामंजस्य केवल तभी संभव होगा जब शर्तें दोनों ही के लिए स्वीकार्य हों।

प्रो. एस.के. मोहंती, आरआईएस, प्रो. गुलशन सचदेवा, जेएनयू, श्री प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार और सुश्री सुप्रिया रॉयचौधरी, क्राइसिस एक्शन में एमर्जिंग पॉवर्स की समन्वयक, जो इस पुस्तक में योगदान करने वाले लेखक–लेखिका हैं, ने भारत के विकास सहयोग प्रयासों और साझेदार देश के दृष्टिकोणों पर करीबी नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय सहायता एजेंसी की प्रासंगिकता पर भी चर्चा की।

इस खंड में भारतीय नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं वैश्विक विकास प्रोफेशनलों की ओर से भारत के बढ़ते विकास सहायता कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर पेश की गई अनेक अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण शामिल हैं। इसमें भारतीय विकास सहयोग के उद्भव का उल्लेख एवं विश्लेषण किया गया है और वैश्विक विकास के साथ–साथ

श्री अमर सिन्हा, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय श्री श्याम सरन के साथ 'इंडियाज एप्रोच टू डेवलपमेंट कॉऑपरेशन' नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) श्री सागर परसाई, देश प्रतिनिधि, द एशिया फाउंडेशन, प्रो. एस. के. मोहंती, श्री प्रबोध सक्सेना, सुश्री अंथिया मुलाकाला, सुश्री सुप्रिया रॉयचौधरी, प्रो. गुलशन सचदेवा और प्रो. सचिन चतुर्वेदी।

भारतीय विदेश नीति को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए भी भारतीय अनुभवों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह शिक्षाविदों, प्रोफेशनलों और निर्णय लेने वालों पर समान रूप से लक्षित है।

इस पुस्तक का विमोचन श्री तरनजीत एस. संधू, उप मिशन प्रमुख, भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका द्वारा 14 सितंबर 2016 को विदेश विभाग में भी किया गया। इसके बाद योगदानकर्ताओं द्वारा इस पर चर्चा की गई। सुश्री बारबरा स्मिथ, प्रशासक की उप सहायक, नीति, नियोजन एवं अध्ययन ब्यूरो, यूसेड इस अवसर पर संचालक थीं। इसी तरह 12 सितंबर 2016 को ओटावा में भी आरआईएस, कनाडा–इंडिया उत्कृष्टता सेंटर, कार्लटन यूनिवर्सिटी और द एशिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से बुक विमोचन समारोह आयोजित किया गया। श्री अरुण साहू, कनाडा में भारत के उप उच्चायुक्त ने भी पैनल परिचर्चा में भाग लिया।

प्रो. बिबेक देबरॉय, सदस्य, नीति आयोग ने दूसरे दिन 'टिकाऊ एवं लचीले बुनियादी ढांचे का विकास करने' पर पहले सत्र की अध्यक्षता की। परिचर्चा में श्री अमरजीत सिन्हा , सचिव, श्री मनोज सिंह, सलाहकार, नीति आयोग, श्री प्रवीण मेहतो, सलाहकार, नीति आयोग, श्री अपूर्व चंद्र, प्रधान सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र सरकार और श्री पी. संपत कुमार, निवासी आयुक्त, मेघालय सरकार शामिल थे।

सत्र के दौरान बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण एवं सार्वजनिक–निजी भागीदारी, गुणवत्ता, स्थायित्व एवं लचीलापन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे, किफायती एवं पहुंच (अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक कनेक्टिविटी) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अपने संबोधन में प्रो. बिबेक देबरॉय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार का फोकस बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे, विशेषकर भौतिक बुनियादी ढांचे पर है। इस बात पर बल दिया गया कि यदि बुनियादी ढांचे को सचमुच टिकाऊ बनाना है, तो हमें यह समझना होगा कि लचीला बुनियादी ढांचा आखिरकार किस तरह दिखता है। यही नहीं, सबसे लचीला परिणाम हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे के डिजाइनों एवं प्रणालियों की आपस में तुलना करने की आवश्यकता है।

यह महसूस किया गया कि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में भारी–भरकम निवेश करने की आवश्यकता है, अत; नीतियां इस तरह से तैयार की जानी चाहिए जिससे कि इन परियोजनाओं में निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इस लिहाज से पीपीपी एक सफल मॉडल है। यदि बुनियादी ढांचे में सुधार होता है, तो कनेक्टिविटी बेहतर होगी जिससे व्यापार बढ़ेगा। इससे अंततः जीडीपी वृद्धि दर बढ़ जाएगी और फिर इससे गरीबी उन्मूलन संभव होगा जो एसडीजी के मूल में है।

प्रो. रथिन राय, निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) ने 'हरित वित्त पोषण एवं हरित लेखांकन' पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. पी.के. आनंद, श्री कृष्ण कुमार, उप महानिदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओपीएसआई), डॉ. चंद्र भूषण, उप महानिदेशक, सीएसई और डॉ. दिव्य दत्त, फेलो एवं एसोसिएट डायरेक्टर, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) परिचर्चा थे। सत्र के दौरान इन मुद्दों पर चर्चाएं की गईं; हरित राष्ट्रीय लेखांकन; चुनौतियां एवं समाधान, वित्तीय बाजार और भारत की हरित वित्त संबंधी जरूरत और हरित वित्त के नए स्रोत एवं उपकरण।

डॉ. सी. मुरलीकृष्ण कुमार, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग ने 'सतत औद्योगीकरण और विकास के लिए नवाचार' विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र में परिचर्चा में भाग लेने वाले थेः डॉ. अश्विनी गुप्ता, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, डॉ. जतिंदर कौर अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), पंजाब

सरकार, सुश्री मिशिको एनोमोतो, प्रमुख, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशिया–प्रशांत केंद्र (एपीसीटीटी) और श्री राघवेन्द्र साहा, वरिष्ठ सलाहकार, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)। सत्र के दौरान इन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया; प्रौद्योगिकी में अंतर और सतत औद्योगीकरण की जरूरत, विकास के लिए स्थायित्व उन्मुख वैज्ञानिक अनुसंधान – स्वास्थ्य, कृषि, शहरी विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी व्यवस्थाएं और इस संदर्भ में भारत के कदम।

प्रो. टी. सी.ए. अनंत, सचिव, एमओएसपीआई ने समापन सत्र में विशेष भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एसडीजी हमारे लिए व्यापक अवसर हैं। विकास की व्यापक अभिव्यक्ति और उनमें अंतर्निहित तरक्की वैश्विक आम सहमति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समक्ष अत्यंत जटिल और आपस में संबद्ध चुनौतियां हैं, अत; भारत में चुनौतियों का सामना करने के लिए सही प्रकार की नीतियां बनाने की जरूरत है। नीति के अंतर्गत स्पष्ट रूप से मापने योग्य नतीजे भी होने चाहिए। उन्होंने यह कहते हुए अपना संबोधन समाप्त किया कि अगले 15 सालों में हम क्या करने जा रहे हैं, ये चर्चाएं इस प्रक्रिया की शुरुआत हैं। श्री श्याम सरन, श्री यूरी अफानसीव और प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने भी समापन सत्र को संबोधित किया।

जीवित संशोधित जीवों (एलएमओ) के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश और तरीके विकसित करना

आरआईएस ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के साथ मिलकर 24 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में 'जीवित संशोधित जीवों (एलएमओ) के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश और तरीके विकसित करने' से संबंधित परियोजना की अंतिम कार्यशाला का आयोजन किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक (एनपीसी), एमओईएफ एंड सीसी ने विशेष भाषण दिया। डॉ. एस.आर. राव, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेषज्ञ भाषण दिया। डॉ. अमिता प्रसाद, अपर सचिव, एमओईएफ एंड सीसी ने मुख्य भाषण दिया।

इस अवसर पर 'जीवित संशोधित जीवों (एलएमओ) के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश और तरीके विकसित करने' विषय पर रिपोर्ट भी पेश की गई। डॉ. अमिता प्रसाद ने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि यह रिपोर्ट आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए रूपरेखा संबंधी दस्तावेज के रूप में काम करेगी। जीएम फसलों को केवल सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के बाद ही अनुमोदित किया जा सकता है क्योंकि इन फसलों को लेकर किसानों और उपभोक्ताओं के मन में चिंताएं घर कर गई हैं। भारत इस तरह की रूपरेखा दस्तावेज पेश करने वाला पहला देश है। कई देशों ने इसी तरह की रूपरेखा तैयार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है जिसे निश्चित रूप से भारत उनके साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज 'सीओपी–एमओपी' में प्रस्तुत किया जाएगा जिसका आयोजन दिसंबर में मेक्सिको में किया जाएगा।

श्री ज्ञानेश भारती ने विशेष भाषण देते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत पांच महत्वपूर्ण पहलुओं यथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और पर्यावरण

का व्यापक अध्ययन किया गया है, जिन्हें रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि सीपीबी के अनुच्छेद 26 को लागू करने के लिए रूपरेखा के कार्यान्वयन के बाद भारत इस क्षेत्र में अग्रण ी हो जाएगा।

डॉ. एस.आर. राव ने अपने विशेषज्ञ भाषण में कहा कि जीएम के महत्व को स्पष्ट रूप से फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षा एवं प्रभावकारिता जीएम फसलों की एक तरफ और प्रभावशीलता इसकी दूसरी तरफ है। यह रिपोर्ट भी समान नजरिए को ही साझा करती है।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने भाषण में प्रतिभागियों को बताया कि जीएम प्रौद्योगिकियां वर्ष 1988 से ही आरआईएस के रडार पर रही हैं। यह परियोजना उस दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थायित्व के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट में जीएम फसलों के प्रभावों के विस्तृत विश्लेषण को समाहित करने की कोशिश की गई है। यह रूपरेखा निश्चित रूप से सभी पहलुओं में जीएम का आकलन करेगी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में तीन प्रमुख मुद्दे शामिल हैंः यथा सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए उपकरण एवं तरीके, सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए एक मॉडल प्रश्नावली और मार्गदर्शन दस्तावेज के साथ लागत–लाभ विश्लेषण के लिए एक रूपरेखा।

डॉ. रंजिनी वारियर, पूर्व सलाहकार, एमओईएफ एंड सीसी एवं सह–अध्यक्ष, एसईसी पर सीबीडी तदर्थ तकनीकी विशेषज्ञ समूह ने बिल्कुल ठीक समय पर परियोजना को पूरा करने और इस तरह के उत्तम अनुसंधान वाले दस्तावेज पेश करने हेतु किए गए व्यापक प्रयासों के लिए आरआईएस की सराहना की। उन्होंने बताया कि जब यह परियोजना शुरू की गई तो जीएम फसलों के सामाजिक–आर्थिक आकलन पर कोई डेटा या सूचना उपलब्ध नहीं थी और यह मुख्यत; बीटी–कपास के बारे में सुलभ थी। बाद में अनेक संशोधन किए गए और एरोबिक चावल, बीटी–बैंगन, सरसों एवं अन्य फसलों को भी सामाजिक–आर्थिक प्रभाव आकलन के अध्ययन में शामिल किया गया।

यह रिपोर्ट देश के इन सात विशेषज्ञ संस्थानों के कंसोर्टियम द्वारा तैयार की गई है; आरआईएस, गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान (जीआईडीआर), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी

डॉ. अमिता प्रसाद मुख्य भाषण देते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री ज्ञानेश भारती और डॉ. एस.आर. राव।

(एनएएआरएम), सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस)। अध्ययन से पता चला है कि किसान विभिन्न फसलों में बेहतर फसल किस्में चाहते हैं और वे बीज के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं, बशर्ते कि फसल से उनकी लाभप्रदता बढ़ जाएगी। रायचूर में किसान बेहतर उत्पादकता वाली किस्मों के लिए 50 प्रतिशत से भी अधिक का भुगतान करने के इच्छुक थे। कई किसानों का मानना है कि जीएम फसलें उपयोगी साबित हो सकती हैं और सूखा प्रतिरोधी के साथ–साथ बाढ़ प्रतिरोधी फसलें भी विकसित की जानी चाहिए। जीएम फसलें लाभदायक हैं क्योंकि वे कीटनाशकों एवं कीटाणुनाशकों के उपयोग को कम कर देती हैं और इसके परिणामस्वरूप पैदावार भी कहीं अधिक होती है। रसायनों के कम उपयोग का पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ता है क्योंकि मिट्टी की उर्वरता के साथ–साथ भूजल की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। आरआईएस रिपोर्ट में जीएम फसलों पर किसानों की धारणा और लागत के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी गई है।

सामाजिक–आर्थिक निहितार्थों को समझने की जटिलता और व्यापक आंकड़ा की अनुपलब्धता को देखते हुए आरआईएस रिपोर्ट समग्र तरीके से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने और इससे निपटने का एक ईमानदार प्रयास है। यह निश्चित रूप से नीति निर्माताओं और नियामकों के लिए एक उपयोगी संदर्भ या मापदंड के रूप में काम करेगी।

कार्यशाला में विभिन्न उपकरणों या साधनों एवं तरीकों को कवर करने वाले राज्य सर्वेक्षणों और विशेषज्ञों के प्रमुख निष्कर्षों पर प्रस्तुतियां दी गईं। डॉ. आर. एन. पदरिया, आईएआरआई, नई दिल्ली, प्रो. एन. ललिता, जीआईडीआर, अहमदाबाद, डॉ. ए.वी. मंजूनाथ, आईएसईसी, बंगलुरू, प्रो. के. आर. अशोक, टीएनएयू, कोयंबटूर और डॉ. के. श्रीनिवास, एनएएआरएम, हैदराबाद ने प्रस्तुतियां दीं। प्रो. टी. पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, आरआईएस, डॉ. रवि खेत्रपाल, क्षेत्रीय सलाहकार, दक्षिण एशिया, सीएबीआई, प्रो. ई. हरिबाबू, पूर्व उप कुलपति, एचसीयू एवं सहायक सीनियर फेलो, आरआईएस और डॉ. अल्का सिंह, प्रोफेसर, आईएआरआई, नई दिल्ली इस दौरान आयोजित परिचर्चाओं में प्रतिभागी थे।

प्रो. पी. जी. चेंगप्पा, राष्ट्रीय आईसीएआर प्रोफेसर, आईएसईसी और प्रो. संगीता बंसल, प्रोफेसर, जेएनयू ने पहले सत्र की सह–अध्यक्षता की। प्रो. वसंत पी. गांधी, नाबार्ड चेयर प्रोफेसर, आईआईएम–अहमदाबाद और डॉ. रंजिनी वारियर ने दूसरे सत्र की सह–अध्यक्षता की।

कार्यशाला की समाप्ति अध्यक्ष डॉ. टी. हक, अध्यक्ष, भूमि पट्टे पर विशेषज्ञ समूह, नीति आयोग एवं प्रतिष्ठित संकाय, सीएसडी के समापन भाषण के साथ हुई। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कार्यशाला की रिपोर्ट पेश की। डॉ. रंजिनी वारियर, प्रो. पी. जी. चेंगप्पा, राष्ट्रीय आईसीएआर प्रोफेसर, आईएसईसी ने भी समापन सत्र को संबोधित किया। डॉ. के. रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

एसडीजी के लिए तकनीकी सुविधा व्यवस्था

भारत ने प्रमुख साझेदार देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में वैश्विक तकनीकी सुविधा व्यवस्था (टीएफएम) को लांच करने के लिए सतत विकास एजेंडा 2030 के तहत जारी वार्ताओं की हिमायत की है। टीएफएम का उद्देश्य हाल ही में अमल में लाए गए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता सुलभ कराना है। अत; टीएफएम को संचालित करने के लिए संभावित

व्यवस्थाओं और रूपरेखाओं का पता लगाना मुनासिब हो सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने 30 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में इस विषय पर एक परामर्श बैठक बुलाई।

श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री श्याम सरन ने अपने भाषण में बताया कि संयुक्त राष्ट्र की ज्यादातर एजेंसियों का वित्त पोषण पश्चिमी देशों द्वारा किया जाता है, अत; अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करने और तदनुसार नीतियों को प्रभावित करने की आवश्यकता है। उन्होंने वित्त का इंतजाम करने की जरूरत पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था प्रस्तावित की जिसका उद्देश्य किसी विशेष प्रौद्योगिकी को खरीदना, क्षमता निर्माण, एक क्रमबद्ध प्रणाली की स्थापना करना है जिसमें विकसित राष्ट्र कुछ राशि के बदले विकासशील देशों की पहुंच प्रौद्योगिकी तक सुनिश्चित करते हैं और आगे चलकर ये प्रौद्योगिकियां शून्य कीमतों पर अल्प विकसित देशों को मुहैया कराई जाती हैं। इस प्रक्रिया से वैश्विक जनता को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने भारत की भूमिका, जरूरतों और एसडीजी लक्ष्यों एवं चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने एक वैचारिक रूपरेखा, आपस में संबद्ध क्षेत्रों और इंटरनेट आधारित व्यवस्था का उपयोग करते हुए एक फोरम का निर्माण करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने विभिन्न देशों में नवाचार के उपयोग, अनुकूलन और प्रतिकृतियां सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों के बारे में भी चर्चाएं कीं।

सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण देते हुए कहा कि एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनपुट के रूप में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। अत; अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लक्ष्य को प्रौद्योगिकी स्वदेश लाने से संबंधित व्यवस्था की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए। विकासशील देशों के बीच वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों को अवश्य रेखांकित किया जाना चाहिए और उन्हें निश्चित तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर ही जुटाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र के तहत चलती है, तो यह बजटेतर होगी।

डॉ. बलदेव राज, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बंगलुरू ने व्यवस्था निर्माण और सर्वोत्तम समाधानों में नेतृत्व की भूमिका निभाने से संबंधित भारत के फैसले के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने एक मजबूत आंतरिक व्यवस्था करने की आवश्यकता जताई क्योंकि इस देश में इसके लिए पर्याप्त गुंजाइश है। डॉ.

परामर्श बैठक में मौजूद प्रतिभागी।

बलदेव राज के अनुसार, व्यवस्था में विफलता समस्याओं को जन्म देती है और एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें हम किसी चरण में उन्नत होते हैं, जबकि कुछ चरण में विकासशील होते हैं। उन्होंने दूसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया।

श्रीमती साधना रेलिया, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (बहुपक्षीय–क्षेत्रीय), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्त सृजित करने के लिए एक संभावित क्षेत्र के रूप में एसएमई और स्टार्ट–अप पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एसएमई की जरूरतों को ध्यान में रखने वाली नीतियां बनाने का प्रस्ताव रखा। डॉ. साधना रेलिया के अनुसार, हमें पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे विभिन्न उद्यम पूंजी विकल्पों पर गौर करना चाहिए जो धन सृजित कर सकते हैं। उन्होंने आसियान देशों के मलेरिया अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि विश्व भर में इसी तरह के समान सफल उद्यमों की पुनरावृत्ति भारत में की जा सकती है।

डॉ. अजय माथुर, महानिदेशक, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान ने प्रौद्योगिकी जुटाने के मुद्दे का उल्लेख करते हुए ऐसे डिजाइन पर फोकस किया जिसके तहत आपसी हितों का गठबंधन बनाने के लिए इच्छुक देशों–कंपनियों का समूह बनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। उन्होंने अनुकूलन को सुविधाजनक बनाने और पहुंच (आउटरीच) कार्यक्रम के लिए नीतियां बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने इस तरह के प्रासंगिक प्रश्न उठाए कि कोई भी व्यक्ति यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि बड़े पैमाने पर तैनाती व्यवस्था एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित हो जाए और कोई भी व्यक्ति इस विशेषज्ञता को तीसरी दुनिया के देशों को किस तरह उपलब्ध करा सकता है। टीएफएम की संभावित क्रियाविधि पर विशेष जोर देते हुए डॉ. अजय माथुर ने एसएमई को आवश्यक सहायता देने, सेवा प्रदाता द्वारा अनुकूलन को संभव करने और तैनाती से संबंधित सूचनाओं का आदान–प्रदान करने की सिफारिश की। उन्होंने सही साझेदार और वित्त का पता लगाने के मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. अजय माथुर के मुताबिक, मुख्य मुद्दा आईटी आधारित प्लेटफॉर्म का है। उत्तर–दक्षिण साझेदारी को टीएफएम के लिए आदर्श बताया गया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने बहु हितधारकों की ओर से परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए कहा कि क्षेत्रीय आधार पर संगठित होने का निर्णय एसटीआई फोरम में लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित प्रत्येक क्षेत्र को अपनी खुद की तकनीकी विशिष्ट आवश्यकताओं को विकसित करना होगा, अत; क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने एसडीजी के एक बड़ी चुनौती होने के मद्देनजर सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी बैंकों और संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय संस्थानों को आपस में जोड़ने की चुनौती के बारे में सविस्तार बताया। उन्होंने ऐसी व्यवस्थाऐं कायम करने का आह्वान किया जो इन एजेंसियों का आपस में मिलान करेंगी। उन्होंने तकनीकी आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत एपीसीसीटी का उदाहरण दिया।

परामर्श के दौरान खुली परिचर्चा आयोजित की गई। सुश्री मिशिको एनोमोतो, प्रमुख, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियाई–प्रशांत केंद्र, यूएन एस्कैप ने उन प्रयासों पर रोशनी डाली जो प्रौद्योगिकी के विकास, ऑनलाइन प्रौद्योगिकी इंटरफेस के रूप में हस्तांतरण एवं साझा करने और पोर्टल्स का आदान–प्रदान सुनिश्चित करने हेतु किए गए हैं। उन्होंने प्रशांत क्षेत्रों में सुविधा के प्रावधानों और क्षमता निर्माण के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि, वित्त की सीमाओं और निवेश की आवश्यकता को फिर से बाधा के रूप में प्रस्तुत किया गया।

डॉ. पी.के. आनंद, सलाहकार, नीति आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत वित्त पोषण की एक वैकल्पिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए परिचर्चा में योगदान दिया। उन्होंने विकसित देशों की ओर से ऐसे दान का प्रस्ताव रखा जो ओडीए की ओर निर्देशित हों। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई उत्पाद नहीं है और इसे हासिल करने के लिए शुरू में कीमत का भुगतान करना होगा और फिर उसके बाद ही इसे अल्प विकसित देशों के साथ साझा किया जा सकता है। डॉ. आनंद के अनुसार, प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में सार्वजनिक करने के लक्ष्य के साथ–साथ यह भी अवश्य होना चाहिए कि संबंधित देश को कुछ विशेष आर्थिक लाभ हों। चूंकि वित्त पोषण बोद्धिक संपदा से संबंधित है, इसलिए यदि भारत कोई तकनीक खरीदता है तो उसे इसका लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए और उसके बाद ही इसका निर्माण करना चाहिए और फिर इसे कुछ राशि के बदले में अफ्रीका जैसे अल्प विकसित देशों को भेजना चाहिए। उन्होंने इसके लिए 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' की व्यवस्था का प्रस्ताव किया।

प्रो. प्रणव एन. देसाई, जेएनयू ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि प्रौद्योगिकी में केवल हार्डवेयर शामिल नहीं होता है, बल्कि इसमें मानव संसाधन और प्रशिक्षण भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि उपकरण और प्रशिक्षण पर कोई विशेष जोर नहीं है। प्रौद्योगिकी का भी उन्नयन करने की आवश्यकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाले स्वैच्छिक बजट पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर उठाए गए एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू के तहत विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग समस्याएं रहने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर निर्णयों को विकेंद्रित करने की आवश्यकता जताई गई। उन्होंने प्रौद्योगिकी खरीदने के दौरान विकासशील देशों द्वारा दृढ़ता के साथ अपनी पसंद का जिक्र करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी का आकलन करना और शाश्वत समस्याओं पर फोकस करना भी जरूरी है।

प्रो. के.जे. जोसेफ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम, केरल ने पूरे मुद्दे पर एक अलग परिप्रेक्ष्य प्रदान किया और इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि नवाचार के तहत प्रौद्योगिकी को एक सीधी प्रक्रिया से अलग हटकर देखा जाता है। प्रौद्योगिकी में सुविधा के बजाय नवाचार में सुविधा की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नवाचार को विशेष रूप से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के मामले में और विकास के लिए एक कुंजी या समाधान के रूप में पेश किया गया। हालांकि, नवाचार समावेशी नहीं है। उन्होंने खासकर 'आईसीटी' के मामले में दक्षिण–दक्षिण सहयोग में निहित संभावनाओं पर अधिक जोर दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टर) के संदर्भ में विकेन्द्रीकरण, नवाचार मंच का निर्माण करने में भारत द्वारा अहम भूमिका निभाने और बैंक से इतर जाने की जरूरत बताई।

श्री भास्कर बालाकृष्णन ने कारोबारी समुदाय की भूमिका, मजबूत राष्ट्रीय व्यवस्था और विशेषज्ञ समूहों की मौजूदगी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अल्प विकसित देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता के लिए विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया।

डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस ने अपनी प्रस्तुति के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को उत्प्रेरित करने और व्यापक लाभ हेतु ज्ञान को साझा करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रस्तुति के दौरान प्रौद्योगिकी उद्यम को क्रियान्वित करने में वित्तीय बाधाओं पर विस्तार से बताते हुए त्रिस्तरीय मॉडल का प्रस्ताव किया गया।

परामर्श के दौरान टीएफएम को आगे ले जाने वाली नीतियों और वाणिज्यिक फायदे के लिए अभिनव तरीके ढूंढ निकालने पर प्रकाश डाला गया। एसडीजी को व्यावहारिकता से जोड़ने और बहुपक्षीय सहयोग को लक्षित करने पर विशेष जोर देते हुए अनुभव साझा करने को अत्यंत आवश्यक माना गया।

भारत–नेपाल विकास सहयोग को सुदृढ़ बनाना

प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल के बीच सुदृढ़ भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संबंध रहे हैं। हालांकि, विगत कुछ महीनों से इन प्राचीन संबंधों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनका समाधान उन सभी लोगों को निकालने की जरूरत है जो सभी स्तरों पर भारत–नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने और गहन करने की प्रक्रिया में शामिल हैं।

नेपाल की व्यवस्थापिका संसद की विकास संबंधी संसदीय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और राजनयिकों के साथ बातचीत करने के लिए भारत का दौरा किया। आरआईएस ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद–भारत (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारतीय परिषद) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 10 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ एक संवादात्मंक सत्र का आयोजन किया। परामर्श का उद्देश्य यह पता लगाना था कि हम भारत–नेपाल संबंधों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और भारत–नेपाल विकास सहयोग से संबंधित मुद्दों पर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। परामर्श का उद्देश्य यह पता लगाना भी था कि नेपाल के समक्ष मौजूद विकास संबंधी चुनौतियां कौन–कौन सी हैं और इनसे पार पाने में भारत किस तरह मदद कर सकता है।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और श्री श्याम परांडे, सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद–भारत (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारतीय परिषद) ने स्वागत भाषण दिए। श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने विशेष भाषण दिया। माननीय रबीन्द्र अधिकारी, अध्यक्ष, विकास पर संसदीय समिति, नेपाल की व्यवस्थापिका संसद ने बयान दिया।

श्री श्याम सरन ने भारत के विकास सहयोग के बारे में एक संक्षिप्त अवलोकन देते हुए बताया कि यह विगत वर्षों में किस तरह से विकसित हुआ। उन्होंने कहा कि भारत की विकास सहयोग नीति के अभ्युदय में नेपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि मुख्यत; नेपाल ही पहला ऐसा देश था, जिससे स्वतंत्र भारत ने विकास

माननीय रबींद्र अधिकारी परामर्श में बोलते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री श्याम सरन और श्री श्याम परांडे।

सहयोग स्थापित करने के संदर्भ में संपर्क किया था और नेपाल से प्राप्त अनुभवों, चाहे वे सकारात्मक रहे हों या नकारात्मक, से हमारे समग्र विकास सहयोग को तैयार करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही भारत का यह मानना रहा है कि विकासशील देशों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें आपस में बहुत कुछ साझा करना है और इस संबंध में भारत ने नेपाल से जुड़ाव सुनिश्चित किया है चाहे वह जल विद्युत संयंत्रों, हवाई अड्डों के निर्माण या शिक्षा क्षेत्र में ही क्यों न हो। यह विकास सहयोग के उस भारतीय दर्शन को दर्शाता है जिसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के विकास की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण भारत की विकास सहयोग नीति के प्रमुख घटकों में से एक है। लघु विकास परियोजनाएं भारत–नेपाल विकास संबंधों की नई विशेषताएं हैं और भूकंप के बाद की विकास चुनौतियों के मद्देनजर ये समय पर डिलीवरी की बदौलत अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं।

अपने स्वागत भाषण में प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग विभिन्न देशों और विभिन्न भागीदारों के साथ हमारी सहभागिता के मामले में प्रमुख साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। आजादी के शुरुआती वर्षों से ही नेपाल के विशिष्ट रिश्ते रहे हैं।

श्री श्याम परांडे ने कहा कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध भारत और नेपाल को एक साथ बांधते हैं। सच्चाई यही है कि भले ही ये दो राष्ट्र हों, लेकिन आत्मा एक ही है और यही वह खास बात है जो आपसी संबंधों को बिल्कल स्पष्ट कर देती है। इस तरह का बहुत ही खास रिश्ता दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। भारत नेपाल के लोगों, यहां तक कि सशस्त्र बलों के लिए भी खुला है। ऐसी कोई भी सीमा नहीं है। दरअसल, यह खुली सीमा है और यह रिश्ता भविष्य में भी नई मजबूती के साथ जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद लंबे समय से किसी भी तरह की आवश्यकता के वक्त नेपाल से संपर्क साधती आई है।

माननीय रबींद्र अधिकारी ने कहा, 'हमारे बीच खुली बातचीत हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। भारत लंबे समय से नेपाल में छोटे और बड़े आकार की परियोजनाओं को कार्यान्वित करता रहा है। अब तक हम राजनीतिक सहयोग के साथ–साथ इस बारे में ही ज्यादा से ज्यादा बातें करते रहे हैं कि लोकतंत्र की दिशा में हमारी प्रगति में भारत ने किस तरह से समर्थन किया। अब आर्थिक पहलू पर अधिक फोकस करने का समय आ गया है। पारंपरिक संबंधों को अब विकास साझेदारी की ओर ले जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए ही हमने इस विकास समिति का गठन किया।' उन्होंने कहा, 'दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली संसद का दौरा किया था और बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया था। उनका संदेश यही था कि राजनीतिक विकास के साथ–साथ हमें आर्थिक पहलू और कनेक्टिविटी पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। हम उससे प्रेरित हैं और इस पर काम कर रहे हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि सदियों से भारत एवं नेपाल के बीच आर्थिक साझेदारी विकसित हो रही है और भारत नेपाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है।

उन्होंने यह बात रेखांकित की कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत से यह सीखना है कि उसने गुजरात में आए भूकंप के बाद की संकटपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन किस तरह से किया और आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण कैसे हासिल किया, क्योंकि नेपाल पर आपदा का खतरा सदैव मंडराता रहता है। इस यात्रा का दूसरा उद्देश्य यह पता लगाना है कि समय पर विकास परियोजनाओं को कैसे पूरा किया जाए, जो इस समय नेपाल में नहीं हो पा रहा है। उन्होंने एफडीआई के संदर्भ में भारत की विकास सहयोग

परियोजनाओं से कुछ सीखने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस तरह के और अधिक विचार–विमर्श को लेकर आशान्वित हैं।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में ये शामिल थे ; माननीय रबींद्र अधिकारी, माननीय अजय शंकर नायक, माननीया अनिता देवकोटा, माननीया रंजना कुमारी सरकार, माननीय कर्ण बहादुर बीके, माननीय बैजनाथ चौधरी (थारू), माननीया सीता देवी यादव, माननीय तुलसा राणा, माननीय इश्तियाक अहमद खान, माननीय प्रेम बहादुर एले, माननीय जनार्दन ढकाल, माननीय जीवन बहादुर शाही, माननीय महेंद्र यादव, माननीया कल्पना चौधरी, माननीय राजेंद्र अमात्य, श्री घनिंद्र राज चिमौरिया, श्री शिव दत्ता बराल और श्रीमती दीपा कुमारी दुलाल।

अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स बैठक के लिए प्रस्तावना

भारतीय विकास सहयोग मंच ने वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) और हेनरिच बॉल स्टिफतुंग (इंडिया) के साथ मिलकर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स बैठक के लिए प्रस्तावना का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स फ्रेमवर्क के संदर्भ में सिविल सोसायटी के सुचारू कामकाज के लिए एक सहयोगपूर्ण माहौल (सरकार के साथ) का निर्माण करना और उसे व्यवस्थित रूप देना था। बैठक में मौजूदा चुनौतीपूर्ण माहौल (नियामक संबंधी सुधार, घटते संसाधान एवं सीएसओ का क्षमता निर्माण) और ब्रिक्स देशों के बीच संसाधनों के संभावित आदान–प्रदान, इत्यादि के संदर्भ में एक प्रभावकारी सिविल सोसायटी संगठन बनाने के बारे में भी चर्चा की गई। श्री हर्ष जेटली, सीईओ, वाणी, डॉ. एक्सेल हरनीत–सीवर्स, निदेशक, भारत कार्यालय, हेनरिक बॉल फाउंडेशन, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, प्रोफेसर अनुराधा चेनॉय, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू एवं भारतीय विकास सहयोग मंच चेयर और श्री मैथ्यू चेरियन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हेल्पएज इंडिया एवं वाणी चेयर ने सिविल सोसायटी के लिए ब्रिक्स के विषयगत एजेंडे की प्रासंगिकता के बारे में चर्चाएं कीं।

सिविल सोसायटी की ओर से प्रमुख मुद्दों पर देश प्रस्तुतियां इन लोगों ने दीं; श्री अधेमर मिनेइरो, रीब्रिप – रेडेब्रासीलीरापेला इन्टेग्राकोओ डॉस पोवोस (ब्राजीलियन नेटवर्क फॉर पीपुल्स इंटिग्रेशन), ब्राजील, डॉ. ज्योत्स्ना मोहन, वाणी, भारत, सुश्री एलेना टोपोलवा सोल्डुनोवा, द एजेंसी फॉर सोशल इन्फॉरमेशन, रूस, श्री मुहम्मद इब्राहिम, बांग्लादेश एनजीओ संघ (एफएनबी), बांग्लादेश, श्री झाओ डैक्सिंग, चीन एसोसिएशन फॉर एनजीओ कोऑपरेशन, चीन, श्री शेल्डन ग्राकोन मैगार्डी, दक्षिण अफ्रीका और श्री कृष्ण गौतम, एनजीओ फेडरेशन ऑफ नेपाल।

वित्तीय सुधारों, गरीबी एवं विषमता, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा सहित अनेक ब्रिक्स विषयगत मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान नव विकास बैंक की निगरानी पर भी एक सत्र आयोजित किया गया। बैठक के दौरान एसएससी ढांचे के अंतर्गत सहायता के प्रवाह, अफ्रीका में भारत के अनुदान एवं निवेश और ब्रिक्स में महिला–पुरुष समानता को मुख्यधारा में लाने से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

उभरती शक्तियों पर भारतीय थिंक–टैंक संवाद

ब्रिक्स शैक्षणिक फोरम के दौरान आरआईएस और ओआरएफ ने 18–19 सितंबर 2016 को गोवा में 'उभरती शक्तियों पर भारतीय थिंक–टैंक संवाद' का आयोजन किया। यह आयोजन अमेरिकन सेंटर, सेंटर फॉर राइजिंग पावर्स एंड ग्लोबल

डेवलपमेंट (सीआरपीडी), इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम (ईपीएफ), जर्मन कोऑपरेशन, ड्यूश गेसेल्सीचौफ्ट फर इंटरनेशनले जुसाममेनारबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच, एमर्जिंग मार्केट सस्टेनेबिलिटी डायलॉग्स (ईएमएस) के साथ साझेदारी में किया गया। श्री संजय जोशी, निदेशक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिए। श्री समीर सरन, उपाध्यक्ष, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इस अवसर पर संचालक थे।

इस संवाद के दौरान व्यापार, विकास, सुरक्षा और स्थिरता के नजरिए से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इंटरनेट के बढ़ते महत्व पर चर्चा की गई। दो केंद्रीय वैश्विक रुझानों का पता लगाया गया; पहला, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नीतिगत थिंक–टैंक नियम–प्राप्तकर्ताओं के बजाय नियम–निर्माताओं में कैसे तब्दील हो रहे हैं और दूसरा, डिजिटल विस्तार के कारण बड़े–बड़े वैश्विक गवर्नेंस सवाल कैसे उठ रहे हैं। सत्रों के दौरान इन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया; उभरती अर्थव्यवस्थाएं, भू–अर्थशास्त्र एवं वैश्विक गवर्नेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य, सतत विकास का वित्तपोषण, 20वीं सदी की परियोजनाओं को पूरा करना; उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने वैश्विक विकास को समुचित स्वरूप प्रदान करने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के थिंक–टैंकों की भूमिका पर प्रकाश डाला और इसके साथ ही समापन भाषण भी दिया। श्री संजय जोशी ने भी समापन सत्र को संबोधित किया।

वृद्धि, संकट और फिर से बेहतरी का दौर

वैश्विक अर्थव्यवस्था को अक्सर कुछ समय के लिए तगड़े झटके लगते रहते हैं और ऐसी स्थिति में उसे भारी उथल–पुथल एवं तेज उतार–चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संकट के अनेक दौर आए हैं और बीच–बीच में अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आती रही है। यही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तेजी यानी बूम के दौर भी आए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि वित्तीय बाजारों में जो भी कुछ खास होता है उसका महत्वपूर्ण असर अक्सर वास्तविक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसी तरह वास्तविक अर्थव्यवस्था के अहम घटनाक्रमों का प्रभाव अक्सर वित्तीय बाजारों पर भी पड़ता है। इन मुद्दों को अच्छी तरह समझने के लिए आरआईएस ने 7 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में 'वृद्धि, संकट और फिर से बेहतरी के दौर' पर पैनल परिचर्चा का आयोजन किया, ताकि पर्याप्त नीतिगत कदम उठाए जा सकें। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। प्रो. रथिन राय, निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली ने सत्र की अध्यक्षता की। प्रतिष्ठित परिचर्चा में मुख्य वक्ता थे: डॉ. श्वेता सी. सक्सेना, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, अनुसंधान विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी.सी., श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, परामर्शदाता संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड और प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस।

प्रौद्योगिकी और निवेश में भारत–जापान सहयोग

एक जापानी प्रतिनिधिमंडल ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र की संभावनाओं एवं बाधाओं पर चर्चा करने और निवेश, प्रौद्योगिकी एवं विभिन्न संबंधित मुद्दों के संदर्भ में भारत–जापान सहयोग बढ़ाने के लिए 29 अगस्त 2016 को आरआईएस का दौरा किया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जिसकी अगुवाई डॉ. तेत्सुजी कवामुरा, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व डीन,

होसेई विश्वविद्यालय और प्रोफेसर तोशीयुकी बाबा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विभाग, होसेई विश्वविद्यालय–ग्रेजुएट विश्वविद्यालय ने की।

प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में ये शामिल थे; डॉ. मिवा तनाका, शोधकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एवं प्रबंधन संस्थान, डॉ. शिनिया ओरिहाशी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर, तोहोकु गकुइन विश्वविद्यालय, प्रो. इत्सुयजिरोयू योकोता, निप्पन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉ. मोतोयोशी सोनो (युआन झिजिया), अर्थशास्त्र संकाय, रिस्शो विश्वविद्यालय, प्रो. (डॉ.) तात्सुहिको आइजावा, शिबाउरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉ. यासुहिको कवाबे, कार्यक्रम निदेशक, बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बिजनेस मुख्यालय, ह्यूमनिटी एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवैंस कॉरपोरेशन, डॉ. ईत्सुजिरो योकोता, शैक्षणिक समन्वयक, जापान डाई एंड मोल्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन, डॉ. तोमोया कनेमुरा, प्रोफेसर, मत्सुमोतो विश्वविद्यालय, डॉ. यासुहिको कवाबे, एनपीओ एशियन डाई एंड मोल्ड फोरम के निदेशक, होसेई विश्वविद्यालय और डॉ. कोजी सेरिता, अर्थशास्त्र संकाय, रिस्शो विश्वविद्यालय। आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक और प्रो. राम उपेंद्र दास ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की।

भारत–बांग्लादेश सहयोग

श्री फखरूल इमाम की अगुवाई में माननीय सांसदों के एक बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने 3 अगस्त 2016 को भारत–बांग्लादेश सहयोग पर संकाय के साथ एक संवादात्मक सत्र के लिए आरआईएस का दौरा किया।

श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने अपने विशेष भाषण में भारत–बांग्लादेश सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और भारत के सहयोग कार्यक्रम में बांग्लादेश की विशेष अहमियत के बारे में चर्चा की। अन्य माननीय सदस्यों में ये शामिल थे; श्री जियाउद्दीन अहमद (बबलू), सांसद चटगांव, अधिवक्ता मोहम्मद अल्ताफ अली, सांसद बोगरा–2, श्री पीर फजलुर रहमान, सांसद, श्री मोहम्मद आमिर हुसैन भुइयां, सांसद और श्री नूरुल इस्लाम मिलॉन।

आरआईएस की ओर से प्रो. टी. सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, डॉ. बीना पांडे, रिसर्च एसोसिएट, डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर और डॉ. प्रियदर्शी दास, रिसर्च एसोसिएट ने भी प्रतिनिधिमंडल के साथ संवादात्मक सत्र में भाग लिया। डॉ. जोयीता भटाचार्जी, फेलो, दक्षिण एशिया कार्यक्रम, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) और सुश्री सबा इश्तियाक, अनुसंधान सहायक, ओआरएफ भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

दक्षिण–दक्षिण और विकास सहयोग में निजी क्षेत्र की भूमिका

आरआईएस ने द एशिया फाउंडेशन, कोरिया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (केडीआइ) और वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) के सहयोग से नई दिल्ली में 10–11 अगस्त 2016 को 'एशियाई विकास सहयोग में भागीदार; निजी क्षेत्र की भूमिका' विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य दक्षिण–दक्षिण और विकास सहयोग में निजी क्षेत्र के कार्यकलापों की भूमिका के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना था।

श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक आरआईएस 'विकास सहयोग के प्रति एशियाई दृष्टिकोण (एएडीसी)' पर संवाद के दौरान प्रतिभागियों के साथ।

सम्मेलन का शुभारंभ श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस, डॉ. तेजोंग किम, प्रबंध निदेशक, केडीआई स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, कोरिया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (केडीआई), डॉ. गॉर्डन हेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, द एशिया फाउंडेशन और श्री हर्ष जेटली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया के स्वागत भाषणों से हुआ। प्रतिभागियों ने दक्षिण–दक्षिण एवं विकास सहयोग में निजी क्षेत्र के कार्यकलापों की भूमिका, दक्षिण–दक्षिण और विकास सहयोग के प्रति निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण, भारत की ओर से अभिनव दृष्टिकोण और विकास के लिए निजी क्षेत्र की साझेदारी में नई सीमाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। सम्मेलन की समाप्ति प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, डॉ. तेजोंग किम, डॉ. गॉर्डन हेन और श्री हर्ष जेटली के समापन भाषणों से हुई।

बड़ी संख्या में प्रख्यात शिक्षाविदों, विद्वानों, प्रमुख शोध संस्थानों के विषय विशेषज्ञों, विदेशी राजनयिकों, उच्च रैंकिंग वाले सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों , भारत एवं विदेश के उद्योग जगत और मीडिया जगत के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

भारत में प्रौद्योगिकी और विज्ञान नीति को नया स्वरूप

आरआईएस ने 15 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी के हाथों 'ए लाइफटाइम ऑफ मॉउल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस पॉलिसी इन इंडिया' नामक पुस्तक के विमोचन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। माननीय उपराष्ट्रपति ने इस पुस्तक (वॉल्यूम) का विमोचन किया और इसे प्रो. अशोक पार्थसारथी को पेश किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने यह बात रेखांकित की कि हमारे देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियां तैयार करते समय जिस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा की जाती रही है वह हमारे विश्वविद्यालयों का विकास, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान की अहम आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) नीतियां तैयार करते समय विश्वविद्यालयों की उस केंद्रीय भूमिका को अवश्य ही ध्यान में रखा जाएगा जो वे राष्ट्र के नवाचार और नवविचार केंद्रों के रूप में निभा सकते हैं। चेन्नई स्थित एम एस स्वामीनाथन

रिसर्च फाउंडेशन के एमेरिटस अध्यक्ष प्रो. एम एस स्वामीनाथन, बंगलुरू स्थित उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय केंद्र के एमेरिटस प्रोफेसर रोद्दम नरसिम्हा (अनुपस्थिति में), नई दिल्ली स्थित जलवायु परिवर्तन अनुसंधान संस्थान की कार्यकारी निदेशक डॉ. मालती गोयल, प्रो. अशोक पार्थसारथी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस पुस्तक को संपादित किया है और इसमें प्रख्यात हस्तियों ने भी योगदान दिया है।

एशिया में सेवा व्यापार और नियामकीय सुधारः एक व्यापक दृष्टिकोण की तलाश में

आरआईएस में स्थापित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने टोक्यो स्थित एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) और आईएमआई कोलकाता के सहयोग से कोलकाता में 26–27 अक्टूबर 2016 को 'एशिया में सेवा व्यापार और नियामकीय सुधारः एक व्यापक दृष्टिकोण की तलाश में' नामक विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला सेवा व्यापार में मौजूद बाधाओं से संबंधित मुद्दों सहित एशिया में सेवा व्यापार की वर्तमान स्थिति, घरेलू नियमों, नियामकीय ढांचे, सेवा व्यापार से जुड़े सुधारों और वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर उनके प्रभाव पर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिहाज से एक उत्तम अवसर थी। कार्यशाला में भाग लेने वालों में वरिष्ठ नीति निर्मातागण, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सेवा व्यापार से जुड़े निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों के बीस अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। आईएमआई– कोलकाता के निदेशक प्रो. अरिंदम बानिक ने स्वागत भाषण दिया, एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) के डिप्टी डीन डॉ. बोकवान यू ने आरंभिक भाषण दिया, आरआईएस में स्थापित एआईसी के प्रोफेसर/समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने भी भाषण दिया और एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) के प्रमुख (प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण) डॉ. अलादीन डी. रिल्लो ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। एडीबीआई, आईडीई–जेट्रो, अपेक सचिवालय, नैस्कॉम, आईएमआई कोलकाता, आईसीआरआईईआर, इत्यादि के प्रख्यात विद्वानों और प्रोफेशनल ने विशेष व्याख्यान दिए। डॉ. प्रबीर डे ने 'सेवा व्यापार की बाधाओं को दूर करने एवं व्यापार प्रवाह पर उनके असर' पर एक प्रस्तुति दी और 'सेवा व्यापार में महत्वपूर्ण मुद्देः डिजिटल सेवाएं एवं ई–कॉमर्स' विषय पर आयोजित एक सत्र की अध्यक्षता की। प्रो. अरिंदम बानिक और डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

विकास की उभरती मिसाल के रूप में ब्लू इकोनॉमी

ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) की अवधारणा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण बन गई है। आईओआरए और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आरआईएस ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों में काफी सक्रियता के साथ भाग लेता रहा है। संस्थान ने कई प्रकाशन भी प्रस्तुत किए हैं और इसने हाल के महीनों में ब्लू इकोनॉमी से जुड़े विभिन्न विषयों पर सम्मेलन आयोजित किए।

इस तरह के प्रयासों को जारी रखते हुए आरआईएस ने 29 दिसंबर 2016 को 'विकास की उभरती मिसाल के रूप में ब्लू इकोनॉमी' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रो. वी.एन. अत्री, चेयर, हिंद महासागर अध्ययन, हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए), मॉरीशस विश्वविद्यालय ने विषयगत प्रस्तुति दी। राजदूत राजीव भाटिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन

चतुर्वेदी ने आरंभिक भाषण दिया और आरआईएस के प्रोफेसर डॉ. एस. के. मोहंती ने विशेष भाषण दिया। आईडीएसए की सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉ. रुचिता बेरी ने विशेष परिचर्चा में भाग लिया। इसके बाद आयोजित की गई खुली चर्चा में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसे प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आ रही है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। समुद्री संसाधनों की बदौलत उत्पादक और टिकाऊ विकास अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला सृजित करने की जो भरपूर क्षमता ब्लू इकोनॉमी में निहित है, उसी से यह संभव हो पा रहा है। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि (एक्वाकल्चर), अक्षय समुद्री ऊर्जा, समुद्री बंदरगाहों एवं शिपिंग और अपतटीय हाइड्रोकार्बन एवं समुद्र तल में मौजूद खनिजों के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं और अवसर हैं।

एसडीजी एवं टिकाऊ विकास के प्रति समेकित दृष्टिकोण

आरआईएस ने 27 से 29 दिसंबर, 2016 को तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में आयोजित इंडियन इकोनोमिक एसोसिएशन के 99वें वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर ' एसडीजी एवं टिकाऊ विकास के प्रति समेकित दृष्टिकोण' पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। यह सत्र 28 दिसंबर, 2016 को आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान हाल में अंगीकृत वैश्विक टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की पृष्ठभूमि में टिकाऊ विकास के नए एवं उभरते आयामों और उसके द्वारा भारतीय मॉडल विकास की चुनौतियों और अवसरों की खोज करने पर विचार विमर्श किया गया और निम्नलिखित मुद्दों पर गौर किया गया : नया विकास मॉडल–विकास वर्णन में आदर्श बदलाव, विकास की एक समेकित दृष्टि–स्वास्थ्य एवं अन्य एसडीजी, टिकाऊ विकास को मापना एवं औद्योगिकीकरण एवं रोजगार सृजन के जरिये टिकाऊ आर्थिक विकास। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के पूर्व निदेशक प्रोफेसर पुलिन नायक; आरआईएस के विजिटिंग फेलो प्रो. टी.सी. जेम्स; यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के इकोनोमेट्रिक्स विभाग के प्रमुख प्रो. टी लक्ष्मणसामी; एवं आरआईएस के असिस्टैंट प्रोफेसर डा. सब्यसाची साहा ने इन विषयों पर प्रस्तुतिकरण किए। प्रस्तुतिकरण के बाद अन्य प्रतिभागियों के साथ एक संवादमूलक सत्र आयोजित किया गया।

इंडोनेशिया के विशिष्टमंडल की यात्रा

इंडोनेशिया के एक शिष्टमंडल ने 14 नवंबर, 2016 को आरआईएस संकाय सदस्यों के साथ एक संवादमूलक सत्र के लिए आरआईएस की यात्रा की। राष्ट्रीय विकास योजना मंत्रालय के विदेश राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग निदेशालय, एसएसटीसी के निदेशक श्री प्रियांतो रोहमतुल्लाह ने इस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों में : कृषि मंत्रालय के कृषि मानव संसाधन विकास एजेंसी के सीनियर प्लानर श्री डाइडिंग हरदेदी; कृषि मंत्रालय के विदेश सहयोग केंद्र की कोपरेशन मैटेरियल्स कंपोजर श्रीमती हपसारी श्री सुसांति; राष्ट्रीय विकास योजना मंत्रालय के विकास आवंटन निधियन निदेशालय की युवा प्लानर श्रीमती वुलंदरी; वित मंत्रालय के ऋण एवं अनुदान निदेशालय के श्री इमाम रुसदियांत्रो; एसएसटीसी के जरिये टिकाऊ आर्थिक विकास के कम्युनिकेशन एवं मोनिटरिंग एसोसिएट सिटी अमीनाह स्याहिदाह और आईएफएडी, इंडिया कंट्री रिप्रजेंटेटिव सुश्री राशा उमर शामिल थी।

आरआईएस की तरफ से महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. एस. के. मोहंती, प्रो. राम उपेंद्र दास; विजिटिंग फेलो प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती; विजिटिंग फेलो डा. टी.

पी. राजेंद्रन; विजिटिंग फेलो प्रो. टी.सी. जेम्स; रिसर्च एसोसिएट डा. बीना पांडेय एवं सहायक प्रोफेसर डा. सब्यसाची साहा ने विचार विमर्शों में भाग लिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विमुद्रीकरण

आरआईएस ने 15 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विमुद्रीकरण पर एक परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किया। एनआईपीएफपी के निदेशक डा. रथिन रॉय एवं पहले इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य तथा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), नई दिल्ली के सीनियर फेलो डा. राजीव कुमार इसके सह–अध्यक्ष थे। विचार विमर्श आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ आरंभ हुआ। आरआईएस के सलाहकार श्री सुभोमोयी भट्टाचार्य ने विषयगत प्रस्तुति दी। इसके बाद एक खुली चर्चा आयोजित हुई जिसमें विख्यात विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान रूप में विमुद्रीकरण भारत द्वारा अब तक का सबसे गंभीर कदम और सबसे बड़ा सूक्ष्म आर्थिक (माइक्रोइकोनोमिक) कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह विश्वास की एक बड़ी छलांग रही है। इसका अन्य विकासशील देशों के लिए भी काफी महत्व है जिनके लिए इसी प्रकार के सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता हो सकती है।

ईआरआईए शिष्टमंडल की यात्रा

अपने अनुसंधान एवं प्रचार कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए, आरआईएस दुनिया भर में अपने सहयोगी अनुसंधान संस्थानों के साथ नियमित रूप से वार्ता आयोजित करता है। इनमें कई अन्य मुद्दों के अतिरिक्त, वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, एसडीजी, विकासशील देशों के बीच सहयोग, विकास सहयोग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आरआईएस की हमेशा से ही जकार्ता के ईआरआईए के साथ एक विशेष रूप से, भारत की 'पूरब की ओर देखो' नीति पर परस्पर लाभदायक अनुसंधान साझीदारी रही है।

इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, आरआईएस ने 21 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक के लिए जकार्ता के ईआरआईए से टीम–सदस्यों को आमंत्रित किया। शिष्टमंडल के सदस्यों में सीओओ एवं महानिदेशक श्री इजुरु कोबयाशी; महानिदेशक सुश्री अनीता प्रकाश; वरिष्ठ ऊर्जा अर्थशास्त्री श्री वेंकटचलम अंबुमोझी; एवं अर्थशास्त्री श्री यासिशी यूएकी शामिल थे। महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी; प्रो. एस.के.मोहंती एवं प्रो. राम उपेंद्र दास के नेतृत्व में आरआईएस टीम ने परामर्श बैठक में हिस्सा लिया।

डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक एजेवेडो ने आरआईएस के सत्र को संबोधित किया

विश्व व्यापार संगठन में कृषि और मत्स्य पालन से संबंधित वार्ताएं सदा ही भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं क्योंकि इसकी विशाल आबादी इन क्षेत्रों पर निर्भर है। आरआईएस इस तरह के विचार–विमर्श में सबसे आगे रहा है। अपने इन अथक प्रयासों के तहत आरआईएस ने नई दिल्ली में 9 फरवरी, 2017 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के महानिदेशक श्री रॉबर्टो एजेवेडो के साथ एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के आरंभिक संबोधन के साथ सत्र का शुभारंभ हुआ। डॉ. राम उपेंद्र दास, प्रोफेसर, आरआईएस, डॉ. मुकेश भटनागर, प्रोफेसर एवं डॉ. सचिन कुमार शर्मा, सहायक प्रोफेसर (ये दोनों ही डब्ल्यूटीओ

अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की ओर से), डा. रानजा सेनगुप्ता, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क, डॉ. अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय सह–संयोजक, एसजेएम, सुश्री दीपा सिन्हा, भोजन के अधिकार का अभियान , श्री युद्धवीर सिंह, महासचिव, किसान आंदोलन की अखिल भारतीय समन्वय समिति, डॉ. विजू कृष्णन, संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा ने भारत एवं अन्य विकासशील देशों से संबंधित डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर अपने–अपने संक्षिप्त विचार पेश किए। अपने जवाब में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने अनसुलझे मुद्दों पर आम सहमति कायम करने के लिए सदस्य देशों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाने का आह्वान किया।

(बाएं से चौथे) श्री रॉबर्टो एजेवेडो, महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन संवादात्मक सत्र में बोलते हुए।

एसडीजी पर मंत्रणाः सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) वाले वर्ष 2030 के सतत विकास एजेंडे में विकास के तीन आयामों अर्थात सामाजिक, आर्थिक और स्थायित्व को कवर किया गया है। भारत आर्थिक प्रगति, समावेश और स्थायित्व के कई क्षेत्रों में खुद के लिए पहले ही कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर चुका है। इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन के साथ–साथ एसडीजी के साथ तालमेल बैठाने में भी राज्य सरकारों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

पिछले कई महीनों के दौरान आरआईएस ने एसडीजी पर राष्ट्रीय स्तर की मंत्रणा आयोजित करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। इस श्रृंखला

डॉ. अरविंद पनगड़िया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग मुख्य भाषण देते हुए।

में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) ने आरआईएस और नीति आयोग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 23 फरवरी, 2017 को एसडीजी 7 – 'सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा' पर राष्ट्रीय स्तर की मंत्रणा का आयोजन किया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. अशोक कुमार जैन, सलाहकार (ग्रामीण विकास), नीति आयोग, डॉ. अनिल कुमार जैन, अपर सचिव, नीति आयोग, डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, डॉ. अजय माथुर, महानिदेशक, टेरी और श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग ने भी उद्‌घाटन सत्र को संबोधित किया। सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सर्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, एनडीसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि और ऊर्जा दक्षता पर चर्चाएं भी कार्यक्रम में शामिल थीं।

कंपनियों की निर्यात संबंधी क्षमता में वित्तीय पहुंच और वित्तीय विकास की भूमिका

आरआईएस की ब्रेकफास्ट संगोष्ठी श्रंखला के तहत 'कंपनियों की निर्यात संबंधी क्षमता में वित्तीय पहुंच एवं वित्तीय विकास की भूमिकाः एशिया–प्रशांत से अनुभवजन्य साक्ष्य' पर एक संगोष्ठी 3 जनवरी, 2017 को आरआईएस में आयोजन की गई थी। श्री टी. सी.ए. रंगनाथन, पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। आरआईएस स्थित आसियान इंडिया सेंटर के सलाहकार डॉ. दुरायराज कुमारसामी इस अवसर पर वक्ता थे और उन्होंने इस विषय पर अध्ययन का यह निष्कर्ष पेश किया कि 'वित्त और वित्तीय विकास तक पहुंच आखिरकार कैसे एशिया–प्रशांत देशों में कंपनियों की निर्यात करने संबंधी क्षमता को प्रभावित करती है।' 'विश्व बैंक उद्यम सर्वेक्षण' से प्राप्त कंपनी स्तर के आंकड़ों का उपयोग करने पर अध्ययन में यह पाया गया कि वित्त तक पहुंच इन कंपनियों की निर्यात करने की क्षमता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र में विकास होने से कंपनियों द्वारा निर्यात बाजार में कदम रखने की संभावना बढ़ जाती है। वित्तीय विकास का प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण है। अध्ययन में पाया गया कि वित्त तक पहुंच, वित्तीय विकास और स्थान विशेष का जो पारस्परिक प्रभाव पड़ता है उससे कंपनियों की निर्यात करने संबंधी क्षमता पर स्थान विशेष का नकारात्मक असर कम हो जाता है। अध्ययन से पता चला है कि वित्त तक पहुंच बढ़ने और वित्तीय विकास (बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि) होने की स्थिति में राजधानी या मुख्य शहरों से दूर रह कर अपना परिचालन करने वाली कंपनियों को निर्यात बाजार में प्रवेश करने में आसानी होगी। अध्ययन में इस बात का समर्थन किया गया है कि वित्तीय विकास को मजबूत करने से कंपनियों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही अध्ययन में दूरस्थ स्थानों के लिए कंपनियों की निर्यात गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने हेतु वित्त तक पहुंच की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है।

नीली अर्थव्यवस्था पर उभरते परिपेक्ष्य

नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) पर अपने अनुसंधान कार्यक्रम के तहत आरआईएस ने हिंद महासागर के लिए ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं ' पर भी एक व्यापक रिपोर्ट पेश की थी। आरआईएस वर्ष 2015 से ही 1.5 ट्रैक मोड के तहत 'आईओआरए' क्षेत्र के लिए ब्लू

इकोनॉमी पर संवाद का संचालन कर रहा है। चूंकि ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधन भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आरआईएस का लक्ष्य ब्लू इकोनॉमी फोरम (बीईएफ) बनाकर अपने कार्यक्रम को समेकित करना है, ताकि अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करना, वाद–विवाद, अनुसंधान करना एवं जागरूकता बढ़ाना और शोध निष्कर्षों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना संभव हो सके। इस संबंध में आरआईएस ने 23 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में 'ब्लू इकोनॉमी पर उभरते परिप्रेक्ष्य' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने विचार पेश किए और आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी. एस. शेषाद्री ने इसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर *'ब्लू इकोनॉमी की संभावना को उन्मुक्त करना'* नामक संक्षिप्त नीतिगत पुस्तिका भी पेश की गई थी। आरआईएस के प्रोफेसर डॉ. एस. के. मोहंती ने हाल ही में आरआईएस में स्थापित किए गए ब्लू इकोनॉमी मंच (बीईएफ) के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।

ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं को उन्मुक्त करने पर संक्षिप्त नीतिगत पुस्तिका पेश करते हुए।

एशिया–प्रशांत व्यापार और निवेश रिपोर्ट

आरआईएस ने 16 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में *'एशिया–प्रशांत व्यापार और निवेश रिपोर्ट (एपीटीआईआर) 2016: मुख्य निष्कर्ष एवं क्षेत्र के लिए निहितार्थ'* पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। विश्व व्यापार संगठन में भारत के पूर्व राजदूत जयंत दासगुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की। बैंकाक स्थित संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के व्यापार, निवेश और नवाचार प्रभाग की निदेशक डा. सुसान एफ. स्टोन मुख्य वक्ता थीं। उनकी प्रस्तुति के बाद एक खुली परिचर्चा आयोजित की गई।

चाइनीज पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के प्रतिनिधिमंडल साथ संवाद

चाइनीज पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (सीपीआईएफए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 फरवरी, 2017 को एक संवादात्मक सत्र के लिए आरआईएस का दौरा किया। चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में ये शामिल थे: चाइनीज पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (सीपीआईएफए) के कार्यकारी उपाध्यक्ष

राजदूत लू शुमिन, सीपीआईएफए के उपाध्यक्ष राजदूत पेंग केयू, कोलकाता के पूर्व महावाणिज्य दूत श्री माओ सिवेई, सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज चाइना रिफॉर्म फोरम के निदेशक प्रोफेसर एम.ए. जियाली, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज स्थित नेशनल इंस्टी्ट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के दक्षिण एशिया अध्ययन के संपादकीय निदेशक श्री वाई.ई. हैइलिन, एशियाई, अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिकी मामलों के विभाग (सीपीआईएफए) की निदेशक सुश्री शेन जून, चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च एसोसिएट डा. जेग एइपिंग और सीपीआईएफए की स्टाफ सुश्री लिन मिनस्क्यू। विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की ओर से रिसर्च फेलो डॉ. संजीव कुमार उपस्थित थे। आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल में ये शामिल थेः प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, डॉ. एस.के. मोहंती, प्रोफेसर, डॉ. राम उपेंद्र दास, प्रोफेसर, प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, डा. टी.पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, डॉ. बीना पांडे, रिसर्च एसोसिएट, डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, डॉ. प्रियदर्शी दास, रिसर्च एसोसिएट, डॉ. अमित कुमार, रिसर्च एसोसिएट और डॉ. सुशील कुमार, सलाहकार।

उभरता भारत 2030

सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय, आरआईएस, नीति आयोग और भारत एवं भूटान के लिए संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र ने 15—17 फरवरी, 2017 को पुणे में 'उभरता भारत 2030: सशक्त विकास लक्ष्यों के लिए रणनीतियां' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। परिचर्चाओं के विषयों में ये शामिल थेः गरीबी एवं विषमताएं, शिक्षा और महिला—पुरुष स्थिति, टिकाऊ शहर, नौकरियां एवं आर्थिक विकास, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने सत्र के दौरान 'लक्ष्यों के लिए साझेदारी' पर प्रस्तुति दी।

पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता की पुनर्संरचना

भारतीय विकास सहयोग मंच की मासिक संगोष्ठी श्रंखला के तहत 22 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में 'पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता की पुनर्संरचनाः नए अवसर और चुनौतियां' विषय पर डॉ. एम्मा मौडस्ले की एक प्रस्तुति आयोजित की गई। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत संबोधन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। श्री दिनकर अस्थाना, संयुक्त सचिव (डीपीए— II), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने इसकी अध्यक्षता की।

डॉ. मौडस्ले ने पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता के अंतर्निहित घरेलू एवं बाह्य आधारों को समझाया और इसके साथ ही इस तथ्य की ओर संकेत किया कि संबंधित नीति निर्माण को 'गैर तर्कसंगत' प्रभावों से अछूता नहीं रखा जा सकता है। इस वक्ता के मुताबिक, उत्तर—दक्षिण विभाजन की होड़ दरअसल अपनी समस्तं विविधता में निजी क्षेत्र को शामिल करने के साथ—साथ सहायता संबंधी बहस का एक सकारात्मक आकलन भी है। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव का भी उल्लेख किया जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बजाय अब वित्त (निवेश बैंकिंग, बीमा, आर्बिट्रेज, परिसंपत्ति प्रबंधन, उद्यम पूंजी, मुद्रा व्यापार, इत्यादि) की ओर उन्मुख होती जा रही है। उन्होंने इस बदलाव को 'वित्तीयकरण' की संज्ञा प्रदान की है। 'वित्तीयकरण' के विभिन्न स्तरों की भी व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था और माइक्रोफाइनेंस के रूप में की गई। उन्होंने विभिन्न विषयों जैसे कि 'विदेशी सहायता' से 'विकास वित्त' की ओर कदम, वित्तीय हितों एवं संस्थानों की सूक्ष्म एवं वृहद परिधियों के बीच

संबंध और द्विपक्षीय दानदाताओं के बीच रुझान पर परिचर्चाओं के जरिए फिलहाल गहराते वित्तीयकरण–विकास गठजोड़ के बारे में विस्तार से बताते हुए अपनी प्रस्तुति समाप्त की।

भारत–सिंगापुर सीईसीए रिपोर्ट

आरआईएस स्थित एआईसी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से 27 मार्च 2017 को नई दिल्ली में *'भारत–सिंगापुरः व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)'* रिपोर्ट जारी करने का कार्यक्रम आयोजित किया। सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने 'भारत–सिंगापुरः व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)' नामक एआईसी–आरआईएस रिपोर्ट जारी की, जिसे आरआईएस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. वी.एस. शेषाद्री ने लिखा है।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री श्रीकांत सोमानी, सदस्य, सीआईआई राष्ट्रीय परिषद और चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, सोमानी सिरामिक्स लिमिटेड ने आरंभिक भाषण दिया। वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने विशेष भाषण दिया। राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने भी विशेष भाषण दिया। सिंगापुर उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त डॉ. एडमंड चिया और नास्कॉम के निदेशक श्री गगन सभरवाल ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया।

डॉ. वी.एस. शेषाद्री ने रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति दी। इस रिपोर्ट में सीईसीए और आसियान–भारत एफटीए के परिप्रेक्ष्य में भारत–सिंगापुर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर गौर किया गया है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ हैं। एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय *भारत–सिंगापुरः व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते सीईसीए* पर रिपोर्ट जारी करती हुईं।

सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के छात्रों के साथ बैठक

पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 32 छात्रों के एक समूह ने 24 फरवरी, 2017 को एक संवादात्मक सत्र में भाग लेने के लिए आरआईएस का दौरा किया। समूह की अगुवाई एसएसआईएस के निदेशक डॉ. शिवाली लवाले ने की

थी। प्रो.सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और डॉ. एस.के. मोहंती, प्रोफेसर, आरआईएस ने छात्रों के इस समूह को आरआईएस की अनुसंधान गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

'पारंपरिक चिकित्सा' पर मंत्रणा

आरआईएस ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर 19 जनवरी 2017 को 'व्यापार, मानक और बोद्धिक संपदा सहित पारंपरिक चिकित्सा' से संबंधित मुद्दों पर एक रणनीति विकसित करने के लिए हितधारकों से मंत्रणा का आयोजन किया। मंत्रणा का उद्देश्य बोद्धिक संपदा और अन्य नियामक उपायों सहित उन वैश्विक घटनाक्रमों पर नियमित चर्चा एवं निगरानी करने और रणनीतियां बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार करना था जिनसे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आईटीएम) की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसका एक अन्य उद्देश्य विश्व भर में आईटीएम तक पहुंच बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने एवं पारंपरिक चिकित्सा पर और अधिक शोध अध्ययन सुनिश्चित करने के तरीकों पर गहन चर्चा करना था। इसमें उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों एवं संगठनों और सिविल सोसायटी के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और आईटीएम उत्पादों के व्यापार के मार्ग में मौजूद तकनीकी बाधाओं के बारे में बताया। श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश के पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने और स्वास्थ्य के लिए इस ज्ञान का निरंतर उपयोग करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। आयुष मंत्रालय में सचिव श्री अजीत एम शरण ने अपने आरंभिक भाषण में पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच के मामले में लाभ साझा करने से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आईटीएम और अन्य पारंपरिक ज्ञान के विकास पर व्यापक विचार विकसित करने के लिए सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण को एकीकृत करने हेतु सार्थक बहस का आह्वान किया। आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अनिल कुमार गनेरीवाला ने योग के वैश्वीकरण के बारे में बताया और इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) में भारत का रुख तय करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। आयुष मंत्रालय में वैज्ञानिक–4 डॉ. गजाला जावेद ने आयुष प्रणालियों

श्री अजीत एम. शरण, सचिव, आयुष मंत्रालय उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए।

के वैश्वीकरण के साथ–साथ इन प्रणालियों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अवसरों से लाभ उठाने की राह में मौजूद चुनौतियों का अवलोकन पेश किया।

यह कहा गया कि व्यापार, मानक, पारंपरिक ज्ञान और बोद्धिक संपदा से संबंधित मुद्दों पर मंत्रालय को नियमित रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर एक फोरम बनाने की आवश्यकता है। मंत्रणा के दौरान भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर एक फोरम (एफआईटीएम) बनाने संबंधी आरआईएस के प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया गया। खुली चर्चा में भाग लेने वालों में डॉ. एच. पुरुषोत्तम, सीएमडी, एनआरडीसी, आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ, अनुसंधान संगठनों के निदेशक, आयुष मंत्रालय के सलाहकार, निदेशक एवं अन्य तकनीकी अधिकारी, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों के शिक्षाविद, उद्योग संगठनों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। प्रोफेसर टी. सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने अपने समापन संबोधन में यह प्रस्ताव रखा कि आरआईएस इस मंत्रणा के दौरान दिए गए विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय के समक्ष समुचित प्रस्ताव पेश करेगा।

बांग्लादेश में भारत के विकास सहयोग पर सम्मेलन

बांग्लादेश में भारत के विकास सहयोग पर एक सम्मेलन पीआरआईए, भारतीय विकास सहयोग मंच और ऑक्सफैम इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से 24 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डॉ. राजेश टंडन, संस्थापक–अध्यक्ष, पीआरआईए ने 'बांग्लादेश के साथ भारत के विकास सहयोगः मुख्य निष्कर्षों' पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की। श्री कास्तुव चक्रबर्ती, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, पीआरआईए ने इस अवसर पर प्रस्तुति दी। सम्मेलन में प्रमुख चर्चाकर्ता या प्रतिभागी ये थेः राजदूत पिनक रंजन चक्रबर्ती, प्रतिष्ठित फेलो, ओआरएफ एवं पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस। ऑक्सफैम इंडिया के निदेशक–नीति, अनुसंधान एवं अभियान डॉ. रानू भोगल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

नाइजीरियाई दक्षिण–दक्षिण एकजुटता मॉडल

आरआईएस ने 7 फरवरी, 2017 को 'नाइजीरियाई दक्षिण–दक्षिण एकजुटता मॉडलः संचालक शक्ति (ड्राइविंग फोर्स), प्रेरणा और विदेश नीति फोकस' के विषय पर मासिक ब्रेकफास्ट संगोष्ठी का आयोजन किया। डॉ. सैदु नासिरु सुलेमान, सलाहकार, आरआईएस ने इस विषय पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद खुली चर्चा हुई।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर संवादात्मक सत्र

चाइना सेंटर फॉर कंटेम्परेरी वर्ल्ड स्टडीज (सीसीसीडब्ल्यूएस) के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संवादात्मक सत्र के लिए 22 मार्च, 2017 को यहां का दौरा किया। चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ये थेः डॉ. चाई शांगजिन, सीनियर रिसर्च फेलो, डा. वांग लियांग, डॉ. चेन यिंग, डॉ. वू हांग, एसोसिएट रिसर्च फेलो, डा. झोऊ यूयुन, काउंसलर, भारत में चीनी जनवादी गणराज्य का दूतावास। चर्चा का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स थिंक टैंक के सहयोग और आपसी हित के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करना था।

आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, प्रो. एस.के. मोहंती, प्रो. राम उपेंद्र दास, डॉ. बीना पांडे और डॉ. सब्यसाची साहा उपस्थित थे। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल की सुविधा के लिए प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने आरआईएस के कार्यकलापों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इसके बाद आरआईएस के संकाय ने विशेषज्ञता और अनुसंधान वाले अपने व्यक्तिगत क्षेत्रों पर संक्षिप्त विवरण पेश किए। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल ने दोनों संस्थानों के बीच गहन अकादमिक सहयोग के हितों एवं अवसरों के परस्पर व्याप्त होने के साथ–साथ भावी संवादों की संभावनाओं की भी सराहना की।

ब्रिक्स से संबंधित कार्यकलापों और वर्ष 2017 में ब्रिक्स की चीनी अध्यक्षता के दौरान सहयोग के अवसरों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों महत्वपूर्ण थिंक टैंकों की यह बैठक विशेष अहमियत रखती है। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर आरआईएस ने ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2016 में आयोजित ब्रिक्स शैक्षणिक और सिविल सोसायटी फोरमों के कार्यक्रम एवं परिणामों से जुड़े विवरण साझा किए।

सतत विकास के लिए जैव विविधता पर आम सहमति

आरआईएस ने नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सहयोग से 8–9 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में 'सतत विकास लक्ष्यः भारत के सतत विकास के लिए जैव विविधता संबंधी चिंताओं, पारिस्थितिकी मूल्यों और जलवायु से जुड़े लचीलेपन को एकीकृत करने पर राष्ट्रीय मंत्रणा' का आयोजन किया जिस दौरान एसडीजी 13, 14 और 15 पर फोकस किया गया।

एजेंडे में कई विषय शामिल थे जैसे कि एसडीजी 15 भूमि पर जीवन–स्थलीय पारिस्थिति की संरक्षण और मानव की भलाई, एसडीजी 14 पानी के नीचे जीवन–तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों का सतत प्रबंधन, एसडीजी 13 लचीलेपन का निर्माण एवं जलवायु परिवर्तन का मुकाबला तथा इसके प्रभाव, उप समूह की सिफारिशें और आगामी कदम। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और एसडीजी 13, 14 और 15 का अवलोकन पेश किया। प्रो. एस.के. मोहंती ने सिफारिशें पेश कीं और आगामी कदमों के बारे में भी बताया।

भारत–अफ्रीका आर्थिक साझेदारी

भारत अफ्रीका के आर्थिक एकीकरण का समर्थन करता है। जहां एक ओर भारत सभी अफ्रीकी देशों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारत आम सार्वजनिक वस्तुएं बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अफ्रीकी क्षेत्रीय निकायों के साथ भी मिलकर काम कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की पहुंच इन तक हो सके। अतः भारत इसे ध्यान में रखते हुए इकोवास, कोमेसा, और ईएएस के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहा है। इसके साथ ही भारत उन बाजार अवसरों से लाभ उठाने के लिए अफ्रीका के साथ भागीदारी करने की तैयारी में है जो अफ्रीकी विकास एवं अवसर अधिनियम (एजीओए) जैसे समझौतों के बल पर अफ्रीका के लिए उपलब्ध हैं। भारत किस तरह से उन अवसरों को बेहतरीन तरीके से हासिल करने में अफ्रीका की सहायता कर सकता है जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत उसके लिए उपलब्ध हैं? इस तरह के समझौते आखिरकार कैसे दीर्घकालिक द्विपक्षीय संस्थागत साझेदारी और कारोबारी गठबंधनों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? इन सवालों के साथ–साथ अन्य प्रश्नों पर भी 12वें सीआईआई एक्जिम बैंक सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया था।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

egkfun'kd

- नई दिल्ली में 4 अप्रैल 2016 को जीडीआई और आईसीआरआईईआर द्वारा आयोजित मैनेजिंग ग्लोबल गवर्नेंस (एमजीजी) की राष्ट्रीय पूर्व छात्र बैठक में 'पेरिस सीओपी 21 के नतीजों और भारत की भावी ऊर्जा नीति के लिए इसके निहितार्थ' पर एक पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता की।
- 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित राजीव भाटिया की पुस्तक *'इंडिया–म्यांमार रिलेशंस : चेंजिंग कन्टुर्स'* के विमोचन समारोह के अवसर पर परिचर्चा बैठक में परिचर्चा थे।
- 8 अप्रैल 2016 को हैदराबाद में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा 'अनुभवों को साझा करने के लिए जैव सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन' के दौरान 'एलएमओ में सामाजिक–आर्थिक चिंताएंः मुख्य चुनौतियां' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 27 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) द्वारा आयोजित थिंक टैंक प्रमुख (एचओटीटी) फोरम की बैठक में भाग लिया।
- 3 मई 2016 को बर्लिन में जीआईजेड और बीएमजेड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'जर्मनी की विकास नीति और विकास सहयोग पर फ्यूचर लैब' में भाग लिया।
- 4–5 मई 2016 को नई दिल्ली में स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव (एसआरआई) द्वारा जल, सूखा और संबंधित मुद्दों पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में परिचर्चा का संचालन किया।
- 6 मई 2016 को नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 'भारत की आर्थिक संभावनाओं' पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।
- 11 मई 2016 को बर्लिन में आयोजित बीएमजेड और एमजीजी नेटवर्क के अनौपचारिक संवाद के दौरान 'एसडीजी और प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था पर एक प्रस्तुति दी।
- 12 मई 2016 को बर्लिन में जर्मन विदेश संबंध परिषद (डीजीएपी), जर्मन विकास संस्थान (डीईई) और शंघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (एसआईआईएस) द्वारा संयुक्त रूप से 'संक्रमण में वैश्विक गवर्नेंसः क्षेत्रीय विखंडन पर काबू पाने में जी–20 कैसे सहायक हो सकता है?' पर आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 13 मई 2016 को बर्लिन में आयोजित '2030 एजेंडे और सतत विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग तथा चीन एवं जर्मनी की जी–20 अध्यक्षता पर बर्लिन टी20 सम्मेलन में 'समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था में जी–20 के योगदान' पर आयोजित सत्र में एक वक्ता थे।
- 19 मई 2016 को श्रीलंका में गरीबी विश्लेषण केंद्र (सीईपीए) और सदर्न वॉयसेज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'मजबूत शुरुआत पर एशियाई क्षेत्रीय संवादः एसडीजी के प्रथम 1000 दिन – एशियाई क्षेत्रीय संवाद' के दौरान ''एसडीजी और प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था पर एक प्रस्तुति दी।
- 23 मई 2016 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय और एक्जिम बैंक द्वारा 'नव

विकास बैंक संस्थान (एनडीबीआई) के आइडिया पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से आयोजित 'अनौपचारिक लंचन मीट' में भाग लिया।

- 27 मई 2016 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन (एलएसी) पर आयोजित व्यापार रणनीति पर चर्चा में भाग लिया।
- 1 जून 2016 को नई दिल्ली में मानव विकास संस्थान (आईएचडी) और विश्व बैंक द्वारा 'समृद्धि, समानता और स्थायित्वः एक बेहतर दुनिया के लिए परिप्रेक्ष्य और नीतियां' पर संयुक्त रूप से आयोजित वैश्विक सम्मेलन में 'पर्यावरण में सुधार की चुनौती' पर विषयगत सत्र की अध्यक्षता की।
- 1 जून 2016 को नई दिल्ली में नीतिगत अनुसंधान केंद्र और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मध्य प्रदेश के कृषि एटलस लांचिंग समारोह में भाग लिया।
- 2 जून 2016 को नई दिल्ली स्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा 'भारत और हिंद महासागरः स्थायित्व, सुरक्षा और विकास' पर आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- 6 जून 2016 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आईएटीटी (एसडीजी के लिए एसटीआई पर अंतर–एजेंसी टास्क टीम) के प्रथम बहु–हितधारक फोरम (एसटीआई फोरम) में 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए अनुकूल माहौल' विषय पर आयोजित सत्र में वक्ता थे।
- 13 जून 2016 को मुंबई में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और गेटवे हाउस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस की थिंक 20 (टी20) बैठक पर संवाद के दौरान व्यापार और निवेश पर चर्चा में भाग लिया।
- 14 जून 2016 को मुंबई में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और गेटवे हाउस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'गेटवे ऑफ इंडिया संवादः आर्थिक और सामरिक उद्देश्यों में तालमेल बैठाने का अवसर' के दौरान 'मेगा व्यापार समझौतेः आर्थिक विखंडन या एकीकरण? विषय पर आयोजित सत्र का संचालन किया।
- 15 जून 2016 को नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) द्वारा आयोजित एएसईएम राजनयिकों के लिए दूसरे विशेष पाठ्यक्रम में 'बहुपक्षीय कूटनीति के उभरते संदर्भ' पर एक प्रस्तुति दी।
- 20 जून 2016 को नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग द्वारा 'मध्य एवं दक्षिण एशिया' पर आयोजित देवको क्षेत्रीय संगोष्ठी में 'क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यः भू–रणनीतिक अवलोकन, राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 21 जून 2016 को वारसा में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेट काउंसिल के विकास अनुसंधान केंद्र (डीआरसी), अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सतत विकास केंद्र (सीआईआरएसडी) और पोलिश सूचना एवं विदेशी निवेश एजेंसी (पीएएलआईएलजेड) द्वारा सिल्क रोड फोरम 2016 में 'सतत विकास को बढ़ावा देना' विषय पर आयोजित सत्र में एक प्रस्तुति (अपनी अनुपस्थिति में) दी।
- 1 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में आईआईएफटी द्वारा 'उभरते एवं समकालीन अनुसंधान और विकास तथा राष्ट्रीय एसएंडटी प्रणाली में नवाचार संकेतक और नीतिगत निहितार्थ – एक व्यापक अध्ययन' विषय पर आयोजित डीएसटी

प्रायोजित परियोजना के लिए स्थानीय परियोजना सलाहकार समिति (एलपीएसी) की दूसरी बैठक में भाग लिया।

- 4 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन–मीडिया आउटरीच में भाग लिया।
- 7 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 'समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और नौकरी से भरपूर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने' विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद में भाग लिया।
- 11 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा 'भारत और महासागर अर्थव्यवस्था' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।
- 12 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा आयोजित आईसीएमआर–विदेश मंत्रालय भारत–अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान शिखर सम्मेलन की नियोजन समिति की पहली बैठक में भाग लिया।
- 13 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर फोकस करने वाले 'सतत विकास के लिए भागीदारी' पर आयोजित सत्र में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोगः उत्पत्ति और विकास' पर एक प्रस्तुति दी।
- 19 जुलाई 2016 को नैरोबी, केन्या में अंकटाड–14 की पूर्व संध्या पर जर्मन विकास संस्थान (डीआईई) के सहयोग से दक्षिणी थिंक–टैंकों के नेटवर्क (नेस्ट) द्वारा 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) को मापना एवं रिपोर्ट करना; एसडीजी को प्राप्त करने के लिए एसएससी के योगदान को कैसे समझें ' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में परिचर्चा रहे।
- 20 जुलाई 2016 को नैरोबी, केन्या में अंकटाड द्वारा 'सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में साक्ष्य–सूचित विकास सहयोग और दक्षिण–दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग के प्रबंधन' पर अलग से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
- 22 जुलाई 2016 को न्यूयॉर्क में यूएनडीसीएफ की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अलग से आयोजित एक कार्यक्रम के रूप में दक्षिणी थिंक–टैंकों के नेटवर्क (नेस्ट) और जर्मन विकास संस्थान (डीआईई) द्वारा 'एसएससी और टीओएसएसडी के सिद्धांत; दक्षिण में कौन–कौन से प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) हमें अभिसरण और विसंगति के बारे में बता सकते हैं' पर संयुक्त रूप से आयोजित पैनल परिचर्चा में परिचर्चा रहे।
- 27 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं योजना सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'राज्यों–संघ शासित प्रदेशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को मुहैया कराने' पर आयोजित सत्र में परिचर्चा रहे।
- 28 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में वादा ना तोड़ो अभियान, ऑक्सफैम इंडिया और पीपुल्स बजट इनिशिएटिव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'ब्रिक्स और समानता एवं परिवर्तन के एजेंडे पर अंतर्राष्ट्रीय सिविल सोसायटी परामर्श' के दौरान 'दक्षिणी व्यापार संबंधों को सुदृढ़ बनाने में ब्रिक्स की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।
- 10 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 'ब्रिक्स–बिम्सटेक की तैयारी बैठक' में भाग लिया।

- 11 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एसडीजी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 12 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में एक्जिम बैंक द्वारा आयोजित एक्जिम बैंक ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड 2016 पर पुरस्कार समिति की पहली ज्यूरी बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 23 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विदेशी राजनयिकों के लिए 62वें प्रोफेशनल पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) में 'बहुपक्षीय कूटनीति के स्वरूप' पर एक प्रस्तुति दी।
- 29 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा 'एजेंडा 2030 और इसके कार्यान्वयन पर भारत के दृष्टिकोण' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 30 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) द्वारा 'भारतीय संदर्भ में एसडीजी एजेंडे में प्रवासन को मुख्यधारा में लाने' पर आयोजित सम्मेलन में 'प्रवासन और एसडीजी; भारत की ओर से परिप्रेक्ष्य' पर विशेष भाषण दिया।
- 31 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति और निर्यात 2016–2017' पर सीआईआई समिति की पहली बैठक में भाग लिया।
- 1 सितंबर 2016 को मलेशिया के क्वालालम्पुर में कोरिया एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (केएआईडीईसी) द्वारा एशियाई विकास अध्ययनों पर आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'विकास चुनौतियां, स्थायित्व और एसटीआई की भूमिका; क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशियाई दृष्टिकोण और गुंजाइश की तलाश' पर एक प्रस्तुति दी।
- 2 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में वादा ना तोड़ो अभियान द्वारा आयोजित 'एजेंडा 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने' की पहली वर्षगांठ में भाग लिया।
- 3 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर आईसीएमआर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत–अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान सम्मेलन में 'साझेदारी के लिए अवसरों पर अफ्रीका क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की।
- 9 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) द्वारा 'विदेश में भारतीय छात्रों और भारत में एनआरआई छात्रों के समक्ष आने वाली समस्याओं' पर आयोजित पैनल परिचर्चा में परिचर्चा के रूप में भाग लिया।
- 15 सितंबर 2016 को वाशिंगटन डीसी में ओईसीडी द्वारा 'न्यूरोटेक्नोलॉजी और समाज; मस्तिष्क विज्ञान में उत्तरदायी नवाचार को सुदृढ़ बनाने' पर आयोजित कार्यशाला में 'भारत में मस्तिष्क अनुसंधान और न्यूरोटेक्नोलॉजी से संबंधित कार्यक्रम; वैज्ञानिक और सामाजिक परिणामों को जोड़ने वाली व्यवस्था' पर आयोजित सत्र में परिचर्चा रहे।
- 26 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की भारत यात्रा के दौरान एसडीजी पर एक कार्यक्रम के बारे में आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 29 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा 'भारत–भूटान ऊर्जा सहयोग समझौता और भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन' पर रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर आयोजित प्रसार कार्यशाला में मुख्य भाषण दिया।

- पोषण के लिए कृषि एवं खाद्य प्रणालियों पर वैश्विक पैनल के साथ 6 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान (पीएचएफआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पोषण एवं विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व (सैपलिंग) के शुभारंभ में भाग लिया।
- 15–16 अक्टूबर, 2016 को ढाका में सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग बांग्लादेश, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), भारत, व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया वॉच (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल, टिकाऊ विकास नीति संस्थान (एसडीपीआई), पाकिस्तान एवं श्रीलंका का नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नौवें दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन (एसएईएस–9), '2030 में दक्षिण एशिया की पुनर्कल्पना', में 'दक्षिण एशिया में एक समावेशी, न्यायोचित एवं शांतिपूर्ण समाज की दिशा में कौन हैं बदलाव के कारक' सत्र की अध्यक्षता की।
- 22 अक्टूबर 2016 को उदयपुर में आयोजित सेवा मंदिर की अर्ध वार्षिक कार्यकारी परिषद बैठक में भाग लिया।
- संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, चाइनीज एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनोमिक कॉपरेशन (सीएआईटीईसी), नेटवर्क ऑफ साउदर्न थिंक टैंक्स (एनईएस्टी) द्वारा 7 नवंबर 2016 को बीजिंग में संयुक्त रूप से आयोजित विकासशील देश के बीच सहयोग प्रदाता एवं एसडीजी 17 : टिकाऊ विकास लक्ष्यो, उपलब्धियों को आगेबढ़ाने पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में ' एसएससी एवं अन्य देशों की तुलना में इसका अनूठापन' पर सत्र में पैनलिस्ट रहे।
- संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, चाइनीज एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनोमिक कॉपरेशन (सीएआईटीईसी), नेटवर्क ऑफ साउदर्न थिंक टैंक्स (एनईएस्टी) द्वारा 8 नवंबर, 2016 को बीजिंग में संयुक्त रूप से आयोजित विकासशील देश के बीच सहयोग प्रदाता एवं एसडीजी 17 : टिकाऊ विकास लक्ष्यो, उपलब्धियों को आगे बढ़ाने पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में 'एसएससी की प्रभावशीलता, एमएंडई एवं उसके मॉडलों से तुलना पर प्रस्तुति दी।
- 13 नवंबर 2016 को भोपाल में प्रज्ञा प्रवाह एवं भारत भवन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रथम वार्षिक लोकमंथन 2016 में 'भारत, भू–राजनीति एवं वैश्विक परिदृश्य' पर एक विशेष संबोधन प्रस्तुत किया।
- असम विधानसभा द्वारा 22 नवंबर 2016 को गुवाहाटी में आयोजित अनुकूलन कार्यक्रमों में 'टिकाऊ विकास लक्ष्यो' पर प्रस्तुति दी।
- जापान इकोनोमिक फाउंडेशन (जेईएफ) एवं केंद्रीय आर्थिक प्रबंधन संस्थान (सीआईईएम) द्वारा 24 नवंबर 2016 को हनोई में संयुक्त रूप से आयोजित भारत प्रशांत फोरम में 'व्यापार को घरेलू नीति सुधारों के साथ जोड़ना : आर्थिक विकास की दिशा में समन्वित कदम के लिए सर्वसहमति का निर्माण' पर एक सत्र में परिचर्चा में भाग लिया।
- एनईएसटी, एसएआईआईए, आरआईएस एवं शियामेन विश्वविद्यालय द्वारा 30 नवंबर 2016 को नैरोबी में संयुक्त रूप से आयोजित जीपीईडीसी के एचएलएम2 के दौरान '2030 कार्यसूची के तहत विकास सहयोग के लिए प्रयास एवं

जवाबदेहीः अभिसरण की दिशा में कदम' पर आयोजित कार्यशाला में 'अभिसरण या सुस्पष्ट विशेषता : विकासशील देश के बीच सहयोग के केस अध्ययनों और वैचारिक रुझानों से प्रमुख सीख' पर प्रस्तुति दी।

- जर्मन डेवेलपमेंट इंस्टीच्युट, ड्यूश इंस्टीच्युट फॉर इंटविकलुंग्सपोलिटिक (डीआईई) एवं साउथ अफ्रीकन इंस्टीच्युट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (एसएआईआईए) दक्षिण अफ्रीका द्वारा 30 नवंबर 2016 को संयुक्त रूप से आयोजित 2030 एजेंडा के लिए कारगर विकास सहयोग के लिए जवाबदेही : आगे कैसे बढ़ें' विषय पर एक सत्र में परिचर्चा में भाग लिया।
- 30 नवंबर 2016 को नैरोबी में केन्याइ सरकार, मलावी सरकार, एयू–एनईपीएडी, रियल्टी ऑफ ऐड नेटवर्क के सहयोग से एनईएसटी अफ्रीका द्वारा आयोजित 'अफ्रीका के विकास के लिए विकासशील देशों के बीच साझीदारी–जबावदेही को बेहतर बनाना' पर सम्मेलन में परिचर्चा में भाग लिया।
- 7 दिसंबर 2016 को मुंबई में भारतीय एक्जिम बैंक द्वारा आयोजित ब्रिक्स अंतः बैंक सहयोग तंत्र : उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैकल्पिक रेटिंग एजेन्सियों की स्थापना की व्यावहार्यता खोजने के लिए कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया।
- 12 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलेंटरी एक्शन तथा वादा ना तोडो (डब्ल्यूएनटीए) द्वारा आयोजित परामर्श बैठक में 'टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी) को समर्थन एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान पर ब्रिक्स उच्च स्तरीय बैठक में' पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग–ब्रिक्स परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- मौलाना अब्दुल कलामआजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज (मकायास) और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (आईएससीएस) द्वारा संयुक्त रूप से 4 जनवरी, 2017 को कोलकाता में 'भारत–अफगानिस्तानः वर्तमान संबंध एवं भावी दिशा' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- बेंगलुरू में 7 जनवरी, 2017 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए 14वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) 2017 संगोष्ठी के दौरान 'ज्ञान के हस्तांतरण और नवाचार को प्रोत्साहन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका' सत्र में भाग लिया।
- भारत की वीएनआर तैयार करने के लिए नीति आयोग द्वारा 9 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई कार्यदल की बैठक में 'भारत के लिए एचएलपीएफ 2017 टेम्पलेट हेतु स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाओं (वीएनआर)' पर एक प्रस्तुति दी।
- ब्राजील में 16 जनवरी 2017 को रियो डी जनेरियो के बिशप कैथोलिक विश्वविद्यालय (पीयूसी–रियो), अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान (आईआरआई/(पीयूसी–रियो) और ब्रिक्स पॉलिसी सेंटर द्वारा 'ब्राजील के दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर संवादः एमएंडई' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए संगोष्ठी में 'मूल्यांकन और एसडीजी' पर एक प्रस्तुति दी।
- ब्राजील में 17 जनवरी 2017 को रियो डी जनेरियो के बिशप कैथोलिक विश्वविद्यालय (पीयूसी–रियो), अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान (आईआरआई/(पीयूसी–रियो) और ब्रिक्स पॉलिसी सेंटर द्वारा 'ब्राजील के दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर संवादः एमएंडई'

पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए संगोष्ठी में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग के मात्रा निर्धारण' पर एक प्रस्तुति दी।

- भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योगमंत्रालय द्वारा 19 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग पर सचिवों के समूह के तहत व्यापार और निवेश पर आयोजित की गई बैठक में भाग लिया।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग नेटवर्क (एनआईडीसी), द एशिया फाउंडेशन (टीएएफ), थाईलैंड रिसर्च फंड (टीआरएफ), और थमसैट यूनिवर्सिटी द्वारा 26 जनवरी 2016 को थाईलैंड के बैंकॉक में संयुक्त रूप से 'त्रिकोणीय सहयोगः सबक सीखा और भविष्य की संभावना' विषय पर आयोजित किए गए एनआईडीसी फोरम 2017 के दौरान 'प्रमुख देशों के दृष्टिकोण से टीआरसी' पर विशेष सत्र के पैनल में शामिल थे।
- नई दिल्ली में 9 फरवरी 2017 को 3आईई, जीडीएन एवं कैंपबेल कोलेबोरेशन और प्रभाव आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल द्वारा 'भारत में गवर्नेंस और सेवा वितरण पर प्राप्त राष्ट्रीय एवं वैश्विक साक्ष्य से लाभ उठाने' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए आधे दिन के आयोजन में भाग लिया।
- अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू) और भारत की संसद द्वारा 18–19 फरवरी 2017 को इंदौर में 'सशक्त विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करनाः क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना और एसडीजी के लिए संसाधन' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया।
- सतत विकास एवं गवर्नेंस के लिए संस्थान (आईएसडीजी) और ओक्सफैम इंडिया द्वारा 20 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में 'विकास सहयोग का भविष्यः उभरते भारत के लिए नीतिगत प्राथमिकता' पर संयुक्त रूप से आयोजित की गई राष्ट्रीय संगोष्ठी और मंत्रणा के दौरान 'विकास सहयोग के लिए वकालत और गठबंधन' पर समापन सत्र को संबोधित किया।
- नई दिल्ली में 20–21 फरवरी 2017 को 'भारत का उदय और विकास चुनौतियांः अमेरिका के लिए नीतिगत निहितार्थ' पर एस्पेन कांग्रेसनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 'भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक भूमिकाः विकास और गरीबी का संबंध और अमेरिकी नीति के प्रति इसकी प्रासंगिकता' पर आयोजित किए गए सम्मेलन में वक्ता थे और इससे पहले ब्रेकफास्ट बैठक में भाग लिया।
- मोहाली में 26 फरवरी, 2017 को इंटरनेशनल सोसायटी फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी (आईएसईईएस) और सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड एप्लायड बायोप्रोसिंग द्वारा 'सतत ऊर्जा और पर्यावरण चुनौतियां (एसईईसी–2017)' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया।
- नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, नेपाल (नेनेप), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारतीय परिषद और नेपाल–भारत सहयोग मंच (एनबीएसएम), बीरगंज द्वारा 3–4 मार्च, 2017 को बीरगंज, नेपाल में 'नेपाल–भारत संबंधः अर्थशास्त्र विकास और सहयोग' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए संगोष्ठी में उद्घाटन भाषण दिया।
- बैंकॉक रिसर्च सेंटर, आईडीई–जेट्रो, सचिवालय द्वारा 7 मार्च 2017 को जकार्ता, इंडोनेशिया में 'नया सामान्य, एकता और विषमता' पर अनुसंधान संस्थान नेटवर्क बैठक (आरआईएनएम) पर आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 15 मार्च 2017 को नई दिल्ली में 'जैव सुरक्षा पर चरण द्वितीय क्षमता निर्माण परियोजनाः परिणाम और आगे की राह' पर आयोजित की गई कार्यशाला में 'एलएमओ का सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकनः परिणाम और आगे की राह' पर एक प्रस्तुति दी और उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया।
- पार्टनरिंग होप इन टू एक्शन (फिया) फाउंडेशन और वादा ना तोड़ो अभियान (डब्ल्यूएनटीए) द्वारा 17 मार्च 2017 को नई दिल्ली में 'लक्ष्य 5ः लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना – सहयोगियों' पर संयुक्त रूप से आयोजित की गई राष्ट्रीय मंत्रणा में 'एसडीजी लक्ष्य और प्रस्तावित राष्ट्रीय संकेतक, 2017' पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 24 मार्च 2017 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा 'स्टार्ट–अप्स को नई गति प्रदान करने के लिए नवाचार परितंत्र से लाभ उठाने' पर आयोजित किए गए 43वें एनआरडीसी मेधावी आविष्कार पुरस्कार समारोह और सम्मेलन के दौरान 'समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट–अप्स को सक्षम बनानाः राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य' पर एक सत्र की अध्यक्षता की।
- नैरोबी में भारत के उच्चायोग, नैरोबी स्थित एशियाई अफ्रीकी विरासत ट्रस्ट और भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान द्वारा 28 मार्च 2017 को नैरोबी में 'कनेक्टिविटी पर दोबारा गौर कियाः भारत, केन्या और हिंद महासागर' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए संगोष्ठी में 'विकास उन्मुख व्यापार नीतियां और सहयोगः भारत–केन्या भागीदारी के लिए नई संभावनाओं की तलाश' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. एस.के. मोहंती

- 27 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में 'अपने दक्षिण एशियाई साझेदारों के साथ भारत की नीली अर्थव्यवस्था संबंधी सहभागिता के बढ़ते महत्व' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 27 मई 2016 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 'लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन (एलएसी) से जुड़ी व्यापार रणनीति' पर आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- 2 जून 2016 को नई दिल्ली में सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्व ारा 'भारत एवं हिंद महासागरः स्थायित्व, सुरक्षा और विकास' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए आयोजित संवाद में भाग लिया और 'भारत एवं हिंद महासागरः उभरते क्षेत्रीय मुद्दों' पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में आईसीडब्ल्यूए द्वारा 'भारत और महासागर अर्थव्यवस्था' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक रूपरेखा; भारत में एक सतत महासागर नीति की ओर' पर एक प्रस्तुति दी।
- 25 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित नीली अर्थव्यवस्था पर फिक्की कार्यदल की पहली बैठक में भाग लिया।
- 15–19 जुलाई 2016 को भुवनेश्वर स्थित आईसीएआर–सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवॉटर एक्वाकल्चर में द्वितीय आईओआरए ब्लू इकोनॉमी संवाद पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

- 3 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में 'शेष दक्षिण एशिया के साथ भारत के आर्थिक संबंध; देश अध्ययन श्रृंखला ' पर अध्ययन के बारे में आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 17 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा 'ब्लू इकोनॉमी पर ज्ञान रिपोर्ट' के लिए आयोजित मसौदा समिति की बैठक में भाग लिया।
- 18 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में 'सार्क अध्ययन – टैरिफ अनुसूचियां' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- फिक्की द्वारा नीली अर्थव्यवस्था पर गठित कार्यदल के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए।
- राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा 'सामान्यत; ट्रेडिंग वाली जिंस' पर पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए।
- 10–14 अक्तूबर 2016 को जकार्ता में आयोजित हिंद महासागर रिम एकेडेमिक समूह की 22वीं बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।
- 12 अक्तूबर 2016 को जकार्ता में आयोजित हिंद महासागर रिम एकेडेमिक समूह की 22वीं बैठक में 'आईओआरए में मछली पालन के आर्थिक आयाम' पर एक प्रस्तुति दी।
- 9 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा आयोजित गोल मेज वार्ता 'राष्ट्रकुलः व्यापार एवं आर्थिक अवसर' में परिचर्चा में भाग लिया।
- 24 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में आयोजित भारत–मर्कासुर पीटीए विस्तार पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 30, नवंबर 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में आयोजित ईरान, बांग्ला देश, मालदीव एवं अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 5 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में भारतीय निर्यात–आयात बैक द्वारा भारत में निर्यात एवं रोजगार के बीच अंतःसंपर्कों पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- 6 दिसंबर, 2016 को सामुद्रिक अर्थव्यवस्था पर फिक्की कार्य बल समिति द्वारा आयोजित सामुद्रिक अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों पर परिचर्चा में भाग लिया
- 8 दिसंबर, 2016 को भारतीय निर्यात–आयात बैंक द्वारा एक्जिम बैंक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान वार्षिक (आईआरए) पुरस्कार समिति के लिए जूरी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया।
- 9 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग में आयोजित ईरान, बांग्ला देश, मालदीव एवं अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 13 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझीदारी समझौता (सीईसीपीए) वार्ताओं एवं भारत–इजरायल एफटीए वार्ताओं पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 19 दिसंबर 2016 को पुणे में सिंबायोसिस अंतरराष्ट्रीय विद्यालय द्वारा सिंबायोसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भारत एवं हिन्द महासागर पर चौथे अंतरराष्ट्रीय संबंध सम्मेलन : सततता, सुरक्षा एवं विकास में 'सामुद्रिक अर्थव्यवस्था के लिए एक रूपरेखा : टिकाऊ सामुद्रिक सहयोग की दिशा में दृष्टिकोण' पर एक प्रस्तुति दी।

- नई दिल्ली में 11 जनवरी 2017 को विदेश मंत्रालय में ब्लू इकोनॉमी फोरम पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 11 जनवरी 2017 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आयोजित ब्लू इकोनॉमी फोरम पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 16 जनवरी 2017 को नीति आयोग द्वारा 'भारत में पोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 18 जनवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में भारत–मॉरीशस संयुक्त अध्ययन समूह पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 19 जनवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में वाणिज्य और उद्योग पर गठित सचिवों के समूह के अंतर्गत 'व्यापार और निवेश' पर आयोजित समूह की परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 27 जनवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में व्यापार और निवेश पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 7 फरवरी 2017 को यूएमआईएसएआरसी और दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र, पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परिचर्चा बैठक में 'क्या दक्षिण एशिया का आर्थिक प्रदर्शन दमदार है?: मजबूत क्षेत्रीय गवर्नेंस की बदौलत निरंतर क्षेत्रीय विकास संभव है' विषय पर एक संयुक्त पेपर प्रस्तुत किया।
- नई दिल्ली में 13 फरवरी, 2017 को एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आईईआरए अवार्ड 2016 की प्रथम ज्यूरी बैठक की अध्यक्षता की।
- 16 और 20 फरवरी 2017 को फिक्की द्वारा आयोजित ब्लू इकोनॉमी पर टास्कफोर्स की बैठकों में भाग लिया।
- 21 फरवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 28 फरवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में आयोजित यूरोपीय संघ और एलएसी में व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 27 मार्च 2017 को वाणिज्य विभाग में आयोजित 'भारत–मॉरीशस संयुक्त अध्ययन समूह' की परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

प्रो. राम उपेंद्र दास

- 6 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 'यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने के लिए संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) की रिपोर्ट' पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 12 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान द्वारा 'क्षेत्रीय समूहः आसियान और ब्रिक्स' पर विदेशी राजनयिकों के लिए आयोजित 61वें प्रोफेशनल पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) को संबोधित किया।
- 29 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 'सीआईएस क्षेत्र के लिए भारत की निर्यात रणनीति' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

- 29 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बैठक में 'भारत–म्यांमार सीमा व्यापार' पर एक प्रस्तुति दी।
- 2 मई 2016 को नई दिल्ली में मलेशिया के उच्चायोग द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रीदातो' श्री मुस्तपा बिन मोहम्मद के लिए 'मलेशिया के मित्र' पर आयोजित एक सत्र में प्रस्तुति दी।
- 11 मई 2016 को नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के दूतावास द्वारा 'भारत–ईएफटीए' पर आयोजित एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 25 मई 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 'भारत एवं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) के बीच जेएसजी और सीआईएस क्षेत्र के लिए निर्यात रणनीति' विषय पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- 28–30 मई 2016 को इंडोनेशिया के बाली में एकेडमी फॉर वर्ल्ड वॉच, शंघाई द्वारा 'चीन, भारत और आसियान – अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से सामरिक त्रिपक्षीय संबंध' विषय पर आयोजित अकादमिक आदान–प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया।
- 6 जून 2016 को इंफाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय, मणिपुर राज्य सरकार द्वारा 'भारत–म्यांमार सीमा व्यापार' पर आयोजित एक आउटरीच कार्यक्रम में एक प्रस्तुति दी।
- 13 जून 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 'भारत एवं यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) के बीच जेएसजी और सीआईएस क्षेत्र के लिए निर्यात रणनीति'पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 22 जून 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 'भारत एवं यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) के बीच जेएफएसजी और सीआईएस क्षेत्र के लिए निर्यात रणनीति' विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 29 जून 2016 को चीन के बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदान–प्रदान के लिए चीन केंद्र (सीसीआईईई) द्वारा 'वैश्विक गवर्नेंस, खुलेपन और सहयोग की एक नई शुरुआत' पर आयोजित जी20 थिंक टैंक संगोष्ठी में भाग लिया।
- 19 जुलाई, 10 अगस्त, 29 अगस्त, 12 सितंबर और 15 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में प्रवेश करने के लिए 'संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) की रिपोर्ट' पर आयोजित बैठकों में भाग लिया।
- 21 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 'सार्क में पहल; भारत की भूमिका' विषय पर आयोजित मंथन सत्र में भाग लिया।
- 1 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में एफएसआई, विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 'क्षेत्रीय समूह; आसियान और ब्रिक्स' पर विदेशी राजनयिकों के लिए 62वें प्रोफेशनल पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) को संबोधित किया।
- 4 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा 'अर्थव्यवस्था की तिमाही समीक्षा (क्यूआरई)' पर आयोजित परिचर्चा में एक प्रतिभागी के रूप में भाग लिया।
- 19 अगस्त और 16 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित 'भारतीय और रूसी थिंक टैंकों के फोरम' की बैठकों में भाग लिया।

- 30 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में सार्कस्टैट और सार्क सचिवालय द्वारा आयोजित सार्क सांख्यिकीय संगठनों (सार्कस्टैट) के प्रमुखों की 8वीं बैठक में 'सेवाओं में सार्क व्यापार' पर एक प्रस्तुति दी।
- 1–3 सितंबर 2016 को मास्को, रूस में यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन द्वारा आयोजित 'यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) एवं उसके सदस्य देशों और भारत गणराज्य' के बीच एफटीए में प्रवेश करने के लिए संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) के विशेषज्ञ समूह' की एक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक नेता (लीडर) के रूप में भाग लिया।
- 12 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 19–20 सितंबर 2016 को मॉस्को, रूस में यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन द्वारा आयोजित यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) एवं उसके सदस्य देशों और भारत गणराज्य के बीच एफटीए में प्रवेश करने के लिए 'संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी)' पर दूसरी बैठक में भाग लिया।
- 22–23 सितंबर 2016 को मॉस्को, रूस में आईसीडब्ल्यूए, भारत के दूतावास और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 'भारत–रूस थिंक टैंकों' की बैठक में भाग लिया।
- 26 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 'संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी)' पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- 1 अक्तूबर 2016 को भारत में यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल द्वारा केपीएमजी एवं सी–डीईपी, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित 'ईयू–भारत डिजिटल एजेंडा : 2020 को मजबूत बनाना : व्यापार प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन' पर एक कार्यशाला में हुई परिचर्चा में भाग लिया।
- 5 अक्तूबर, 2016 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 'व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक का विकास' पर निर्यात समिति की 22वीं बैठक में भाग लिया।
- 7–8 अक्तूबर 2016 को अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) एवं स्नातक अध्ययन तथा कृषि में अनुसंधान के लिए दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्रीय केंद्र (एसईएआरसीए), लॉस बनोस, लुगना, फिलीपींस द्वारा 'आसियान क्षेत्र में कृषि रूपांतरण एवं बाजार समेकनः खाद्य सुरक्षा एवं समावेशन चिंताओं का प्रत्युत्तर' विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में परिचर्चा में भाग लिया।
- 17 अक्तूबर, 2016 को नई दिल्ली में उद्योग चैंबर पीएचडी द्वारा आयोजित 'भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाएं' पर एक संगोष्ठी में एक शिष्टमंडल को संबोधित किया।
- 25 अक्तूबर 2016 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 'नैरोबी घोषणापत्र : क्या भारत अपने कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा कर सका ध' पर 2004–2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों के उप सचिव स्तर के लिए मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक परिचर्चा में भाग लिया।
- 25 अक्तूबर 2016 को कोनरैड –एडेनायूर – स्टिफटंग, गुड़गांव, हरियाणा के साथ टेरी द्वारा आयोजित 'संसाधन सुरक्षा : वैश्विक व्यापार एवं निवेश संरचना में

घरेलू हितों के प्रासंगीकरण' पर एक संसाधन वार्ता में भाग लिया तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं ब्रिक्स के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों–भूमिका का लाभ उठाने पर पत्र प्रस्तुति दी।

- 12 नवंबर 2016 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'व्यापार मुद्दे एवं भूमंडलीकरणः डब्ल्यूटीओ एवं क्षेत्रीय व्यापार गुट' पर एडवांस्ड लीडरशिप कार्यक्रम को संबोधित किया।
- 22 नवंबर 2016 को ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी), गुड़गांव, हरियाणा द्वारा आयोजित 'व्यापार एवं टिकाऊ विकास : विकासशील देशों के बीच एवं क्षेत्रीय सहयोग' पर सम्मेलन के आईटीईसी प्रतिभागियों को संबोधित किया।
- 28 नवंबर 2016 को भारतीय इंजीनियरिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ' भारत का विजन 2030–इंजीनियरिंग एवं तकनीकविद् क्या कर सकते हैं ?' पर 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में परिचर्चा में भाग लिया।
- 30 नवंबर–2 दिसंबर 2016 को ड्यूशेज इंस्टीच्युट फॉर एंटविकलुंग्सपॉलिटिक एवं जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीच्युट, बर्लिन, जर्मनी द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय किक ऑफ सम्मेलन' थिंक 20 (टी20) में परिचर्चा में भाग लिया।
- 7 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में पीएचडी उद्योग चैंबर द्वारा आयोजित ' दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार–अवसर एवं चुनौतियों' पर एक क्रेता–विक्रेता बैठक में एक वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 9 दिसंबर, 2016 को एमिटी स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उ.प्र. की विभागीय शोधकर्ता समिति (डीआरसी) के सदस्य के रूप में मनोनित हुई।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 6, 9, 18 और 30 जनवरी, 2017 को आयोजित भारतीय और ईएईयू एफटीए के बीच संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) पर बैठकों में भाग लिया।
- 6 जनवरी, 2017 को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'आर्थिक मामलों की समिति की प्रथम समिति बैठक' में भाग लिया।
- थाईलैंड के बैंकाक में एशिया–प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनएस्कैप) द्वारा 11–12 जनवरी, 2017 को आयोजित 'एशिया–प्रशांत व्यापार समझौताः एक भावी रोडमैप' पर एपीटीए की स्थायी समिति के 50वें सत्र में और 13 जनवरी, 2017 को आयोजित एपीटीए की मंत्रिस्तरीय परिषद के चौथे सत्र में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।
- 17 जनवरी 2017 को नई दिल्ली स्थित दक्षिण कोरिया के दूतावास द्वारा आयोजित भारत–दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की बैठक में भाग लिया।
- 23 जनवरी, 2017 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रोफेसर (डॉ.) इडेसबाल्ड गोद्देइरिस, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन, बेल्जियम के साथ आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 27 जनवरी, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा व्यापार और निवेश पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 1–3 फरवरी, 2017 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान (एसएआईआईए) द्वारा टी–20 जर्मनी के सह–अध्यक्ष जर्मन विकास संस्थान/ड्यूश इंस्टीट्यूट फर एंटविकलंगस्पोलिटिक

(डीआईई) और इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी (आईएफडब्ल्यू कील) के सहयोग से 'अफ्रीका और जी–20ः सतत विकास के लिए गठजोड़ के निर्माण' पर आयोजित टी20 अफ्रीका सम्मेलन में पैनल के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।

- 7 फरवरी, 2017 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एफटीए के अंतर्गत उत्पत्ति के नियमों पर वार्ता के तहत आयोजित एक मंथन सत्र में भाग लिया।
- 14 फरवरी, 2017 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 'व्यापार की रोजगार सृजन क्षमता' पर आयोजित एक बैठक में एक प्रस्तुति दी।
- 14 फरवरी, 2017 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 'बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच उप–क्षेत्रीय सहयोग' पर आयोजित एक प्रारंभिक बैठक में भाग लिया।
- 15 फरवरी, 2017 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्पत्ति के आरसीईपी नियमों पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा 21 फरवरी, 2017 को 'नए बाजार नए अवसरः गंतव्य सीआईएस' पर आयोजित एक बैठक में एक प्रस्तुति दी।
- 23–26 फरवरी, 2017 को ईआरआईए, जकार्ता, इंडोनेशिया द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 'शेष एशिया के साथ पूर्वी और दक्षिण–पूर्व एशिया को एकीकृत करने के लिए एक आर्थिक केंद्र के रूप में भारत' पर एक प्रस्तुति दी।
- 28 फरवरी, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारत–नाफ्टा व्यापार संबंधों पर आयोजित एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 3, 9 और 27 मार्च, 2017 को ईएईयू देशों के साथ एफटीए पर आयोजित एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 07 मार्च, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 'संगोष्ठी से व्यापार में सुविधा' विषय पर आयोजित एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 10 मार्च, 2017 को एक्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली के सहयोग से भारत–अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर आयोजित 12वें सीआईआई एक्जिम बैंक सम्मेलन में पैनल के सदस्य के रूप में रहे।
- 20 मार्च, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सेवाओं में व्यापार सुविधा (टीएफएस) पर भारत के प्रस्ताव पर आयोजित एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 23–24 मार्च, 2017 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विश्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा सेवाओं में व्यापार सुविधा (टीएफएस) पर आयोजित कार्यशाला में एक संचालक (मॉडरेटर) के रूप में भाग लिया।
- 28 मार्च, 2017 को रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), नई दिल्ली द्वारा 'कनेक्टिविटी का अर्थशास्त्रः क्षेत्र से परिदृश्य' पर आयोजित 10वें आईडीएसए दक्षिण एशिया सम्मेलन के एक सत्र को संचालित किया।

प्रो. टी.सी. जेम्स

fof t fVx Qyk

- 26 अप्रैल 2016 को पुणे स्थित जॉन डीयरे कोर के कर्मचारियों और अधिकारियों के समक्ष 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के वाणिज्यीकरण' पर विषेश व्याख्यान दिया।
- 26 अप्रैल 2016 को सिम्बायोसिस विष्वविद्यालय, पुणे द्वारा 'मेक इन इंडियाः मूल्य सृजित करने में उद्योग–विष्वविद्यालय सहयोग की भूमिका' विशय पर आयोजित विष्व आईपी दिवस कार्यषाला में मुख्य भाशण दिया।
- 25 और 28 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली स्थित विष्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) समर स्कूल, आईएसआईएल में 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' पर व्याख्यान दिया।
- 4 मई 2016 को नई दिल्ली में स्पीकर्स रिसर्च इनिषिएटिव द्वारा आयोजित सांसदों की कार्यषाला में 'पेयजल संरक्षण और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी उपयोग' विशय पर एक प्रस्तुति दी।
- 18 मई 2016 को आईसीएमआर की बोद्धिक संपदा समिति की बैठक में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
- 24 मई 2016 को लोकसभा टीवी पर 'राश्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति' विशय पर आयोजित परिचर्चा में परिचर्चा थे।
- 1 और 2 जून 2016 को अगरतला में सभापतियों एवं उप सभापतियों के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया और विधायकों के लिए अनुसंधान सहायता की आवष्यकता एवं माननीया लोकसभा अध्यक्ष की नई षोध पहल के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।
- 13 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में बोद्धिक संपदा अध्ययन के लिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इनोवेषन एंड कंपीटीषन, आर्थिक अध्ययन एवं नियोजन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विष्वविद्यालय और औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान द्वारा 'पेटेंट संरक्षण पर घोशणा पत्र; ट्रिप्स के तहत नियामकीय संप्रभुता' पर आयोजित कार्यषाला में 'कोई भी चीज सबके लिए एकसमान नहीं' विशय पर एक प्रस्तुति दी।
- 7 एवं 8 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में इग्नू विशेषज्ञ समिति की बैठकों में पीजी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए एक सदस्य के रूप में भागीदारी की।
- 21 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में 'पारंपरिक बैंडों की सुरक्षा के लिए एक माध्यम के रूप में भौगोलिक संकेतक' विषय पर महिला उद्यमियों के परिसंघ द्वारा आयोजित बौद्विक संपदा अधिकारों पर सम्मेलन को संबोधित किया।
- 21 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में भारतीय विधि संस्थान में कॉपीराइट एवं संबंधित अधिकारों की समझ पर एक सप्ताह चलने वाले राष्ट्रीय कार्यशाला में 'कॉपीराइट में विशिष्ट आर्थिक अधिकारों' पर व्याख्यान दिया। 24 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया (एनएफआई), एलाइव एंड थ्राइव (ए एंड टी) एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव (एमआई) के साथ मिल कर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए सहयोग, भारत (सीएफएनएस) द्वारा 'एसडीजी एवं डब्ल्यूएचए के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण लक्ष्यों को अर्जित करने पर प्रतिबद्धता एवं कदम ' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में एक परिचर्चा के रूप में

भाग लिया। सम्मेलन में एक संयुक्त सिविल सोसाइटी घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया जिसमें महिलाओं की अगुवाई में भारत को रूपांतरित करने के लिए एक ' सतत पोषण क्रांति' की अपील की गई।

- 11 दिसंबर 2016 को जमीनी स्तर के वकीलों एवं गैर सरकारी संगठनों के लिए सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, अहमदाबाद एवं एनएलयू, दिल्ली में सेंटर फॉर इनोवेशन, आईपी एवं कंपटीशन लॉ द्वारा भारत की पारंपरिक ज्ञान सुरक्षा व्यवस्था पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में ' पारंपरिक ज्ञान का पैटेंटीकारण : दुरुपयोग के खिलाफ रक्षात्मक एवं आक्रात्मक सुरक्षा' पर प्रस्तुति दी।
- 16 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में बोद्धिक संपदा चेयर, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ' ट्रिप्स एवं उभरता परिदृश्य : ट्रिप्स एवं मुद्दों का एक दशक' सत्र की अध्यक्षता की।
- यूरोपीय संघ के बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा क्रमषः 16, 18, 20, और 21 जनवरी, 2017 को कोचीन, चेन्नई, विजयवाड़ा और बेंगलुरू में उत्पादकों, सलाहकारों और अटार्नी के लिए जीआई पर आयोजित कार्यशालाओं में भारतीय भौगोलिक संकेतक विषेशज्ञ के रूप में भाग लिया और भारतीय भौगोलिक संकेतकों (जीआई) के व्यवसायीकरण पर प्रस्तुति दी।
- 4–6 फरवरी, 2017 को महात्मा गांधी विष्वविद्यालय, कोट्टायम द्वारा 'वैष्वीकरण और भारत की नवाचार प्रणालीः एक रचनात्मक विनाष' पर आयोजित अंतर्राश्ट्रीय संगोश्ठी में भाग लिया और 'उपेक्षित उश्णकटिबंधीय रोगों और अनुसंधान एवं विकास' के बारे में बताया और इसके साथ ही कुछ सत्रों की अध्यक्षता भी की।
- 6 फरवरी, 2017 को कोच्चि में 'ट्रिप्स समझौते पर एक प्रतिक्रिया के रूप में पेटेंट कार्यालयों में सुधार' के बारे में कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय को संबोधित किया।
- 9 फरवरी, 2017 को सीएसआईआर एचआरडीसी, गाजियाबाद में 'बोद्धिक संपदा और आरएंडडी में नैतिकता' पर सीएसआईआर के वैज्ञानिकों को संबोधित किया।
- 18 फरवरी 2017 को इंदौर में आयोजित दक्षिण एषियाई स्पीकर षिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- 24 फरवरी, 2017 को तिरुवनंतपुरम में राश्ट्रीय जैव विविधता कांग्रेस 2017 में 'जैव विविधता, स्वास्थ्य और तंदरुस्ती' विशय पर आमंत्रण भाशण दिया।
- 03 मार्च 2017 को दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा 'अधिनिर्णय में ज्ञान, कौषल और दृश्टिकोण के एकीकरण' पर आयोजित सम्मेलन में दिल्ली के जिला न्यायाध ीषों को संबोधित किया।
- नई दिल्ली स्थित अंतर्राश्ट्रीय कानून के लिए भारतीय सोसायटी में 'एमएसएमई के लिए बोद्धिक संपदा पर जागरूकता/संवेदनषीलता' के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम के दौरान 4 मार्च, 2017 को 'एमएसएमई हेतु भौगोलिक संकेतकों की गुंजाइष' विशय पर विषेश भाशण दिया।
- 17 मार्च, 2017 को पंडित बी डी षर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विष्वविद्यालय, रोहतक द्वारा 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता' पर आयोजित स्वर्ण जयंती एक दिवसीय राश्ट्रीय संगोश्ठी में मुख्य भाशण दिया।

- 27–28 मार्च 2017 को 'एजेंडा 2030 के लिए आधिकारिक सांख्यिकी के परिवर्तन में तेजी लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने' पर एषिया–प्रषांत सम्मेलन में और 29 मार्च, 2017 को थाईलैंड के बैंकाक में सतत विकास पर एषिया–प्रषांत फोरम में भाग लिया। सम्मेलन में सांख्यिकी के विकास के लिए राश्ट्रीय रणनीति बनाने की आवष्यकता पर बल दिया गया। एषिया–प्रषांत फोरम में नीति आयोग–आरआईएस का एक मंडप (पवेलियन) स्थापित किया गया था और एसडीजी को लेकर भारत के प्रयासों पर साहित्यिक रचना एवं अन्य प्रचार सामग्री पेष की गई तथा आगंतुकों को उपलब्ध कराई गई।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

fof t fVx Qyk

- 8 अप्रैल 2016 को हैदराबाद में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अनुभवों को साझा करने के लिए जैव सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
- 20–21 सितंबर 2016 को ओस्लो में आयोजित आरआरआई–कार्यप्रणाली शुभारंभ कार्यशाला में भाग लिया।
- 1–2 दिसंबर 2016 को पेरिस में एएफडी द्वारा आयोजित 'कॉमंस एंड डेवलपमेंट विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ' जर्मप्लाज्म एवं कॉमंस : फ्रॉम ग्लोबल टू द फील्ड' पर प्रस्तुति दी।
- 29–30 नवंबर 2016 को ओईसीडी एसटीआई नीति प्रभाग एवं यूनेस्को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति प्रभाग, पेरिस में आयोजित चर्चा बैठकों में भाग लिया।
- 1 फरवरी 2017 को कानून संकाय, यूसीएल, लंदन में 'प्रतिस्पर्धा कानून में वैश्विक वैल्यू चेन' पर आयोजित सम्मेलन में वैश्विक वैल्यू चेन, बीजों और प्रतिस्पर्धा कानून पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 मार्च 2017 को सिराड, मॉन्टेपिलर, फ्रांस में 'विकल्पों की तैयारी?: पौधों की किस्मों/बीजों के लिए लोक और खुला स्रोत दृष्टिकोण' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- 22 मार्च 2017 को सीसीएस, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू में 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियां एवं पहुंच, समानता तथा समावेशः सिद्धांत, व्यवहार और मापन से जुड़े मुद्दों' पर भाषण दिया।

डॉ. प्रियदर्शी दास

fj l p ,lkfl ,V

- 6–9 जुलाई 2016 के दौरान चीन के चेंगदू स्थित सिचुआन यूनिवर्सिटी (आईएसएएस) के दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान में आयोजित दूसरे एसएडब्ल्यूसीसीएडी–वीआईएफ संवाद के दौरान 'भारत–चीन आर्थिक संबंध; वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के एक वैकल्पिक विवरण को सही स्वरूप प्रदान करना' विषय पर प्रस्तुति दी। 15–16 अक्तूबर 2016 को ढाका, बांग्ला देश में सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी) द्वारा आयोजित 9वें दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन में 'दक्षिण एशिया में विकास का वित्तपोषणः पारंपरिक दृष्टिकोणों से आगे' में प्रस्तुति दी।
- 27 अक्तूबर 2016 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित 'स्वर्ण नीति–विजन 2020' पर गोल मेज चर्चा पर भाग लिया।

- 22 मार्च 2017 को चोंगयांग इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज (आरडीसीवाई), रेनमिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, बीजिंग, चीन में वित्तीय सहयोग को सुदृढ़ करने और ब्रिक्स विकास को बढ़ावा देने पर आयोजित 2017 ब्रिक्स थिंक टैंक संगोष्ठी में 'ब्रिक्स वित्तीय सहयोगः चिन्हित क्षेत्रों और भविष्य में गुंजाइश' पर एक प्रस्तुति दी।
- 23 मार्च 2017 को दक्षिण एशिया–पश्चिम चीन सहयोग और विकास अध्ययन केंद्र, सिचुआन विश्वविद्यालय, चेंगदू, चीन में 'ब्रिक्स की संभावनाएं: ब्रिक्स फोरम में चीन–भारत सहयोग' पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. सब्यसाची साहा

lgk;d çkQlj

- 11 मई 2016 को आयोजित दक्षिणी थिंक टैंक नेटवर्क (नेस्ट) और बीएमजेड की बैठक में जर्मन सरकार, बर्लिन के संघीय आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय (बीएमजेड) के प्रतिनिधि थे।
- 12–13 मई 2016 को जर्मनी के बर्लिन में शंघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (एसआईआईएस), जर्मन विकास संस्थान (डीआईई) और फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन (एफईएस) द्वारा आयोजित टी20 बर्लिन सम्मेलन के दौरान 'व्यापार और निवेश' विषयक सत्र में प्रतिभागी थे।
- 31 मई 2016 को नई दिल्ली में बिजनेस स्टैंडर्ड और भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ द्वारा 'विनिमय दर एवं निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता' पर आयोजित परिचर्चा में परिचर्चा थे।
- 21 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटैबिलिटी (सीबीजीए) एवं फाइनेंशियल ट्रांसपैरेसी कोलिशन द्वारा आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं वित्तीय पारदर्शिता में सुधार : एशिया के लिए एक क्षेत्रीय एजेंडा की दिशा में ' पर आयोजित कार्यशाला परिचर्चा में भाग लिया।

IV

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

विज्ञान कूटनीति पर भारतीय तकनीकी एवंम आर्थिक सहयोग कार्यक्रम

आरआईएस ने 'विज्ञान कूटनीति पर भारतीय तकनीकी एवंम आर्थिक सहयोग कार्यक्रम क्षमता निर्माण कार्यक्रम' का शुभारंभ किया जो 9–20 जनवरी, 2017 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत

आरआईएस संकाय के सदस्यों के साथ विज्ञान कूटनीति पर भारतीय तकनीकी एवंम आर्थिक सहयोग कार्यक्रम कार्यक्रम के प्रतिभागीगण।

भाषण के साथ उद्घाटन सत्र की शुरुआत हुई। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) के निदेशक प्रो. बलदेव राज ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री दिनकर अस्थाना, संयुक्त सचिव (डीपीए ण्), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. साधना रेलिया, प्रमुख, (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने भी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। डॉ. अमित कुमार, रिसर्च एसोसिएट, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। 21 देशों के 32 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

विज्ञान कूटनीति पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम में ये विषय शामिल थेः संस्कृति और विज्ञान कूटनीति, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान और सेवाओं की तलाश में वैश्विक सहभागिता– एक भारतीय अनुभव, एसटीआई में दक्षिण–दक्षिण और उत्तर–दक्षिण व्याख्यान, विज्ञान कूटनीति और एसडीजी, क्षेत्रवार फोकसः स्वास्थ्य तनाव प्रबंधन, कृषि, विज्ञान कूटनीति और टीएफएम, भारत की विदेश नीति में दोहरे उपयोग वाला एसएंडटी, भारतीय विज्ञान कूटनीतिः कुछ परिवर्तनकारी लम्हे, एक विज्ञान पत्रकार की वृहद राय, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विज्ञान कूटनीति की भूमिका, नीली अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सीडीएम, दक्षिण में क्षमता निर्माण में विज्ञान कूटनीति की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय आरएंडडी ढांचा और विज्ञान कूटनीति, ग्रामीण नवाचार और विज्ञान कूटनीति, तकनीकों में सामंजस्य–अवसर और चुनौतियां, और विज्ञान कूटनीति का उपयोग करके एसएससी को मजबूत करना।

प्रतिभागियों को संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ता ये थेः डॉ. टी. रामासामी, पूर्व सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, डॉ. शैलेश नायक, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं पूर्व सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. वी. सिद्धार्थ, भारत के प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद के पूर्व सचिव एवं एमेरिटस वैज्ञानिक, डीआरडीओ, डॉ. एच. पुरुषोत्तम, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी), डॉ. एस आर राव, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, डॉ. एस.के. सक्सेना, निदेशक, भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद, डॉ. सचिन गोयल, वरिष्ठ सलाहकार, अंर्तनाद, प्रो. प्रणव एन देसाई, प्रोफेसर, विज्ञान नीति में अध्ययन के लिए केंद्र, जेएनयू, प्रो. आराधना अग्रवाल, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, डेनमार्क, डॉ. प्रवीण अरोड़ा, प्रमुख, कोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, डॉ. राजेश्वरी रैना, प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर–राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (एनआईएसटीएडीएस), डॉ. पल्लव बागला, विज्ञान संपादक, एनडीटीवी और स्तंभकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास नीति पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवंम आर्थिक सहयोग कार्यक्रम/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत 13 फरवरी, 2017 से लेकर 10 मार्च 2017 तक नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास नीति (आईईआईडीपी)' पर अपना वार्षिक प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। 24 देशों के 32 से ज्यादा प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में इन विषयों को शामिल किया गयाः बहुपक्षवाद, मेगा क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाएं एवं विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ढांचा और बहुपक्षवाद के लिए चुनौतियां, विकासशील देशों में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर समझौता, दक्षिण में आर्थिक सहयोग की एक धुरी के रूप में विकास समझौता,

जी–20 का महत्व और वैश्विक वित्तीय ढांचे के मुद्दे, सेवाओं का व्यापार और गेट्स, वैश्विक शासन के संदर्भ में दक्षिण–दक्षिण सहयोग, 'एशिया–प्रशांत व्यापार एवं निवेश रिपोर्ट (एपीटीआईआर) 2016ः मुख्य निष्कर्ष और क्षेत्र के लिए निहितार्थ', डब्ल्यूटीओ में एंटी–डंपिंग और सब्सिडी से संबंधित मुद्दे, मेगा क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं का उभरता ढांचा, एजेंडा 2030 और एसडीजी को समझना, पेरिस जलवायु समझौता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एसडीजी को अपनाना एवं स्थायित्व की चुनौतियां, स्थायित्व सुनिश्चित करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सहयोग, विकासशील देशों में सांख्यिकी प्रणालियां और एसडीजी संकेतक, पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता की पुनर्संरचनाः नए अवसर और चुनौतियां, विकासशील देश एवं सतत ऊर्जा, भारत–अफ्रीका साझेदारी की उभरती गतिशीलता, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण, भारत–यूरोपीय संघ के संबंधः आगे की राह, विकासशील देश के नजरिए से जी–20 और ब्रिक्स को समझना, और भारत का ऊर्जा क्षेत्र।

आरआईएस संकाय के सदस्यों के साथ भारतीय तकनीकी एवंम आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के प्रतिभागीगण।

विकासशील देशों के बीच सहयोग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी)/अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रकुल सहायता कार्यक्रम (एससीएएपी) के तहत आरआईएस ने 15–25 नवंबर, 2016 के दौरान नई दिल्ली में विकासशील देशों के बीच सहयोग के बारे में शिक्षा पर एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को विकासशील देशों के बीच सहयोग (एसएससी) की व्यापक अवधारणा, विशेष रूप से वैश्विक सहायता ढांचे में देखे जा रहे व्यापक बदलावों के बाद विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में जारी पुनरुत्थान के परिप्रेक्ष्य में विकास सहयोग के बारे में परिचित कराना था। बैठक में अन्य बातों के अलावा संबंधित देशों की एकल उपलब्धियों के आधार पर एसएससी के औचित्य, अवधारणा

एवं रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके जरिये उन्हें एसएससी से होने वाले लाभों एवं उनकी सामूहिक भागीदारी के मार्ग की बाधाओं के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में प्रमुख सिद्धातों, नीतियों, तौर–तरीकों (जिनमें राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय स्वामित्व, स्वतंत्रता, समानता, गैर–शर्त, गैर–हस्तक्षेप एवं आपसी लाभ शामिल हैं) और प्रचलनों पर गौर किया गया जो पूरे एसएससी के दौरान स्पष्ट थी और साथ ही, इस पर भी गौर किया गया कि किस प्रकार नीतिगत झुकावों और एसएससी की ताकतों को व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान इस पर चर्चा की गई कि किस प्रकार एसएससी विकसित–विकासशील देशों के सहयोग (एनएससी) से एक अलग प्रतिमान है और किस प्रकार एसएससी को एक स्वैच्छिक साझीदारी के रूप में देखा जाना चाहिए जो अब राजनीतिक एकजुटता की प्रारंभिक बुनियादों से ऊपर उठ कर एक अधिक परिपक्व मंच में विकसित हो गया था न कि किसी के रूप में एनएससी के एक स्थानापन्न के रूप में।

इस कार्य में विभिन्न देशों से आये 28 प्रतिनिधियों ने वा अन्य मंत्रालयों, विदेश मामले/वित्त/वाणिज्य तथा अन्य मंत्रालयों से संबंधित सिविल सोसाइटी से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे लोगों ने भाग लिया। बौद्धिक सत्रों के अतिरिक्त, एक अध्ययन दौरे का भी आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को समूह चर्चाओं एवं प्रस्तुतिकरणों के माध्यम से उनके अध्ययन परिणामों को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

आरआईएस संकाय के सदस्यों के साथ भारतीय तकनीकी एवंम आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के प्रतिभागीगण।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और अमल पर आरआईएस ग्रीष्मकालीन कार्यशाला

संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले विद्वानों के क्षमता निर्माण में योगदान देने के लिए आरआईएस ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता हासिल कर रहे एम. फिल और पीएचडी छात्रों के लिए अपना पहला ग्रीष्मकालीन कार्यशाला शुरू किया। यह कार्यक्रम 6 जून से लेकर 10 जून 2016 तक आयोजित किया गया था। पहले दिन प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस और डॉ. नागेश कुमार, प्रमुख, यूएन–एस्कैप दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय ने उद्घाटन भाषण दिए। प्रो. एस.के. मोहंती ने व्यापार डेटा के बारे में विशेष व्याख्यान दिया। प्रो. शाहिद अहमद, जामिया मिलिया इस्लामिया ने उद्योग और व्यापार डेटाः सामंजस्य से जुड़े मुद्दों पर व्याख्यान दिया। डॉ. प्रियदर्शी दास ने सेवाओं के व्यापार से जुड़े डेटा पर एक व्याख्यान दिया। दूसरे दिन, प्रो. मनोज पंत, जेएनयू ने 'व्यापार सिद्धांतः नई सीमाएं लांघने' पर व्याख्यान दिया। प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस ने एफटीए और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर व्याख्यान दिया। डॉ. सब्यसाची साहा, आरआईएस ने 'व्यापार संबंधी सुअवसर में प्रौद्योगिकी की तीव्रता' के बारे में बताया। प्रो. विजया कट्टी, आईआईएफटी ने भारत में व्यापार नीति की रूपरेखा पर अपने विचार पेश किए। तीसरे दिन का शुभारंभ प्रो. अभिजीत दास, प्रमुख एवं प्रोफेसर, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा विश्व व्यापार संगठन और एफटीए पर दिए गए व्याख्यान के साथ हुआ। इसके बाद डेटा, कार्यप्रणाली एवं तकनीक, प्रौद्योगिकी एवं व्यापार और विश्व व्यापार संगठन एवं एफटीए पर समूह चर्चाएं आयोजित की गईं। प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती, शारदा विश्वविद्यालय एवं विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने कृषि संबंधी व्यापार पर एक व्याख्यान दिया। राजदूत जयंत दासगुप्ता, विश्व व्यापार संगठन में भारत के पूर्व राजदूत ने नए मुद्दों का उल्लेख किया। चौथे दिन का शुभारंभ डॉ. नीलम सिंह द्वारा व्यापार और प्रौद्योगिकी पर दिए गए व्याख्यान के साथ हुआ। श्री अरविंद मेहता, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने भारत के व्यापार संबंधों और रणनीतियों पर व्याख्यान दिया। एनसीएईआर के प्रो. राजेश चड्ढा ने जीटीएपी के प्रतिरूपण (मॉडलिंग) और व्यापार की संपूरकता के बारे में बताया। डॉ. नित्या नंदा, टेरी ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रतिरूपण और व्यापार संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आखिरी

डॉ. नागेश कुमार उद्घाटन भाषण देते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) डॉ. प्रियदर्शी दास, प्रो. एस. के. मोहंती और डॉ. सब्यसाची साहा।

दिन डेटा, कार्यप्रणाली एवं तकनीक, प्रौद्योगिकी एवं व्यापार और डब्ल्यूटीओ एवं एफटीए पर समूह चर्चाएं हुईं। प्रो. रजत कथुरिया ने मेगा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर एक व्याख्यान दिया। समापन सत्र में प्रो. सचिन चतुर्वेदी और प्रो. एस. के. मोहंती ने प्रमाण पत्र वितरित किए।

व्यापार सुविधाः वैश्विक कार्यसूची और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर कार्यशाला

आरआईएस व्यापार और निवेश क्षमता के निर्माण से संबंधित अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के जरिए क्षमता निर्माण में म्यांमार की सहायता करता है। इसके तहत आरआईएस ने बैंकाक स्थित संयुक्त राष्ट्र के एशिया–प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनएस्कैप), म्यांमार स्थित आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र (सीईएसडी) और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से 12–13 मई 2016 को यूएमएफसीसीआई, यांगून में 'व्यापार सुविधा : वैश्विक एजेंडा और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं' पर छठी कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के दौरान व्यापार सुविधा के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को कवर करने वाले छह सत्र आयोजित किए गए। श्री सोए विन, उप महानिदेशक, म्यांमार वाणिज्य मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया। डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस और डॉ. तैंगफेई वैंग, आर्थिक मामलों के अधिकारी, व्यापार सुविधा यूनिट, व्यापार, निवेश और नवाचार प्रभाग (टीआईआईडी), यूएनएस्कैप, बैंकॉक ने प्रतिभागियों के लिए कार्यशालाओं की शुरुआत की। कार्यशाला में इन विषयों पर व्याख्यान दिए गए थे : 'व्यापार सुविधा क्यों?, बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में व्यापार सुविधा और व्यापार सुविधा डेटाबेस का प्रदर्शन एवं विश्लेषण' पर डॉ. प्रबीर डे का व्याख्यान, 'व्यापार प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का विश्लेषण करनाः कारोबारी प्रक्रिया विश्लेषण (बीपीए)' पर श्री तैंगफेई वैंग और डॉ. प्रबीर डे का व्याख्यान, 'व्यापार सुविधा प्रदर्शन को मापनाः व्यापार एवं परिवहन सुविधा निगरानी व्यवस्था (टीटीएफएमएम)' पर श्री तैंगफेई वैंग का व्याख्यान, 'म्यांमार में व्यापार प्रक्रियाओं के कारोबारी प्रक्रिया विश्लेषण (बीपीए)' पर कैप्टन आंग खिन मिंट, अध्यक्ष, म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय माल अग्रेषक (फॉरवर्डर) संघ और अध्यक्ष, जीएमएस माल परिवहन संघ (जीएमएस फ्रेटा), यांगून का व्याख्यान। कार्यशाला विविध समूह अभ्यास के साथ संपन्न हुई।

क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण पर कार्यशाला

म्यांमार के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत आरआईएस ने बैंकाक स्थित यूएनएस्कैंप, म्यांमार स्थित सीईएसडी और म्यांमार वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से 9 से लेकर 11 मई 2016 तक यांगून में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के उप महानिदेशक श्री सोए विन ने उद्घाटन भाषण दिया था। डॉ. मिया मिकिक, प्रमुख, व्यापार नीति अनुभाग, व्यापार नीति एवं विश्लेषण – व्यापार, निवेश और नवाचार प्रभाग (टीआईआईडी), यूएनएस्कैप, बैंकाक और डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस ने प्रतिभागियों को कार्यशालाओं के उद्देश्यों से अवगत कराया। कार्यशाला को ग्यारह सत्रों में विभाजित किया गया था और इस दौरान क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण के कई पहलुओं को कवर किया गया था। डॉ. मिया मिकिक और डॉ. प्रबीर डे ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में विशिष्ट

जानकारियां दीं। कार्यशाला में इन विविध विषयों पर व्याख्यान दिए गए थे : डॉ. मिया मिकिक द्वारा 'व्यापार सिद्धांत एवं क्षेत्रीय एकीकरण' विषय पर, प्रो. अजित्व रायचौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा 'दुनिया में क्षेत्रीय एकीकरणः राजनीतिक एवं आर्थिक आयाम' विषय पर, श्री स्जम्सू रहार्द्जा, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, व्यापार एवं प्रतिस्पर्धात्मकता, विश्व बैंक, म्यांमार द्वारा 'म्यांमार की विकास रणनीति के संदर्भ में क्षेत्रीय व्यापार समझौते' विषय पर, प्रो. अजित्व रायचौधरी द्वारा 'क्षेत्रीय एकीकरण के सिद्धांत एवं रूपरेखाः आसियान एवं बिम्सटेक की भिन्न गाथाएं' विषय पर, डॉ. मिया मिकिक द्वारा 'डब्ल्यूटीओ एवं क्षेत्रीय एकीकरण (डब्ल्यूटीओ के आरटीए डेटाबेस एवं एस्कैप एपीटीआईएडी के प्रदर्शन सहित) और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में आरटीए की विशेषताएं' विषय पर, प्रो. प्रबीर डे द्वारा 'क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय पहलों (आसियान, बीबीआईएन, बीसीआईएम, बिम्सटेक, सार्क) में म्यांमार' विषय पर, डॉ. मिया मिकिक द्वारा 'एशिया में मेगा–क्षेत्रीय साझेदारियां (टीपीपी, आरसीईपी, ईएईयू)' विषय पर, श्री थॉमस बर्नहार्ट, शोधकर्ता एवं नीति विश्लेषक, म्यांमार आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र (सीईएसडी), यांगून द्वारा 'वैश्विक मूल्य श्रृंखला एवं तरजीही व्यापार समझौते' विषय पर और डॉ. मिया मिकिक, डॉ. प्रबीर डे एवं प्रो. अजित्व रायचौधरी द्वारा 'डेटाबेस एवं विश्लेषण' विषय पर। कार्यशाला विविध समूह अभ्यास के साथ संपन्न हुई थी।

आरआईएस के संकाय (फैकल्टी) के सदस्यों द्वारा बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिए गए व्याख्यान

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

egkfun'kd

- विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान द्वारा 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित किए गए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत–अफ्रीका संबंधः नई आर्थिक वास्तविकता' पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 27 मार्च 2017 को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा भारत के विकास सहयोग से जुड़ी कैपस्टोन 10 परियोजना पर आयोजित की गई आरंभिक कार्यशाला में 'भारत के गतिशील विकास सहयोग' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. राम उपेंद्र दास

- 13 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में आईआईएफटी द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मारुति सुजुकी लिमिटेड के लिए व्यापार समझौतों' पर आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'आरटीए, जीएटीटी अनुच्छेद–24 और उद्गम स्थल के नियम' पर एक व्याख्यान दिया।
- 3 अक्तूबर 2016 को विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'डब्ल्यूटीओ, पीटीए एवं विकासशील देशों पर आसियान राजनयिकों के लिए 10वें विशेष कोर्स को संबोधित किया।

प्रो. टी.सी. जेम्स

fof t fVax Qsyks

- 4, 5 और 18 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिशद (टीआईएफएसी) की बैठक में युवा वैज्ञानिकों के समक्ष 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' पर व्याख्यान दिए।
- 13 मई 2016 को मानव संसाधन विकास केंद्र, गाजियाबाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिशद (सीएसआईआर) के तकनीकी अधिकारियों के समक्ष 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' और 'अनुसंधान में नैतिक सिद्धांतों' पर व्याख्यान दिया।
- 28 मई 2016 को दिल्ली न्यायिक अकादमी में बौद्धिक संपदा कानून के विभिन्न उपखंडों पर दिल्ली के जिला न्यायाधीषों को संबोधित किया।
- 16 जून 2016 को नई दिल्ली स्थित राश्ट्रीय कानून विष्वविद्यालय में कानून के षिक्षकों के लिए रिफ्रेषर कोर्स के प्रतिभागियों को पेटेंट कानून के बारे में बताया।
- 12 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिशद के युवा वैज्ञानिकों को संबोधित किया।
- 14 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में अंतर्राश्ट्रीय कानून के लिए भारतीय सोसायटी द्वारा विपो सुमेर स्कूल में आयोजित संवाद के दौरान भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 पर व्याख्यान दिया।
- 15 सितंबर 2016 को नई दिल्ली स्थित आईआईएफटी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रषिक्षुओं के समक्ष बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक व्यांख्यान दिया।
- 4 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ द्वारा आयोजित 'एमएसएमई के लिए बोद्धिक संपदा पर संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एमएसएमई के लिए भौगोलिक संकेतकों के महत्व पर एक व्याख्यान दिया।

V

प्रकाशन कार्यक्रम

रिपोर्ट/पुस्तकें

दक्षिण–दक्षिण सहयोग 2016: सम्मेलन की कार्यवाही
आरआईएस, 2016

एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश और पद्धतियां विकसित करना
आरआईएस, जीआईडीआर, आईएआरआई, आईएसईसी, एनएएआरएम, टीएनएयू, यूएएस के सहयोग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

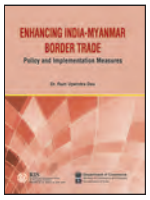

भारत–म्यांमार सीमा व्यापार बढ़ाना: नीति और कार्यान्वयन के उपाय
राम उपेंद्र दास, आरआईएस, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 2016

आसियान–भारत हवाई कनेक्टिविटी रिपोर्ट
आरआईएस में एआईसी, 2016

चेन्नई में भारतीय विकास सहयोग मंच क्षेत्रीय परामर्शः कार्यवाही का सार
आरआईएस, भारतीय विकास सहयोग मंच, 2016

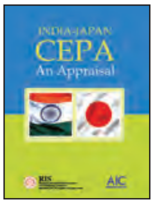

भारत–जापान सीईपीएः प्रगति का आकलन
वी.एस. शेषाद्री, आरआईएस, 2016

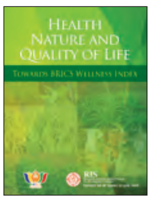

स्वास्थ्य, स्वभाव और जीवन की गुणवत्ता; ब्रिक्स वेलनेस इंडेक्स की ओर
आरआईएस, 2016

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा
आरआईएस, 2016

भारत और टिकाऊ विकास लक्ष्य : भविष्य का रास्ता (इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स : द वे फॉरवर्ड)
आरआईएस, नई दिल्ली, 2016

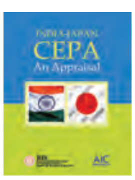

इंडिया–जापान सेपा : ऐन अप्रेजल
वी.एस.शेषाद्री
आरआईएस एंड एआईसी, नई दिल्ली, 2016

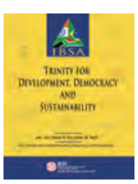

इब्सा : ट्रिनिटी फॉर डेवलपमेंट, डेमोक्रैसी एंड सस्टेनेबिलिटी
आरआईएस, नई दिल्ली, 2016

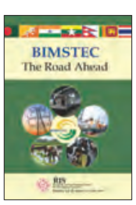

बिम्सटेक : द रोड अहेड
आरआईएस, नई दिल्ली, 2016

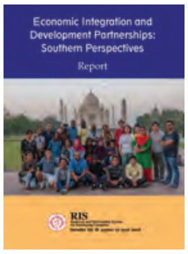

आर्थिक एकीकरण एवं विकास साझेदारियांः दक्षिणी परिप्रेक्ष्य

आरआईएस, नई दिल्ली, 2017

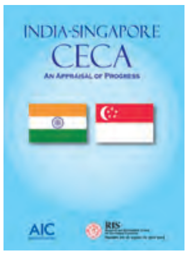

भारत–सिंगापुर सीईसीएः एक आकलन

आरआईएस एवं एआईसी, नई दिल्ली, 2017

हार्ट आफ एशिया एवं कनेक्टिविटी पर संगोष्ठी की रिपोर्टः कार्यवाही का सार

आरआईएस, नई दिल्ली, 2017

जर्नल

साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल

खंड 17, नंबर 1

खंड 17, नंबर 2

एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास समीक्षा

खंड 18, नंबर 2, जुलाई, 2016

खंड 18, नंबर 3, नवंबर 2016

खंड 19, नंबर 1, मार्च 2017

नीति सार

#77 bfM;u bdkukWeh ,M fMekuVkbts'ku% o QkjoM

सुभोमय भट्टाचार्जी, जनवरी 2017

#76 QkbufIlx VDukykth fMfyojh Qkj ,lMhth % v o QkjoM Qkj Vh,Q,e

सचिन चतुर्वेदी, सब्यसाची साहा, नवंबर, 2016

#75 nf{k.k ,f'k;k e vlg;kx dh dher(,d –"Vkr vkj vkx dh jkg

राम उपेंद्र दास, सितंबर, 2016

परिचर्चा प्रपत्र

#203 fodkl d,EiDV% nf{k.k&nf{k.k lg;kx d fy, ,d l)kfrd jpuk

सचिन चतुर्वेदी

#204 Hkkjr d fodkl lg;kx e ,d lk/ku d :i e ,yvklh dk mnHko % mHkjr uhfrxr lnHk vkj ubl pukfr;k

प्रबोध सक्सेना

#205 n fcDl bfuf'k,fVo % VoMl , U;; Qkbuf'k;y vkfdVDpj% ,u vlLeV fon le iikptYl]

सुनंदा सेन

#206 bfM;k&vÝhdk lhM lDVj dkyckj'kl % beftx iLiDVl ,o pyt

टी.पी.राजेंद्रन एवं अमित कुमार

#207 VM bu gkbl VDukykth ikMDVl VMl ,M ikfylh bEijfV0l Qkj fcDl

सचिन चतुर्वेदी, सब्यसाची साहा एवं प्रातिव शॉ

#208 fjofllx çh&eP;kj MhbMfLV;ykbt'ku Qkj tkCl fØ,'ku% yll Qkj ^ed&bu&bfM;k* Ýke ,Dlihfj,ll t vkQ bMfLV;ykbTM ,M bLV ,f'k;u dVht

नागेश कुमार

ब्लू इकोनोमी नीति सार

fQ'kjht lDVj bu vkbvkvkj, % Mkbfox Qkll bu jhtu^l Cy bdkukeh

एस.के.मोहंती, प्रियदर्शी दास एवं आस्था गुप्ता, आरआईएस, नई दिल्ली

भारतीय विकास सहयोग मंच नीति सार

#9 V ,,lMh % lkmnjukbtku vkQ vkMh,

सचिन चतुर्वेदी, मिलिन्दो चक्रबर्ती, हेमंत शिवा, नवंबर 2016

भारतीय विकास सहयोग मंच परिचर्चा प्रपत्र

#2 buckmM bVju'kuy LVMV ekfcfyVh bu bfM;k % ikFk V vphocy lDll

विद्या राजीव येरावदेकर

आरआईएस डायरी

अंक 13 संख्या 2, अप्रैल, 2016

अंक 13 संख्या 3, जुलाई, 2016

अंक 13 संख्या 4, अक्तूबर, 2016

अंक 14 संख्या 1, जनवरी, 2017

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन. 2016. 'स्वास्थ्य कूटनीति की ओरः भारत के दक्षिण–दक्षिण स्वास्थ्य सहयोग में उभरते रुझान' सचिन चतुर्वेदी और एंथिया मुलाकाला (संपादक) *इंडियाज एप्रोच टू डेवलपमेंट कोऑपरेशन*। रूटलेज समकालीन दक्षिण एशिया श्रृंखला। न्यूयॉर्क रूटलेज।

चतुर्वेदी, सचिन और एंथिया मुलाकाला (संपादक) (2016)। *इंडियाज एप्रोच टू डेवलपमेंट कोऑपरेशन*। रूटलेज समकालीन दक्षिण एशिया श्रृंखला, रूटलेज।

चतुर्वेदी, सचिन, के.वी. श्रीनिवास और वी. मुथुस्वामी। 2016. 'भारत में बायोबैंकिंग और गोपनीयता।' *द जर्नल ऑफ लॉ, चिकित्सा और नैतिकता*, 44 (1), 45–57.

चतुर्वेदी, सचिन. 2016. 'दांव पर स्वास्थ्य सुरक्षा।' *इंडियन एक्सप्रेस*, 25 अगस्त।

चतुर्वेदी, सचिन. 2016. 'ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता संस्थागत कुशलता को प्रोत्साहित करती है।'' *द इकोनॉमिक टाइम्स*, 31 अगस्त।

चतुर्वेदी, सचिन. 2016. 'आर्थिक कूटनीति में सयाना होता देश'. *इंडिया टूडे* (हिन्दी वर्षगांठ संस्करण), 30 नवंबर, पीपी 73–75।

दास, राम उपेंद्र. 2016. 'एशिया–यूरोप कनेक्टिविटी ; वर्तमान स्थिति, बाधाएं, और आगे की राह' अनिता प्रकाश (संपादक) *एशिया–यूरोप कनेक्टिविटी विजन 2025 ; चुनौतियां और अवसर*। जकार्ता ; ईआरआईए और विदेश मंत्रालय, मंगोलिया सरकार।

दास, राम उपेंद्र. 2016. 'हाऊ टू टेक रशिया–इंडिया इकोनोमिक्स टाइज टू नेक्स्ट लेवल' *रशिया डायरेक्ट*. 15 अक्तूबर.

दास, राम उपेंद्र 2016. 'मध्य एशियाई गणराज्य 'श्री जूंग–वान चो और श्री राजन सुदेश रत्न (संपादक): *एशिया–प्रशांत व्यापार समझौताः दक्षिण–दक्षिण क्षेत्रीय एकीकरण और सततविकास को प्रोत्साहन,* बैंकाकः यूएनएस्कैप।

दास, राम उपेंद्र। 2016. 'एशिया–प्रशांत व्यापारसमझौताः भविष्य् का रोडमैप' श्री जूंग–वान चो और श्री राजन सुदेश रत्न (संपादक): *एशिया–प्रशांत व्यापार समझौताः दक्षिण–दक्षिण क्षेत्रीय एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा,* बैंकाकः यूएनएस्कैप।

दास, राम उपेंद्र और अनूप कुमार झा। 2017. 'भारत,रूस 2017 में भू–राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे।' *रूस एंड इंडिया रिपोर्ट*। रूस बेयांड द हेडलाइंस, 23 जनवरी

दास, राम उपेंद्र। 2017. ' सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे की ओर सुसंगत जी20 नीतियां' *जी20 इनसाइट्स,* 10 मार्च।

दास, पी. 2016. 'एआईआईबी; हर किसी को साथ ले जा रहा है?' असाधारण और पूर्णाधिकारी कूटनीतिज्ञ, खंड 4, अंक 8, अगस्त, पीपी. 42–46.

डे, प्रबीर और अजित्व रायचौधरी। 2016. 'चुनिंदा एशियाई देशों में व्यापार, बुनियादी ढांचा एवं आय विषमताः एक अनुभवजन्य विश्लेषण' , मालबिका रॉय और सैकत सिन्हा रॉय (संपादक) *अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तः समकालीन मुद्दों का पता लगाना।* नई दिल्ली : स्प्रिंगर, मई।

डे, प्रबीर एवं मुस्ताफिजुर रहमान (संपादक). 2016. रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया : एस्सेज इन ऑनर ऑफ डा. एम. रहमतुल्लाह. *नॉलेज वर्ल्ड.* नई दिल्ली.

डे प्रबीर. 2016. डे, प्रबीर एवं सुतिफंड चिराथिवत (संपादक) में 'लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट : कनेक्टिविटी चैलेंजेज इन इंडिया'ज नॉर्थ ईस्ट'. सेलेब्रेटिंग द थर्ड डिकेड एंड बियोंडः न्यू चैलेंजेज टू आसियान–इंडिया इकोनोमिक पार्टनरशिप. *नॉलेज वर्ल्ड,* नई दिल्ली.

डे, प्रबीर. 2016. डे, प्रबीर एवं मुस्ताफिजुर रहमान (संपादक). में 'बीबीआईएन एमवीएः गुड बिगनिंग बट मेनी चैलेंजेज'। रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया : एस्सेज इन ऑनर ऑफ डा. एम. रहमतुल्लाह. *नॉलेज वर्ल्ड,* नई दिल्ली.

डे प्रबीर. 2016. डे, प्रबीर एवं सुतिफंड चिराथिवत (संपादक) में 'लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट : कनेक्टिविटी चैलेंजेज इन इंडिया'ज नॉर्थ ईस्ट'. सेलेब्रेटिंग द थर्ड डिकेड एंड बियोंडः न्यू चैलेंजेज टू आसियान–इंडिया इकोनोमिक पार्टनरशिप. *नॉलेज वर्ल्ड,* नई दिल्ली।

डे, प्रबीर। 2017. 'बिम्सटेक और आईओआरए के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीके', योगेंद्र कुमार (संपादक) कहां है भारतीय महासागर समुद्री आदेश? नरेंद्र मोदी के सागर भाषण पर संगोष्ठी में योगदान, नॉलेज वर्ल्ड, नई दिल्ली

डे, प्रबीर और श्रेया पैन। 2017. भारत और मंगोलिया के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत करनाः कार्य और अवसर। *नॉलेज वर्ल्ड* , नई दिल्ली

जेम्स, टी.सी. 2016. 'औषधीय एवं सुगंधित पौधों (जड़ी–बूटियां और उनसे संबद्ध उत्पाद) से संबंधित बोद्धिक संपदा मुद्दे।' *पारंपरिक और लोक प्रथाओं का जर्नल,* खंड 02, 03, 04 (1) जून।

जेम्स, टी.सी. 2016. '*अफ्रीका–भारत स्वास्थ्य भागीदारी*।' अफ्रीका पॉलिसी रिव्यू 2016–17.

कुमारस्वामी, दुरैराज एवं इमदादुल इस्लाम हल्दर. 2016. डे, प्रबीर एवं सुतिफंड चिराथिवत (संपादक में ' ट्रेड इन सर्विसेज इन एशिया पैसिफिक। असेसिंग बैरियर्स एंड इंप्लीकेशंस फॉर सर्विसेज ट्रेड फैसिलिटेशन इन इंडिया ', सेलेब्रेटिंग द थर्ड डिकेड एंड बियोंड : न्यू चैलेंजेज टू आसियान–इंडिया इकोनोमिक पार्टनरशिप. *नॉलेज वर्ल्ड,* नई दिल्ली.

श्रीनिवास, के. रवि। 2017. 'विज्ञान में सार्वजनिक सहभागिता क्यों मायने रखती है।' जैव प्रौद्योगिकी में रुझान, खंड 35 अंक 4 अप्रैल।

VI

आंकड़े एवं सूचना केन्द्र

डॉ. सुखामय चक्रवर्ती पुस्तकालय विश्व अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दुनिया की व्यापारिक प्रणालियों, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली, दक्षेश, आसियन, और आईओआर–एआरसी, जैसे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सहित दक्षिण–दक्षिण सहयोग, पूंजी के प्रवाह, एफडीआई, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वहनीय विकास जैसे मुद्दों पर पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी प्रकाशनों, दूसरे शोध संस्थानों के मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों के प्रचुर संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान के अग्रणी शोध संस्थान के रूप में काम करते हुए संस्था के काम–काज का अविभाज्य अंग रहा है। पुस्तकालय न केवल आरआईएस के शोधकर्ता संकाय को समर्थन प्रदान करता है बल्कि पूरे देश के नीति निर्मांताओं, प्रशासकों, सलाहकारों और छात्रों को भी समर्थन देता है। इस वर्ष से पुस्तकालय स्कूल छात्रों के लिए भी खुला है। अभिलेखन केंद्र की अभिलेख संग्रह नीति आरआईएस के शोध संकाय की आवश्यकताओं से निर्देशित होने के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इत्यादि के क्षेत्र में इसे महत्त्वपूर्ण सूचना केंद्र बनाने की व्यापक नीति से संचालित होती है। विषेश संग्रह–सांख्यकीय प्रकाशनों में कृषि सांख्यकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यकी, बजट दस्तावेज़, श्रम सांख्यकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सांख्यकी, व्यापार और विकास सांख्यकी, आर्थिक दृष्टिकोण, एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, यूएनसीटीएडी, वर्ल्ड बैंक, डब्लूटीओ इत्यादि शामिल हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टें शामिल हैं। दस्तावेज़ों में कामकाजी पर्चे, चर्चा पर्चे, पुनर्मुद्रण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसांगिक संगठनों के मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त पर्चे या तो नियमित रूप से पारस्परिक आदान–प्रदान के अंतर्गत प्राप्त होते हैं या संस्थानिक वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाते हैं। ग्रंथालय के संग्रह में पंद्रह हज़ार से अधिक पुस्तकें शामिल हैं जिनमें विकास अध्ययन, अर्थशास्त्र, जनसांख्यकी, सांख्यकी, और दूसरे संबंधित विषयों की पुस्तकें हैं। यह इस समय 475 पत्र–पत्रिकाओं की नियमित ग्राहक है। इसके अलावा, इसे 50 से अधिक पत्र–पत्रिकाएं उपहार के रूप में या पारस्परिक आदान–प्रदान के तहत मिलती हैं। यह ग्रंथालय कई राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रकाशनों के आदान–प्रदान करता है।

अभिलेखन केंद्र के ग्रंथालय का संग्रह

- पुस्तकें
- सांख्यकीय वार्षिक संदर्भ पुस्तकें
- अभिलेख–डब्लूपी–ओपी–डीपी
- पत्र–पत्रिकाएं नियतकालिक (मुद्रित+ऑनलाइन+सीडी–रोम)
- अख़बार–भारतीय + अंतरराष्ट्रीय
- पिछले अंक
- सीडी रोम
- सीडी–रोम में डेटाबेस

आरआईएस का आंकड़ाकोष

डेटा बैंक के पास अच्छी तरह से अनुरक्षित डेटाबेस हैं। हमारे पास घरेलू अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहित व्यापर, निवेश, रोज़गार, पर्यावरण और उद्योगों के डेटाबेस हैं। अपनी परियोजनाओं के लिए डेटाबेस की उपयोगिता के मद्देनज़र इसे नियमित रूप से नवीन बनाई रखा जाता है।

वैश्विक आंकड़ाकोष:

- व्यापारिक डेटाबेस, टैरिफ़ और नॉन टैरिफ़ उपाय
- देय भुगतान
- वित्त सांख्यकी
- विकास सांख्यकी
- औद्योगिक सांख्यकी
- बौद्धिक संपदा सेवाएं, नीति, सूचना और वित्तीय निष्पादन

भारतीय आंकड़ाकोष:

- 8 डिजिटल स्तरों पर व्यापार पर टाइम सिरीज़ के डेटाबेस
- भारतीय कंपनियों के डेटाबेस और उनके वित्तीय निष्पादन
- सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस
- सीमा शुल्क का डेटाबेस

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन अभिलेखन केंद्र

आरआईएस के प्रकाशनों और उसके आयोजनों के अलावा वेबसाइट को वास्तविक

समय के आधार पर नवीनतम किया जाता है। शोध रिपोर्टों, नीति सारों, चर्चा पत्रों, सम्मेलन की रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना पत्रों और समाचार पत्रों में आरआईएस के संकाय सद्स्यों के लेखों जैसे सारे विवरण मुक्त रूप से डाउनलोड किए जा सकते हैं। शोध सामग्रियों को ट्विटर, फ़ेसबुक, और लिंक्डइन जैसी प्रमुख लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से साझा की जा सकती हैं। हिट्स की संख्या में वृद्धि के साथ आरआईएस की साइटों की लोकप्रियता दिनों–दिन बढ़ रही है। आरआईएस की वेबसाइट हमेशा गूगल द्वारा समर्थित तलाश परिणामों में सबसे ऊपर दिखाई देती है, जिसका आशय यह है कि वेबसाइट की दृश्यता सबसे अच्छी होती है। इस वेबसाइट की समाग्री को दुनिया भर में ग्राहक के अनुकूल बनाने के लिए आरआईएस की वेब साइट के पास भाषा अनुवाद है।

आरआईएस यूट्यूब चैनल

आरआईएस पास यूट्यूब चैनल जिसमें टीवी पर आरआईएस का कवरेज और आरआईएस के प्रमुख आयोजन शामिल हैं।

आरआईएस फैसबुक और ट्विटर पर

आरआईएस फेसबुक और ट्विटर पर उपलब्ध है। फेसबुक एकाउंट https://www.facebook.com/RISIndia और ट्विटर हैन्डल @RIS_NewDelhi है।

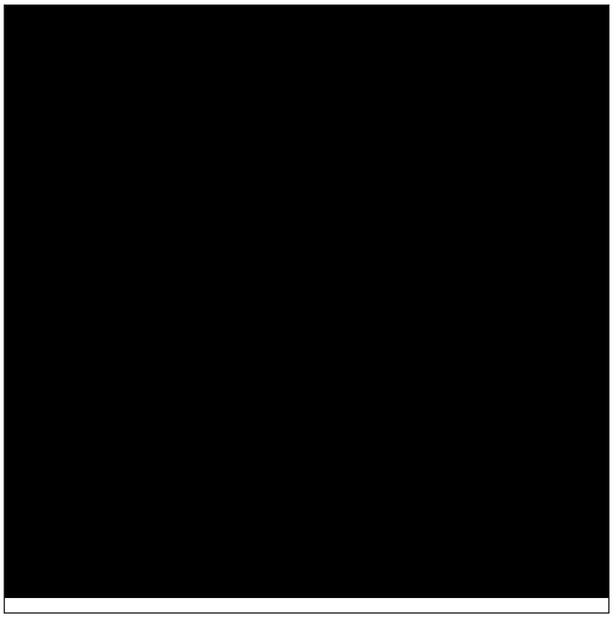

VII

मानव संसाधन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन तथा विकास सहयोग

संकाय

डॉ. एस के मोहंती
प्रोफेसर
विशेषज्ञताः वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

डॉ. राम उपेन्द्र दास (ओन लियन)
प्रोफेसर
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय एकीकरण एवं विकास संबंधी मामले

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर / समन्वयक, एआईसी
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

डॉ. बीना पाण्डेय
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

डॉ. साब्यासाची साहा
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञता: प्रौद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ. प्रियदर्शी दास
अनुसंधान एसोसिएट
विशेशज्ञता: समश्टि अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

डॉ. अमित कुमार
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता: नवप्रवर्तन, दूरदर्शिता एवं नियंत्रण

सुश्री श्रेया पान
अनुसंधान सहायक
विशेषज्ञता: वैश्विक व्यापार

श्री चंदन
अनुसंधान सहायक

श्री इमदादुल इस्लाम हाल्दर
अनुसंधान सहायक
विशेषज्ञता: राजनीति अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

सलाहकार/विजिटिंग फैलो

प्रो. टी सी जेम्स
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर) कानून एवं संबद्ध नीति

डॉ. टी.पी. राजेंद्रन
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर) कानून एवं संबद्ध नीति

डॉ. के रवि श्रीनिवास
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: विकास अर्थव्यवस्था, परिवेक्षण एवम परिणाम निर्धारण

डॉ. सुशील कुमार
सलाहकार
विशेषज्ञता: अतंर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

डॉ. दूराईराज कुमारासामी
सलाहकार
विशेषज्ञता: अतंर्राष्ट्रीय व्यापार, एवं विदेश निवेश एवं व्यवहारिक अर्थमिति

श्री सुभोमॉय भट्टाचार्य
सलाहकार

प्रो. संदीप सिंह परमार
सलाहकार
(20 जुलाई 2016 तक)

सुश्री अदिति गुप्ता
सलाहकार
(8 अगस्त 2016 तक)

श्री एस एन सुलेमान
सलाहकार
(12 जनवरी 2017 तक)

अनुसंधान सहायक

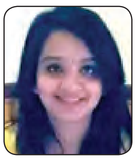

सुश्री आस्था गुप्ता

श्री प्रत्यूष

डॉ ज्योति जैसवाल

सुश्री प्रतिवा सॉव

सुश्री गुलफिसान निजामी

सुश्री मोनिका शर्मा

सुश्री सानुरा फर्नांडिज़

सुश्री श्रुति खन्ना

सुश्री उपासना सिकरी

सुश्री अंकिता गर्ग

सुश्री दिप्ती भाटिया

सुश्री ओपिंद्रं कौर

सुश्री दिशा मेहन्दीरत्ता *(14 अक्टूबर 2016 तक)*
श्री दिव्य प्रकाश *(21 दिसम्बर 2016 तक)*
सुश्री हरप्रीत कोर *(30 अप्रैल 2016 तक)*
सुश्री कशिका अरोड़ा *(15 जूलाई 2016 तक)*

सुश्री कीर्ति सचदेवा *(9 दिसम्बर 2016 तक)*
सुश्री नित्या बत्रा *(30 अप्रैल 2016 तक)*
सुश्री पल्लवी मनचंदा *(31 मार्च 2017 तक)*
सुश्री श्रेया मल्होत्रा *(31 मई 2016 तक)*
सुश्री पंखुड़ी गौर *(14 जून 2016 तक)*

सहायक वरिष्ठ अध्येता

प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल
आरबीआई चेयर प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलेपमेंट स्टडीज़, केरल

प्रोफेसर हरिबाबू एजनावरजाला
पूर्व वाइस–चांसलर इन्चार्ज,
हैदराबाद विश्वविद्यालय

प्रो. मुकुल अशर
प्रोफेसर, ली कुआन येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. बालाकृष्णा पिसुपति
पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, भारत सरकार

डॉ. अमृता नरलिकर
अध्यक्ष, वैश्विक और क्षेत्रीय अध्ययन के लिए जर्मन संस्थान (GIGA), हैम्बर्ग, जर्मनी हैम्बर्ग

डॉ. बेनू शानईडर
संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही, जिनमें अंकटाड भी है, तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी सलहाकार रहीं।

सहायक अध्येता

डॉ. केविन पी गालाघेर,
प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी

डॉ. रामकिशन एस राजन
एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जार्ज मैसॉन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डी.सी.

डॉ. सूमा अथरयी
रीडर, ब्रूनल बिज़नेस स्कूल, ब्रूनल यूनिवर्सिटी, अक्सब्रिज

डॉ. श्रीविद्या रागवन
एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, कॉलेज ऑफ लॉ, नॉरमन, ओक्लाहोमा

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री महेश सी अरोड़ा
निदेशक, वित्त एवं प्रशासन

महानिदेशक कार्यालय

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रभारी, महानिदेशक कार्यालय
श्रे एन एन कृष्णन, निजी सचिव
श्रीमती रिंतु परनामी, निजी सचिव
श्री सचिन कुमार, सचिवीय सहायक

प्रकाशन विभाग

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी
श्री सचिन सिंघल, प्रकाशन सहायक
(वेब और डिजाइन)
सुश्री रूचि वर्मा, प्रकाशन सहायक

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र

श्रीमती ज्योति, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती सुशीला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक

श्रीमती सुषमा भट्ट, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
श्री चन्द्र शेखर पुरी, उपनिदेशक, प्रणाली
श्रीमती पूनम मल्होत्रा, कम्प्यूटर सहायक
श्री सत्यपाल सिंह रावत, जूनियर सहायक
श्रीमती गीतिका शर्मा, डाटा एंट्री आपॅरेटर
श्री राहुल भारती, वेब डिजाइनर

वित्त एवं प्रशासन

श्री वी कृष्णामणि, उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा)
श्री डी पी काला, उपनिदेशक (प्रशासन एवं स्थापना)
श्रीमती शीला मल्होत्रा, अनुभाग अधिकारी (लेखा)
श्री हरकेश, अनुभाग अधिकारी
श्रीमती अनु बिष्ट, सहायक
श्री सुरजीत, लेखाकार
श्री अनिल गुप्ता, सहायक
श्री पियूष वर्मा, अवर श्रेणी लिपिकं
श्रीमती शालिनी शर्मा, स्वागती

अनुसंधान सहयोग

सुश्री किरन वाघ, निजी सचिव
श्री सुरेन्द्र कुमार, निजी सहायक
श्रीमती बिन्दु गंभीर, आशुलिपिक
सुश्री गोहर नाज़, सचिवीय सहायक

सहायक स्टाफ

श्री सत्यवीर सिंह, वरिष्ठ स्टाफ कार चालक
श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक
श्री बलवान, दफ्तरी
श्री प्रदीप
श्री राजू
श्री राज कुमार
श्री मनीष कुमार
श्री सुधीर राणा
श्री राज कुमार
श्री बिरजू
श्री प्रदीप नेगी

VIII

वित्तीय विवरण

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

8, सेकेंड फ्लोर, कृष्णा मार्केट, कालका जी, नई दिल्ली–110019

टेलीफोन : 32500444, टेलीफैक्सः 40590344, ई–मेलः skacamail@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली की आम सभा के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) से संबंधित वित्तीय विवरण, जिनमें 31 मार्च, 2017 तक की बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाते तथा समाप्त हुए वर्ष की रसीद और भुगतान खाता और अन्य विवरणात्मक सूचनाएं भी शामिल हैं, का लेखा जोखा किया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरादायित्व

इन वित्तीय विवरणों, जो आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं सोसाइटी की प्राप्ति और भुगतान की वास्तविक एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन पर है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है जो एक वास्तविक एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, चाहे यह झूठे वर्णन के कारण हो या त्रुटि के कारण।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा जोखा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने से संबंधित है। हमने अपना लेखाजोखा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुरुप किया है। इन मानकों के लिए जरुरी है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें एवं इसका युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा जोखा करें कि ये वित्तीय विवरण भौतिक रूप से त्रृटिरहित हैं या नहीं।

किसी लेखा जोखा में वित्तीय विवरणों की राशियों एवं खुलासों के बारे में लेखा जोखा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रियाएं शामिल रहती हैं। चुनी गई प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की भौतिक त्रुटि, चाहे वे धोखाधड़ी से की गई हों, या गलती से हुई हो, के जोखिमों के आकलन समेत, लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

उन जोखिम आकलनों में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों, जो वास्तविक एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, की इकाई की तैयारी के लिए उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे कि ऐसी लेखा जोखा प्रक्रियाओं की डिजाइन बनाई जा सके जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेकिन इकाई की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्वेश्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

किसी लेखा जोखा में उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतिकरण भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा जोखा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी लेखा जोखा राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं राय

हम रिपोर्ट करते हैं कि

i) हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगी एवं प्राप्त की हैं, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के हमारे प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

ii) हमारी राय में सोसाइटी द्वारा खाता बही को समुचित प्रकार से रखा गया है, जैसाकि अभी तक खाता बही की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

iii) बैलेंस शीट, आय व्यय खाते एवं प्राप्ति तथा भुगतान खाते जो इस रिपोर्ट से संबंधित हैं, खाता बही के अनुरुप हैं।

iv) हमारी राय में, बैलेंस शीट, आय व्यय खाते एवं प्राप्ति तथा भुगतान खाते जो इस रिपोर्ट से संबंधित हैं, खाता बही के अनुरुप हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

v) हमारी राय में एवं हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कथित विवरण वास्तविक एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जो आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं :

क. 31 मार्च, 2017 तक सोसाइटी कार्यों के बैलेंस शीट के मामले में

ख. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटा के आय व्यय खाते के मामले में ;

ग. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों के खाते के मामले में

कृते
सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. 008714C

ह.
(कृष्णा कुमार सिंह)
साझेदार, सदस्य सं. 077494

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26.10.2017

fodkl'khy n'kk d fy, vu l/kku ,o lpuk i.kkyh
1860 d lkslkbVht iathdj.k vf/kfu;e d rgr iathdr ,d lkslkbVh

31 ekp] 2017 rd dh cSyal 'khV

e jkf'k

	Sch. #	31 ekp 2017 rd	31 ekp] 2016 rd
mRrjnkf;Ro			
vul/kku ,o fodkl QM	1	9,22,28,864.03	9,24,18,034.41
LFkk;h ifjlifRr QM ¼xj&,Qlhvkj,½	2	2,59,59,312.23	2,71,76,848.20
LFkk;h ifjlifRr QM ¼,Qlhvkj,½		1,66,436.00	1,95,808.00
ik;kftr ifj;ktukvk ij v0;f;r jkf'k ¼xj&,Qlhvkj,½	3	92,07,221.96	45,10,582.97
ik;kftr ifj;ktukvk ij v0;f;r jkf'k ¼,Qlhvkj,½		83,26,956.23	31,13,547.56
oreku tokcnfg;k ,o iko/kku ¼xj&,Qlhvkj½	4	3,21,73,566.77	4,08,75,987.38
oreku tokcnfg;k ,o iko/kku ¼,Qlhvkj½		3,70,545.00	1,52,558.00
dy		**16,84,32,902.22**	**16,84,43,366.52**
ifjlifRr;k			
LFkk;h ifjlifRr;k ¼xj&,Qlhvkj,½	5	2,59,59,312.23	2,71,76,848.20
LFkk;h ifjlifRr;k ¼,Qlhvkj,½		54,60,017.00	63,00,254.00
ik;kftr ifj;ktukvk l olyh ;kX; jkf'k ¼xj&,Qlhvkj,½	3	1,61,55,234.04	2,76,80,987.92
ik;kftr ifj;ktukvk l olyh ;kX; jkf'k ¼,Qlhvkj,½		2,93,548.00	19,69,918.00
oreku ifjlifRr;k] _.k] vfxe vkfn ¼xj&,Qlhvkj,½	6	4,31,18,772.15	4,11,61,692.55
oreku ifjlifRr;k] _.k] vfxe vkfn ¼,Qlhvkj,½		7,74,46,018.80	6,41,53,665.85
dy		**16,84,32,902.22**	**16,84,43,366.52**

mYy[kuh; y[kkdu uhfr;k ,o y[kk ij ukV 15

vulph 1 l 15 y[kk dk ,d vrjx fgLlk g

gekjh fjikV d vu#i y[kk ijh{kd d gLrk{kj lyXu g

flg d".kk ,M ,lkfl,Vl d fy,
pkVM vdkmVVl
diuh dh jftLV'ku l[;k- 008714lh

fodkl'khy n'kk d fy, vul/kku ,o lpuk i.kkyh

dr
¼d".k dekj flg½
ikVuj
,e- l[;k- 077494

dr
eg'k lh vjkMk
fun'kd ¼foRr ,o i'kklu½

dr
ik- lfpu pronh
egkfun'kd

LFkku% ub fnYyh
rkjh[k % 26@10@2017

fodkl'khy n'kk d fy, vul/kku ,o lpuk i.kkyh
1860 d lkslkbVht iathdj.k vf/kfu;e d rgr iathdr ,d lkslkbVh

31 ekp] 2017 dks lekIr o"k d fy, vk; ,o 0;; y[kk

e jkf'k

	vuqlwph #	31 ekp] 2017 dks	31 ekp] 2016 dks
vk;			
fon'k e=ky;] Hkkjr ljdkj l vunku lgk;rk	4(a)	6,76,73,303.00	5,27,15,708.00
dk;Øe 0;;k dh ifr d fy, gLrkrfjr ik;kftr ifj;ktuk vunku ¼xj&,Qlhvkj, ,o ,Qlhvkj,½	3	4,91,76,714.50	6,16,25,820.29
ik;kftr ifj;ktukvk d lekiu ij gLrkrfjr vf/k'k"k jkf'k ¼xj&,Qlhvkj, ,o ,Qlhvkj,½	3	5,95,109.01	14,83,999.07
jk;YVh] idk'kuk vkfn l vk; ¼ xj&,Qlhvkj,½		98,844.00	97,413.00
vftr 0;kt			
fe;knh tekvk ij ¼,Qlhvkj,½		49,77,652.00	53,86,779.37
fe;knh tekvk ij ¼xj&,Qlhvkj,½		16,58,616.00	23,55,234.60
cpr [kkrk@vkVk Lohi [kkr ¼,Qlhvkj,½		3,36,644.00	1,22,731.00
cpr [kkrk@vkVk Lohi [kkr ¼xj&,Qlhvkj,½		2,87,373.00	7,22,938.00
depkfj;k dk _.k ij ¼xj&,Qlhvkj,½		17,359.00	19,943.00
vk; dj fjQM ij ¼xj&,Qlhvkj,½		27,901.00	-
vU; fofo/k vk; ¼xj&,Qlhvkj,½		36,113.00	2,999.92
ik;kftr ifj;ktukvk l c/k [kp d fy, olyh ¼xj ,Qlhvkj, ,o ,Qlhvkj,½		23,86,569.00	18,42,243.45
io vof/k vk;		2,21,214.00	1,38,090.00
LFkk;h ifjlifRr QM&cph xb@cVV [kkr e Mkyh xb ifjlifRr;k dh MCY;-Mh-oh- l gLrkrfjr jkf'k ¼xj&,Qlhvkj, ,o ,Qlhvkj,½	2	4,176.00	59,805.00
LFkk;h ifjlifRr QM&Hkkjr ljdkj@ik;kftr ifj;ktukvk l vunku lgk;rk [kjhnh xb LFkk;h ifjlifRr;k ij voeY;u l gLrkrfjr jkf'k ¼xj&,Qlhvkj, ,o ,Qlhvkj,½	2	25,69,428.97	25,78,323.80
vul/kku ,o fodkl QM dk gLrkrfjr ?kkVk		1,89,170.38	2,25,499.29
dqy		**13,02,56,186.86**	**12,93,77,527.79**
0;;			
dk;Øe 0;;&ik;kftr ifj;ktuk, ¼xj&,Qlhvkj, ,o ,Qlhvkj,½	7	4,91,76,714.50	6,16,25,820.29
LFkkiuk 0;; ¼xj ,Qlhvkj,½	8	4,66,79,159.00	4,25,37,858.00
i'kklfud ,o vU; dk;Øe 0;; ¼xj&,Qlhvkj,½	9	2,83,00,672.79	2,16,62,160.76
i'kklfud ,o vU; dk;Øe 0;; ¼,Qlhvkj,½	10	1,70,733.39	898.94
LFkk;h ifjlifRr;k dk voeY;u ¼xj ,Qlhvkj, ,o ,Qlhvkj,½	5	33,80,293.97	35,18,582.80
ik;kftr ifj;ktukvk d lekiu ij gLrkrfjr ?kkVk jkf'k ¼xj&,Qlhvkj, ,o ,Qlhvkj,½	3	25,29,539.21	10,371.00
vof/k io 0;;		19,074.00	21,836.00
dqy		**13,02,56,186.86**	**12,93,77,527.79**

mYy[kuh; y[kkdu uhfr;k ,o y[kk ij ukV 15

vuqlph 1 l 15 y[kk d vrjx fgLl dk fuek.k djr g

gekjh fjikV d vu#i y[kk ijh{kd d gLrk{kj lyXu g

flg d".kk ,M ,lkfl,Vl d fy,
pkVM vdkmVVl
diuh iathdj.k l[;k ¼ 008714lh

dr
¼d".k dekj flg½
ikVuj
,e l[;k - 077494

Lfkku% ub fnYyh
rkjh[k % 26@10@2017

fodkl'khy n'kk d fy, vul/kku ,o lpuk i.kkyh d fy,

dr
eg'k lh- vjkMk
fun'kd ¼foRr ,o i'kklu½

dr
ik- lfpu pronh
egkfun'kd

fodkl 'khy n'kk dh fy, vuql/kku ,oa lpuk i.kkyh
1860 dh lkslkbVh iathdj.k vf/kfu;e ds rgr iathd`r ,d lkslkbVh

31 ekp] 2017 dks lekIr o"kZ dh fy, ikfIr ,oa Hkqxrku [kkrk

jkf'k

	ikfIr	o"kZ lekIr 31 ekpZ 2017		o"kZ lekIr 31 ekpZ 2016			Hkqxrku	o"kZ lekIr 31 ekpZ 2017		o"kZ lekIr 31 ekpZ 2016	
d	jksdM					d	O;; ¼xSj ,Q lh vkj ,½				
i)	gkFk jksdM ¼xSj&,Q lh vkj ,½	19,891.00		30,987.00		i)	LFkkiuk O;; lqph vuqlqph 11	4,61,04,957.00		4,12,25,641.00	
ii)	cSad e 'ks"k jkf'k ¼ cpr [kkrk &vkW/kk cSad e	1,01,741.00		87,412.00		ii)	i'kqlfud ,o vU; dk;Øe O;; vuqlqph 12	2,93,80,453.50		2,09,48,767.38	
	cpr [kkrk&vkVks Lohi e &cSad vkQ bfM;k ¼xSj&,Q lh vkj ,½	52,71,972.20		2,41,03,735.28		iii)	dk;Øe O;; &ik;ksftr ifj;kstuk, ¼vuqlqph &14½	4,65,16,738.14		4,68,02,712.47	
	cpcpr [kkrk&vkVks Lohi e &cSad vkQ bfM;k ¼,Q lh vkj ,½	8,21,227.82		28,29,948.96		iv)	io vof/k O;;	19,074.00		21,836.00	
							dqy d		12,20,21,222.64		10,89,98,956.85
	LFkk;h tekvks e &cSad vkQ bfM;k ¼,Q lh vkj ,½	5,96,42,628.55		5,44,75,828.13		[k	O;; ¼,Q lh vkj ,½				
	LFkk;h tekvks e &cSad vkQ bfM;k ¼xSj&,Q lh vkj ,½	3,18,46,957.59		3,00,47,127.45		i)	i'kqlfud ,o vU; dk;Øe O;; vuqlqph 13	1,70,733.39		898.94	
iii)	Ýfdx e'khu e Mkd fVdV 'ks"k ¼xSj&,Q lh vkj½	99,432.00		1,56,248.00		ii)	dk;Øe O;; &ik;ksftr ifj;kstuk, ¼vuqlqph &14½	85,30,542.36		90,00,881.37	
	dqy d		9,78,03,850.16		11,17,31,286.82		dqy [k		87,01,275.75		90,01,780.31
[k	ikfIr vuqnku					x	LFkk;h ifjlEifRr;ksa dh fy,				
i)	fon'k e=ky;] Hkkjr ljdkj l	6,90,00,000.00		5,85,00,000.00		i)	LFkk;h ifjlEifRr;k d fy, Hkqxrku ¼xSj ,Q lh vkj ,½	13,66,838.00		67,45,953.00	
ii)	fofHkUu ik;ksftr ifj;kstukvks l ¼xSj&,Q lh vkj½	5,38,34,438.14		3,40,09,427.97			dqy x		13,66,838.00		67,45,953.00
iii)	fofHkUu ik;ksftr ifj;kstukvks l ¼,Q lh vkj½	1,65,20,017.70		39,26,539.00		?k	vfxze ,oa tek,a				
						i)	vfxze ¼xSj ,Q lh vkj ,½	6,32,189.00		1,55,179.00	
	dqy [k		13,93,54,455.84		9,64,35,966.97	ii)	vfxze ¼,Q lh vkj ,½	1,09,388.00		2,157.00	
						iii)	ikl; VhMh,l ¼xSj ,Q lh vkj ,½	1,77,768.00		4,01,079.00	
x	ikfIr C;kt										
i)	_.kksa vfxzek vkfn ij C;kt ¼xSj&,Q lh vkj ,½	44,852.00		19,943.00		iv)	ijkuk pd ¼xSj ,Q lh vkj ,½	2,815.00		-	
							dqy ?k		9,22,160.00		5,58,415.00
ii)	cpr cSd [kkrk@vkVks Lohi ¼,Q lh vkj ,½	3,36,644.00		1,37,810.00		M	vU;				
						i)	okil fd;k x;k vuqnku ¼xSj&,Q lh vkj ,½	-		5,20,641.00	
iii)	LFkk;h tek [kkrk ij C;kt ¼xSj&,Q lh vkj ,½	6,12,717.76		64,69,662.02		ii)	Hkqxrku fd;k x;k lsok dj	13,60,898.00		15,43,443.00	
						iii)	vkjvkb,l Hkkfo"; fuf/k dk Hkqxrku jkf'k	2,73,240.00		-	
iv)	LFkk;h tek [kkrk ij C;kt ¼,Q lh vkj ,½	44,57,330.48		71,83,438.59			dqy M-		16,34,138.00		20,64,084.00
v)	cpr cSd [kkrk@vkVks Lohi ¼xSj&,Q lh vkj ,½	2,82,741.00		7,19,039.00							
vi)	cpr cSd [kkrk ij C;kt & vkW/kk cSd ¼xSj&,Q lh vkj ,½	4,632.00		3,899.00							
	dqy x		57,38,917.24		1,45,33,791.61						
	dqy vkxs LFkkukarfjr		**24,28,97,223.24**		**22,27,01,045.40**		dqy vkxs LFkkukarfjr		**13,46,45,634.39**		**12,73,69,189.16**

	ikfIr	o"kZ lekIr 31 ekpZ 2017		o"kZ lekIr 31 ekpZ 2016	
	dqy fiNNyk tksM+		**24,28,97,223.24**		**22,27,01,045.40**
?k	vU; vk;				
i)	iqLrdksa dh fcØh ¼xj&,Q lhvkj,½	11,120.00		8,500.00	
ii)	jk;YVh ¼xj&,Q lhvkj,½	80,207.00		1,08,395.00	
iii)	fofo/k vk; ¼xj&,Q lhvkj,½	33,837.00		2,999.92	
iv)	iwoZ vof/k vk;	2,48,174.00		-	
	dqy ?k		3,73,338.00		1,19,894.92
M-	vfxze ,oa tekjkf'k				
i)	_.k@vfxze dh olwyh ¼xj&,Q lhvkj,½	76,288.00		2,26,746.00	
ii)	depkfj;ksa ls izkIr vfxze ¼xj&,Q lhvkj,½	1,18,144.00		2,82,715.00	
iii)	ijkus pSd ¼xj&,Q lhvkj,½	-		24,355.00	
iv)	vfxze esa izkIr jkf'k ¼xj&,Q lhvkj,½	86,737.10		2,73,240.00	
	dqy M-		2,81,169.10		8,07,056.00
p	vU;				
i)	LFkk;h ifjlEifRr;ksa dh fcØh	500.00		1,600.00	
ii)	izkIr lsok dj	7,08,341.00		15,43,443.00	
iii)	vk; dj fjQaM	3,28,229.00		-	
	dqy p		10,37,070.00		15,45,043.00
	dqy		**24,45,88,800.34**		**22,51,73,039.32**

	Hkqxrku	o"kZ lekIr 31 ekpZ 2017		o"kZ lekIr 31 ekpZ 2016	
	dqy fiNNyk tksM+		**13,46,45,634.39**		**12,73,69,189.16**
p	vfrfjDr jkdM+				
i)	gkFk esa udn ¼xj&,Q lhvkj,½	33,130.00		19,891.00	
ii)	cSd esa 'ks"k jkf'k % vk/kkj cSd d cpr [kkrs esa ¼cj&,Q lhvkj,½	1,38,437.00		1,01,741.00	
	cpr [kkrs@vkVks LohIi&cSd vkQ bfM;k esa ¼xj&,Q lhvkj,½	43,71,201.80		52,71,972.20	
	cpr [kkrs@vkVks LohIi&cSd vkQ bfM;k esa ¼,Q lhvkj,½	90,26,540.77		8,21,227.82	
	LFkk;h tekvk&cSd vkQ bfM;k esa ¼,Q lhvkj,½	6,40,99,959.03		5,96,42,628.55	
	LFkk;h tekvk&cSd vkQ bfM;k esa ¼xj&,Q lhvkj,½	3,20,73,086.35		3,18,46,957.59	
iii)	Ýfdx e'khu esa Mkd fVdV dh 'ks"k jkf'k ¼xj&,Q lhvkj,½	2,00,811.00		99,432.00	
	dqy p		10,99,43,165.95		9,78,03,850.16
	dqy		**24,45,88,800.34**		**22,51,73,039.32**

y[kk ij mYy[kuh; y[kkdu uhfr;k ,o ukV l ¼vuqlph 15½

vuqlph 1 l 15 y[kk d ,d vfHkUu fgLl dk fuekZ.k djr g

gekjh fjikVZ d vuq#i y[kk ijh{kd d gLrk{kj lyXu g

fIg d".kk ,M ,IkfI,VI d fy,
pkVMZ vdkmUVsI
diuh dh jftLV'ku l[;k % 008714lh

fodkl'khy n'kksa d fy,vuqla/kku ,o lpuk iz.kkyh d fy,

dr
¼d".kk dekj fIg½
ikVuj
,e l[;k- 077494

dr
eg'k lh vjkMk
fun'kd ¼foRr ,o i'kklu½

dr
ik- lfpuprqonh
egkfun'kd

LFkku % ub fnYyh
rkjh[k % 26@10@2017

आरआईएस विकासशील देशों का शोध संस्थान

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रिय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन कार्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के पटल पर नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इसकी वेबसाइट wwww.ris.org.in देखें।

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003, भारत
दूरभाष: 91-11-24682177-80 फैक्स: 91-11-24682173-74
ई-मेल: dgoffice@ris.orgin वेबसाइट: http://www.ris.org.in